



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(संख्या-171004)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 19 मिनव्वर, 1994 28 भाद्रपद, 1916

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रधिमन्त्रि

शिमला-171004, 19 मिनव्वर, 1994

संख्या-159/94-वि० म०.—हिमाचल प्रदेश नगरपालिका विधेयक, 1994 (1994 विधेयक संख्यांक 21)
जो कि प्राज्ञ दिनांक 19 मिनव्वर, 1994 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरः रखा जा रहा है किमती

प्रति हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रतिभा 05 वारी मजालत नियमावली, 1953 के नियम 135 के अन्तर्गत सभे
समाधारण मजालती राजपत्र में मद्रिप वरने हेतु प्रेषित की जाती है,

प्रकाशित/-

प्रमाणित,
मन्त्रि ।

1994 का विधेयक नम्बर 21

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधेयक, 1994

(विधान सभा में प्रस्तावित रूप में)

हिमाचल प्रदेश में नगरपालिकाओं में सर्वोच्च विधि का अधिकार और सर्वोच्च न्याय प्रविष्टावित्त करने के लिए विधेयक।

नगर नगरपालिका में निम्नलिखित रूप में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निर्धारित रूप में यह अधिनियमित है:

अध्याय।

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का शीर्षक नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 है। संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह 30 मई, 1994 को प्रवृत्त होगा और प्रवृत्त हुआ समस्त लागू।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि अध्याय या संदर्भ में कोई बात विरोध न हो, परिभाषा।

(1) मर्यादित प्रवृत्त निर्मा प्रत्येक विधि में निम्न बात के अर्थ हैं या "नियम न्याय" में अधिनियम है:—

(क) शक्ति की दशा में:—

(i) ऐसा मर्यादित विधि निर्मा या मर्यादित प्रवृत्त विधि निर्माण नियमन में संबंधित विधि के प्रधान नियम उचित विधि के आधार पर निर्माण किया जाएगा; या

(ii) जहाँ मर्यादित (i) में निर्दिष्ट कोई भी उचित विधि निर्माण नहीं किया गया है, वहाँ ऐसा मर्यादित विधि निर्माण, जिस पर उचित विधि पर दिया जाता प्रमाणित है या जिस पर वह वास्तव में विधि पर ही जारी है, उनमें से जो भी अधिक हो:

परन्तु ऐसी शक्ति की दशा में, जिसके अन्तर्गत या उसके अन्तर्गत कोई अन्य कानून निर्माण किया गया है प्रत्येक निर्माण प्रमाणित पूर्णता या धन: निर्माण, प्रमाणित,

भौतिका जगत्सुविष्ट किया गया है, वापिस मूल्य, यदि राज्य सरकार इन प्रकार निर्दिष्ट करे, तो निम्नलिखित शर्तियों के योग से दुगुना समझा जाएगा, अर्थात् :—

- (i) भूमि पर तत्काल निर्धारित भू-राजस्व या उसके बदले में किसी अन्य कर की राशि, चाहे इस प्रकार निर्धारित राशि उद्ग्रहणीय है या नहीं, अथवा जब भू-राजस्व पूर्णतः या अंशतः प्रशमित या मोचित किया गया है, तो वह राशि, जो उद्ग्रह्य होती, यदि ऐसा प्रशमित या मोचित न किया गया होता ; और
- (ii) जब नहर सिंचाई के कारण भूमि के सुधार को भू-राजस्व निर्धारित करने में हिताय में नहीं किया गया, तो स्वामी उप-शुल्क या जल सुविधा उप-शुल्क अथवा ऐसे सुधार के बारे में लगाए गए अन्य उप-शुल्क की राशि ;

(ख) किसी गृह या निर्माण तथा उसके ऐसे अनुलग्नकों या फर्नीचर की दशा में जो उनके साथ उपयोग या उपयोग के लिए निम्नलिखित शर्तियों के अधीन किया पर दिया जाए :—

- (i) मूल्य वापिस किराए के दस प्रतिशत से अधिक की ऐसी कटौती, जिसे समिति प्रत्येक विशिष्ट मामले में ऐसे गृह या निर्माण के साथ किराए पर दिए गए फर्नीचर के मद्दे मुक्तियुक्त छूट समझे ;
- (ii) मुकदमों के खर्च के लिए तथा ऐसे अन्य सभी व्ययों के लिए, जो निर्माण को ऐसा सकल वापिस किया सुनिश्चित करने वाली दशा में बनाए रखने के लिए आवश्यक हों, सकल वापिस किराए के दस प्रतिशत की कटौती। इन उप-खण्ड के अधीन कटौती, मद्दे (1) के अधीन कटौती, यदि कोई हो, करने के पश्चात् सकल वापिस किराए के अतिरिक्त पर संगणित की जाएगी ;
- (iii) जहां किसी निर्माण के साथ भूमि किराए पर दी जाती है सकल वापिस किराए के दस प्रतिशत से अधिक की ऐसी कटौती, जो समिति प्रत्येक विशिष्ट मामले में, ऐसा सकल वापिस किया सुनिश्चित करने वाली दशा में, भूमि को बनाए रखने के लिए स्वामी द्वारा वापिस रूप में दिये गये वास्तविक व्यय, यदि कोई हो, के मद्दे मुक्तियुक्त समझे।

शर्तिकाकरण 1.—इन खण्ड के प्रयोजनों के लिए, इस बात का कोई महत्व नहीं है कि गृह या निर्माण और उसके साथ उपयोग या उपयोग के लिए किराए पर दिया गया फर्नीचर तथा भूमि एक ही संविदा द्वारा किराए पर दिये गये हैं या विभिन्न संविदाओं द्वारा, और यदि विभिन्न संविदाओं द्वारा किराए पर दिये गये हैं तो चाहे ऐसी संविदाएं एक ही समय की गई हैं या विभिन्न समयों पर।

शर्तिकाकरण 2.—“सकल वापिस किया” पद के अन्तर्गत स्वामी द्वारा संदेय कोई ऐसा कर नहीं होगा जिसके बारे में स्वामी और किराएदार सहमत हो गये हैं कि वह किराएदार द्वारा संदेय किया जाएगा ;

- (ग) किसी ऐसे गृह या निर्माण की दशा में जिसका सकल वापिस किराया खण्ड (1) या खण्ड (ख) के अधीन अध्यागत नहीं किया जा सकता ;

- (i) भूमि की दशा में, भूमि की लागत का दस प्रतिशत ; और

(ii) निर्माण की दशा में, परिनिर्माण और भूमि की लागत की राशि का दम प्रतिगत :

परन्तु किसी निर्माण के आनुपातिक मूल्य की संगणना में, इस प्रकार अवधारित अनु-
पातिक मूल्य के दम प्रतिगत की, मरम्मत की लागत और निर्माण को सुरक्षित रखने के
लिए अन्य सभी खर्चों के लिए पटौती की जाएगी :

परन्तु यह और कि जहाँ भवन उनके अपने निवास के प्रयोजनों के लिए स्वामी के अधि-
भोग में है, तो वाणिज्य मूल्य प्रथमतः खण्ड (ग) के अनुसार अवधारित किया जाएगा
और आगे कम किया जाएगा—

(i) जहाँ उसके अपने अधिभोग के अधीन आच्छादित क्षेत्र एक सी वर्ग मीटर से कम
अधिक है; इस प्रकार अवधारित पूरी रकम
द्वारा ।

(ii) जहाँ किसी भवन का आच्छादित क्षेत्र एक सी वर्ग मीटर से अधिक है । प्रथम सी वर्ग मीटर के लिए इस प्रकार
अवधारित पूरी रकम द्वारा और
उस क्षेत्र के लिए, अवधारित रकम
के आधे द्वारा, जिसमें यह एक सी
वर्ग मीटर से अधिक है;

(घ) जहाँ सम्पूर्ण भूमि या निर्माण का सकल वाणिज्य किराया, किसी भी खण्ड
(क), (ख) और (ग) के अधीन अवधारित नहीं किया जा सकता, —

(i) ऐसी भूमि या निर्माण के उस भाग या प्रभाग के संबंध में जिनका खण्ड (क) या
खण्ड (ख) लागू होता है, उक्त खण्ड के अधीन यथा अवधारित ; और

(ii) ऐसी भूमि या निर्माण के शेष भाग या प्रभाग के संबंध में, खण्ड (ग) के
अधीन यथा अवधारित ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए "भूमि की लागत" और "निर्माण के
परिनिर्माण की लागत" में भूमि की लागत और/या, यथास्थिति, किसी
भूमि के कय लिए जले के समय निर्माण के परिनिर्माण और/या
निर्माण की लागत, अभिप्रेत है ।

(2) "पिछड़े वर्ग" में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में निहित ऐसे वर्ग
अभिप्रेत है, जिनकी राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के प्रयोजन
में, पहचान की जाए और अधिसूचित किये जाएं ;

(3) "निर्माण" में अभिप्रेत है कोई दुकान, मकान, झोपड़ी, वाहन-गृह, पशुशाला,
कारखाना, औद्योगिक गैड और तन्त्रियों द्वारा अस्थायी तौर पर परिनिर्मित संरचना और
मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए बनाई गई संरचनाएँ, चाहे उन पर छत लगाई हो या नहीं,
चाहे वह मानवीय निवास के लिए अथवा अन्यथा उपयोग में लाई जाती हों और
चाहे वह संधा, ईंटों, लकड़ी, गारा, फूस, धातु अथवा किसी भी अन्य सामग्री से समन्वित
हो, और इसके अन्तर्गत कोई दीवार तथा कोई कुआँ है ;

(4) "निर्माण रेखा" में कोई ऐसी रेखा, जिसमें परे किसी निर्माण का अधभाग या
उसकी किसी वाहन दीवार का कोई भाग किसी विद्यमान या अस्थापित मार्ग की दिशा में
बाहर न निकले, अभिप्रेत है ;

(5) "निमित्त क्षेत्र" से किसी नगरपालिका क्षेत्र का वह प्रभाग, जिसका अधिकांश भाग गांवबार क्षेत्र या आवासीय क्षेत्र के रूप में विरहित हो चुका है, अभिप्रेत है ;

(6) "उप-विधियों" से इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उप-विधियां अभिप्रेत हैं ;

(7) "समिति" से इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन स्थापित या स्थापित मयसी गई कोई नगरपालिका समिति, अभिप्रेत है ;

(8) "कम्पोस्ट खाद" से, गांव से निधियों द्वारा विहित रीति में कम्पोस्ट खाद बनाने की प्रक्रिया के अधीन तैयार किया गया उत्पाद अभिप्रेत है ;

(9) "उपायुक्त" या "जिले का उपायुक्त" के अन्तर्गत अतिरिक्त उपायुक्त या राज्य सरकार द्वारा किसी जिले या किसी जिलों में इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त के कृत्यों का पालन करने के लिए किसी भी समय नियुक्त कोई अन्य अधिकारी है ;

(10) "निर्देशक" से, राज्य सरकार द्वारा नगराय स्थानाय निकायों का नियुक्त किया गया निर्देशक अभिप्रेत है ;

(11) "जिला" से, राजस्व जिला अभिप्रेत है ;

(12) "जिला योजना समिति" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य घ और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 185 के अधीन जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को जिला स्तर पर लक्षित करने के लिए गठित समिति, अभिप्रेत है ;

(13) "शुद्ध शीचघर" से, ऐसा शीचघर अभिप्रेत है जिसमें मल-मूत्र आशीर्षक तौर पर हटाया जाता है ;

(14) "गांवबार" से बिछा, मल-जल, कूड़ा-करकट, कीचड़, कड़ा-कचरा, गन्दगी या काठ-कबाड़ अथवा किसी प्रकार का जाल्तव द्रव्य, अभिप्रेत है ;

(15) "निर्वाचन" से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निर्वाचन कराए जाने की अधिसूचना की तारीख को और से प्रारम्भ होने वाली और उसके परिणामों को घोषित किए जाने और अधिसूचित किए जाने की तारीख को समाप्त होने वाली सारी निर्वाचन प्रक्रिया है ;

(16) "किसी निर्माण के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण" के अन्तर्गत है —

(क) किसी निर्माण में तात्त्विक परिवर्तन या परिवर्धन ;

(ख) किसी ऐसे निर्माण का जो मूलतः मानवीय निवास के लिए सन्निहित न हो संरचनात्मक परिवर्तन द्वारा मानवीय निवास के लिए स्थान में संपरिवर्तन ;

(ग) किसी ऐसे निर्माण का, जो मूलतः मानवीय निवास के लिए एक स्थान के रूप में सन्निहित हो, मानवीय निवास के लिए एक से अधिक स्थानों में संपरिवर्तन ;

(घ) मानवीय निवास के दो या अधिक स्थानों का ऐसे स्थानों को अधिकतर संख्या में संपरिवर्तन ;

(क) किसी निर्माण के ऐसे परिवर्तन जो उसकी जल-निर्गत व्यवस्थाओं या सफाई व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन लाते हैं, या उसकी मुक्ता कोताधिक रूप में प्रभावित करते हैं ;

(ख) किसी निर्माण में किन्हीं कमरों, निर्माणों, बाह्यगृहों या अन्य संरचनाओं को जोड़ा जाना ;

(ग) किसी ऐसी दीवार में, जो किसी सड़क या ऐसी भूमि से जुड़ी हो, जो दीवार के स्वामी की न हो, ऐसी सड़क या भूमि की ओर खुलने वाले किसी दरवाजे का मर्मनिर्माण ;

(17) "कार्यकारी अधिकारी" से इस अधिनियम की धारा 305 के अधीन किसी नगरपालिका परिषद् के सम्बन्ध में कार्यपालक अधिकारी और नगरपंचायत के सम्बन्ध में सचिव के कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त व्यक्ति, चाहे किसी नाम से पुकारा जाए, अभिप्रेत है ;

1884 का 4 (18) "विस्फोटक", और "पेट्रोलियम" के वे ही अर्थ हैं, जो इन शब्दों के क्रमशः
1934 का विस्फोटक अधिनियम, 1884 तथा पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 में हैं ;
30.

1948 का (19) "कारखाना" का वही अर्थ होगा, जो उसे कारखाना अधिनियम, 1948 में
63. दिया गया है ;

(20) "संक्रामक रोग" से अभिप्रेत है, हैजा, प्लेग, चेचक, क्षय रोग या ऐसा अन्य भयानक रोग, जो राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे ;

(21) "निवासी" के अन्तर्गत है, कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी नगरपालिका क्षेत्र में या किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र में, जिसे सरकार ने, इस अधिनियम के अधीन अधिसूचना द्वारा, नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने की प्रस्तापना की है, सामान्यतः निवास कर रहा है या कारबार चला रहा है अथवा स्थावर संपत्ति का स्वामी है या उनका अधिभोग कर रहा है, और किसी विवाद की दशा में उसमें अभिप्रेत है, उपायुक्त द्वारा निवासी घोषित कोई व्यक्ति या एकाधिक व्यक्ति ;

(22) "नगरपालिका परिषद्" से इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित नगरपालिका परिषद् अभिप्रेत है ;

(23) "नगरपालिका क्षेत्र" से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है और कोई प्रादेशिक क्षेत्र जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर नगरपालिका का भाग है, इसके अन्तर्गत है ;

(24) "नगरपालिका" से, इस अधिनियम के अधीन गठित नगर पंचायत या नगरपालिका परिषद् के रूप में गठित स्वायत्त शासन संस्था, अभिप्रेत है ;

(25) "नगरपंचायत" से, इस अधिनियम के अधीन गठित नगर पंचायत अभिप्रेत है ;

(26) "न्युसेक्स" के अन्तर्गत है, कोई ऐसा कार्य, लोप, स्थान या वस्तु, जो देखने, सुनने या सुनने की शक्ति की क्षति, संकट, क्षोभ या उद्वेग कारित करती है, या उसका ऐसी हानि, संकट, क्षोभ या उद्वेग कारित करना संभाव्य है, अथवा जो जीवन के लिए कठपूर्ण अथवा स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए क्षतिकर है या हो सकती है ;

(27) "सिधोयोगी" के अन्तर्गत है, ग्रामीण स्वयं की भूमि या निर्माण के वास्तविक अधिभाग में, कोई स्वामी और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है, जो स्वामी को उस भूमि या निर्माण पर, जिसके बारे में यह शब्द प्रयुक्त किया जाता है, किया गया प्रयत्न किराये का कोई प्रभाग, उस समय दे रहा है या देने का दावा है, छद्मगत 6 और 10 के प्रयोजनों के लिए अधियोगी के अन्तर्गत होटल का भौतिक, संभाव्यता का स्वामी और कोई ऐसा स्वामी भी है, जिसके परिमर एक किराएदार से अधिक को किराए पर देने गये हैं ;

(28) "पदाधिकारी" से नगरपालिका के सम्बन्ध में नगरपालिका का अध्यक्ष, उप-अध्यक्ष या अध्यक्ष और नगर निगम के सम्बन्ध में नगर निगम का पार्षद, महापौर और उप-महापौर और पंचायत के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 को चारा 2 के खण्ड (23) में यथा परिभाषित पंचायत का पदाधिकारी अभिप्रेत है ;

(29) "स्वामी" के अन्तर्गत है, भूमि और निर्माणों का, प्रयत्न दोनों में से किसी का, चाहे स्वयं अपने लिए प्रयत्न किसी व्यक्ति या संगठित या न्यायी के रूप में या किसी धार्मिक प्रयत्न या पुरातन प्रयोजन के लिए उस समय किराया प्राप्त कर रहा व्यक्ति प्रयत्न वह व्यक्ति, जो यदि भूमि या निर्माण किसी किरायेदार को किराए पर दिया जाए, इस प्रकार किराया प्राप्त करेगा ;

(30) "पंचायत" में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन प्राणीय क्षेत्रों के लिए गठित स्वायत्त शासन संस्था (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए) अभिप्रेत है ;

(31) "जनसंख्या" में, अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिलिखित जनसंख्या, जिसके मुताबिक अंकित प्रकाशित कर दिए गए हैं, अभिप्रेत है ।

(32) "सार्वजनिक स्थान" में कोई ऐसा स्थान, जो जनता के उपयोग और उपयोग के लिए खुला है, चाहे वह निजी संपत्ति हो या नहीं और चाहे वह संपत्ति में निहित हो या नहीं, अभिप्रेत है ;

(33) "सार्वजनिक मार्ग" से अभिप्रेत है, कोई मार्ग, जो—

(i) इसमें पूर्व नगरपालिका विधि या अन्य लोक विधि में से समतल, विछाया, पक्का, धिरीदार, भल-प्रणालयुक्त या सुसज्जित किया गया है, जब तक कि ऐसे कार्य के निष्पादन होने से पूर्व स्वत्वधारी के साथ कोई ऐसा करार नहीं था कि मार्ग उससे सार्वजनिक मार्ग नहीं हो जाएगा, प्रयत्न जब तक ऐसा मार्ग स्वत्वधारी को विवक्षित या अभिव्यक्त सम्पत्ति के बिना नहीं किया गया था; प्रयत्न

(ii) द्वारा 182 के उपबन्धों के अधीन संपत्ति द्वारा सार्वजनिक मार्ग के रूप में घोषित किया जाता है या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन सार्वजनिक मार्ग हो जाता है ;

(34) "नियमों" में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं ;

(35) "अनुसूचित जाति" का वही अर्थ होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) में इसका है ;

(36) "अनुचित जनजाति" का वही धारा होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के अण्ड (25) में इगता है ;

(37) "राज्य निर्वाचन आयोग" मे राज्य सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 1994 का 6 243-ट और 243-यक और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रधीन गठित, निर्वाचन आयोग अधिप्रेत है ;

(38) "राज्य वित्त आयोग" मे राज्य सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-अ और 243-अ और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 98 के अधीन गठित, राज्य वित्त आयोग, अधिप्रेत है ;

(39) "मार्ग" से अधिप्रेत होगा, कोई गड़क, पटरी, चौक, प्रांगण, गण्डगडी, या रास्ता चाहे उस तक जनता की पहुँच स्यपी हो या अस्थापी और चाहे वह कोई सार्वजनिक मार्ग हो अथवा नहीं, और इसके अन्तर्गत होगी प्रत्येक खाली जगह, यह होने पर भी कि वह निजी संपत्ति है तथा किमी द्वारा, सम्वे, जंजीर या अन्य रोशक द्वारा अंगतः या पूर्णतः बाधित है, यदि वह भकानों, डुकानों या अन्य निर्माणों के साथ लगता हो और यदि वह कि-हीं व्यक्तियों द्वारा किमी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग को या से पहुँच के किमी साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, चाहे ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्माणों का अधिभोगी है या नहीं, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी जगह का कोई ऐसा भाग नहीं होगा, जिसके बारे में ऐसे किसी निर्माण को यथापूर्वोक्त रूप में प्रयोग करने में सभी अन्य व्यक्तियों को सभी समयों पर रोकने का अधिकार उसके अधिभोगी को प्राप्त है, और इसके अन्तर्गत होगी, उसके भीतर की, या उसके दोनों ओर में, में से किमी और की, नालियाँ, या पनालियाँ और भूमि, चाहे ये किसी साथ लगी हुई संपत्ति की सीमा तक, जिस तक जनता की पहुँच नहीं है, किमी बड़जे, बरामदे या अन्य परिनिर्माण में आच्छादित हों या नहीं ;

(40) "प्रतिष्ठित क्षेत्र" नगरपालिका की सीमाओं के भीतर कोई ऐसा क्षेत्र है, जो नमिनि की विशेष बैठक में ऐसे संकल्प द्वारा इस रूप में घोषित किया गया है, जो राज्य सरकार द्वारा पुष्ट कर दिया गया है, अथवा जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया गया है ;

(41) "यान" के अन्तर्गत कोई वाइसिकल, ट्राइसिकल तथा स्वचालित मोटर-कार और पहियों वाली प्रत्येक सवारी, जो सार्वजनिक मार्ग पर प्रयुक्त की जाती है या प्रयुक्त की जाने योग्य है ।

अध्याय-2

नगरपालिकाओं और नगरपालिका क्षेत्र का वर्गीकरण

3. (1) इस धारा के उपबन्धों के अनुसार नीचे यथा विनिर्दिष्ट तीन वर्गों की नगरपालिकाएँ गठित की जाएंगी:—

(i) दो हजार में अधिक जनसंख्या वाले संक्रमणशील क्षेत्र के निचे जिसका स्थानीय प्रशासन के लिए प्राप्त वार्षिक राजस्व पाँच लाख रुपये में अधिक है, "नगर पंचायत";

नगरपालिकाओं का वर्गीकरण ।

- (ii) पांच हजार से अधिक जनसंख्या वाले छोटे नगरों क्षेत्र के लिए जिनके स्थानीय प्रशासन के लिए प्राप्त वार्षिक राजस्व बीस लाख रुपये से अधिक है, "नगरपालिका परिषद्"; और
- (iii) पचास हजार से अधिक जनसंख्या वाले बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए जिसका स्थानीय प्रशासन के लिए प्राप्त वार्षिक राजस्व बी करोड़ रुपये से अधिक है और जिसे हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के अधीन शहरी क्षेत्र घोषित किया गया है, "नगर निगम"।

परन्तु इस धारा के अधीन कोई नगरपालिका, ऐसे नगरीय क्षेत्रों अथवा उसके भाग में गठित नहीं की जा सकती, जिसे राज्य सरकार, क्षेत्र के आकार तथा उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापन द्वारा उपबन्धित की जा रही तथा उपबन्धित की जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिका क्षेत्रों तथा ऐसे अन्य कारणों, जिन्हें वह ठीक भूमि, को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगर के रूप में विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु यह और कि कोई सेना छावनी या सेना छावनी का कोई भाग, किसी नगरपालिका का कोई भाग नहीं बनेगा ।

स्पष्टीकरण.— इस उप-धारा में, किसी "संक्रमणकालीन क्षेत्र", "किसी छोटे नगरीय क्षेत्र" या "किसी बृहत्तर नगरीय क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार, क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए प्राप्त राजस्व, कृषि इतर कार्य-कलापों में नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्व या ऐसी ही अन्य बातों को जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे, को ध्यान में रखते हुए इस धारा के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(2) राज्य सरकार, धारा 4 में अधिवर्धित विधि के संश्लेषण के बाद, इस धारा के उपबन्धों के अनुसरण में, अधिसूचना द्वारा नगरपालिकाओं का गठन करेगी और उस वग को विनिर्दिष्ट करेगी जिससे नगरपालिका सम्बन्धित होगी :

परन्तु इन अधिनियम के प्रारम्भ पर, विद्यमान नगरपालिकाएँ तथा इन अधिनियम की अनुसूची में नगर पंचायत के रूप में अथवा नगर परिषद् के रूप में सूचिबद्ध है, इस धारा के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसार इन रूप में गठित की गई और अधिसूचित की गई नमसी जाएंगी :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार अपने ऐसे करने के आशय का तीस दिन से अग्र्यून का व्यक्तिगत सुनवाई का नोटिस देने के बाद अधिसूचना द्वारा अनुसूची को संशोधित कर सकेगी और किसी नगर पंचायत को नगर परिषद् के रूप में या किसी नगर परिषद् को किसी नगर पंचायत के रूप में घोषित कर सकेगी ।

नगर-पालिका क्षेत्र के अधीन नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव कर सकेगी ।

(2) ऐसी प्रत्येक अधिसूचना उस स्थानीय क्षेत्र की सीमाएँ परिनिश्चित करेगी, जिसमें वह सम्बन्धित है ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति ऐसी भाषा में उसके अनुवाद सहित, जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, उस उपायुक्त के, जिसकी अधिकारिता

में वह स्थानीय क्षेत्र है, जिसमें अधिसूचित, संवर्धित है। अधिनियम में जो अधिकार स्थान पर, और उभे स्थानीय क्षेत्र के ए. वा एन. में अधि. महानदृश्य स्थानों पर लगाई जाएगी।

(4) उपर्युक्त, वह तारीख, जिसको वह प्रति और अनुवाद इस प्रकार लगाए गए थे, राज्य सरकार को सूचित किया और इस प्रकार सूचित तारीख, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख समझी जाएगी।

(5) यदि कोई निवासी, उदाहरण (1) के अधीन जारी की गई किसी अधि-सूचना के प्रति आक्षेप करता चाहता है, तो वह उसके प्रकाशन की तारीख में छः सप्ताह के भीतर, उपर्युक्त के माध्यम से राज्य सरकार को, लिखित रूप में अपनी आक्षेप प्रस्तुत कर सकता है और राज्य सरकार उसके आक्षेप पर विचार करेगी।

(6) जब प्रकाशन की तारीख में, छः सप्ताह हो गए हों और राज्य सरकार में ऐसे आक्षेपों पर, जो उसे भेजे गये हों, विचार कर लिया हो और आदेश कर दिये हों, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उक्त स्थानीय क्षेत्र को, इस अधिनियम के प्रावधानों के नियम, नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर सकती है।

(7) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट कर सकती है कि किसी भी नगरपालिका क्षेत्र में प्रवृत्त नियमों में से सभी या कोई ऐसे अधिनियमों और अनुकूलनों सहित, जो आवश्यक समझे जाएं, इस धारा के अधीन नगरपालिका क्षेत्र के रूप में घोषित स्थानीय क्षेत्र को लागू होंगे और ऐसे नियम और प्रकाशन के बिना, ऐसे नगरपालिका क्षेत्र को लागू नहीं होंगे।

(8) जब कोई स्थानीय क्षेत्र, जिसका सम्पूर्ण या कोई भाग, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 के अधीन कोई अधिसूचित क्षेत्र या इस अधिनियम के अधीन नगर पंचायत या, इस धारा के अधीन कोई नगरपालिका परिषद घोषित किया जाता है तो नगरपालिका परिषद्, उसके सभी नियमों, उप-विधियों, तराई और सभी अन्य विषयों के बारे में, जो भी हों, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचित क्षेत्र समिति या नगर पंचायत की शाश्वत् उत्तराधिकारी समझी जाएगी, और नगर पंचायत बना रहेगी और इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, तब तक नगरपालिका परिषद् समझी जाएगी, जब तक सदस्यों की नियुक्ति और निर्वाचन धारा 27 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं कर दिया जाता।

(9) नगरपालिका ऐसे समय पर अस्तित्व में आएगी जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

नगर- 5. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, और ऐसी अन्य रीति में जो वह पालिका क्षेत्र अधिधारित करे, किसी नगरपालिका क्षेत्र के भीतर उसके पड़ोस में स्थित तथा में किसी अधिसूचना में परिनिश्चित किसी स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करने के अपने आशय की स्थानीय घोषणा कर सकती है।

क्षेत्र को सम्मिलित करने के आशय की अधिसूचना।

(2) किसी ऐसे नगरपालिका क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र का, जिसके बारे में उप-धारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना प्रकाशित की गई है, कोई निवासी, यदि वह प्रस्थापित परिवर्तन के प्रति आक्षेप करना चाहे, तो अधिसूचना के प्रकाशन से छः सप्ताह के भीतर, लिखित रूप में अपना आक्षेप उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकता है और राज्य सरकार ऐसे आक्षेप पर विचार करेगी।

(3) जब अधिसूचना के प्रकाशन से छः सप्ताह समाप्त हो गये हों और राज्य सरकार ने आक्षेपों पर, यदि कोई हों, जो उप-धारा (2) के अधीन उसे प्रस्तुत किए गए हैं, विचार कर लिया हो, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित कर सकेगी।

(4) जब इस अधिनियम की उप-धारा (3) के अधीन कोई स्थानीय क्षेत्र किसी नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है, तब वह अधिनियम तथा राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अन्यथा ब्यातिनिष्ट किए जाने के सिवाय, ऐसी सभी अधिसूचनाएँ, नियम, उप-विधियाँ, आदेश, निर्देश तथा शक्तियाँ, जो इस अधिनियम के अधीन जारी की गई, बनाए गये, बनाई गई, किये गये या प्रदत्त की गई हों और उस समय सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में प्रवृत्त हों, ऐसे क्षेत्र को लागू होंगी।

नगर- 6. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी अन्य रीति में, जो वह उपायुक्त पालिका क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र को निकालने के अपने आशय की अधिसूचना।

समक्ष, किसी नगरपालिका क्षेत्र से उनमें समाविष्ट तथा अधिसूचना में परिनिश्चित स्थानीय क्षेत्र को निकालने के अपने आशय की घोषणा कर सकती है।

नगर- 7. (1) किसी नगरपालिका क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र का, जिसके बारे में धारा पालिका 6 के अधीन कोई अधिसूचना प्रकाशित की गई है, कोई निवासी यदि वह प्रस्थापित क्षेत्र से स्थानीय क्षेत्र को निकालने के प्रति आक्षेप करता है, अधिसूचना के प्रकाशन से छः सप्ताह के भीतर अपना लिखित आक्षेप उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकता है और राज्य सरकार उसके आक्षेप पर विचार करेगी।

(2) जब अधिसूचना के प्रकाशन से छः सप्ताह समाप्त हो गये हों, और राज्य सरकार ने ऐसे आक्षेपों पर, यदि कोई हों, जो उप-धारा (1) के अधीन उस प्रस्तुत किये गये हों, विचार कर लिया हो, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, स्थानीय क्षेत्र को, नगरपालिका क्षेत्र से निकाल सकती है।

8. जब कोई स्थानीय क्षेत्र धारा 7 के अधीन किसी नगरपालिका क्षेत्र से निकाल दिया जाता है—

नगर-
पालिका
क्षेत्र से
स्थानीय
क्षेत्र के
निकाले
जाने का
प्रभाव।

(क) यह अधिनियम और तदधीन जारी की गई सभी अधिसूचनाएँ, बनाए गए सभी नियम तथा उप-विधियाँ, किये गए सभी आदेश तथा निर्देश और प्रदत्त सभी शक्तियाँ, उसको लागू नहीं रह जायेंगी; और

(ख) राज्य सरकार, नगरपालिका में परामर्श करने के पश्चात् यह अध्यादेश करते हुए कोई स्कीम बनाएगी कि नगरपालिका में निहित नगरपालिका निधि के अतिशेष का तथा अन्य सम्पत्ति का कौन सा प्रभाग राज्य सरकार में निहित होगा और नगरपालिका के दायित्व किस रीति में नगरपालिका तथा राज्य सरकार के बीच प्रभावित किये जाएंगे और स्कीम के अधिसूचित हो जाने पर तदनुसार सम्पत्ति निहित हो जाएगी तथा दायित्व प्रभावित किये जाएंगे।

9. (1) राज्य सरकार, धारा 4 के अधीन घोषित किसी नगरपालिका क्षेत्र को अधिसूचना द्वारा उत्सादित कर सकती है।

नगर-
पालिका
क्षेत्र को
उत्सादित
करने का
शक्ति।

(2) जब किसी नगरपालिका क्षेत्र के बारे में इस धारा के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाती है, तो यह अधिनियम और इस अधिनियम के अधीन जारी की गई सभी अधिसूचनाएँ, बनाए गए सभी नियम तथा उप-विधियाँ, किये गए सभी आदेश तथा निर्देश और प्रदत्त सभी शक्तियाँ उक्त नगरपालिका क्षेत्र को लागू नहीं रह जायेंगी; अधिसूचना जारी करने के समय नगरपालिका में निहित नगरपालिका निधि का अतिशेष और सभी अन्य सम्पत्ति राज्य सरकार में निहित हो जाएगी और नगरपालिका के दायित्व सरकार को अन्तर्गत हो जाएंगे।

(3) जहाँ उप-धारा (1) के अधीन कोई नगरपालिका उत्सादित कर दी जाती है और तत्पश्चात् इन प्रार उत्सादित नगरपालिका में नमाविष्ट क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन नया क्षेत्र घोषित किया जाता है, वहाँ उप-धारा (2) में निदिष्ट शक्तियाँ और दायित्व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 4 के अधीन इसकी स्थापना की तारीख से सभा क्षेत्र की साम पंचायत में निहित होंगी।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए शक्तियों के अन्तर्गत इस अधिनियम या नियमों अथवा उप-विधियों द्वारा अधिरोपित कर, पञ्जर, सैस, रेट, देयों और फीस की कृत् वक़ाय है जो इस के उत्पादन की तारीख से ठीक पूर्व नगरपालिका को देय हो जाए और वह ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे वसूलीय होंगे मानो य पंचायत को देय हो बताया हो।

अध्याय-3

नगरपालिकाएँ

10. (1) धारा 3 के अधीन गठित नगरपालिकाओं में निर्वाचित सदस्यों की मात से अन्यून ऐसी संख्या होगी जो सरकार द्वारा नगरपालिका के निम्नलिखित जनसंख्या के माप-दण्ड के अनुसार अध्यादेश की जाएगी:—

नगर-
पालिकाओं
का गठन।

(i) 5000 से अधिक जनसंख्या के लिए

7 सदस्य

- (ii) 5000 से अधिक किन्तु 10,000 से अधिक जनसंख्या के लिए 9 सदस्य
 (iii) 10,000 से अधिक किन्तु 20,000 से अधिक जनसंख्या के लिए 11 सदस्य
 (iv) 20,000 से अधिक किन्तु 30,000 से अधिक जनसंख्या के लिए 13 सदस्य
 (v) 30,000 से अधिक किन्तु 40,000 से अधिक जनसंख्या के लिए 15 सदस्य
 (vi) 40,000 से अधिक किन्तु 50,000 से अधिक जनसंख्या के लिए 17 सदस्य
 (vii) 50,000 से अधिक जनसंख्या के लिए 19 सदस्य :

परन्तु यथा-पूर्वोक्त सदस्यों का अवधारण, तब तक नगरपालिका की संरचना को प्रभावित नहीं करेगा जब तक उस माध्यम द्वारा करने वाले निर्वाचित सदस्यों की पर्याप्तता का अवगान नहीं हो जाता है।

(2) उप-धारा (3) में यथा उपर्युक्त के विचार, नगरपालिका में सभी स्थान, नगरपालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों ने अपने जायेंगे और निर्वाचन के प्रयोजन के लिए उपर्युक्त ऐसे नियमों के अनुसार जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे, —

(क) नगरपालिका क्षेत्र को वार्डों में इस रीति में विभाजित करेगा कि—

(i) प्रत्येक वार्ड में से एक सदस्य निर्वाचित किया जायेगा; और

(ii) प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या को, यथासंभव समान रूप से बांटा जायेगा;

(ख) प्रत्येक वार्ड से अल्पतम वित्तीय योगदान करेगा; और

(ग) ऐसे वार्ड या वार्डों का अवधारण करेगा जिनमें धारा 11 के प्रथम स्थान आश्रित किए जाते हैं।

(3) वार्डों में निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के अनिवार्य, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान अथवा अनुभव रखने वाले तब तक से अधिक व्यक्तियों को नगरपालिका के सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित करेगी :

परन्तु इस उप-धारा के अन्तर्गत नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिका की बैठक में मन देने का अधिकार नहीं होगा :

परन्तु यह और कि नगरपालिका परिषद् की दशा में कार्यकारी अधिकारी का और नगर पंचायत की दशा में सचिव का नगरपालिका की सभी बैठकों में उपस्थित होने तथा विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा लेकिन उन्हें मन देने का अधिकार नहीं होगा।

स्थानों का
आरक्षण।

11. (1) नगरपालिका में निम्नलिखित के लिए स्थान आरक्षित किये जाएंगे:—

(क) अनुसूचित जाति; और

(ख) अनुसूचित जनजाति;

श्रीर धी प्र 15 आरक्षित स्थानों की संख्या 11 नगरपालिका के संघ निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या में अनुपात, यथावकाश निश्चित होना होगा जो नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का, नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है।

परन्तु यदि अनुसूचित जाति की कम जनसंख्या के कारण यथापूर्वोक्त स्थानों का आरक्षण संभव न हो और नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या का कम से कम पांच प्रतिशत हो तो, नगरपालिका में एक स्थान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाएगा।

परन्तु यह और कि जहाँ अनुसूचित जाति का व्यक्ति नगरपालिका का सदस्य निर्वाचित किए जाने के लिए पात्र नहीं है, वहाँ अनुसूचित जाति के लिए कोई भी स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह और कि गैर-जनजातीय क्षेत्र में जहाँ नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है, वहाँ अनुसूचित जनजाति के ऐसे सदस्यों के लिए स्थान, अनुसूचित जाति के सदस्यों की उपबंधित आरक्षण के समान आरक्षित किए जाएंगे और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच स्थानों के आरक्षण का अध्यापन उस नगरपालिका क्षेत्र में उनका जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.—इस परन्तु के प्रयोजन के लिए पद "गैर-जनजातीय क्षेत्र" में हिमाचल प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में भिन्न क्षेत्र शामिल है।

(2) उप-धारा (1) के अर्थात् आरक्षित स्थानों का एक-तिहाई, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

(3) सांघे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का एक-तिहाई (जिम्मेदार अर्थात् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

(4) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा नगरपालिका में, पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए स्थानों की इतनी संख्या आरक्षित कर सकेगी, जिसका नगरपालिका में सांघे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या से अनुपात, उस नगरपालिका में पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या के उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात से अधिक न हो, और इस उप-धारा के अर्थात् आरक्षित कुल स्थानों के एक तिहाई स्थान पिछड़े वर्ग से संबंधित महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर सकेगा।

(5) उप-धारा (1), (3) और (4) के अर्थात् आरक्षित स्थानों का नगरपालिका क्षेत्र के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में ओपेंटन, चक्रानुक्रम में ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए।

(6) इस धारा के अर्थात् स्थानों के आरक्षण को, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक निर्वाचन के समय जारी की गई अधिसूचना द्वारा, प्रभावी किया जाएगा।

अध्यक्षों के पदों का प्रावधान।

12. (1) सरकार द्वारा विहित जाति में, राज्य में अध्यक्षाओं के पदों की ऐसी संख्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाएगी, जिसका राज्य में ऐसे कुल पदों की संख्या के साथ, यथाशक्य निम्नतम अनुपात वही होगा जो राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की नगरीय जनसंख्या का, राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या में है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आरक्षित कुल पदों का एक-तिहाई, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

(3) राज्य में, नगरपालिका के अध्यक्षों के पदों को कुल संख्या का एक-तिहाई (जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

(4) राज्य सरकार, माधारण या विशेष आदेश द्वारा नगरपालिका क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए पदों की इतनी संख्या आरक्षित कर सकेंगी, जिनका नगरपालिका में सीधे निर्वाचन द्वारा अने जाने वाले कुल पदों की संख्या में अनुपात, नगरपालिका में पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या के, नगरपालिका की कुल जनसंख्या के अनुपात से अधिक न हो और इस उप-धारा के अधीन आरक्षित कुल पदों के एक-तिहाई पद पिछड़े वर्ग से संबंधित महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर सकेंगी।

(5) उप-धारा (1), (3) और (4) के अधीन आरक्षित पदों का राज्य के भिन्न-भिन्न नगरपालिकाओं में प्रॉबर्टन चक्रानुक्रम में ऐसी रीति में दिया जाएगा जो विहित की जाए।

स्पष्टीकरण.—घोषणाओं को दूर करने के लिए एनद्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए पद "नगरीय जनसंख्या" में, सिवाय हिमाचल प्रदेश नगर निगम अध्यादेश, 1994 के प्रयोजन के लिए नगरपालिका क्षेत्र के रूप में नगरपालिका घोषित क्षेत्र के, राज्य में नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या अभिप्रेत है।

अध्यक्षों की पदावधि।

13. (1) निर्वाचित सदस्यों की पदावधि नगरपालिका की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख में पांच वर्षों होगी।

(2) नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि निर्वाचित सदस्यों की पदावधि के साथ-साथ समाप्त होगी।

(3) जब अध्याय 17 के अधीन की गई किसी जांच के परिणामस्वरूप किसी सदस्य का निर्वाचन अन्य घोषित करने वाले कोई आदेश कर दिया गया है, तब ऐसा सदस्य तत्काल प्रभाव में नगरपालिका या सदस्य नहीं रह जाएगा।

(4) सदस्य, नगरपालिका और इसकी समितियों की बैठकों में हाजिर होने के लिए, ऐसी दूरी पर, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाए, अने प्राप्त करने के द्वारा होगी।

नगर-

14. (1) प्रत्येक नगरपालिका तत्काल प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जब तक पहले ही पालिका की विधित नही कर दी जाती है तब तक, अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से पांच सालावधि। वर्ष तक बनी रहेगी।

यदि उस द्वारा या उपकी ओर से पट्टे पर कोई गई या अधिगृहीत किसी भूमि का

परन्तु किसी नगरपालिका के विघटन से पूर्व उसे युक्तियुक्त गुनवाई का अवसर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले विद्यमान सभी नगरपालिकाएं अपने कार्यकाल की समाप्ति तक, तब तक बनी रहेंगी जब तक राज्य विधान मण्डल द्वारा इस प्राशय का संकल्प पास करके पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है।

(2) किसी नगरपालिका के गठन के लिये निर्वाचन,—

(क) उप-धारा (1) में, विनिर्दिष्ट उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व;

(ख) उसके विघटन की तारीख से छः मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व, पूरा किया जाएगा :

परन्तु जहां वह शेष अवधि, जिसके लिए विघटित नगरपालिका बनी रहेगी, छः मास में कम है, वहां ऐसी अवधि के लिए उस नगरपालिका का गठन करने के लिए इस धारा के अधीन कोई निर्वाचन करना आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् गठित की गई नगरपालिका का प्रथम निर्वाचन उसके नगरपालिका के रूप में अधिसूचित किए जाने के एक वर्ष के भीतर कराया जा सकता है।

(3) अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसी नगरपालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगरपालिका केवल ऐसी शेष अवधि के लिये बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगरपालिका उप-धारा (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित न की जाती।

15. (1) नगरपालिका का सदस्य, प्रधान को, लिखित में त्याग पत्र प्रस्तुत करके, जो तब, यदि त्याग-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर वापस नहीं लिया जाता है, नगरपालिका के समक्ष स्वीकार करने के लिए रखेगा।

नगर-
पालिका के
सदस्य का
पदत्याग।

(2) उप-धारा (1) के अधीन त्याग-पत्र स्वीकार किए जाने पर, सदस्य का स्थान खाली हुआ समझा जाएगा और उसे इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन भरा जाएगा।

16. (1) कोई व्यक्ति नगरपालिका का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निर्वाचित होगा,—

निर्वाचन।

(क) यदि उसे न्यूनतम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उप प्रकार राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निर्वाचित किया है :

परन्तु किसी व्यक्ति को इस आधार पर निर्वाचित नहीं किया जाएगा कि उसकी आय न्यूनतम वर्ष में कम है, यदि उसने इच्छीस वर्ष की आय प्राप्त कर ली है ;

(ख) यदि उसे नैतिक अश्रमता से अन्तर्गत किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया है जब तक कि उसकी दोषसिद्धि में पांच वर्ष की कालावधि का प्रमाण न हो गया है ; या

(ग) यदि उसने राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या नुहकारी संघाई की, या उस द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर ली गई या अधिगृहीत किसी भूमि का

अधिकरण किया है, या वह अधिकरण की गई भूमि का हिताधिकारी है, जब तक कि उप तारीख से जितने उसे उससे वेद-बल किया गया है, छः वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिकारान्तान रहा हो।

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, “हिताधिकारी” अधिव्यक्ति के अन्तर्गत अधिकारान्ता स्थापित या पत्नी या वारिस है; या

- (घ) तत्समय प्रवृत्त किसी व्यक्ति के अधीन किसी निर्वाचन अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है; या
- (ङ) यदि उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 110 के अधीन सध्यवहार के लिए जमानत देने का आदेश दिया गया है; या
- (च) यदि उसे लोक सेवा में नियुक्ति के लिए निरहित किया गया है, सिवाय अस्वस्थता आधार के; या
- (छ) यदि वह पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसाइटी अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियन्त्रण अधीन किसी पब्लिक सक्टर उपक्रम के नियोजन या सेवा में है।

(1974
का 2)

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद “सेवा” या “नियोजन” के अन्तर्गत पूर्ण-कालिक, अर्धकालिक, आकस्मिक, दैनिक या सविदा पर नियुक्त, रखे गए या नियोजित व्यक्ति है; या

- (ज) यदि वह हिमाचल प्रदेश आध्यात्मिक अपराधी अधिनियम, 1969 के अधीन आध्यात्मिक अपराधी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है; या
- (झ) यदि, जैसा इसमें इसके पश्चात् उल्लेखित है, उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नगरपालिका के आदेश द्वारा किए गए किसी संक्रमण या नगरपालिका के साथ अथवा अधीन या उस द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी सविदा या नियोजन में कोई अंश या हिस्सा है; या
- (ञ) यदि उसने नगरपालिका द्वारा अधिरोपित किसी कर की बकाया राशि संदेत नहीं की है या उस द्वारा देय नगरपालिका निधि की किसी प्रकार की बकाया संदेत नहीं की है या उसने कोई ऐसी राशि रख ली है जो नगरपालिका निधि का भाग है; या
- (ट) यदि वह नगरपालिका की प्रभिवृत्ति या पट्टाधृति के अधीन अनिवारी या पट्टाधारी है या नगरपालिका के अधीन धारित पट्टाधारी की लगान की बकाया में है; या
- (ठ) यदि उसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जब तक उसकी ऐसी दोषसिद्धि से छः वर्ष की अवधि का अवसान न हो गया हो; या
- (ड) यदि वह राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरहित है।

(1978
का 8)

(1955
का 22)

(2) यह प्रश्न कि क्या कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन की किसी निरुद्धता के अधीन है या हो गया है, सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् निम्नलिखित द्वारा विनिश्चित किया जाएगा,—

- (i) यदि ऐसा प्रश्न निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उठता है तो, ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए;

(ii) यदि ऐसा प्रश्न निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् उठता है, तो निदेशक द्वारा ।

17. यदि नगरपालिका के सदस्य के रूप में चुना गया कोई व्यक्ति लोक सभा राज्य सभा, राज्य विधान सभा का सदस्य या नगर निगम का पार्षद बन जाता है या पंचायत का पदाधिकारी है या बन जाता है तो पन्द्रह दिन की अवधि के अवसान पर या, क्यास्थिति, लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभा या नगर निगम का पार्षद या पंचायत के पदाधिकारी की पदावधि प्रारम्भ होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर नगरपालिका में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, यदि उसने हस्तुर्द, क्यास्थिति, लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभा या नगर निगम या पंचायत के अपने पद से त्याग-पत्र न दे दिया हो।

एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन ।

18. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नगरपालिका के किसी सदस्य को हटा सकती है,—

सदस्यों को हटाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की शक्तियाँ ।

(क) यदि वह कार्य करने से इन्कार करता है या राज्य सरकार की राय में कार्य करने में असमर्थ हो जाता है या किसी सभ्य न्यायालय द्वारा शोचन अश्रम या दिवानिया घोषित किया गया है या किसी दण्ड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष किया गया है या किसी ऐसे अदेश के अधीन किया गया है, जिससे राज्य सरकार की राय में ऐसा चरित्रदोष विदित है, जो उसे सदस्य होने के लिये अनुपयुक्त बनाता है ;

(ख) यदि वह, अधिसूचना द्वारा, लोक सेवा में निरोधन के लिये निरहित घोषित किया गया है, या उससे पदच्युत किया गया है और ऐसी निरहता या पदच्युति का कारण ऐसा है, जिसमें राज्य सरकार की राय में ऐसा चरित्र दोष विदित है, जो उसे सदस्य होने के लिये अनुपयुक्त बनाता है ;

(ग) यदि राज्य सरकार की राय में नगरपालिका के बैठकों से तीन से अधिक क्रमवर्ती मसों के लिये, अनुपस्थित कारण के बिना, अनुपस्थित रहा है ;

(घ) यदि वह बाधा करने वाले नोटिस की तारीख के पश्चात् तीन मास के भीतर उस द्वारा नगरपालिका को देय किसी राशि को संश्लेषण करने में असफल रहता है । राशि देय होने के पश्चात् सश्लेषण पूर्वतन तारीख को ऐसे नोटिस की तारीख करना, कार्यकारी अधिकारी का कर्तव्य होगा ;

(ङ) यदि राज्य सरकार की राय में उसने नगरपालिका के सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का धोरं बुराप्रयोग किया है या वह अपनी उपेक्षा अथवा अक्षर के कारण नगरपालिका के किसी धन या संपत्ति की हानि या बुराप्रयोग के लिये उत्तरदायी रहा है ;

(च) यदि वह, अपने निर्वाचन या नामनिर्देशन के पश्चात् किसी ऐसी निरहता के अधीन हो गया है जो यदि उसके निर्वाचन या नामनिर्देशन के समय विद्यमान रही होती, तो उसको निर्वाचन या नामनिर्देशन के लिये उम्मीदवारों की शर्तों को विनियमित करने वाली हस्तमय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अमान्य बना देती या यदि यह प्रतीत होता है कि वह अपने निर्वाचन या नामनिर्देशन के समय ऐसी निरहता का भाजन था ;

(छ) यदि वह, विधि व्यवसायी होते हुए, किसी व्यक्ति की ओर से नगरपालिका के विरुद्ध या राज्य सरकार की ओर से या उसके विरुद्ध किसी विधिक कार्यवाही में कार्य करता है, या उपस्थित होता है, जहाँ राज्य सरकार की राय में ऐसा कार्य करना या उपस्थित होना समिति के हितों के प्रतिकूल है ;

परन्तु किसी सदस्य का हटया जाना तब तक अधिसूचित नहीं किया जाएगा जब तक कि सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा जो अतिरिक्त उपायुक्त की पंक्ति में नामित हो, मामले को जांच में कर ली गई हो और सम्बंधित सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(2) कोई व्यक्ति, जो इन धारा के अर्धीन हटया गया है या जिसका निर्वाचन धारा 295 के उपबन्धों के अर्धीन अष्ट आचरणों या अधिवास के लिये शून्य घोषित किया गया है, छः वर्षों से अधिक अवधि के लिये निर्वाचन के लिये निरहित होगा।

आकस्मिक
रिक्तियों का
भरा जाना।

19. (1) जब कभी किसी सदस्य की मृत्यु अथवा उसके पदत्याग या हटये जाने से, या धारा 13 की उप-धारा (3) के उपबन्धों के अर्धीन उसका स्थान रिक्त होने से कोई रिक्ति होती है तो रिक्ति ऐसी रिक्ति होने की तारीख से छः मास के भीतर इस अधिनियम और नियमों के अनुसार भरी जाएगी।

(2) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व अधिकारी की शपथ पदावधि के लिये कार्य करने के लिए निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

नगर-
पालिका का
निगमन।

20. प्रत्येक नगरपालिका अपने नगरपालिका क्षेत्र की नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के नाम से निर्गमित निगम होगा, और उसका शाश्वत उत्तराधिकार और मानान्य मुद्रा होगी तथा उसे जंगल और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति के अर्जन और धारण करने की शक्ति प्राप्त होगी और इस अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के अर्धीन रहते हुए प्रारित किसी संपत्ति का अन्तरण करने, संविदा करने तथा अपने गठन के प्रयोजनों के लिये आवश्यक अन्य सभी बातें करने की शक्ति प्राप्त होगी और वह अपने निर्गमित नाम में वाद ला नकेगी और उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

कर्मचारियों
और सदस्यों
का लोक
सेवक
होना।

21. नगरपालिका द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका नियोजन पूर्णकालिक हो या अंशकालिक, और नगरपालिका का प्रत्येक सदस्य भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

1860 का 45

अध्यक्ष
तथा उपा-
ध्यक्ष का
निर्वाचन।

22. (1) प्रत्येक नगर पंचायत या नगरपालिका परिषद् समय-समय पर अपने सदस्यों में से एक को ऐसी अवधि के लिये, जो विहित की जाये, अध्यक्ष निर्वाचित करेगी और इस प्रकार से निर्वाचित सदस्य नगर पंचायत या परिषद् का अध्यक्ष बन जाएगा।

परन्तु नगर पंचायतों तथा नगर परिषदों में अध्यक्ष का पद धारा 12 में किये गये उपबन्धों के अनुसार अनुसूचित जातियों, जन जातियों और स्त्रियों के लिये आरक्षित होंगे।

परन्तु यह और कि यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद, मृत्यु, त्याग-पत्र, या अविश्वाम प्रस्ताव के कारण उसकी पदावधि के दौरान रिक्त हो जाता है तो शेष अवधि के लिये नया निर्वाचन उसी प्रवर्ग से कराया जायेगा।

23. (1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पदावधि पांच वर्षों या सदस्य के रूप में उनकी पदावधि का शेष, जो भी कम हो, होगा।

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पदावधि और मानदेय।

(2) पदावरोही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यदि अन्यथा अहित हो तो पुनः निर्वाचन या पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नगरपालिका और इनकी समितियों की बैठकों में हाजिर होने के लिए, ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाएं, ऐसे मानदेय और भत्तों के संदाय के हकदार होंगे।

24. (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद-त्याग।

(2) उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(3) उप-धारा (1) या (2) के अधीन, यथास्थिति, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष का त्याग-पत्र इसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा।

25. (1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव नियमों में अधिवेशन प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा।

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव।

(2) जहां नगरपालिका का कुछ निर्वाचित सदस्यों के बहुमत या अन्योन्य द्वारा हस्ताक्षरित, नगरपालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से अपना पद त्याग करने की अपेक्षा के लिए संकल्प प्रस्तुत करने के आशय का नोटिस दिया जाता है और यदि साधारण या विशेष बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के बहुमत द्वारा जिसकी गणपूर्ति इसके निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अन्योन्य है, पारित संकल्प द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव को पारित किया जाता है, तो, वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके विरुद्ध ऐसा संकल्प पारित किया जाता है, तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रहेगा।

(3) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे जिनमें उनके विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाता है। ऐसी बैठक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी और ऐसी रीति में बुलाई जाएगी जो विहित की जाए और उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, बैठक में मतदान करने और इसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा।

(4) ऐसा अविश्वास प्रस्ताव, इस धारा के अधीन, उसके ऐसे पद पर निर्वाचित की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर नहीं रखा जा सकेगा और कोई भी पञ्चातुर्वर्ती अविश्वास प्रस्ताव अन्तिम अविश्वास प्रस्ताव से एक वर्ष के अन्तराल के बीच नहीं रखा जा सकेगा।

26. राज्य सरकार, किसी भी समय अधिसूचना द्वारा, किसी अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को, उसकी शक्तियों के दुरुपयोग के, अथवा उसके दत्तव्यों के पालन में प्रायिक असफलता के, आधार पर उसके पद से हटा सकेगी।

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का हटाया जाना।

परन्तु अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का हटाया जाना तब तक अधिसूचित नहीं किया जाएगा, जब तक, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा जो उप-मण्डल अधिकारी (सिविल) से

नीच को पेशा का न हो, इन विषय की जांच न कर ली गई हो और, तथास्ति, प्रत्यक्ष या
उपाध्यक्ष को नुनवाई का मुक्तिपुक्त अवसर न दे दिया गया है।

निर्वाचनों
और नाम-
निर्देशनों की
अधिसूचना।

27. (1) किसी नगर पंचायत अथवा नगरपालिका परिषद् के किसी सदस्य या प्रत्येक
निर्वाचन और नामनिर्देशन तथा उसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या निर्वाचन राजपत्र में अधिसूचित किया
जाएगा और कोई भी सदस्य अपना कार्यभार तब तक नहीं संभालेगा, जब तक उसका
निर्वाचन अथवा नाम-निर्देशन इस प्रकार अधिसूचित नहीं कर दिया जाता और जब तक
वह नगर पंचायत या नगरपालिका परिषद् की बैठक में, निम्नलिखित प्रहम में भारत के
संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ नहीं ले लेता या उसका प्रतिज्ञान नहीं कर लेता,
अर्थात् :—

“मैं न, ख, की नगरपंचायत या नगरपालिका
परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित (या नाम-निर्दिष्ट) किए जाने पर सदस्यनिष्ठा से शपथ
लेता हूँ या प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथास्थापित
भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूँगा और अच्छी निष्ठा रखूँगा तथा जिन कर्तव्यों
का भार मैं संभालूँगा, उनका श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।”

(2) किसी सदस्य या प्रत्येक निर्वाचन राजपत्र निर्वाचन आयोग द्वारा राजपत्र में
अधिसूचित किया जाएगा और किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या प्रत्येक निर्वाचन ऐसे निर्वाचन के
परिणाम की घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में
अधिसूचित किया जाएगा और यदि उक्त अवधि के भीतर कोई अधिसूचना जारी नहीं की
जाती तो निर्वाचन अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।

(3) यदि ऐसा कोई व्यक्ति अपने निर्वाचन या नामनिर्देशन, अर्थात् की स्थिति हो,
की अधिसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उप-धारा (1) द्वारा यथास्थिति शपथ
लेने या प्रतिज्ञान करने में लीन या इत्तार करता है, तो उसका निर्वाचन अथवा
नामनिर्देशन अविविमान्य समझा जाएगा, और उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

देखें करने
का समय।

28. (1) प्रत्येक नगरपालिका कारवार की संव्यवहार के लिए, प्रत्येक मास में कम से
कम एक बार ऐसे समय पर, जो उप-विधियों द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए,
देखें करेंगे।

(2) अध्यक्ष अथवा, उसकी अनुपस्थिति में या कर्तव्यों के पालन में उसकी असमर्थता
या उसकी पद-रिक्ति के दौरान, उपाध्यक्ष, नगरपालिका के सदस्यों की कुल संख्या का आधे
भाग में अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अपेक्षा-पत्र की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की अवधि
के भीतर या तो नाशरण अथवा विशेष बैठक बुलाएगा :

परन्तु अपेक्षा-पत्र में वह प्रयोजन विनिर्दिष्ट होगा, जिसके लिए बैठक की जाएगी।

(3) यदि अध्यक्ष या उपअध्यक्ष नियुक्त-पत्र की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर नगरपालिका की बैठक बुलाने में असफल रहता है, तो उप-अध्यक्ष हस्ताक्षरित करने वाले सदस्य बैठक बुलाने के लिए उपमण्डलाधिकारी (सिविल) से प्रार्थना कर सकते हैं।

(4) उपमण्डलाधिकारी (सिविल), उप-धारा (3) के अधीन प्रार्थना की प्राप्ति पर, ऐसी प्रार्थना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर बैठक बुलाएगा।

29. (1) किसी नगरपालिका की प्रत्येक बैठक या तो सामान्य होगी या विशेष।

सामान्य
तथा विशेष
बैठके।

(2) कोई भी कार्य किसी सामान्य बैठक में संपादित किया जा सकेगा जब तक उसका किसी विशेष बैठक में संपादित किया जाता इस अधिनियम या नियमों द्वारा अपेक्षित नहीं है।

30. (1) किसी नगरपालिका की किसी विशेष बैठक में कार्य संपादन के लिए आवश्यक गणपूर्ति नगरपालिका में आमतौर पर सदस्यों की संख्या की आधी से होगी।

गणपूर्ति।

(2) किसी नगरपालिका की किसी सामान्य बैठक में कार्य संपादन के लिए आवश्यक गणपूर्ति नगरपालिका के सदस्यों की ऐसी संख्या या उनका ऐसा अनुपात होगा, जो उप-विधियों द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, किन्तु तीन से कम नहीं होगी।

परन्तु यदि किसी नगरपालिका की किसी सामान्य या विशेष बैठक में गणपूर्ति नहीं है तो सभापति, बैठक को ऐसे अन्य दिन के लिए स्थगित कर देगा, जो वह उपयुक्त समझे, और वह कार्य जो मूल बैठक के समक्ष, यदि गणपूर्ति होती, लाया जाता, स्थगित बैठक के समक्ष लाया जाएगा और उसमें संपादित किया जाएगा, चाहे गणपूर्ति हो अथवा नहीं।

31. किसी नगरपालिका की प्रत्येक बैठक में, अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में अथवा उसके पद में रिक्त के दौरान, उपाध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं तो तब तक जो भी कोई ऐसा सदस्य, जिसे उपस्थित सदस्य निर्वाचित करें, बैठक का सभापतित्व करेगा।

बैठक का
सभापति।

32. इस अधिनियम या नियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के विना, किसी नगरपालिका को किसी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में बैठक के सभापति को द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा।

बहुसंख्या के
मत का
विनिश्चयक
होना।

33. (1) किसी नगरपालिका की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त तैयार किए जाएंगे तथा इस प्रयोजन के लिए रखी गई बही में अभिलेखित किए जाएंगे, उन बैठक के या आगामी बैठक के सभापति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

कार्यवृत्तियों
का अभिलेख
और
प्रकाशन।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कार्यवाहियों के कार्यवृत्त ऐसी रीति में प्रकाशित किए जाएंगे, जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

(3) किसी नगरपालिका की किसी बैठक में पारित प्रत्येक संकल्प को एक प्रति बैठक की तारीख से तीन दिन के भीतर उपायुक्त और निदेशक को भेजी जाएगी।

उप-विधियाँ।

34. राज्य सरकार, नगरपालिकाओं में से सभी या किसी के लिए, इस अधिनियम और नियमों में संगत उप-विधियों द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेगी —

- (क) नगरपालिका की बैठकों का समय और स्थान ;
- (ख) रीति, जिसमें सामान्य और विशेष बैठकों का तथा संगत बैठकों का नोटिस दिया जाएगा ;
- (ग) सामान्य बैठकों में कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक गणपूर्ति ;
- (घ) बैठकों में कार्यवाहियों का संचालन और बैठकों का स्थगन ;
- (ङ) सामान्य मुद्दा की अभिरक्षा और प्रयोग, जिनको यह प्रयुक्त की जाएगी ;
- (च) उप-समितियों की नियुक्ति और उनके कर्तव्य, नगरपालिका के सदस्यों के बीच कर्तव्यों का विभाजन और ऐसे सदस्यों द्वारा प्रोजेक्ट शक्तियाँ, जो सामान्य कार्यपालक प्रशासन के लिए प्राथमिक रूप में उत्तरदायी हैं, उन्हें उप-समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य हों या व्यक्तिगत सदस्य ;
- (छ) व्यक्ति, जिनके द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त धन के लिए नगरपालिका की ओर से रसीदें दी जाएँगी ;
- (ज) शर्तें, जिस पर नगरपालिका के रजिस्ट्रारों, दस्तावेजों, मान-चित्रों तथा रेखाओं का जनसाधारण द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है और उनकी प्रतियों का प्रदाय किया जा सकता है और ऐसे निरीक्षण के लिए अथवा ऐसी प्रतियों के प्रदाय के लिए संदेय फीसें ;
- (झ) नगरपालिका के कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्तव्य, कार्यपालक शक्तियाँ, छुट्टी, निवृत्तन और हटाया जाना ;
- (ञ) उप-समितियों के कार्यपालक आदेशों और नगरपालिकाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारियों के कार्यपालक आदेश के विरुद्ध अपील ;
- (ट) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उप-विधियों के अधीन विहित किया जाना है या किया जाए।

निदेशक
की
नियुक्ति।

35. (1) राज्य सरकार, अधिमूचना द्वारा निदेशक नियुक्त कर सकेगी, और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए, जो यह उचित समझे, उसे राज्य सरकार को इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों को निहित कर सकेगी।

(2) अधिकांशियों के ऐसे अन्य वर्ग भी होंगे, जिन्हें राज्य सरकार अधिमूचना द्वारा घोषित करे और राज्य सरकार इतने व्यक्तियों को इन वर्गों के अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जो यह उचित समझे और यह घोषणा कर सकेगी कि प्रत्येक वर्ग के अधिकारियों द्वारा इस अधिनियम के अधीन किन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।

अधिनियमों
और कृत्यों
का प्रत्यापन
योग्यता।

36. (1) राज्य सरकार, अधिमूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों को धारा 279 के अधीन, प्ररूप या नियम बनाने की शक्ति के सिवाय, किसी अधिनियम अधिकांश को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन ऐसे निबन्धनों और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, जो अधिमूचना में विनिर्दिष्ट की जाएँ।

(3) जब कभी लोकहित में और इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका को सीपे गए कृत्यों के दस्त-पूर्ण अनुपालन के लिए ऐसा करना समीचीन ही तो नगरपालिका, किसी विषय के सम्बन्ध में जिसको नगरपालिका की शक्ति विस्तारित होती है राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपनी किन्हीं नागरिक सेवाओं और सुख सुविधाओं को, (जिसे अन्तर्गत करें और राजस्व का संग्रहण है) ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जो यह अधिरोपित करना उचित समझे किसी व्यक्ति या एजेंसी को सौंप सकेंगी।

37. (1) किसी ऐसी घटना के होने पर या उसके होने की आशंका पर, जिसमें मृत्यु को व्यापक हानि या मानवीय जीवन को संकट अथवा जनता को गम्भीर अनुविधा हो सकती है अथवा होनी संभाव्य है, अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अथवा उसके पद की रिक्ति के दौरान उपाध्यक्ष, या दोनों की अनुपस्थिति में, कार्यपालक अधिकारी यदि उसकी राय में ऐसी कोई आपात स्थिति है, जिसमें नगरपालिका द्वारा मामले पर विचार कर करने से पूर्व कार्यवाही की आवश्यकता है, किसी ऐसे संकर्म के निष्पादन या कार्य के करने का निदेश कर सकता है, जो उसकी राय में आपात स्थिति में न्यायोचित या अपेक्षित है और जिसके निष्पादन या करने के लिए नगरपालिका सक्षम है, और निदेश कर सकता है कि ऐसे संकर्म के निष्पादन या ऐसे कार्य के करने का व्यय नगरपालिका निधि से संदत्त किया जाए :

आपात की दशा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की शक्तियाँ।

परन्तु प्रत्येक ऐसी कार्यवाही की रिपोर्ट, नगरपालिका को उसकी आगामी बैठक में की जाएगी।

(2) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा कार्यपालक अधिकारी इस धारा के अधीन नगरपालिका के किसी प्रादेश के उत्ल्लेखन में कार्य नहीं करेगा।

(3) अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में अथवा उसका पद खाली रहने के दौरान कोई उपाध्यक्ष नगरपालिका द्वारा मामले पर विचार किए जाने तक, किसी ऐसे कार्य का करना प्रतिषिद्ध कर सकता है, जो उसकी राय में लोक हित में अवांछनीय है ; किन्तु यह तब जब कार्य ऐसा है, जिसे प्रतिषिद्ध करने की शक्ति नगरपालिका को प्राप्त है।

38. कोई नगरपालिका किसी अन्य नगरपालिका के साथ या किसी जिला परिषद् या किसी पंचायत समिति के साथ या किसी छावनी प्राधिकरण के साथ या बिन्हीं ऐसी एक से अधिक नगरपालिकाओं, जिला परिषदों, पंचायत समितियों अथवा प्राधिकरणों के साथ किसी ऐसे प्रयोजन के लिये, जिसमें से वे संयुक्त हितबद्ध हैं, अपने-अपने निकायों में से कोई संयुक्त समिति नियुक्त करने में, और किसी ऐसी संयुक्त समिति को ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग करने में, जो किन्हीं सम्बद्ध समितियों, जिला परिषदों, पंचायत समितियों अथवा सम्बद्ध प्राधिकरणों में से किसी या किन्हीं द्वारा प्रयुक्त की जा सकती थी और ऐसी किसी संयुक्त समिति की कार्यवाहियों के बारे में, और उनसे सम्बद्ध पत्र-व्यवहार के मंचानन के सम्बन्ध में विनियम बनाने या उनमें उपान्तर करने में सहमत हो सकती है।

संयुक्त समितियाँ।

39. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु सरकार के किसी माधुरण या विशेष प्रादेश के अध्यक्षीन जहाँ नगरपालिका के कुल सदस्यों का दो तिहाई निर्वाचित किए जा चुके हों, तो वहाँ इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका शक्ति की गई समझी जाएगी।

रिक्तियों तथा अनियमितताओं के कारण कार्यों और

(2) इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्यवाहियाँ केवल इस

कार्यवाहियों का अधिकार धारण न होना।

आधार पर किसी नगरपालिका में किसी व्यक्ति, या नगरपालिका अध्यक्ष संयुक्त समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पठित्वी प्राधिकारी या सदस्य के निर्वाचन या बहिर्गता में किसी व्यक्ति की विद्यमानता या ऐसे किसी कार्य या कार्यवाही अध्यक्ष मामले के गुणगुण को प्रभावित न करने वाली इसकी प्रक्रिया के कारण प्रभावित नहीं की जाएगी।

संविदा प्राधिकारी।

40. कोई नगरपालिका निदमों तथा धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अपनी ओर से कोई विशिष्ट संविदा या ऐसे किसी वर्ग की संविदाएं करने की शक्ति अपने सदस्यों में से किसी एक या अधिक को प्रत्ययोजित कर सकती है।

संविदा के निष्पादन और सम्पत्ति के प्रसारण का ढंग।

41. (1) नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से की गई प्रत्येक संविदा, लिखित रूप में होगी और दो सदस्यों, जिनमें से एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा तथा, यथास्थिति, नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी या सचिव द्वारा भी हस्ताक्षरित होगी।

(2) किसी नगरपालिका से सम्बन्धित स्थावर सम्पत्ति या प्रत्येक अन्तरण किसी लिखित निश्चित द्वारा ही किया जाना चाहिए जो नगरपालिका के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष तथा, यथास्थिति, नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी अथवा सचिव, द्वारा निष्पादित की जाएगी।

नगरपालिका के साथ की गई किसी संविदा में हितवद्ध किसी सदस्य या कर्मचारी पर शक्ति।

42. (1) यदि किसी नगरपालिका अथवा संयुक्त समिति का कोई सदस्य या कर्मचारी उपायुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना धारा 38 के अधीन उस नगरपालिका या संयुक्त समिति के साथ की गई किसी संविदा में स्वयं को स्वेच्छा से हितवद्ध करता है, अथवा यदि ऐसी किसी संविदा में अपने हितवद्ध होने के एक मास के भीतर वह न तो पद त्याग करता है और न ही ऐसी संविदा में अपने हितवद्ध होने के बाद वह उस नगरपालिका या संयुक्त समिति का सदस्य, अथवा कर्मचारी बने रहने के लिए उपायुक्त से लिखित अनुज्ञा प्राप्त करता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 168 के अधीन अपराध के लिए दण्डनीय होगा। 1860 का

(2) किसी नगरपालिका अथवा संयुक्त समिति का कोई भी सदस्य या कर्मचारी किसी निगमित अथवा पंजीकृत सम्पत्ति में केवल अग्रधारी या सदस्य होने के कारण उक्त सम्पत्ति और नगरपालिका अथवा संयुक्त समिति के बीच की गई किसी संविदा में हितवद्ध नहीं माना जाएगा किन्तु अपात्रवर्कता ऐसी कोई भी व्यक्ति जिन्होंने ऐसी संविदाओं के बारे में नगरपालिका अथवा संयुक्त समिति की किसी कार्यवाहियों में भाग नहीं लिया।

नगरपालिका तथा उसके कर्मचारियों के विरुद्ध बंद।

43. किसी नगरपालिका या किसी नगरपालिका के किसी कर्मचारी के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में, जिसके बारे में यह तार्क्यित है कि वह नगरपालिका द्वारा या उसके कर्मचारी द्वारा अपनी पदोप हैतियत में किया गया है, कोई भी वाद तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा, जब तक किसी नगरपालिका की दशा में, उसके कार्यालय में, और किसी कर्मचारी की दशा में उसके कार्यालय अथवा उसके निवास स्थान पर अनुयोजन का हेतुक तथा आशयी वादी का नाम और निवास स्थान ब्यक्त करते हुए, लिखित नोटिस परिदत्त करने या छोड़ने के पश्चात् एक मास समाप्त नहीं गया हो, और वादपत्र में यह स्पष्ट होगा कि ऐसा नोटिस इस प्रकार परिदत्त कर दिया गया है या छोड़ दिया गया है।

परन्तु इस धारा की कोई भी बात विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 38 के अधीन संस्थित किसी वाद पर लागू नहीं होगी। 1963 का 47

44. कोई भी सिविल न्यायालय —

- (क) किसी व्यक्ति को इस आधार पर किसी न्यायाधीश के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या समेचारी के रूप में उचित रूप में निर्वाचित, नामनिर्दिष्ट या नियुक्त नहीं किया गया है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, सदस्य या समेचारी की शक्तियों का प्रयोग करने अथवा पुरस्चों या उत्तरों का पालन करने से रोके जाने वाला; अथवा
- (ख) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को या किसी न्यायाधीश को कोई निर्वाचन करने या किसी विशिष्ट रीति में कोई निर्वाचन करने से रोके जाने वाला;

निर्वाचन
न्यायालयों
में अधि-
कारिता का
वर्जन।

कोई अस्थायी आदेश नहीं देगा या कोई अन्तर्गम आदेश नहीं देगा।

45. इस अधिनियम, नियमों तथा उप-विधियों के अनुसरण में सदभावपूर्वकों काई या जो जाने के लिए प्राणित किसी बात के बारे में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिवत कार्यवाही किसी न्यायाधीश के विरुद्ध अथवा किसी न्यायाधीश के किसी समेचारी के विरुद्ध या ऐसी किसी न्यायाधीश अथवा समेचारी के या किसी राजस्व के निदेशों के अधीन तथा उनके अनुसरण में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हो सकेंगे।

सदभाव-
पूर्वकों की
गई कार्रवाई
के लिए
संरक्षण।

46. (1) न्यायाधीशों का प्रत्येक सदस्य, अधिवक्ता या पदधारी न्यायाधीश को किसी धर्म या अन्य सम्पत्ति की हानि दुर्घट्य अथवा दुरुपयोग के लिए दायी होना, यदि ऐसी हानि, दुर्घट्य या दुरुपयोग के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रित महानेखा-परिक्षेत्र या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त राजकाश अन्य ऐका-परिक्षेत्र अधिनियमों द्वारा निर्धारित की जाती है कि वह हानि अधि उसके न्यायाधीशों के सदस्य, अधिवक्ता या पदधारी होने के दौरान अपने उत्तरों के निर्वहन में उपेक्षा या अन्याय का प्रत्यक्ष परिणाम है, और उनको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में समानों की तामील के लिए उपबन्धित रीति में नोटिस की तामील करके, लिखित या मौखिक शपथवेदन द्वारा, यह हेतु दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात् कि उस में हानि की पूर्ति की अपेक्षा क्यों न की जाए, उपर्युक्त द्वारा ऐसी सम्पत्ति के मूल्य अथवा ऐसी धन राशि से अधिभारित किया जाएगा; और यदि उप-धारा (2) द्वारा विहित अपील की अवधि के समाप्त के चौदह दिन के भीतर राशि संदत्त नहीं की जाती, तो लक्कर, उपर्युक्त के निवेदन पर, उस राशि की वसूली के लिए तत्क्षण इस प्रकार अवसर होगा, मानो वह सू-राजस्व का बनाया हो, और उनको न्यायाधीशों की विधि में जमा करवा देगा।

हानि के
लिए
दायित्व।

1908 का 5

(2) वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उप-धारा (1) के अधीन आदेश किया जाता है, ऐसे आदेश के अधिगृहीत किए जाने के तीस दिन के भीतर, राज्य सरकार को अपील कर सकता है, जो अपील की सुनवाई के लिए एक अधिवक्ता नियुक्त करेगी, और अपील अधिवक्ता को अधिवक्ता को पुष्ट, उपान्तरित अथवा रद्द करने का अधिवक्ता प्राप्त होगा:

परन्तु इस धारा के अधीन किसी भी व्यक्ति से ऐसी हानि, दुर्घट्य अथवा दुरुपयोग से चार वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अथवा अपने सदस्य न रहने के समय से चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात् हेतु दर्शित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई भी बात, व्यक्ति पक्ष को उप-धारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में उपचार के लिए प्रयत्न करने से विवर्जित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

अध्याय-4

नगरपालिकाओं के कृत्य

नगर-पालिकाओं की साधारण शक्तियाँ। 47. (1) इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और उप-विधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लघुतर नगरीय क्षेत्र और संक्रमणवालीन क्षेत्र के नगरपालिका को प्रथम क्रम में नगरपालिका परिषद् और नगर पंचायत में निहित होगा।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राप्तियों और सवितरण की सभी विवरणीयों और प्रगति की सभी रिपोर्टों पर विचार करना और उस पर ऐसे संकल्प पारित करना जो यह उचित समझे, नगरपालिका का कर्तव्य होगा।

नगर-पालिकाओं की शक्तियाँ और प्राधिकार। 48. (1) धारा 47 की उप-धारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नगरपालिकाओं को, स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कृत्य करने के लिए समर्थ बनाने के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएँ, निम्नलिखित के बारे में ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेंगी, जो आवश्यक हो, —

- (i) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना ;
- (ii) निम्नलिखित सहित, ऐसे कृत्यों का अनुपालन तथा स्कीमों को कार्यान्वित करना, जो उन्हें सौंपी जाएँ :—

- (1) नगरीय योजना जिसमें नगर योजना शामिल है ;
- (2) भूमि उपयोग तथा निर्माण संरचना विनियमन ;
- (3) आर्थिक और सामाजिक विकास योजना ;
- (4) सड़कों और पुल ;
- (5) घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय ;
- (6) जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई व्यवस्था और कूड़ा करकट का प्रबन्ध ;
- (7) अग्निशमन सेवाएं ;
- (8) नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थिति की आयातों की अभिवृद्धि ;
- (9) समाज कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना, इनमें विकलांग और मंदबुद्धि भी शामिल हैं ;
- (10) गन्दी बस्ती सुधार और उन्नति ;
- (11) नगरीय निर्धनता उन्मूलन ;
- (12) नगरीय सुख सुविधाओं और सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदान की व्यवस्था ;
- (13) सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयातों की अभिवृद्धि ;
- (14) दफन और कब्रिस्तान, शवदाह और भ्रमशान और विद्युत शवदाह गृह ;
- (15) कांजी हाऊस, पशुओं के प्रति कृपा का निवारण ;
- (16) जन्म मरण सांख्यिकी इसमें जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण शामिल हैं ;
- (17) सार्वजनिक सुख-सुविधाएं इसमें मार्ग प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस-स्टॉप और जनसुविधाएं शामिल हैं ;
- (18) पशु वक्शालाओं और चर्मशोधन शालाओं का विनियमन :

परन्तु प्रथमतः इस धारा के अधीन शक्तियों के त्यागभन के सम्बन्ध में अभिमतता इन अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से तीन मास के भीतर जारी की जाएगी।

(2) इस धारा के उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बान का अर्थ, नगरपालिकाओं में इन अधिनियम, नियमों और अधीन बनाई गई उप-विधियों के भिन्न-भिन्न उपबन्धों द्वारा उनमें निहित विभिन्न शक्तियों और कृत्यों से, निनिहित करने के रूप में नहीं लगाया जाएगा।

49. (1) नगरपालिका की निम्नलिखित स्थायी समितियां होंगी :-

स्थायी
समितियां।

- (क) साधारण न्यायी समिति ;
- (ख) वित्त, संपरीक्षा और योजना समिति ;
- (ग) सामाजिक न्याय समिति।

(2) प्रत्येक स्थायी समिति, नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सहित तीन से अधिक और पांच से अधिक सदस्यों से गठित होगी :

परन्तु सामाजिक न्याय समिति में कम से कम एक सदस्य महिला होंगी या अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति में होंगी।

(3) अध्यक्ष साधारण न्यायी समिति और वित्त संपरीक्षा और योजना समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष भी होगा। उपाध्यक्ष, सामाजिक न्याय समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा :

परन्तु यदि उपाध्यक्ष, नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने में सामाजिक न्याय समिति के सदस्य अपने ने से इनके अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे।

(4) नगरपालिका का कोई निर्वाचित सदस्य, दो से अधिक स्थायी समितियों में कार्य करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) नगरपालिका का कार्यकारी अधिकारी और सचिव प्रत्येक स्थायी समिति का पदेन सचिव होगा।

50. (1) साधारण स्थायी समिति, स्थापन विधियों और मंचार, भवन, नगरीय आवास, प्राकृतिक विपत्ति के लिए राहत, जल प्रदाय और महबद्ध सभी प्रकारों के अतिरिक्त विषयों में से सम्बन्धित, कृत्यों का पालन करेगी।

स्थायी
समितियों
के कृत्य।

(2) वित्त, संपरीक्षा और योजना समिति नगरपालिका के वित्त, वृद्ध बनाने, राजस्व की वृद्धि के लिए प्रस्तावों की संवीक्षा करने, प्राप्ति और व्यय की विवरणों का परीक्षण, नगरपालिका के वित्त को प्रभावित करने वाले सभी प्रस्तावों पर विचार करने और नगरपालिका के राजस्व तथा व्यय के साधारण प्रवीक्षण और सहकारिता, लघु वृत्त नदियों और नगरपालिका क्षेत्र के विकास से संबंधित कृत्यों का पालन करेगी।

(3) सामाजिक न्याय समिति निम्नलिखित से सम्बन्धित कृत्य करेगी, -

- (क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य हितों की अभिवृद्धि ;
- (ख) सामाजिक धन्याय और अन्य प्रकार के सभी शोषणों से उनका संरक्षण ;
- (ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की बेहतर ;
- (घ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ।

(4) स्थायी समिति उक्त निर्दिष्ट कृत्यों का गालन नगरपालिका द्वारा इसे प्रत्यायोजित शक्तियों के विस्तार तक करेगी ।

स्थायी
समितियों
द्वारा काम-
काज का
संचालन ।

51. (1) नगरपालिका स्थायी समिति के सदस्यों के निर्वाचन, उनमें कामकाज को संचालन और उनसे सम्बन्धित अन्य सभी विषयों से सम्बन्धित उप-विधियाँ बना सकेंगी ।

(2) प्रत्येक समिति का अध्यक्ष, समिति के कार्य के बारे में नगरपालिका को कार्यालय से कोई जानकारी, विवरण, कथन, लेखा या रिपोर्ट संचालन और नगरपालिका की किसी जगह सम्पत्ति या नगरपालिका के कार्य से सम्बद्ध चल रहे संकर्मों में प्रवेश करने और इसमें निरीक्षण करने का हकदार होगा ।

(3) प्रत्येक स्थायी समिति नगरपालिका कार्य से सम्बद्ध नगरपालिका के किसी अधिकारी को, अपनी बैठक में उपस्थित होने की प्रपक्षा करने की हकदार होगी । समिति को अनुदेशों के अधीन, यथास्थिति, कार्यपालक अधिकारी या सचिव नोटिस जारी करेगा और अधिकारी को उपस्थिति सुनिश्चित करेगा ।

अध्याय-5

नगरपालिका निधि तथा सम्पत्ति

नगरपालिका
निधि का
गठन ।

52. प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र के लिए एक नगरपालिका-निधि गठित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित राशियाँ जमा की जाएँगी—

(क) नगरपालिका द्वारा अथवा उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन या अन्यथा प्राप्त सभी राशियाँ ; और

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय नगरपालिका क्षेत्र की नगरपालिका-निधि में जमा अतिशेष, यदि कोई हो ।

निधि का
उपयोजन ।

53. (1) नगरपालिका, नगरपालिका-निधि में से निम्नलिखित को अलग रखेगी और उनका उपयोग करेगी—

(क) प्रथमतः, ऐसी राशि, जो उसके द्वारा वैध रूप से लिए गए किसी कार्य पर देय होने वाली किन्हीं राशियों के संदाय के लिए अपेक्षित हो ;

(ख) द्वितीयतः ऐसी राशि, जो राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका से, ऐसे स्थानीय स्वशासन बोर्ड या निदेशालय के खर्चे हेतु अभिदाय के लिए अपेक्षित

हो, जिसे राज्य या नगरपालिकाओं या अन्य स्थानीय निकायों के कार्य में सहाय देते, सहायता प्रदान करने अथवा पर्यवेक्षण करने के प्रयोजन के लिए स्थापित करें :

परन्तु ऐसी राशि उक्त वर्ष से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का आय के एक प्रतिशत के बराबर की राशि से अधिक नहीं होगी, जिसमें नगरपालिका से अभिदाय करने की अपेक्षा की जाती है ;

(ग) तृतीयतः ऐसी राशि, जो स्थापना व्यय की पूर्ति के लिए और नगरपालिका सेवाओं के सदस्यों तथा नगरपालिका के अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, भविष्य-निधि तथा उपदान की पूर्ति के लिए अपेक्षित हो, जिसके अन्तर्गत ऐसे ग्रंथशाला तथा अभिदाय भी हैं, जो हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994 में निर्दिष्ट है :

परन्तु स्थापना पर व्यय, नगरपालिका क्षेत्र के व्यय के एक तिहाई से अधिक नहीं होगा ;

(घ) चतुर्थतः ऐसी राशि, जो नगरपालिका के लेखों की संपरीक्षा में हुए व्ययों के संदाय के लिए अपेक्षित हो और केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक व्यय का वह प्रभाग, जिसे राज्य सरकार, नगरपालिका को दी गई सेवाओं के बदले में नाम्य के आधार पर नगरपालिका द्वारा नंदेय अभिनिर्धारित करे ;

(ङ) पंचमतः, ऐसी राशि, जिसकी राज्य के भीतर या उसके बाहर, मनोरोग विनिर्देशालयों या सार्वजनिक आश्रय स्थानों में, राज्य के किसी स्थान से भेजे गए अधिकतम पागलों अथवा अधिकतम कोढ़ियों के पोषणार्थ अभिदाय करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका से अपेक्षा की जाए ;

(च) षष्ठमतः ऐसी राशियाँ, जो राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के प्रति की गई सेवाओं के लिए और उसके द्वारा नगरपालिका की ओर से जल-सकर्म, जन निकास, भूत बहन प्रणाली, सड़कों आदि के अनुरक्षण के लिए खर्च की सम्बन्ध में राज्य सरकार को देय हों :

परन्तु नगरपालिका को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा अन्य व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी विनिर्दिष्ट कार्य या प्रयोजन के लिए आवंटित रकम, अनन्य रूप से ऐसे कार्य या प्रयोजन के लिए और ऐसे अनुदेशों के अनुसार उपयोग की जाएगी जो राज्य सरकार द्वारा साधारणतया या विशेषतया इस निमित्त जारी किए जाएं ।

(2) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रभागों के तथा ऐसे नियमों के अधीन, जो राज्य सरकार, नगरपालिका के विभिन्न कर्तव्यों को प्राथमिकता दिये जाने के सम्बन्ध में बनाए, नगरपालिका निधि, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर और राज्य सरकार की स्वीकृति से नगरपालिका क्षेत्र के बाहर निम्नलिखित विषयों के प्रभागों तथा उनके आनुषंगिक व्ययों के पूर्णतः या अंशतः संदाय के लिए उपयोज्य होंगी, अर्थात्:—

(क) सभी सार्वजनिक मार्गों, पुलों नगर दोबारों नगर-द्वारों, तटबन्धों, नालियों,

मलकुण्डों, शीवालियों, भूत्रालयों, जलाशयों और जल-मार्गों का सन्निर्माण, अनुरक्षण, सुधार, तफाई तथा मरम्मत करना तथा कम्पोस्ट खाद तैयार करना ;

- (घ) ऐसे मार्गों पर या उनमें से किसी पर जन क्लिष्टताय तथा प्रताप व्यवस्था ;
- (ग) शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए या मार्बजनिह स्वास्थ्य के लाभ के लिए विद्यालयों, अस्पतालों तथा औषधालयों का, तथा विश्रामगृहों, सरायों, दीनालयों, मंडियों, स्टालों, शिवर लागने के प्रांगणों, पशु-अवरोधशालाओं तथा अन्य लोकप्रयोगी स्थाओं का सन्निर्माण, स्थापना तथा अनुरक्षण और इस प्रकार किन्हीं मार्बजनिक संस्थाओं का निवन्त्रण तथा प्रजानन ;
- (घ) विद्यालयों, अस्पतालों, औषधालयों, दीनालयों, कुण्डालयों तथा अन्य शैक्षणिक या पुण्यार्थ संस्थाओं को अनुदान ;
- (ङ) प्रशासकों का प्रशिक्षण तथा छात्रवृत्तियों की स्थापना ;
- (च) श्रमिक या श्रमिकों के नमय राहत देना तथा राहत संतमों की स्थापना तथा अनुरक्षण ;
- (छ) मनुष्यों या जीव जन्तुओं के प्रयोग के लिए जन या प्रदाय, भंडारकरण तथा दूषण से परिरक्षण ;
- (ज) वृक्षारोपण तथा उनका परिरक्षण और मार्बजनिक उप वनों तथा उद्यानों की स्थापना तथा अनुरक्षण ;
- (झ) जनगणना करना, जन्म, विवाह तथा मृत्यु का पंजीकरण, मार्बजनिक टीका और स्वच्छता का कोई उपाय ;
- (ञ) मेलों तथा औद्योगिक, प्रदर्शनियों का आयोजन ;
- (ट) स्थावर सम्पत्ति में प्रविष्टियों का कोई अभिलेख तैयार करना तथा उनका अनुरक्षण ;
- (ड) ऐसे सभी कार्य तथा बातें, जिनमें निवासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण या सुखिता का संबंध संभाव्य है, या जिन पर व्यय, नगरपालिका द्वारा, राज्य सरकार का स्थापित है, नगरपालिका निधि पर समुचित भार घोषित किया जाए ; और
- (ड) बारा 47 और 48 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए और अन्य सभी प्रयोजनों के लिए जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा या तत्कमय प्रवृत्त अन्य किसी विधि द्वारा नगरपालिका को शक्ति का प्रदत्त की जाती है या कर्तव्य अधिरोपित किये जाते हैं :

परन्तु नगरपालिका निधि से भिन्न उन मामलों के जो विहित किए जाएं तब तक व्यय नहीं किया जाएगा जब तक उनके लिए वजह में उपबन्ध नहीं किया जाता है या समयक रूप से अनुपस्थित पुनर्विनियोग द्वारा निधि प्राप्त नहीं की जाती है ।

(3) पूर्वोक्त उप-धाराओं में किसी बात के होने हुए भी, ऐसे किसी विषय के अनुषंगी कोई भी प्रसार या व्यय, जो राज्य सरकार द्वारा, माध्याम या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कोई ऐसा विषय घोषित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में किसी भी व्यय की नगरपालिका निधि में पुन नहीं की जाएगी, नगरपालिका निधि में से नहीं दिए जाएंगे ।

(4) इस अधिनियम तथा नियमों और उप-विधियों के उपबन्धों के अधधीन किमी सम्पत्ति तथा किमी नगरपालिका के या उनको समिति की किसी बैठक में सम्भाषित करने

बाले किसी मददगार का कर्तव्य होगा कि वह किसी ऐसे विभाग पर, जिसके लिए इस धारा में प्रावधान है, या उसी अन्य धारा में उपलब्ध नहीं किया गया है, विचार या विचार-विमर्श अनुज्ञात नहीं करे।

54. इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका और उनकी समितियों के सदस्यों का मंद्य होने द्वारा 52 के अधीन गठित नगरपालिका निधि में से मंद्य किए जाएंगे।

नगरपालिका निधि में से सदस्यों को भत्ते का संदाय।

1934 का 2 बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 में यथापरिभाषित कोई राष्ट्रीयकृत बैंक या सहकारी बैंक या अनुसूचित बैंक अथवा ऐसा बैंक जिसका सरकारी कोष का कारण हो गया है अथवा डाकघर है, नगरपालिका निधि ऐसे किसी कोष, उपकोष, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, अनुसूचित बैंक या बैंक अथवा डाकघर में रखा जाएगा।

नगरपालिका निधि की अभिरक्षा।

(2) ऐसे स्थानों में, जहाँ कोई ऐसा कोष या उपकोष या राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा सहकारी बैंक या अनुसूचित बैंक या डाकघर नहीं है, तो वहाँ नगरपालिका निधि, उपकोष का पूर्व सञ्चालन से किसी बैंकदार या बैंक के रूप में कार्यरत व्यक्ति और जिसने इस प्रकार निक्षेप निधि की सञ्चालन अभिरक्षा और भाग पर प्रतिभूति देने के लिए ऐसा प्रतिभूति दी है उसी उपयुक्त प्रत्येक मामले में पर्याप्त रूपसे, के पास निक्षेप का जा सकेगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा में "सहकारी बैंक" अभिव्यक्ति में ऐसा सहकारी बैंक अभिमत होगा जो बैंककारी कामकाज करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 2 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति प्राप्त करना है।

56. नगरपालिका के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे अधिशेष धनों को जिसकी प्रवेष्टा चालू व्ययों के लिए न हो, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खण्ड (ख-11) में यथा परिभाषित सहकारी बैंक, या किसी अनुसूचित बैंक में या किसी डाकघर में आज पर जमा करे और ऐसे धनों का विनिधान केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में तथा ऐसी अन्य लोक प्रतिभूतियों में करे, जिन्हें राज्य सरकार उस निमित्त विनियमित करे।

अधिशेष निधियों को जमा और उनका विनिधान करने की शक्ति।

57. (1) राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी विशेष आरक्षण या उसके द्वारा अधिरोपित किसी विशेष धनों के अधिर्धान, इस धारा में इन के बाद विनियमित संग्रहण को नया नगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्थित सभी सम्पत्ति नगरपालिका में निहित होगी तथा नगरपालिका के नियन्त्रणाधीन होगी और ऐसी अन्य सम्पत्ति सम्पत्ति सहित, जो नगरपालिका में पहले से ही निहित है जो इसके बाद निहित हो, नगरपालिका द्वारा धारित की जाएगी तथा इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रयोगों के लिए उपयोगित की जाएगी, अर्थात्,—

नगरपालिका में निहित सम्पत्ति।

(द) सभी सार्वजनिक नगर दीवारें, द्वार, मण्डप, स्तूप, वृक्षालय, याद तथा विष्ठा के आगार तथा प्रत्येक प्रकार के सार्वजनिक निर्माण, जो नगरपालिका निधि में से सन्निमित्त किए गए हैं या अनुज्ञित किए जाने हैं;

- (ख) सभी सार्वजनिक जल स्रोत, चबूतरे तथा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये जल प्रदाय, जन-भंडारण तथा जल संचितरण के संकर्म तथा सभी पुल, निर्माण, इजन, उनसे सम्बद्ध और अनुलग्न सामग्री तथा वस्तुएं, और किसी सार्वजनिक जलाशय या कुएं से अनुलग्न तथा समाप्त स्थित कोई भूमि भी, जो निजी सम्पत्ति नहीं ;
- (ग) सार्वजनिक मल-प्रणाल तथा नालियां तथा किसी सार्वजनिक मार्ग में या उसके नीचे, या किसी सार्वजनिक मार्ग के साथ-साथ नगरपालिका द्वारा या उसके लिये मन्त्रिमित सभी मल-प्रणाल, नालियां, और जल मार्ग, और उनसे अनुलग्न सभी संकर्म, सामग्रियां तथा वस्तुएं ;
- (घ) समस्त धूल, गन्दगी, गोबर, भस्म, कूड़ा कचरा, किसी भी प्रकार का जान्तव-द्रव्य या गन्दगी या काठ-कवाड़ या जीव-जन्तुओं की लाशें, जो नगरपालिका ने मार्गों, पारों, चौकगतों, मल-प्रणालों, मलकुण्डों, या अन्य स्थानों से एकत्रित की है, या नगरपालिका द्वारा धारा 154 के अधीन नियत स्थानों में जमा की गई है ;
- (ङ) सभी सार्वजनिक दीप-स्तम्भ, और उनसे सम्बद्ध या अनुलग्न साधित ;
- (च) राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका को अंतरित या दान या क्रय द्वारा या अन्यथा स्थानीय सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अजित सभी भूमि या अन्य सम्पत्ति ;
- (छ) सभी सार्वजनिक मार्ग, जिनकी भूमि राज्य सरकार के स्वाभिविवाधान नहीं है, और उनके खड्डे, पत्थर तथा अन्य सामग्री तथा साथ उगने वाले वृक्ष और ऐसे मार्गों के लिये उपबन्धित परिनिर्माण, सामग्रियां, औरार तथा वस्तुएं ।

(2) जहां राज्य सरकार कोई स्थावर सम्पत्ति किसी नगरपालिका को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये विक्रय से अन्यथा अंतरित करती है, वहां जब तक तत्प्रतिकूल विशेषतया उपबन्धित न हो, ऐसे अंतरण को शर्त यह समझी जाएगी कि यदि सरकार द्वारा सम्पत्ति का किसी भी समय पुनर्ग्रहण कर लिया जाता है तो उसके लिये संदेय प्रतिकर, किसी दशा में उस राशि से, यदि कोई हो, अधिक नहीं होगा, जो राज्य सरकार को अंतरण के लिये संदत्त राशि तथा नगरपालिका द्वारा भूमि पर परिनिर्मित किन्हीं निर्माणों या निष्पादित किन्हीं अन्य संकर्मों की लागत या वर्तमान मूल्य, इन में जो भी कम हो, को जोड़ने से आती है ।

(3) नगरपालिका सभी ऐसी म्यावर सम्पत्तियों का रजिस्टर तथा मानचित्र रखेगी जिनकी वह स्वत्वधारी है या जो उनमें निहित है या जिन्हें वह राज्य सरकार के लिए म्यावर के रूप में धारण करती है ।

(4) कार्यपालक अधिकारी, नगरपालिका के पूर्व अनुमोदन ने,

- (i) नगरपालिका की किसी जंगम सम्पत्ति को, जिसका मूल्य एक लाख रुपए से अधिक नहीं है, विक्रय द्वारा या अन्यथा व्ययनित कर सकता है; या
- (ii) नगरपालिका की किसी स्थावर सम्पत्ति को, 10 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए, पट्टे पर दे सकता है; या
- (iii) नगरपालिका की किसी स्थावर सम्पत्ति का जिसका मूल्य एक लाख रुपए से अधिक नहीं है या जिसका वार्षिक भाटक दस हजार रुपए से अधिक नहीं है, विक्रय कर सकता है या उसको शाश्वतिक पट्टे पर दे सकता है ।

(5) कार्यपालक अधिकारी, नगरपालिका के पूर्व अनुमोदन से दायित्वों को परिनिर्धारित करने के लिए गैर मरजरी स्त्रांतों से उधार ली गई सम्पत्तियों, सुख सुविधाओं और जनोपयोगी सेवाओं का विक्रय कर सकेगा या उन्हें पट्टे पर दे सकता है ।

58. (1) नगरपालिका तथा ऐसी स्थावर सम्पत्तियों की तालिका तथा उनका मानचित्र रखेगी, जिनकी नगरपालिका स्वत्वधारी है या जो उसमें निहित है या जिन्हें वह राज्य सरकार के लिए न्याय के रूप में धारण करता है।

नगरपालिका की तालिका तथा मानचित्र।

(2) ऐसी तालिका और मानचित्र की प्रतियां निदेशक और ऐसे अन्य अधिकारी या प्राधिकारी के कार्यालय में जमा की जाएंगी, जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे और उसमें किये गये सभी परिवर्तन तुरन्त ऐसे निदेशक को या अन्य अधिकारी अथवा प्राधिकारी को सूचित किये जायेंगे।

59. प्रत्येक नगरपालिका धारा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में उपबन्धित अपने प्राधिकाराधीन नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं का परिबन्धित सीमाओं को परिनिष्पन्न करने वाले पर्याप्त सीमा-चिह्न परिनिर्मित और स्थापित कराएंगी तथा सदुपरास्त उन्हें अनुरक्षित करेगी।

नगरपालिका क्षेत्र के सीमा-चिह्नों का परिनिर्माण तथा अनुरक्षण।

60. (1) नगरपालिका निधि में से पोषित प्रत्येक मार्बर्जल संस्था का प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन नगरपालिका में निहित होगा।

(2) जब कोई मार्बर्जल संस्था नगरपालिका के निदेशाधीन, प्रबन्धाधीन और नियन्त्रणाधीन कर दी गई है, तो उसकी सारी सम्पत्ति, विन्यास तथा निधियां नगरपालिका द्वारा न्याय के रूप में ऐसे प्रयोजनों के लिए धारण की जाएंगी, जिनके लिए ऐसी सम्पत्ति विन्यास तथा निधियां उस समय विधिपूर्वक उपयोग्य थी, अब संस्था इन प्रकार उसके अधीन की गई थी:

मार्बर्जल संस्थाओं का प्रबन्ध।

परन्तु ऐसी किसी संस्था के बाएं में नगरपालिका के स्वतन्त्र प्राधिकार की सीमा राज्य सरकार द्वारा विहित की जा सकती है।

परन्तु यह और कि इस धारा की किसी भी बात के सम्बन्ध में यह अर्थनिर्धारित नहीं किया जाएगा कि वह बात पूरे विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) के अधीन किसी न्यास सम्पत्ति का पूर्व विन्यासों के कोषपाल में निहित होना निवारित करता है।

61. जब कोई भूमि चाहे वह नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर है या बाहर, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है, तो राज्य सरकार नगरपालिका के निवेदन पर भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अधीन उसका अर्जन करने के लिए कार्यवाही कर सकती है, और उस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णित प्रतिर और भूमि को अर्जन करने में किए गये जितने अन्य प्रभावों का नगरपालिका द्वारा संदाय किया जाने पर भूमि नगरपालिका में निहित हो जाएगी।

भूमि का अर्जन।

स्पष्टीकरण.—जब कोई भूमि किसी नए मार्ग के लिए या किसी विद्यमान मार्ग के सुधार के लिए अपेक्षित है तो राज्य सरकार नगरपालिका के निवेदन पर मार्ग के लिए अपेक्षित भूमि के अतिरिक्त मार्ग के दोनों ओर परिनिर्मित किए जाने वाले निर्माणों के स्थलों के लिए आवश्यक भूमि अर्जन करने के लिए कार्यवाही कर सकती है और ऐसी भूमि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित समझी जाएगी।

नगरपालिका क्षेत्र के मार्ग का सुधार।

62. नगरपालिका राज्य सरकार की मंजूरी में धारा 557 या धारा 660 के अधीन नगरपालिका में निहित किसी सम्पत्ति का राज्य सरकार को अर्जन करने में सक्षम है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि वह किसी ऐसे न्यास या मार्बर्जल प्राधिकारों को प्रभावित करे, जिनके अधीन सम्पत्ति धारण की जाती है।

नगरपालिका में निहित सम्पत्ति का अर्जन की शक्ति।

जल-संकर्मों, मूल-प्रणाल-संकर्मों तथा सड़कों, आदि का प्रबन्ध ग्रहण करने की शक्ति।

63. (1) जब किसी राज्य सरकार या समाधान हो जाता है कि नगरपालिका ने जल संकर्मों, मूल प्रणाल-संकर्मों या सड़कों के अन्वेषण या मर्मण के सम्बन्ध में अपने कर्तव्यों के पालन में उल्लेख की है तथा ऐसे जल-संकर्मों, मूल प्रणाल संकर्मों या सड़कों का दम वापस अतिरिक्त अवधि के लिए प्रबन्ध ग्रहण करना लोचनहित में है, तो वह, यथास्थिति, जल संकर्मों, मूल प्रणाल संकर्मों या सड़कों का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए आदेश, नगरपालिका को प्रस्थापित कार्यवाही के विरुद्ध हेतुक दशित करने या व्यक्तिगत अवसर देने के पश्चात्, कर सकेगी।

(2) यथास्थिति, जल संकर्मों, मूल-प्रणाल संकर्मों या सड़कों का प्रबन्ध, ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् जिसके लिए वह राज्य सरकार द्वारा ग्रहण कर लिया गया था, अथवा, यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसा समीचीन समझा जाता है तो उसमें पूर्व भी, नगरपालिका को वापस हो जाएगा।

(3) नगरपालिका का यह दायित्व होगा कि वह राज्य सरकार द्वारा जल-संकर्मों, मूल-प्रणाल संकर्मों या सड़कों के अन्वेषण, मर्मण, प्रबन्ध तथा नियंत्रण के लिए और उनके सम्बन्ध में किए गए व्यय, यदि कोई हो, संदत्त करे, गाथ हो। प्रबन्ध ग्रहण से पूर्व उक्त प्रयोजनों के लिए या उनके सम्बन्ध में अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों के वेतन तथा भत्ते संदत्त करने का दायित्व भी नगरपालिका का ही होगा।

(4) जब किसी किसी नगरपालिका के, यथास्थिति, किन्हीं जल-संकर्मों, मूल प्रणाल संकर्मों या सड़कों का प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, तो ऐसे जल संकर्मों, मूल-प्रणाल संकर्मों या सड़कों के सम्बन्ध में इन अधिनियम के अधीन नगरपालिका की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों का पालन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

वित्त
आयोग।

64. (1) राज्य सरकार द्वारा, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 98 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-अ और 243-म के अधीन, गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विचार करेगा और निम्नलिखित के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सिफारिश करेगा,—

(क) निम्नलिखित जो —

(i) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पय करों, और फीसों के निवल आगमों के जो उनमें विभाजित किए जाएं, राज्य सरकार और नगरपालिकाओं के बीच ऐसे आगमों के अपने-अपने भागों के सभी स्तरों पर नगरपालिकाओं के बीच आवंटन को;

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पय करों और फीसों के अवधारण को, जो नगरपालिकाओं को अनुदित या उनके द्वारा विनियोजित की जाएं;

(iii) राज्य की सनेकित निधि में से नगरपालिकाओं के लिए महायत्ता अनुदान को;

(ख) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अभ्युपयोगों को;

(ग) नगरपालिकाओं के सुदृढ़ वित्त हित में सरकार द्वारा वित्त आयोग को निदित किए गए किसी अन्य विषय को;

शामिल करेगा।

(2) सरकार इस धारा के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई टार्वार्ड के व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखेगी।

अध्याय-6

कराधान

65. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और उसके उपबन्धों के अध्याधीन, प्रत्येक नगरपालिका निम्नलिखित कर अधिरूपित करेगी, अर्थात्:—

- (क) निर्माणों और भूमियों पर स्वामी द्वारा संदेय तथा ऐसे निर्माणों और भूमियों के वाणिज्य मूल्य का कम से कम आठे भाग प्रतिशत तथा अधिक से अधिक साढ़े बारह प्रतिशत कोई ऐसा कर, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे;
- (ख) यदि सरकार द्वारा ऐसे प्राधिकृत की गई हों तो हिमाचल प्रदेश में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 द्वारा सम्पत्ति के अन्वयण के विक्रय, दान और नगरपालिका क्षेत्र में स्थित स्थावर सम्पत्ति का कच्चा मूल्य वधक निश्चित पर अधिरूपित शुल्क पर, यथास्थिति, प्रतिफल की राशि, सम्पत्तिक मूल्य या निश्चित पर यथा उपबन्धित वधक द्वारा प्रतिभूत राशि के दो प्रतिशत से अतिरिक्त ऐसा दर पर जो सरकार द्वारा नियत की जाय, अधिभाग के रूप में शुल्क;

उक्त शुल्क दस्तावेज के पंजीकरण के समय न्यायिकोत्तर स्टाम्प के रूप में रजिस्ट्रार शायब उप-रजिस्ट्रार द्वारा संगृहीत किया जाएगा तथा उसकी वसूली नगरपालिका को तुरन्त भेजी जाएगी। इस प्रकार संगृहीत शुल्क की राशि सम्बद्ध नगरपालिका को संचित कर दी जाएगी।

66. (1) राज्य सरकार को इस निम्नलिखित किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के तथा नियमों के अध्याधीन नगरपालिका उभय-पक्ष पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में या उनके भाग में, निम्नलिखित करों, पय-करों और फीसों में से कोई अधिरूपित कर सकती है, अर्थात्:—

- (i) वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं तथा नियोजनों पर कर;
- (ii) नगरपालिका क्षेत्र के भीतर बाड़े पर चल रहे या उनमें रखे गये मोटर यानों में भिन्न यानों पर कर;
- (iii) गवारी, भारवाहन अध्याधोक्ष उठान के लिए प्रयुक्त ऐसे पण्यों पर कर, जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर उपयोग के लिए रखे जाते हैं, बाड़े के वस्तुतः नगरपालिका क्षेत्र के भीतर रखे जाते हैं या उनके बाहर;
- (iv) नगरपालिका क्षेत्र के भीतर रखे गये कुत्तों पर कर;
- (v) प्रदर्शन कर;
- (vi) नगरपालिका क्षेत्र में प्रवेश करने वाले मोटरयानों में भिन्न यानों पर और अन्य गवारीयों पर पय कर;
- (vii) नगरपालिका क्षेत्र के भीतर घातबद्ध नाकाशों पर कर;
- (viii) नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा उपभुक्त विद्युत की प्रत्येक यूनिट पर एक पैसे की दर से विद्युत की उपभोग पर कर;
- (ix) गमाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों में अन्यथा विज्ञापनों पर कर;
- (x) भवन रेखांक की मंजूरी के आवेदन के साथ संदेय भवनों पर कर;
- (xi) तीर्थ यात्राओं के सम्बन्ध में फीस;
- (xii) जल-विकास के सम्बन्ध में फीस;
- (xiii) प्रकाश व्यवस्था के सम्बन्ध में फीस;
- (xiv) अपमार्जन के सम्बन्ध में फीस;
- (xv) शौचालयों तथा शौचगर्तों की सफाई के लिए फीस;
- (xvi) धारा 205 के अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन आन्तरिक सेवाओं की व्यवस्था के लिए लागत स्वरूप फीस;

कर, जो नगरपालिका अधिरूपित करेगी।

कर, जो अधिरूपित किया जा सकेगा।

(xvii) शिखा उपकर ;

(xviii) भू-राजस्व पर स्थानीय कर ;

(xix) राज्य सरकार की पूर्ण स्वीकृति में, कोई अन्य कर, पथकर अथवा फीस, जिसे राज्य में लगाने की शक्ति भारत के संविधान के अधीन राज्य विधान मण्डल को प्राप्त है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी कर, पथकर या फीस की दर, उम्मेद खण्ड (viii) के अधीन कर की दर के सिवाय नगरपालिका द्वारा अवधारित की जाएगी :

परन्तु ऐसी दरें, उन अधिकतम सीमाओं से अधिक नहीं होगी जें राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

कर लगाने की शक्ति का परिसी-
मन।

67. धारा 65 तथा 66 की कोई भी बात, किसी नगरपालिका को कोई ऐसा कर, पथकर अथवा फीस उद्ग्रहीत करने के लिये प्राधिकृत नहीं करे, जिसे राज्य में अधिरोपित करने की शक्ति भारत के संविधान के अधीन राज्य विधान मण्डल को प्राप्त नहीं है :

परन्तु किसी ऐसे कर, पथकर या फीस का, जो संविधान के प्रांग्ग में नुरन्त पूर्व किसी नगरपालिका क्षेत्र में विधिपूर्वक उद्ग्रहीत की जा रही थी, इस प्रकार उद्ग्रहण तब तक चानू रखा जा सकता है, जब तक समद द्वारा, विधि द्वारा, उसके प्रतिकूल उपबन्ध नहीं कर दिया जाता।

स्पष्टीकरण.—इस धारा में "कर" के अन्तर्गत है, कोई शुल्क अथवा उपकर।

धारा 65 के अधीन करों के सम्बन्ध में प्रक्रिया।

68. (1) नगरपालिका किसी विशेष अधिवेशन में धारा 65 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संकल्प पारित करेगी, जिसमें संकल्प में नियत की जाने वाली तारीख से कर के अधिरोपण का निर्देश होगा। यदि नगरपालिका ऐसा कोई संकल्प पूर्वोक्त अवधि के भीतर पारित करने में असफल रहती है, तो इस निमित्त संकल्प के सम्बन्ध में वह समझा जाएगा कि वह नगरपालिका द्वारा उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर पारित कर दिया गया है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन संकल्प पारित किए जाने या पारित नमजे जाने के पश्चात् राज्य सरकार, नियत तारीख से कर का अधिरोपण राजपत्र में अधिसूचित करेगी।

बिजली के उपभोग पर कर का संग्रहण तथा संदाय।

69. (1) धारा 66 की उप धारा (1) के खण्ड (viii) में निर्दिष्ट बिजली के उपभोग पर कर का संग्रहण, यथास्थिति, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं में उपभोग के लिए बिजली का प्रदाय करता है, किया जाएगा और सम्बद्ध नगरपालिका को संदत्त किया जाएगा :

परन्तु जहां कोई व्यक्ति अपने निजी उपयोग या उपभोग के लिए बिजली पैदा करता है, वहां कर ऐसा व्यक्ति देगा।

(2) ऐसे कर का संग्रहण और संदाय, ऐसी रीति में किया जाएगा, मानो वह हिमाचल प्रदेश बिजली (शुल्क) अधिनियम, 1975 के अधीन राज्य सरकार को संदेय बिजली शुल्क हो।

(3) ऐसा कर, भारत सरकार द्वारा बिजली के उपभोग पर, अथवा जहां किसी रेलवे के अन्तिमोप, अन्तर्क्षण या प्रचालन के लिए भारत सरकार द्वारा बिजली का उपभोग किया जाता है, वहां उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

1948 का
केन्द्रीय अधिनियम 54.

70. (1) नगरपालिका किसी विषय पर अधिवेशन में, धारा 66 के अर्धीन किसी कर का अधिरोपण प्रस्थापित करने के लिए सकल्प पारित कर सकती है।

धारा 66 के अर्धीन कर अधिरोपित करने की प्रक्रिया।

(2) जब ऐसा संकल्प पारित हो गया है तो नगरपालिका, कर लगाए जाने के लिये प्रस्थापित व्यक्तियों का वर्ग अथवा सम्पत्ति का विवरण, लगाए जाने वाले कर की राशि या दर तथा अपनी जाने वाली निर्धारण पद्धति परिनिश्चित करने हुए नोटिस प्रकाशित करेगी।

(3) प्रस्थापित कर के सम्बन्ध में आक्षेप करने वाला कोई निवासी, उक्त नोटिस के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर, अपना आक्षेप लिखित रूप में नगरपालिका को प्रस्तुत कर सकता है तथा नगरपालिका उनके आक्षेप पर विचार किसी विषय अधिवेशन में करेगी।

(4) यदि नगरपालिका अपनी प्रस्थापनाओं का या उनमें से किसी का मंजूर करने का विनिश्चय करती है तो वह मंजूरित प्रस्थापनाओं को, यह उपदेशित करने वाले नोटिस के साथ प्रकाशित करेगी कि वे उन प्रस्थापनाओं के उपांतरण में हैं, जो आक्षेप के लिए पहले प्रकाशित की गई थी।

(5) संशोधित प्रस्थापनाओं के प्रति किन्हीं ऐसे आक्षेपों के सम्बन्ध में, जो उनके प्रकाशन से तीस दिन के भीतर प्राप्त हों, उप-धारा (3) में विहित रीति में कार्यवाही की जाएगी।

(6) जब नगरपालिका ने अपनी प्रस्थापनाएं अन्तिम रूप से दाय कर ली हैं, तो वह, यदि प्रस्थापित कर धारा 66 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) से खण्ड (xvi) तक के अन्तर्गत आता है, निर्दिष्ट करेगी कि कर अधिरोपित किया जाये, और उस आशय के अपने आदेश की एक प्रति उपायुक्त, निदेशक, और राज्य सरकार को भेजेगी और यदि प्रस्थापित कर किसी अन्य उपबन्ध के अन्तर्गत आता है तो वह अपनी प्रस्थापनाएं, उनके सम्बन्ध में किये गये आक्षेप सहित, यदि कोई हो, उपायुक्त को प्रस्तुत करेगी।

(7) यदि प्रस्थापित कर धारा 66 की उप-धारा (1) के खण्ड (xvi) से (xix) के अन्तर्गत आता है तो उपायुक्त प्रस्थापनाएं तथा आक्षेप, अपनी निफारिश सहित निदेशक के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(8) राज्य सरकार उप-धारा (7) के अधीन कराधान के लिये प्रस्थापनाएं प्राप्त होने पर उन्हें स्वीकृत कर सकती है या स्वीकृत करने से इनकार कर सकती है अथवा उन्हें आगे विचारण के लिए नगरपालिका को वापस कर सकती है।

(9) जब—

(क) उप-धारा (6) और (7) के अधीन आदेश की प्रति प्राप्त हो गई है, या

(ख) उप-धारा (8) के अधीन कोई स्थापना स्वीकृति हो गई है,

तब राज्य सरकार कर का अधिरोपण ऐसे आदेश या प्रस्थापना के अनुरार अधिसूचित करेगी और अधिसूचना में, अधिसूचना की तारीख से कम से कम एक मास पश्चात् की कोई तारीख विनिर्दिष्ट करेगी, जिसको कर प्रवृत्त होगा।

(10) वार्षिक रूप से उद्घटनीय कर, किसी वर्ष में जनवरी के प्रथम दिन को या वर्ष के प्रथम दिन को या नूनाई के प्रथम दिन का या अक्षर के प्रथम दिन को प्रयुक्त होगा, और यदि वह उस वर्ष के प्रथम दिन में बिना दिन को, तब तो वही वह उद्घटनीय है, प्रयुक्त होता है, तो ऐसे वर्ष के प्रथम दिन तक वैसाविक रूप में उद्घटनीय होगा, जो तत्पश्चात् आगामी वर्ष हो।

5

(11) इस अधिनियम के अधीन कर के अधिरोपण की कोई अधिसूचना इस बात का निश्चयायक साक्ष्य होगी कि कर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार लगाया गया है।

कराधान के
मन्त्रालय में
राजपत्र की
प्रति।

71. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचित विशेष या साधारण आदेश द्वारा, किसी नगरपालिका में, धारा 66 में वर्णित कोई कर, जो पहले लगाया न गया हो, ऐसी दर पर तथा ऐसी अवधि के भीतर अधिरोपित करने की प्रवृत्ति कर सकती है, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए और नव नगरपालिका तदनुसार कार्य करेगी।

10

(2) राज्य सरकार पहले लगाए गए किसी दर की दर को उपांतरित करने की किसी नगरपालिका में प्रवृत्ति कर सकती है और नव नगरपालिका कर को ऐसी अवधि के भीतर, जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, अधिरोपित करेगी।

(3) यदि नगरपालिका उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन पारित किसी आदेश को कार्यान्वित करने में असफल रहती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचित उपयुक्त आदेश द्वारा, कर अधिरोपित या उपांतरित कर सकती है। इस प्रकार किया गया आदेश इस प्रकार प्रवृत्ति होगा, मानो वह नगरपालिका द्वारा उचित रूप में पारित संकेत में और नामा प्रकाशना धारा 70 में दी गई शर्तों के अनुसार स्वीकृत की गई हो।

15

निर्धारण-
सूची तैयार
करना।

72. नगरपालिका उन सभी निर्माणों और भूमियों की, जिन पर कोई कर लगाया जाता है, निर्धारण सूची तैयार कराएगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे—

20

(क) मार्ग या प्रभाग का नाम, जिनमें सम्पत्ति स्थित है;

(ख) सम्पत्ति के नाम या संख्या के अनुसार उसका ऐसा विवरण, जो पहचान के लिये पर्याप्त हो;

(ग) स्वामी तथा अधिभोगी के नाम, यदि ज्ञात हों,

(घ) वार्षिक मूल्य;

(ङ) नगरपालिका द्वारा उस पर निर्धारित कर की राशि।

25.5

निर्धारण-
सूची
का पूरा
किया जाता
तथा उनका
प्रकाशन।

73. जब निर्धारण सूची पूरी कर ली गई है, तो नगरपालिका, सूची के बारे में और उस स्थान के बारे में जहां सूची या उसकी प्रति का निरीक्षण किया जा सकता है, मार्गदर्शक नोटिस देगी और सूची में सम्मिलित सम्पत्ति का स्वामी या अधिभोगी होने का दावा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, तथा ऐसे व्यक्ति का कोई प्राधिकृत अधिकारी, सूची का निष्प्रचार निरीक्षण करने तथा उसमें से उद्धरण लेने के लिये स्वतन्त्र होगा।

30

74. (1) नगरपालिका, ऐसी निर्धारण सूची को प्रकाशन के समय, प्रकाशन के कम से कम एक मास बाद के किसी ऐसे समय के सम्बन्ध में सार्वजनिक नोटिस देगी, जब वह मूल्यांकन तथा निर्धारण का पुनरीक्षण करने के लिये प्रयत्न होगी, और उन सभी दशाओं में, जिनमें किसी सम्पत्ति का प्रथम बार निर्धारण किया जाता है या उसके निर्धारण में वृद्धि की जाती है वह इस बात का विशेष नोटिस सम्पत्ति के स्वामी या अधिभागी को देगी।

(2) मूल्यांकन तथा निर्धारण के सम्बन्ध में सभी आदेश, नोटिस में नियत समय में पूर्व लिखित रूप में प्रथम नियत समय पर मौखिक या लिखित रूप में किए जाएंगे।

75. (1) आशेषों को आंच करने और आशेषकर्ता व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा, जो भी वे ठीक समझें, सुनवाई का अवसर देने तथा मूल्यांकन और निर्धारण का पुनरीक्षण पूरा करने के पश्चात् सूची में किये गये संशोधन नगरपालिका में कम से कम दो सप्ताहों के हस्ताक्षरों द्वारा अधिप्रमाणित किये जाएंगे जो उम्मीदमय रूप से प्रमाणित करने कि सूची में दिये गये, मूल्यांकन तथा निर्धारण के प्रति, निवासे उन दशाओं में, जिनमें उम सूची में संशोधन दर्ज किये गये हैं, कोई भी विविधान्य आक्षेप नहीं किया गया है, और ऐसे संशोधनों के अधीन, जो उसके बाद उचित रूप में किए जाएं इस प्रकार निर्धारित कर प्रारंभ के प्रथम दिन को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिए किया गया समझा जाएगा जिसमें अधिनियम की धारा 73 या 74 के अधीन नोटिस जारी किया गया था :

परन्तु ऐसी तारीख उम तारीख में पूर्वतर नहीं होगी जिस को ऐसा भवन अस्तित्व में आता है।

(2) इस धारा के अधीन सूची संशोधन किए जाने के बाद नगरपालिका के कार्यालय में जाना की जाएगी और उसमें दी गई सम्पत्ति के सभी स्वामियों या अधिभागियों या उनके प्राधिकृत अधिकारियों के निरीक्षण के लिये कार्यालय समय के दौरान खुली रखी जाएगी तथा उसके खुले रखे जाने का एक सार्वजनिक नोटिस तत्क्षण प्रकाशित कर दिया जाएगा।

76. (1) नगरपालिका किसी भी समय किसी भी व्यक्ति का नाम, जिसका नाम सम्मिलित किया जाना चाहिए या किया जाना चाहिए या कोई सम्पत्ति जो सम्मिलित की जाती चाहिए या की जाती चाहिए सम्मिलित करके, या किसी सम्पत्ति पर जिसका मूल्यांकन या निर्धारण बाह्य नगरपालिका के या निर्धारित के कपट, संयोग या भूल से, गन्त हो गया है, निर्धारण में परिवर्तन करके या अधिभागों द्वारा संशोधन कर की दशा में संशोधन द्वारा प्रभावित किसी व्यक्ति को नोटिस की तारीख की तारीख में कम से कम एक मास के समय का, जिस पर संशोधन किया जाना है, नोटिस देने के पश्चात् अधिनियम में परिवर्तन करके, सूची का संशोधन कर सकती है।

(2) ऐसे किसी संशोधन में हितवद् कोई व्यक्ति अपना आक्षेप नोटिस में नियत समय में पूर्व लिखित रूप में प्रथम नियत समय पर मौखिक या लिखित रूप में नगरपालिका के समक्ष कर सकता है, और उम आक्षेप के समर्थन में, स्वयं या प्राधिकृत अधिकारियों के माध्यम से, जैसा वह उचित समझे, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका, इस अधिनियम की धारा 2 क खण्ड (1) में यथा परिभाषित "आपिक मूल्य" का प्रभावित करने की दृष्टि से किसी भी समय संशोधन से प्रभावित होने वाले व्यक्ति को तारीख की उम तारीख से एक मास में अनुरोध अवधि का नोटिस देने के पश्चात् जिसका संशोधन किया

निर्धारण-
सूचियों को
पुनरीक्षण
करने के
लिये नियत
समय का
सार्वजनिक
नोटिस।

सूची का
स्थिरीकरण।

निर्धारण-
सूची के
और संशो-
धन।

जाएगा, सुसंगत वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारम्भ होने वाले वर्ष की अवधारण सूची को, किसी सम्पत्ति के वापिक मूल्य को बढ़ाने या घटाने के लिए संशोधित कर सकेगी और नगरपालिका, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा की गई अपील पर विचार करेगी और संशोधित अवधारण सूची उस वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से प्रभावी होगी जिसमें प्रभावित व्यक्ति को नोटिस दिया गया था।

प्रत्येक वर्ष नई सूची तैयार करना आवश्यक नहीं।

77. सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए नई निर्धारण सूची प्रति वर्ष तैयार करना या किसी वर्ष के लिए सूची में दिये गये मूल्यांकन तथा निर्धारण को, ऐसे परिवर्तनों सहित, जो विशिष्ट मामलों में आवश्यक समझे जाएं, ऐसे परिवर्तनों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को मूल्यांकन या निर्धारण के सम्बन्ध में बैसा ही नोटिस देते हुए, मानो नई निर्धारण सूची तैयार की गई है, उस वर्ष के लिए मूल्यांकन तथा निर्धारण के रूप में अपनाना नगरपालिका के विवेकाधीन होगा :

परन्तु किसी वर्ष के लिए सूची में दिए गए मूल्यांकन और निर्धारण पांच वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिए नहीं अपनाए जाएंगे।

प्ररूप की सृष्टि के लिये कर वा अधिविभाग्य न होता।

78. इस अधिनियम के अधिकार को अधीन किया गया कर का कोई भी निर्धारण और उसका प्रभार या उसकी मांग, कर देने के दायी किसी व्यक्ति के नाम, निवास-स्थान, कारबार या उपजीविका के स्थान में, अथवा कर के दायित्वाधीन किसी सम्पत्ति या वस्तु के विवरण में, अथवा निर्धारण या कर की राशि में किसी भूल के कारण, अथवा किसी लेजल-गलती या प्ररूप की अन्य सृष्टि के कारण अधिभिन्न नहीं की जाएगी या प्रभावित नहीं होगी, तथा सम्पत्ति पर ऐसे किसी कर, या ऐसे किसी कर के प्रयोजन के लिए किसी मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में यह पर्याप्त होगा, यदि कर लगाई गई या निर्धारित सम्पत्ति का वर्णन इस प्रकार किया जाता है जैसे वह साधारणतः ज्ञात है और उसके स्वामी या अधिभोगी का नाम लिखना आवश्यक नहीं होगा।

करों के संदाय में छूट देने की नगरपालिका की शक्ति।

79. (1) नगरपालिका, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसकी राय में निर्धनता के कारण कर देने में असमर्थ हो, किसी ऐसे कर के संदाय से, अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि के लिए, पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है, और ऐसी छूट उतनी बार दे सकती है, जितनी बार आवश्यक हो।

(2) नगरपालिका, किसी विशेष बैठक में पारित और राज्य सरकार द्वारा संपुष्ट किसी संकल्प द्वारा,—

(क) उपबन्ध कर सकती है कि सभी या किन्हीं व्यक्तियों को धारा 65 के अधीन, धारा 66 की उपधारा (1) क खण्ड (ii), (iii), (iv), (vi), (xiv), (xv), (xvi) तथा (xix) के अधीन तथा धारा 67 के अधीन अधिरोपित करों के सम्बन्ध में समझौता करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है;

(ख) धारा 65, 66 और 67 के अधीन अधिरोपित किसी कर को उतारदित, निलंबित या उसकी राशि में कमी कर सकती है;

(ग) किसी व्यक्ति या व्यक्ति-वर्ग को अथवा किसी सम्पत्ति या सम्पत्ति के प्रकार को ऐसे किसी कर क संदाय से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है।

80. (1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्ति-वर्ग को अथवा किसी करों के सम्पत्ति या सम्पत्ति के प्रकार को एक किसी कर के संदाय में वर्गित या अग्रतः छूट दे सकती है। संदाय में छूट देने

(2) यदि किसी भी अन्य परिवाद किये जाने पर या अन्यथा, राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि पूर्वगामी धाराओं के अधीन अधिरक्षित किसी कर का भार सरकार की शक्ति है या ऐसे कर का या उनके किसी भाग का उद्ग्रहण जनसाधारण के हित के प्रति अधिकार है, तो वह नगरपालिका से अपेक्षा कर सकती है कि वह ही गई अवधि के भीतर उस आक्षेप को दूर करने के लिए उपाय करे; और, यदि उस अवधि के भीतर राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में अपेक्षा का पालन नहीं किया जाता, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, कर या अथवा उसके किसी भाग का उद्ग्रहण तब तक निलम्बित कर सकती है, जब तक आक्षेप दूर नहीं कर दिया जाता।

81. (1) जब धारा 65 के खण्ड (क) के अधीन किसी कर के लिए निर्धारित किसी ऐसी सम्पत्ति का जिस पर कर वास्तविक रूप में या किस्तों में संदेय है, वर्ष भर या उस अवधि के दौरान, जिनके सम्बन्ध में कोई किस्त संदेय है, अधिभोग नहीं किया गया है या किराया नहीं मिला है, तो नगरपालिका, यथास्थिति, कर की या किस्त की राशि को छूट देगी :

अनुचित
स्थान पर
सम्पत्ति पर
कर की
छूट।

परन्तु ऐसी कोई भी छूट तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक उस अवधि की, जिसके सम्बन्ध में ऐसा दावा किया जाता है, समाप्ति के पश्चात् प्रथम मास के भीतर उन परिस्थितियों का निश्चित हो जाय, जिनके अधीन छूट का इस प्रकार दावा किया जाता है नगरपालिका को नहीं दे दिया गया है।

(2) जब--

(क) यथापूर्वोक्त किसी सम्पत्ति का कम से कम क्रमवर्ती साठ दिन की अवधि के लिए अधिभोग नहीं किया गया है या किराया नहीं मिला; या

(ख) यथा पूर्वोक्त कोई सम्पत्ति पृथक-पृथक वानगृहों से मिलकर बनी है, जिसमें से एक या अधिक को यथापूर्वोक्त किसी अवधि के लिए अधिभोग नहीं किया गया या किराया नहीं मिला है; या

(ग) यथापूर्वोक्त कोई सम्पत्ति अनि द्वारा या अन्यथा पूर्णतः या अधिकांशतः बंजित या नष्ट हो गई है ;

तो नगरपालिका कर या किस्त के ऐसे प्रभाग की, यदि कोई है, छूट दे सकती है, जिसे वह नाम्यापूर्ण समझे।

(3) किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन छूट का दावा करने के लिए हकदार बनाने वाले तथ्यों को सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर ही होगा।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसे निवास-गृह का, जो अन्यथा अधिभोग में नहीं है, अधिभोग में होना न तो इसलिए कहा जाएगा कि उसमें अधिरक्षक मौजूद है और न कि इसलिए कि उसमें आम तौर से प्रयुक्त होने वाला फर्नीचर रखा है।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी गृह के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उसका किराया मिल रहा है, यदि वह किसी ऐसे किराएदार को किराये पर दिया

गया हो, जिसके पास उसके अधिभोग के सतत अधिकार है, चाहे ऐसे क्रियाएँ द्वारा उसका अधिभोग वस्तुतः किया जाना है अथवा नहीं।

(6) इस धारा के अधीन कोई छूट दी जाए या नहीं, इसके विनिश्चय के लिए आवश्यक जाँच कार्यपालक अधिकारी या सचिव द्वारा की जाएगी, जो नगरपालिका से ऐसी मिफारिश करेगा, जो वह उचित समझे :

परन्तु नगरपालिका कर की कोई छूट तब तक नहीं देगी, जब तक उस छूट की सफारिश कार्यपालक अधिकारी या सचिव द्वारा नहीं की जाती।

जानकारी
देने का
कर्तव्य।

82. (1) प्रत्येक व्यक्ति, नगरपालिका द्वारा इस निमित्त सम्यक्तः प्राधिकृत किसी अधिकारी की मांग पर, ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो यह अभिविषय करने की दृष्टि से आवश्यक हो, कि क्या ऐसा व्यक्ति कोई नगरपालिका कर देने का दायी है, और प्रत्येक होटल या संवास-गृह का स्वामी या आवासीय क्लब का सचिव भी, यथापूर्ववर्त मांग किए जाने पर ऐसे होटल, संवास-गृह या क्लब में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि तथाकथित कोई व्यक्ति, जिससे ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की इस प्रकार अपेक्षा की जाती है, ऐसा करने में तोष करता है या ऐसी जानकारी प्रस्तुत करता है, जो मिथ्या है, तो वह जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक पाँच सौ रुपये होगा।

हकों के
अन्तरण
पर नोटिस।

83. (1) जब कभी ऐसी सम्पत्ति पर संपत्ति कर देने के प्राथमिक रूप से दायी किसी व्यक्ति का किसी निर्माण या भूमि पर हक अंतरित किया जाता है, तो अंतरक और अंतरित, यदि अंतरण विलेख पंजीकृत किया जाए तो उसके पंजीकरण से तीन मास के भीतर, या यदि वह पंजीकृत न किया जाये तो उसके निष्पादन से तीन मास के भीतर या यदि कोई भी लिखित निष्पादित न की जाये, तो उसके वास्तविक अंतरण से तीन मास के भीतर, ऐसे अंतरण का लिखित नोटिस नगरपालिका को देगे।

(2) किसी संपत्ति पर कर देने का प्राथमिक रूप से दायी प्रत्येक व्यक्ति, जो यथापूर्ववर्त नगरपालिका को ऐसे अंतरण का नोटिस दिये बिना ऐसी संपत्ति पर अपना हक अंतरित करता है, किसी अन्य दायित्व के अतिरिक्त, जो ऐसी उपेक्षा के कारण उसका वचना है, उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर संदेय ऐसे सभी कर देने का तब तक दायी बना रहेगा, जब तक ऐसा नोटिस नहीं दे देता या जब तक नगरपालिका की वहीनों में अन्तरण अभिलिखित नहीं कर दिया जाता।

(3) जब कभी किसी निर्माण या भूमि का हक किसी व्यक्ति पर विरासत से न्यायत हो गया है, तो वारिस, पूर्व स्वामी की मृत्यु की तारीख से तीन मास के भीतर ऐसी विरासत का लिखित नोटिस नगरपालिका को देगा।

(4) इस धारा की किसी बात के सम्बन्ध में यह अभिविधित नहीं किया जाएगा कि वह उक्त करों के सम्बन्ध में अन्तरिती या वारिस के दायित्व को कम करती है या सम्बद्ध सम्पत्ति के बारे में देय करों की वसूली के लिए नगरपालिका को पुबिक ढावे को प्रभावित करती है।

(5) कोई भी व्यक्ति, जो उप-धारा (1) और (3) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, किसी अन्य शक्ति के अतिरिक्त, जो वह इसी उपधारा के कारण उपगत करता है, जमाने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पचास रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा, और अनवरत भंग की दशा में, ऐन अतिरिक्त जमाने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान भंग होता रहता है, दस रुपये होगा।

84. नगरपालिका किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत कर सकती है—

प्रवेश करने की शक्ति।

(क) किसी निर्माण या भूमि के अधिभागी को, या यदि कोई अधिभागी न हो, तो स्वामी को, चौबीस घण्टे का नोटिस देने के पश्चात् म्यूजियम और भूदान के बीच किसी भी समय, मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए किसी निर्माण में प्रवेश करना, उसका निरीक्षण करना और उसे मापना;

(ख) किसी अस्तबल, यानगृह या अन्य स्थान में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना, जिसके सम्बन्ध में यह विश्वास करने का कारण हो कि उसमें कोई ऐसा यान या पशु है, जो इस अधिनियम के अधीन कार्यक्षेत्र है, या जिसके लिए अनुज्ञप्ति उचित रूप में नहीं ली गई।

85. धारा 68 और धारा 70 की उप-धारा 7 और 8 तथा धारा 75 के उपबन्धों के अन्वये इस अध्याय के अधीन अधिरक्षित तथा नियन्त्रणकालिक रूप में मंदिर कोई कर, ऐसी शारीरों पर तथा ऐसी किस्तों में, यदि कोई हो, जो नगरपालिका, उपायुक्त की पूर्व स्वीकृति से, समय-समय पर निदिष्ट करे, संदेय होगा।

कर कर संदेय।

86. (1) जब किसी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा उसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर के मद्दे कोई राशि देय है, तो नगरपालिका कर देने के लिए दायी व्यक्ति को, सम्पत्ति का, जिसके सम्बन्ध में तथा अधिभागी के जित के लिए प्रभाव लगाया जाता है, विवरण देते हुए उस राशि के लिए बिल परिदत्त करेगा।

सम्पत्ति करों की वसूली।

(2) यदि बिल का संदाय उसके परिदान से दस दिन के भीतर नहीं कर दिया जाता है, तो नगरपालिका बिल के संदाय के लिए दायी व्यक्ति पर मांग के नोटिस की तामील कर सकती है और यदि वह नोटिस की तामील से सात दिन के भीतर नोटिस के लिए उद्ग्रहणीय किसी फीस के सहित देय राशि संदेय नहीं करता या असंदाय के लिए पर्याप्त कारण दर्शित नहीं करता, तो फीस सहित देय राशि कर का बकाया समझी जाएगी।

(3) प्रत्येक ऐसे बकाया की राशि, इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित किसी अन्य रीति में वसूली योग्य होने के अतिरिक्त उस सम्पत्ति पर, जिसके सम्बन्ध में यह संदेय है, राज्य सरकार की ओर से किसी दावे के अन्वये प्रथम भार होगी, और नगरपालिका द्वारा इस निमित्त कलेक्टर को आवेदन करने पर ऐसे वसूली-योग्य होंगे, मानो सम्पत्ति भू-राजस्व निर्धारित सम्पदा हो और बकाया उस पर देय ऐसे राजस्व का बकाया हो।

(4) यदि इस अधिनियम के अधीन स्वामी से उद्ग्रहणीय कोई कर या राशि अधिभागी से वसूल कर ली जाती है, तो किसी तत्प्राप्तिकूल संविदा के न होने पर

ऐसा अधिमोर्गी उन स्वामी से उन वसूल करने का हवादार होगा और उसे अपने द्वारा स्वामी को उस समय या तत्पश्चात देय किए गए में से काट सकता है।

करों की वसूली।

87. (1) इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका द्वारा दावा योग्य कोई कर, जन-उपभूत, रियायत, फीस या अन्य धन, नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या किसी अन्य स्थान में, जहाँ वह व्यक्ति, जिस से धन दावा-योग्य है, तत्समय निवास करता हो, अधिगिरिता प्राप्त किसी मजिस्ट्रेट को आवेदन करने पर, उसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर ऐसे व्यक्ति की किसी जंगम सम्पत्ति के परस्थान तथा विक्रय द्वारा वसूल किया जा सकता है। ऐसा कार्यवाहियों का खर्च, व्यक्तियों से उसी रीति में वसूली योग्य होगा, जिस रीति में उक्त वादा वसूली योग्य होते हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई आवेदन लिखित रूप में होगा तथा नगरपालिका के अध्यक्ष, किसी उपअध्यक्ष, कार्यपालक अधिकारी या सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होगा, किन्तु इसे व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

यान तथा पशु का अभिग्रहण और विक्रय।

88. (1) यदि कोई व्यक्ति, कर देने बिना ऐसे यान या पशु का स्वामी है या उसका अधिमोर्ग करता है, जिसके सम्बन्ध में धारा 65 या धारा 66 के अधीन कर संदेय है, मांग पर देय कर देने में असफल रहता है, तो नगरपालिका द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, ध्यास्थिति, ऐसे यान को तथा पशु को, यदि कोई है, जिसके द्वारा यान खींचा जाता है या वहन किया जाता है, अभिगृहीत तथा निरुद्ध कर सकता है।

(2) ऐसे अभिग्रहण के पश्चात् नगरपालिका द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, अभिगृहीत यान या पशु के श्रवण दोनों के स्वामी को एक लिखित नोटिस रजिस्ट्री डाक से तत्क्षण भेजेंगे कि नोटिस की तारीख की तारीख से पन्द्रह दिनों की समाप्ति के पश्चात् वह ऐसे यान को या पशु को श्रवण दोनों को बेच देगा।

(3) यदि अभिग्रहण की तारीख से पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर अभिगृहीत पशु या यान का दावा न दिया जाए तथा उस पर देय कर दे न दिया जाए, तो उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी निदेश कर सकता है कि यान या पशु या दोनों आवश्यक नीलामी में बेच दिये जाएंगे और विक्रय आगमों का उपयोग निम्नलिखित के संदाय के लिए किया जाएगा:—

(क) यान या पशु या दोनों पर देय कर, यदि कोई है;

(ख) कर की राशि से अनधिक ऐसी शास्ति, जो उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी निर्दिष्ट करे; और

(ग) ऐसे संसदाय, अभिग्रहण, निरोध तथा विक्रय के कारण हुए सभी व्यय।

(4) अधिग्रहण विक्रय आगम, यदि कोई है, नगरपालिका निधि में जमा करा दिये जाएंगे और उनको, यान या पशु के श्रवण दोनों के स्वामी की मांग पर या उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को समाधान प्रदत्त रूप में उनके हवादार किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता है :

परन्तु यदि विवाद की समाप्ति में पूर्व किसी गण, गिरा व्यक्ति या उसका प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका को अथवा यान या पशु का विवाद करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उप-धारा (3) में निर्दिष्ट दाय राशि निविदित करता है, तो उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी इस प्रकार अभिगृहीत यान या पशु को, अथवा दोनों को, नत्क्षण छोड़ देगा।

89. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी नगरपालिका द्वारा दावा-योग्य किसी घर, जल-उपगृह, किराया, फीस अथवा किसी अन्य धन के बायों के गृहे कोई राशि, इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित किसी अन्य रीति में वसूली योग्य होने के अतिरिक्त, नगरपालिका द्वारा कलक्टर को इस निमित्त आर्षेदन किए जाने पर भू-राजस्व की वसूली के रूप में वसूली की जा सकती है।

देयों की भू-राजस्व की वसूली के रूप में वसूली।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार किसी नगरपालिका के आर्षेदन पर या अन्यथा किसी व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 के अधीन कलक्टर को शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सक्ती और जहाँ कलक्टर, इस प्रकार नियुक्त कर दिया गया हो, वहाँ उक्त उप-धारा के अधीन आर्षेदन ऐसे कलक्टर को किया जाएगा।

90. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी कर के निर्धारण या उद्ग्रहण के विषय अथवा किसी कर का प्रतिदाय करने से इनकार करने के विषय कोई अपील, उपयुक्त को या ऐसे अन्य अधिकारी को हाँ हो सकती, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मनस्क किया जाए।

अपील।

(2) यदि इस धारा के अधीन किसी अपील की सुनवाई पर किसी कर के दायित्व के या निर्धारण के सिद्धांत के बारे में कोई ऐसा प्रश्न उठता है, जिसके उत्तर के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई करने वाले अधिकारी को सुनिश्चित संदेह है, तो वह या तो स्वप्रेरणा से अथवा किसी हितवद्ध व्यक्ति के आर्षेदन पर, मामले के तथ्यों का और उस प्रश्न का जिसके उत्तर के सम्बन्ध में संदेह है, विवरण तैयार कर सकता है और उस प्रश्न पर अपनी राय सहित विवरण उच्च-न्यायालय को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट कर सकता है।

1908 का 5 (3) उप-धारा (2) के अधीन निर्देश किए जाने पर, इस मामले में पश्चात्पूर्व कार्यवाहियाँ, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 को धारा 113 और आदेश 46 में अन्तर्विष्ट उच्च-न्यायालय को निर्देशों से सम्बन्धित उपबन्धों के अधामम्भव अनु रूप होगी।

(4) प्रत्येक अपील में खर्च, अपील का विनिश्चय करने वाले अधिकारी के विवेकाधीन होगा।

(5) इस धारा के अधीन नगरपालिका के पक्ष में अधिनिर्णीत खर्च नगरपालिका द्वारा ऐसे वसूली-योग्य होने मालो के अपीलार्थी से देय किसी घर के वसूली हो।

(6) यदि नगरपालिका अपीलार्थी के पक्ष में अधिनिर्णीत खर्च उन के संदाय के आदेश की तारीख के पश्चात् दस दिन के भीतर संदत्त करने में अनफन रहती है, तो खर्च अधिनिर्णीत करने वाला अधिकारी नगरपालिका निधि के अतिशेष की अग्ररक्षा रखने वाले व्यक्ति को राशि संदत्त करने के लिए आदेश कर सकता है।

अपीलों को परिसीमा।

91. (1) किसी भूमि या निर्माण पर किसी कर के सम्बन्ध में कोई भी अपील तब तक नहीं हो सकेगी जब तक वह, यथा-स्थिति, धारा 75 या धारा 76 या धारा 77 द्वारा विहित नोटिस के प्रकाशन के पश्चात् या धारा 78 के अधीन अन्तिम आदेश की तारीख के पश्चात् एक मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती तथा किसी अन्य कर के सम्बन्ध में कोई भी अपील तब तक नहीं हो सकेगी, जब तक वह उस समय से, जब कर के लिए मांग की जाती है, एक मास के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती :

परन्तु किसी अपील के लिए इस धारा द्वारा विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी वह ग्रहण की जा सकती है यदि अपीलार्थी उस अधिकारी का, जिसके समक्ष अपील प्रस्तुत की जाती है, समाधान कर देता है कि उसके पास अपील का उस अवधि के भीतर प्रस्तुत न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था।

(2) कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी ने ऐसी अपील की तारीख तक नगरपालिका को अपने डांग देय अन्य सभी नगरपालिका कर संवत्त न कर दिए हैं।

पुनरीक्षण।

92. (1) राज्य सरकार, नगरपालिका द्वारा अधिरोपित किसी कर के किसी मूल्यांकन या निर्धारण के अभिलेख मंगवा सकेगी, और यदि यह प्रतीत हो कि ऐसी नगरपालिका ने,—

- (क) ऐसी शक्ति का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा इसमें विहित नहीं है; या
- (ख) इसमें विहित अन्य शक्ति का प्रयोग करने में असफल रही है; या
- (ग) अपनी शक्ति के प्रयोग में अवैध रूप से या तारिख अनियमितता से कार्य किया है, तो राज्य सरकार इस विषय में ऐसा आदेश कर सकेगी जैसा वह उचित समझे:

परन्तु राज्य सरकार, इस धारा के अधीन, नगरपालिका द्वारा अधिरोपित किसी कर के निर्धारण या मूल्यांकन में केरफार या उन्ट्रा नहीं करेगी विवाय जहां,—

- (क) कर का निर्धारण या मूल्यांकन जो, यदि यह पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया हो, विषय का अन्तिम रूप में निरधारित करे; या
- (ख) कर का निर्धारण या मूल्यांकन, यदि होता अनुज्ञात किया जाता है, तो यह उस पक्षकार के पक्ष में, जिसके विरुद्ध यह किया गया था, न्याय का न होना होता या अपूर्ण्य हानि कारित होती।

(2) राज्य सरकार, उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति के हितों के प्रतिकूल उस को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर दिए बिना कोई आदेश पारित नहीं करेगी।

निर्धारण प्रश्नगत करना बर्जित।

93. (1) इस अधिनियम में उपबन्धित रीति से मिश्र किसी रीति में या उपबन्धित प्राधिकारी से मिश्र किसी प्राधिकारी के समक्ष, किसी मूल्यांकन या निर्धारण के बारे में न तो कोई आक्षेप किया जाएगा और न ही किसी व्यक्ति के निर्धारणीय या कराधेय होने के बाधित्व के सम्बन्ध में कोई आपत्ति की जाएगी।

(2) इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार से अन्यथा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी कर का कोई भी प्रतिदाय दावा योग्य नहीं होगा।

अध्याय-7

पुलिस सहायता

94. (1) यदि राज्य सरकार की राय है कि नगरपालिका को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए एक मास से अधिक किसी निनिर्दिष्ट अवधि के लिए पूर्ण-कालिक आधार पर पुलिस बल की अपेक्षा है तो वह नगरपालिका द्वारा, उपायुक्त के माध्यम से इस निमित्त आवेदन किये जाने पर ऐसे पुलिस बल की व्यवस्था कर सकती है।

पुलिस बल।

(2) नगरपालिका उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल की व्यवस्था करने के बारे में किये गये व्यवहारी।

95. (1) इस अधिनियम के अधीन पुलिस बल का प्रयोग सम्पूर्ण, इस अधिनियम या नियमों प्रयत्न उप-विधियों के विरुद्ध किये गए किसी अपराध की सूचना सुन्त नगरपालिका को देगा, और नगरपालिका के सभी सदस्यों तथा कर्मचारियों को उनके विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रयोग में सहायता देने के लिए आवश्यक होगा।

पुलिस की शक्तियाँ और कर्तव्य।

(2) ऐसे पुलिस बल का प्रयोग सदस्य इस अधिनियम या नियमों प्रयत्न उप-विधियों के विरुद्ध कोई अपराध करने सामने करने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है—

(क) यदि व्यक्ति का नाम तथा पता उसे मालूम नहीं है, और

(ख) यदि व्यक्ति अपना नाम तथा पता देने से इनकार करता है, प्रयत्न यदि, नाम तथा पता किये जाने पर उसके ठीक होने के बारे में सन्देह है।

(3) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किया गया कोई भी व्यक्ति, मन्त्रालय निरुद्ध रखा जा सकता है, जब तक उसका नाम तथा पता ठीक रूप से अभिलिखित नहीं कर लिया जाता।

परम्पु इस प्रकार गिरफ्तार किया गया कोई भी व्यक्ति, उसके निरोध के विषय किसी मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, उसने समय से अधिक समय के लिए निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, जितना उसे किसी मैजिस्ट्रेट के समक्ष लाए जाने के लिए आवश्यक हो।

96. जब राज्य सरकार की राय है कि किसी ऐसे मेले, कृषि प्रदर्शन प्रयत्न औद्योगिक प्रदर्शनों के अवसर पर, जिसका प्रबन्ध नगरपालिका ने किया है, अथवा महामारी के कारण खाली किये गए मकानों की रक्षा के प्रयोजन के लिए, विशेष पुलिस संरक्षण प्रपेक्षित है, तब राज्य सरकार ऐसे संरक्षण की व्यवस्था कर सकती है और नगरपालिका उसका सम्पूर्ण व्यय या ऐसे व्यय का वह प्रमाण देगी, जिसे राज्य सरकार माग्य के आधार पर नगरपालिका द्वारा संदेय समझे।

मेलों आदि में विशेष पुलिस सहायता।

अध्याय-8

अग्नि का प्रभुत्व और नियंत्रण

97. नगरपालिका, अग्नि के प्रभुत्व तथा नियंत्रण के विषय, अग्निजामक बल की स्थापना तथा उसका प्रभुत्व कर सकती है, और यदि राज्य सरकार इस प्रकार निर्देश करे, तो ऐसा करेगी, और दल द्वारा अपने कर्तव्यों के दक्षतपूर्ण निर्वहन के विषय शोचन, मशीनरी अथवा प्रामुखता सम्प्रेषित करने के साधनों की व्यवस्था करेगी।

अग्निजामक बल की स्थापना और प्रभुत्व।

अग्नि यमन
के लिये
अग्निशामक
दन तथा
अन्य
व्यक्तियों की
शक्ति ।

98. (1) किसी नगरपालिका क्षेत्र में आग लगने के कारण पर, धोक या कोई अन्य-
कारी मैजिस्ट्रेट, कार्यपालक अधिकारी, नगरपालिका का मजिद, नगरपालिका का कोई
सदस्य, नगरपालिका द्वारा अनुरक्षित अग्निशामक दल का कोई ऐसा सदस्य जो दल के
व्यक्तियों के कार्य का निर्देशन उसी समय तथा वहाँ कर रहा हो, तथा उन-निरीक्षित की
पदवी से अग्निमन पदवी का कोई पुलिस अधिकारी —

- (क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अपनी उपस्थिति द्वारा आग बुझाने के या जीवन या
सम्पत्ति को बचाने के कार्यों में हस्तक्षेप करता है अथवा बाधा डालता है, हटा
सकता है अथवा हटाये जाने का आदेश कर सकता है ;
- (ख) किसी ऐसे मार्ग अथवा रास्ते को, जिसमें या जिसके निकट आग लग रही है,
बन्द कर सकता है ;
- (ग) आग बुझाने के प्रयोजन के लिये, किसी परिसर में अथवा उसमें होकर, प्रवेश
कर सकता है अथवा उसे छ्वस्त कर सकता है अथवा उसमें या उसमें से होकर
प्रवेश करा सकता है अथवा उसे छ्वस्त करा सकता है अथवा होज या अन्य
उपकरण गुजारने हेतु उसका उपयोग करा सकता है ;
- (घ) मुख्य नल तथा नालियों को बन्द कर सकता है, ताकि उस स्थान में या उसके
निकट जहाँ आग लगी है, पानी का अधिक दबाव दिया जा सके ;
- (ङ) किसी अग्नि शक्ति (फायर इंजन) के भारसाधक व्यक्तियों से ऐसी सहायता
देने के लिए अपेक्षा कर सकता है, जो संभव हो ;
- (च) साधारणतः ऐसे उपाय कर सकता है, जो जीवन अथवा संपत्ति के परिरक्षण के
लिए आवश्यक प्रतीत हों, तथा

जब ऐसी आग से कोई सरकारी निर्माण संछापत्र हो, तो लोकनिर्माण विभाग का ऐसा
अधिकारी, जो तत्समय निर्माण का भारसाधक हो, इस उप-धारा द्वारा मैजिस्ट्रेट को प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग कर सकता है ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन सदभावपूर्वक किए गए किसी कार्य के लिए कोई भी
व्यक्ति हर्जा देने का दायी नहीं होगा ।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में अथवा अधिरोपित किसी
कानून के निर्बहन में हुआ नुकसान, किसी अग्नि बीमा पालिसी के अधीनस्थित, अग्नि द्वारा
किया गया नुकसान समझा जाएगा ।

नियमों और
विनियमों
का अनु-
पालन ।

99. पूर्वगामी अंतिम धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ, किन्हीं ऐसे नियमों और विनियमों
के अधीन होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन
विरचित किए जाएं ।

अध्याय-9

जल प्रदाय

जल प्रदाय
जो
व्यवस्था ।

100. (1) नगरपालिका अपने नियन्त्रणाधीन क्षेत्र में या उसके किसी भाग में सार्व-
जनिक और घरेलू प्रयोजनों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्यप्रद जल के प्रदाय की व्यवस्था कर सकती
है और जब राज्य सरकार इस प्रकार निर्देश करे तो ऐसी व्यवस्था अवश्य करेगी ।

(2) नगरपालिका क्षेत्र के भीतर ऐसे प्रदाय की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए,
नगरपालिका ऐसे तालाबों, जलाशयों, इंजनों, नलों, टॉटियों और अन्य संक्रमों को, जो
आवश्यक हों, चाहे नगरपालिका क्षेत्र के भीतर या बाहर सन्निहित या अनुरक्षित कराएंगी
और जनता को जल के निःशुल्क प्रदाय के लिए, पर्याप्त स्थायी जल या अन्य सुविधाएँ प्रार्थि
परिनिर्भर कराएंगी ।

(3) जब स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ज्ञेयित हो, तो नगरपालिका यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या जल स्थान्यप्रद है, मानवीय उपयोग के लिए प्रदत्त जल की परीक्षा की व्यवस्था करेगी।

101. (1) नगरपालिका, किसी निमाण के स्वामी द्वारा आवेदन पर, निकटतम मुख्य नल से उसकी परेल प्रयोजनों के लिए ऐसी मात्राओं में जल-प्रदाय की व्यवस्था कर सकती है, जैसी वह व्यक्तिगत समझती है, और किसी भी समय इस प्रकार प्रदत्त जल की मात्रा को, जब कभी वह ऐसा करना आवश्यक समझती है, सीमित कर सकती है।

घरेलू प्रयो-
जनों के
लिए जल-
प्रदाय।

(2) किसी ऐसे नगरपालिका क्षेत्र में, जिसमें जल को उद्गृहीत किया जाता है, ऐसे प्रदाय के बारे में कोई भी अतिरिक्त प्रभाव पड़े नहीं होगा, किन्तु ऐसी मात्रा में, जिस तक ऐसा प्रदाय उप-धारा (1) के अधीन सीमित है, आवश्यक में प्रदत्त जल के लिए और अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में इस धारा के अधीन प्रदत्त सम्पूर्ण जल के लिए, संदाय ऐसी दर पर किया जाएगा, जो उप-विधियों द्वारा नियत की जाए।

स्पष्टीकरण.—घरेलू प्रयोजनों के लिए जल के किसी प्रदाय में निम्नलिखित प्रदाय सम्मिलित नहीं समझे जाएंगे —

- (क) जीव-जन्तुओं के लिए या यानों को धोने के लिए, अर्थात् ऐसे जीव-जन्तु या यान विक्रय अथवा किराये के लिए रखे जाते हैं;
- (ख) किसी व्यापार, विनिर्माण या कारखाने के लिए;
- (ग) फव्वारों, तैरने के स्नानागारों के लिए अथवा किसी सजावटी या शैत्यक प्रयोजन के लिए;
- (घ) उद्यानों के लिए या सिंचाई के प्रयोजनों के लिए;
- (ङ) सड़कों अथवा पथों पर पानी छिड़कने के लिए;
- (च) निर्माण प्रयोजनों के लिए।

102. (1) ऐसे प्रयोजन को, जिसके लिए ऐसा प्रदाय अपेक्षित है, और उस मात्रा को, जिसके उपभोग किए जाने की संभावना है, विनिर्दिष्ट करने वाले लिखित आवेदन की प्राप्ति पर नगरपालिका घरेलू प्रयोजन से निम्न प्रयोजन के लिये जलप्रदाय कर सकती है :

घरेलू प्रयो-
जनों से
निम्न प्रयो-
जनों के
लिए जल-
प्रदाय।

परन्तु निर्माण प्रयोजनों के लिए, तत्काल अधिकारी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र में मंजूर भवन रेखांक की प्रति सहित आवेदन करने पर प्रथमतः जल प्रदाय एक वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा और तत्पश्चात् जो निर्माण को पूरा करने के लिए अनुज्ञात अवधि से अतिरिक्त अवधि के लिए या तीन वर्ष के लिए, जो भी कम हो, एक समय में छः मास के लिए, बढ़ाया जा सकेगा।

परन्तु यह और भी इस अतिनिम्न के प्रारम्भ होने पर या से पूर्व निर्माण प्रयोजनों के लिए किया गया जल प्रदाय तीन वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगा जिसकी गिनती ऐसे प्रारम्भ से की जाएगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त सम्पूर्ण जल के लिए संदाय धारा 101 की उप-धारा (2) के अधीन विहित दर से अन्य किसी दर पर किया जाएगा।

(3) नगरपालिका यदि उसे घरेलू प्रयोजनों के लिए पर्याप्त जल-प्रदाय बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो तो, ऐसे प्रदाय को किसी भी समय बंद कर सकती है।

जल संयोजन के लिए प्रक्रिया।

103. (1) जहाँ धारा 101 या धारा 102 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त हुआ है, वहाँ सभी आवश्यक संचरण-नालियों तथा अन्य फिटिंग नगरपालिका द्वारा प्रदत्त की जाएंगी और ऐसी संचरण-नालियों तथा फिटिंग को बिछाने और उपयोजित करने का कार्य नगरपालिका के आदेशों के अधीन नगरपालिका-अधिकरण द्वारा निष्पादित किया जाएगा; किन्तु कोई ऐसा संवेदन करने पर और इस प्रकार प्रदत्त सभी संचरण-नालियों और फिटिंग पर और इस प्रकार निष्पादित सभी संकर्मों पर हुआ खर्च ऐसा आवेदन करने वाले स्वामी या व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा। नगरपालिका या तौ मीटर की व्यवस्था कर सकती है और उसके लिए किराया प्रभारित कर सकती है अथवा स्वामी या आवेदक से अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे आकार, सामग्री अथवा विवरण के मीटर की व्यवस्था करे, जिसे नगरपालिका अनुमोदित करे।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका जल प्रदाय के लिए आवेदन करने वाले किसी स्वामी या व्यक्ति से अपेक्षा कर सकती है कि वह सभी संचरण-नालियों और फिटिंग की व्यवस्था करे और ऐसी संचरण-नालियों और फिटिंग बिछाने और उपयोजित करने का सारा कार्य अपने निजी खर्च पर और उसके पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण के अधीन कराए।

पानी के दुर्व्यय का नोटिस देने की स्वामी या अधि-भागी की बाध्यता।

104. किसी ऐसे निर्माण या भूमि का स्वामी या अधिभागी, जिस में या जिस पर इन अधिनियम के अधीन प्रदत्त जल की उपेक्षा के कारण या उनके नियंत्रणाधीन अन्य परिस्थितियों के कारण दुरुपयोग किया जाता है, अथवा धारा 101 या धारा 102 के अधीन नियत मात्रा से अधिक्य में उसका उपयोग अनुज्ञा के बिना किया जाता है या जिसमें नालियाँ, मुख्य नल या अन्य संकर्म ऐसी सीमा तक सुरक्षित के बिना हैं, जिन्हें जल का दुर्व्यय होता है, यदि उसे इसका ज्ञान है, तो वह ऐसे अधिकारी को नोटिस देने के लिए आवेदक होगा, जिसे नगरपालिका इस निमित्त नियुक्त करे।

परिसरों को प्रदाय बंद करना।

105. यदि कोई व्यक्ति जिसके परिसर को जल-प्रदाय किया जाता है, जल-कर का या धारा 101 या धारा 102 के अधीन संदेय किसी राशि का, जब देय हो, संदाय करने में या पूर्ववर्ती अन्तिम धारा में उपबंधित नोटिस देन में, उपेक्षा करता है अथवा जानबूझ कर या उपेक्षा से जल का दुरुपयोग या दुर्व्यय करता है, तो नगरपालिका सम्बन्ध नोटिस के पश्चात् उक्त परिसर को जल देना बंद कर सकती है।

संचरणों के सम्बंध में नगरपालिका की शक्तियाँ।

106. जल-प्रदाय की व्यवस्था या अनुरक्षण करने अथवा मुख्य नलों के साथ संचरण या सम्बन्धन स्थापित करने या उनका अनुरक्षण करने के प्रयोजन के लिए अथवा साधारणतः इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, नगरपालिका को वे सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो उसे धारा 136 से 141 द्वारा जल-निकास के सम्बन्ध में प्रदत्त की गई हैं।

निर्माण के स्वामियों से वर्षों के पानी के लिए अपने परिसर में संग्रहण जला-णय की

107. (1) जब भी, नगरपालिका या राज्य सरकार को, सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र की परिधीयताओं में या उसके किसी भाग में स्थित निर्माण या भूमि के स्वामी से, नालियों को साफ करने और पीने के पानी के रूप में प्रयोग करने के प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए वर्षों के पानी का संग्रहण और संरक्षण की उचित व्यवस्था करने की अपेक्षा करना वांछनीय प्रतीत हो तो, ऐसी नगरपालिका, यदि सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, तदनुसार लोक नोटिस द्वारा और किसी अन्य मामले में राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से निदेश दे सकती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन दिए गए नोटिस में निम्नलिखित वर्णित किया जाएगा:--

- (क) स्थानीय क्षेत्र का विस्तार जिसकी परिसीमाओं में निर्माण और भूमि के स्वामियों द्वारा वर्षा के पानी के संग्रहण की व्यवस्था की जानी है;
- (ख) वह रीति जिसमें ऐसे स्वामी द्वारा संग्रहण के लिए धनाय आवतन (धारिता) के स्थान की व्यवस्था नियत की जाएगी, अर्थात् क्या ऐसे आवतन (धारिता) का विस्तार भूमि के क्षेत्र के अनुसार निर्माण के आकार, अधिभोगियों की संख्या या उसके आकलित जमावर्दी मूल्य अथवा इन दो बातों में अधिक रीतियों द्वारा विनियमित किया जाएगा;
- (ग) उस जलाशय या अन्य संग्रहण के स्थान की रचना, सामग्री, स्थिति और संनिर्माण जिसकी व्यवस्था की जानी है;
- (घ) एकत्रीकरण, संग्रहण, प्रदूषण में संरक्षण, और अच्छी स्थिति में रखने और एकलित और संगृहीत वर्षा के पानी के प्रयोग का ढंग; और
- (ङ) वह समय जिसके भीतर नोटिस की अपेक्षाएं पूरी की जाएंगी।

व्यवस्था करने की अपेक्षा करने की शक्ति।

108. नगरपालिका, संग्रहण जलाशय के निर्माण के पर्यवेक्षण और निरीक्षण के लिए और उससे संबद्ध या उससे संबंधित अन्य सभी कार्यों के लिए उपयुक्त बना सकेगी और यदि सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तो बनाएगी और निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी सामग्री और बातों को समय-समय पर उपलब्ध करेगी,--

संक्रमों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण।

- (क) कि संग्रहण जलाशय और यथा पूर्वांकृत अन्य संक्रमों, पूर्ववर्ती धारा के अधीन दिए गए नोटिस के अनुसार निर्मित और कार्यन्वित किए जाएं; और
- (ख) कि ऐसे सभी जलाशय और अन्य संक्रम पूर्वांकृत मजबूती और स्वाधिश्य वाले हैं और किन्हीं ऐसे जलाशयों या अन्य संक्रमों को जो नोटिस की अपेक्षाओं के अनुपालन में नहीं हैं या अनुपयुक्त अथवा अनुरक्षित हैं, हटवा सकेगी और पुनः निर्मित या नगरपालिका के सहायानप्रद रूप में परिवर्तित करवा सकेगी।

109. नगरपालिका, किसी निर्माण या भूमि के स्वामी या अधिभागी से, जिसके बारे में धारा 107 के अधीन वर्षा के पानी के संग्रहण और संरक्षण के बारे में जलाशय की व्यवस्था की गई है, नोटिस द्वारा उक्त जलाशय को मुरम्मत करने, परिवर्तन करने या उसे ठीक स्थिति में रखने की अपेक्षा कर सकेगी।

जलाशयों की मुरम्मत।

अध्याय-10

स्वच्छता और अन्य प्रयोजनों के लिए शक्तियां

110. (1) नगरपालिका, स्नान के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त स्थान अलग बना सकती है और ऐसे समय नियत कर सकती है और महिलाओं तथा पुरुषों के लिए अलग-अलग ऐसे स्थान विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिन पर स्नान किया जा सकता है, और जीव-जन्तुओं या कपड़ों को धोने के लिए अथवा निवासियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता या सूख से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी उपयुक्त स्थान अलग बना सकती है, और सार्वजनिक नोटिस द्वारा इस प्रकार अलग न बनाए गए किसी सार्वजनिक स्थान पर या ऐसे गम्य पर जो नियत न किए गए हों, व्यक्तियों द्वारा, स्नान करना या जीव-जन्तुओं या कपड़ों का धोना, और कोई अन्य कार्य जिससे सार्वजनिक स्थानों का जन कल्पित या उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाए, प्रतिषिद्ध कर सकती है और व्यक्तियों के किसी विनिर्दिष्ट वर्गों या वर्गों

स्नान करने और धुलाई स्थान।

द्वारा या साधारणतया जन-साधारण द्वारा स्थानों के उपयोग के लिए फीस प्रभारित कर सकती है।

(2) नगरपालिका, नोटिस द्वारा ऐसे स्थान नियंत्रण कर सकती है जहाँ कपड़े, विस्तर से संबंधित वस्तुएँ, जो संक्रामण के लिए उच्छेदन रही हैं, धोई जाएंगी तथा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार नियंत्रण किए गए किसी स्थान पर ऐसी कोई वस्तु नहीं धोएगा।

कब्रिस्तानों और श्मशानों के बारे में शक्तियाँ।

111. (1) नगरपालिका, सार्वजनिक नोटिस द्वारा आदेश कर सकती है कि नगरपालिका सीमाओं के भीतर या उनके एक किलोमीटर के भीतर स्थित कोई कब्रिस्तान या श्मशान, जिसका पड़ोस में निवास कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए संतुष्टपूर्ण होना स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है, नोटिस में नियंत्रण की जाने वाली तारीख से बन्द रहेंगे और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसा निदेश किया जाए तो, यह समझा जाएगा कि नगरपालिका ने ऐसे निदेश की अधिसूचना के एक मास के भीतर इस प्रकार आदेश किया है, और ऐसे मामले में, यदि व्यक्तिगत दूरी के भीतर कब्रिस्तान या श्मशान के लिए कोई उचित स्थान विद्यमान नहीं है तो उस प्रयोजन के लिए उचित स्थान की व्यवस्था करेगी।

(2) ऐसी शर्तों के अधीन, जो नगरपालिका इस निमित्त अधिरक्षित करे, ऐसे कब्रिस्तान में से निजी कब्रिस्तानों को नोटिस से छोड़ा जा सकता है:

परन्तु ऐसे कब्रिस्तानों की सीमाएं पर्याप्त रूप से परिनिश्चित होंगी और वे केवल उनके स्वामियों के कुटुम्ब के सदस्यों को दफनाने के लिए ही उपयोग में लाए जायेंगे।

(3) किसी भी कब्रिस्तान या श्मशान को, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् नगरपालिका की लिखित स्वीकृति के बिना, बनाया या विरचित नहीं किया जाएगा। ऐसी स्वीकृति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक स्वास्थ्य अधिकारी ने नगरपालिका की सूचना के लिए लिखित रूप में प्रमाणित न कर दिया हो कि ऐसा कब्रिस्तान या श्मशान लोक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं है:

परन्तु राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना ऐसा कोई कब्रिस्तान या श्मशान बनाया या विरचित नहीं किया जाएगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति, नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना, ऐसे स्थान पर, जो कब्रिस्तान या श्मशान नहीं है, या किसी ऐसे कब्रिस्तान या श्मशान में, जो इस धारा के उपबंधों के प्रतिकूल बनाया या विरचित किया गया है, या उसे बन्द करने के लिए तदधीन नियंत्रण तारीख के पश्चात् कोई जल दफनाता या जलाता है, अथवा दफनवाता या जलवाता है अथवा उसका दफनाया जाना या जलाया जाना अनुज्ञा करता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये तथा अधिक से अधिक पाँच सौ रुपये होगा।

नागल तथा
आवारा
कुत्तों और
अन्य जीव-
जन्तुओं का
व्ययन।

112. (1) नगरपालिका—

(क) किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत कर सकती है—

(i) किसी कुत्ते या अन्य जीव-जन्तु को, जो अलर्न रंग से पीड़ित है या जिसके अलर्न रंग से पीड़ित होने का व्यक्तिगत रूप में संदेह हो अथवा जिसको इस

प्रकार पीड़ित या अपायोक्त संस्थानों में, कुत्ते या अन्य जानवरों के द्वारा, नष्ट करना या नष्ट करना अथवा उसे ऐसा अवधि के लिए जो नगरपालिका निर्दिष्ट करे, परिरुद्ध करना या परिरुद्ध करना ;

(ii) मार्गों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर घूमते हुए ऐसे अवधारी कुत्तों को, जहाँ पट्टों या ऐसे अन्य चिन्हों के बिना हों, जिसे व निजी सम्पत्ति के रूप में सूचित प्रतीत हों, परिरुद्ध करना या परिरुद्ध करना और ऐसे निरोध के लिए कोई फीस प्रभारित करना और ऐसे किसी कुत्ते को, यदि उसका एक सप्ताह के भीतर दावा नहीं किया जाता तथा फीस सदैव नहीं की जाती, नष्ट करना या अन्यथा व्ययन करना ;

(ख) कोई अस्वास्थ्य या स्थायी आदेश जारी करना कि कोई कुत्ता, जो उन्हें निजी सम्पत्ति के रूप में सूचित धातित करने वाले पट्टे या अन्य चिन्हों के बिना, मार्गों पर या ऐसे कुत्तों के स्वामियों के गृहों के अहातों से बाहर भटकते हुए पाए जाते हैं, नष्ट किए जाएं और तदनुसार उन्हें नष्ट कर या नष्ट कर सकती है। ऐसे प्रत्येक आदेश के बारे में सार्वजनिक नोटिस दिया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन नष्ट किए गए या अन्यथा व्ययन किए गए किसी कुत्ते या अन्य जीव-जन्तु के बारे में कोई भी हर्जाना संदेय नहीं होगा ।

113. कोई भी व्यक्ति, जो किसी कुत्ते का स्वामी या भारताधिक है और जो उसे निम्नलिखित दशाओं में इस प्रकार अविरुद्ध करने में उपेक्षा करता है कि वह मुख्य-पट्ट के बिना किसी गली में स्वच्छन्द न घूमे —

(क) यदि ऐसे कुत्ते द्वारा किन्हीं यात्रियों को क्षुब्ध या अभिन्नस्त किए जाने की सम्भावना है, या

(ख) यदि नगरपालिका ने अलर्क रोग फैलने के दौरान सार्वजनिक नोटिस द्वारा निर्दिष्ट किया है कि बिना मुख्य-पट्ट के कुत्ते स्वच्छन्द नहीं किए जाएंगे, जुमाने से दण्डनीय होगा, जो कम से पच्चास रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा ।

114. जो कोई भी किसी हाथी, भालू या ऊँट का प्रभारी होते हुए ऐसा अनुरोध करने पर, अपने हाथी, भालू या ऊँट को बाँडे की पहुँच से, जिस पर नवारी की जा रही हो या जिसे ले जाया जा रहा हो, जहाँ तक व्यवहार्य हो, सुरक्षित दूरी पर नहीं हटाता है, जुमाने से जो दो सौ रुपये तक हो नक़्का, दण्डनीय होगा ।

115. जो कोई भी, नगरपालिका के आदेशों के विरुद्ध, हाथी की मार्ग के साथ-साथ ले जाता है, जुमाने से, जो बीस रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

116. यदि कोई निर्माण, या कोई कूप, तालाब, जलाशय, कुण्ड यत्त या उत्खनन पर्याप्त सुरम्मत, संरक्षण या बाड़े के अभाव में, उसमें या पड़ोस में रहने वाले या कार्य करने वाले व्यक्तियों अथवा वहाँ से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिये संकटपूर्ण हो, तो नगरपालिका नोटिस द्वारा उसके स्वामी या अधिकारी से उसकी सुरम्मत करने, संरक्षण करने या बाड़ा लगाने की अपेक्षा कर सकती है और यदि आसन्न संकट को निवारित करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो तो वह ऐसे संकट के निवारण के लिए तुरन्त ऐसे कदम उठाएगा, जो आवश्यक हों ।

कुत्तों का स्वच्छन्द होना ।

हाथियों, भालू या ऊँटों का नियन्त्रण ।

लोक मार्ग के साथ-साथ हाथी को ले जाना ।

निर्माणों, कूपों, तालाबों आदि को सुरक्षित रखने की अपेक्षा करने की शक्ति ।

निर्माण प्रादि
का संकट-
पूर्ण स्थिति
में होना ।

117. यदि कोई निर्माण, दीवार या संरचना या उनसे जुड़ी हुई कोई वस्तु या कोई बांध अथवा वृक्ष नगरपालिका द्वारा नज़र रियति में या किसी भी प्रकार से संकटपूर्ण स्थिति में नमना जाए या कोई निरा दुष्टा निर्माण या गन्ना या अन्य गामभी पुष्पाग्नक है या किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य के लिए अतिकर है तो वह नोटिस द्वारा उनके स्वामी से उसे हटाने या निर्माण, दीवार, संरचना या बांध में ऐसी मरम्मतें करवाने को अपेक्षा कर सकती है, जो नगरपालिका सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे और यदि आगमन संकट को निवारित करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो तो नगरपालिका स्वामी के धर्ने पर संकट के निवारण के लिए तुरन्त ऐसे कदम उठाएगी, जो आवश्यक हों ।

गन्दे निर्माण
या भूमि
को नफाई ।

118. यदि किसी निर्माण या भूमि का स्वामी, आधिकारिक स्वामी या अधिभागी उसे गन्दी या अस्वास्थ्यकर अवस्था में रहने देता है, तो नगरपालिका नोटिस द्वारा, उससे उसे चौबीस घण्टों के भीतर साफ करने या अन्यथा समुचित प्रवस्था में बनाए रखने और तत्पश्चात् उसे साफ और समुचित अवस्था में बनाए रखने की अपेक्षा कर सकती है और यदि स्वच्छता के प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो तो वह नोटिस द्वारा किसी भी समय किसी निर्माण के अधिभागी को उक्त निर्माण के भीतर और बाहर ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो नोटिस में दी गई हो, नफेदी कराने या अन्यथा साफ करने के लिए निदेश कर सकती है ।

पशु झड़्डों
पर खड़्डा
लगाता या
जल निवास
करता ।

119. नगरपालिका नोटिस द्वारा किसी ऐसी भूमि के स्वामी या अधिभागी से, जिस पर पशु या अन्य जीव-जन्तु प्रायः झूटे पर बांधे जाते हैं, यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उस पर समुचित रूप में खड़्डा लगाए या जल-निकास की व्यवस्था करे या दोनों ही करे ।

अनुपयुक्त
भवनों के
उपयोग को
प्रतिषिद्ध
करने की
शक्ति ।

120. यदि कोई निर्माण या किसी निर्माण का कोई भाग, नगरपालिका को, जल-निकास के समुचित साधन या हवा आने-जाने के साधन के प्रभाव में या किसी पर्याप्त कारण के परिणामस्वरूप मानवीय निवास के लिए अनुपयुक्त प्रतीत हो, तो नगरपालिका नोटिस द्वारा उसके स्वामी या अधिभागी को मानवीय निवास के लिए उसका उपयोग करने से, या उसे इस प्रकार उपयोग करने देने से, तब तक रोक सकती है, जब तक वह ऐसे उपयोग के लिए नगरपालिका के नमाखानप्रद रूप में उपयुक्त नहीं बना दिया गया हो, और कोई भी ऐसा स्वामी या अधिभागी ऐसे निर्माण में तब तक निवास नहीं करेगा या किसी को निवास नहीं करने देगा, जब तक नगरपालिका न स्वामी या अधिभागी को निश्चित रूप में सूचित न कर दिया हो कि प्रतिषेध वापस ले लिया गया है ।

स्वामी से
हानिकर
वनस्पति
नाश करने
की अपेक्षा
करने की
शक्ति ।

121. नगरपालिका नोटिस द्वारा, भूमि के स्वामी या अधिभागी से कोई वनस्पति या झाड़ू-संवाड़ साफ करने तथा हटाने की अपेक्षा कर सकती है, जो नगरपालिका को स्वास्थ्य के लिए अतिकर या गड़बड़ के लिए उद्देजक प्रतीत हो ।

122. नगरपालिका, नोटिस द्वारा किसी भी भूमि के स्वामी या यमिनीको से जम पर उगी और किसी मार्ग से लगी झाड़ियों या उन पर उगे वृक्षों की किसी ऐसी शर्तों को तीन दिन के भीतर काटने या छांटने की अपेक्षा कर सकती है, जो किसी मार्ग पर प्रलम्बी है और उसे बाधा पहुंचाती या संकट हासित करती है, या जो ऐसे किसी कूप, तालाब या अन्य स्त्रोत पर जम में सार्वजनिक उपयोग के लिए जल लिया जाता है, इस प्रकार प्रलम्बी है कि उनसे उनका जल दूषित होने की संभावना है या जो किसी प्रकार स्वास्थ्य के लिए उद्देक या क्षतिकर है।

शायिमी
और वृक्षों
का काटने-
छांटने की
अपेक्षा करने
की शक्ति।

123. नगरपालिका नोटिस द्वारा, ऐसे किसी निर्माण या भूमि के, जो परिस्थान या विवादग्रस्त स्वामित्व के कारण या अन्य हेतु से किराए पर नहीं रही है और निम्नलिखित तथा उच्छुद्धल व्यक्तियों का छड़ड़ा बन गई है अथवा अन्यथा न्यूनतम है स्वामी या प्रांशिक स्वामी या स्वामी अथवा प्रांशिक स्वामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति में, नोटिस में निम्न व्यक्तिगत समान के भीतर, उसे सुरक्षित करने या वाइ युक्त करने की अपेक्षा कर सकती है।

न्यूनतम
बनने वाले
ऐसे निर्माणों
का जो
किराए पर
नहीं रहे
हैं, सुरक्षित
या वाइ-
युक्त करने
की अपेक्षा
करने की
शक्ति।

124. (1) यदि स्वास्थ्य अधिकारी प्रमाणित करता है कि किसी ऐसे स्थान पर किसी प्रकार की फल की खेती या किसी प्रकार की खाद का उपयोग या किसी विनिर्दिष्ट रीति में भूमि की सिंचाई, —

स्वास्थ्य के
लिए क्षति-
कर खेती
का या
खाद के
उपयोग का
या सिंचाई
का प्रतिषेध।

(क) किसी नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर पड़ोश में निवास कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए क्षतिकर है या ऐसी क्रियाओं को मुक्त बनाती है जो क्षतिकर है; या

(ख) किसी नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या बाहर, ऐसे नगरपालिका क्षेत्र के जन प्रदाय को संदूषित करती है या अन्यथा उसे पीने के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त बनाती है;

तो नगरपालिका ऐसी फसल की खेती को, ऐसी खाद के उपयोग को या सिंचाई को ऐसी पद्धति के प्रयोग को, जिसके सम्बन्ध में इस प्रकार क्षतिकर होने की शर्तों की गई है, रोक सकती है, या उनके बारे में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकती है, जिसे ऐसी क्षति या संदूषण निवारित किया जा सके :

परन्तु यदि राज्य सरकार द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि ऐसी फसल की खेती, ऐसी खाद का उपयोग या सिंचाई को ऐसी पद्धति का प्रयोग प्रतिषिद्ध है या उनके सम्बन्ध में शर्तें अधिरोपित हैं, तो नगरपालिका के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उनसे ऐसा प्रतिषेध लगाया है, या ऐसी शर्तें लगाई हैं, और वह अधिसूचना के अनुसार नोटिस जारी करेगी :

परन्तु यह और कि जब किसी भूमि पर, जिसे ऐसा प्रतिषेध लागू होता है, प्रतिषिद्ध कार्य खेती के सामान्य अनुक्रम में प्रतिषेध में नूतन पूर्व पांच वर्षों के दौरान किया जाना

रहा है, तो उमरें हितवद् सभी व्यक्तियों को, जैसे प्रतिपेक्ष के प्रभाव के कारण हुए किसी नुकसान के निष्प्रतिकर नगरपालिका निधि में से दिया जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन जारी किए गए प्रतिपेक्षात्मक नोटिस की तारीख के छः मास के भीतर उमका अनुपालन करने में असफल रहता है, तो वह जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो दस रुपये होगा।

उद्देजक तथा
संकटपूर्ण
व्यापार
विनियम।

125. (1) किसी नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान का उपयोग, स्वामी या अधिभागी द्वारा नगरपालिका से प्राप्त तथा वर्षानुवर्ष नवीकरणीय अनुज्ञप्ति के अधीन के निवाय, निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी के लिए नहीं किया जाएगा—

- (क) चर्बों पिघलाना, कच्चा चमड़ा साफ करना, हड्डियां, मांसावशिश्ट या रक्त उबालना;
- (ख) साबुन के कारखाने, तेल उबालने के कारखाने, रंगरेजी के कारखाने या चर्मशोधन के कारखाने;
- (ग) ईंटों के क्षेत्र, ईंटों के भट्ठे, लकड़ी के कोयले के भट्ठे, मिट्टी के बर्तनों के कारखाने या चूने के भट्ठे;
- (घ) कोई अन्य विनिर्माणशाला, इजन गृह भंडार या कारखाने स्थान, जिससे उद्देजक या अस्वास्थ्यकर गंध, गैसों, आवाजें या धुआं निकलता है;
- (ङ) अनुज्ञा चूना, सूखी घान, भूसी, छप्पर ढालने की घास, लकड़ी, काठ-कोयला या कोयला या खतरनाक रूप से मुदाह्य अन्य सामग्री में व्यापार करने के लिए याई या प्रागार;
- (च) किसी विस्फोटक के लिए या पेट्रोल या किसी मुदाह्य तेल या स्पिरिट के लिए भंडार।

(2) अनुज्ञप्ति देने से इन्कार तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक नगरपालिका का यह विचार नहीं है कि वह कारखाने, जिसे स्थापित करना या बनाए रखना आशयित है, वहां निवास करने वाले या निकटतम पड़ोस में आने-जाने वाले व्यक्तियों के साथ, उद्देग या संकट का हेतुक होगा अथवा किस क्षेत्र को, सामान्य कारणों के लिए, ऐसे कारखाने की स्थापना से बचा रखना चाहिए।

(3) नगरपालिका, उपायुक्त द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले माप-भान के अनुसार ऐसी अनुज्ञप्तियों के लिए कोई फीस प्रभारित कर सकती है और उनके बारे में ऐसी शर्त अधिरोपित कर सकती है, जो वह आवश्यक समझे। अन्य शर्तों के साथ-साथ वह यह भी विहित कर सकती है कि ऐसे व्यापार से सम्बद्ध कोई भट्टी, यथासाध्य अपना धुआं स्वयं ही खपा लेगी।

(4) कोई भी व्यक्ति, जो अनुज्ञप्ति के बिना, किसी स्थान का उपयोग, किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जो इस धारा में विनिर्दिष्ट है या किसी ऐसी अनुज्ञप्ति की शर्त का

उल्लंघन करते हुए करता है, जुमाने में दण्डनीय होगा जो कम से कम पच्चास रुपये और अधिक से अधिक दंड मौजूद होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध चालू रहता है, दंड रुपये के अतिरिक्त जुमाने में दण्डनीय होगा।

126. (1) किसी नगरपालिका क्षेत्र के भीतर, कोई भी व्यक्ति नगरपालिका को सम्मति प्राप्त किये बिना किसी नए कारखाने या कर्मशाला की स्थापना नहीं करेगा।

नए कार-
खाने या
कर्मशाला
स्थापित
करने के
लिए नगर-
पालिका को
सम्मति।

(2) नगरपालिका को सम्मति बिना शर्त के या दण्ड शर्त के अधिधीन दी जा सकती है कि उनके कारखाने का स्वामी या उपयोगकर्ता कारखाने में नियोजित श्रमिकों या ऐसे श्रमिकों के किसी अनुपात या वर्ग के लिए पर्याप्त आवास-स्थान की व्यवस्था करेगा।

परन्तु नगरपालिका को सम्मति, ऐसे स्वामी या उपयोगकर्ता के ऐसी शर्त का अनुपालन करने में इनकार करने के विचारों किसी कारण से नहीं जाएगी।

परन्तु यह और कि यदि नगरपालिका आवेदन की तारीख से दंड माम को अवधि के भीतर अपनी सम्मति देने में उपेक्षा या लापरवाही करती है, तो ऐसी सम्मति बिना शर्त के दी गई समझी जाएगी।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के उपबन्धों को भंग करता है, दण्डविधि पर जुमाने में दण्डनीय होगा जो कम से कम एक सौ रुपये और अधिक से अधिक एक हजार रुपये होगा और यदि भंग चालू रहने वाला हो तो अतिरिक्त जुमाने में दण्डनीय होगा, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान प्रथम भंग के पश्चात् भंग चालू रहता है, एक सौ रुपये होगा।

127. (1) किसी निमैमेटोफाफ अथवा अन्य समकक्ष नाशिव के माध्यम से चिन्तों या अन्य दृश्यों का कोई भी प्रदर्शन, जिसके प्रयोग के लिए, उल्लंघनशील किस्मों प्रयोग में लाई जाती है, और कोई भी नावर्जनिक नाट्य अथवा मर्कम अभिनय या मूक-भिनय किसी नगरपालिका-क्षेत्र में ऐसे परिचरों में निमैमेटोफाफ में नहीं किया जाएगा, जिसके लिए नगरपालिका द्वारा इन धारा के अधीन कोई अनुज्ञप्ति दी गई है।

अनुज्ञप्ति
परिचरों में
निमैमेटोफाफ
नाशिव और
अभिनयों पर
प्रतिषेध।

(2) यदि इस धारा के उपबन्धों के, या इस धारा के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त के उल्लंघन में किसी निमैमेटोफाफ या अन्य नाशिव का स्वामी ऐसे उपकरण का उपयोग करता है या उनका उपयोग अनुज्ञात करता है, अथवा कोई व्यक्ति किसी नावर्जनिक नाट्य या मर्कम अभिनय या मूकभिनय में भाग लेता है, या किन्हीं परिचरों का अधिभाग्य उन परिचरों का उपयोग अनुज्ञात करता है, तो वह जुमाने का दायी होगा, जो कम से कम पच्चास रुपये और अधिक दंड भी रुपये होगा और चालू रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, पचास रुपये हो सकती है और अनुज्ञप्ति, यदि कोई हो, नगरपालिका द्वारा प्रतिसहृत की जा सकती है।

128. (1) जब कभी ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन पंजीकृत या अनुज्ञप्त कोई स्थान पहचान के लिए कोई न्यून है या उसका जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए संकटपूर्ण होता संभाव्य है, तो नगरपालिका उनके अधिभाग्य में ऐसे स्थान का उपयोग बन्द करने या उनमें ऐसे परिवर्तन, परिवर्तन या गुंथार करने की अपेक्षा कर सकती है, और यदि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार अपेक्षित हो तो ऐसा करेगी, जिससे नगरपालिका की राय में वह न्यूनता या संकटपूर्ण न रहे जाए।

आपारा की
प्रतिषेध
करने की
क्षमता।

(2) जो कोई भी व्यक्ति, इस धारा के अधीन किए गए किसी निर्माण के परमाणु ऐसी किसी रीति में ऐसे स्थान का उपयोग करता है या उसका उपयोग अनुज्ञात करता है जिसमें ऐसा करना पड़ोसी के लिए स्वस्थ या गंदापूर्ण बन जाता है या ऐसे परिवर्तन, परिवर्धन या सुधार नहीं करता है, जुमाने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पचास रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, पचास रुपये के प्रतिदिन जुमाने से दण्डनीय होगा।

वाण-चालित
रीटियों
हत्यादि का
प्रयोग।

129. (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी कारखाने या अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार की सीटी या तुरही या ऐसी किसी अन्य यांत्रिक प्रयुक्ति, जो अशुभकर और उत्तेजित करने वाली है, का प्रयोग, कर्मचारियों या नियोजित व्यक्तियों को बुलाने या विमर्जन करने के प्रयोजन के लिए नहीं करेगा, न ही कोई व्यक्ति किसी प्रयुक्ति द्वारा ऐसे किसी कारखाने या स्थान पर उत्तेजित और का, मिकासी पाईप या हजन द्वारा, नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना नहीं बढ़ाएगा, ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने समर्थ नगरपालिका ऐसी सीटी या तुरही या अन्य प्रयुक्ति के प्रयोग के समर्थ को निर्दिष्ट करने हुए, ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जैसी वह उचित समझे।

(2) नगरपालिका उप-धारा (1) के अधीन दी गई किसी भी अनुज्ञा का एक भाग का नोटिस देकर प्रसिद्ध कर सकती है।

(3) जो कोई इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किसी भी प्रकार की सीटी, तुरही या प्रयुक्ति का प्रयोग या निर्वाहन करता है, ऐसे जुमाने से दण्डनीय होगा जो पचास रुपये तक का हो सकेगा और प्रतिदिन जुमाने में जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पांच रुपये तक का हो सकेगा।

नालियों,
शौचगर्तों
आदि की
व्यवस्था
करना।

130. (1) नगरपालिका, नोटिस द्वारा, किसी निर्माण या भूमि के स्वामी से अपेक्षा कर सकती है कि वह किसी नाली, शौचगर्त, शौचालय, मूत्रालय, मलकुण्ड या गन्दगी भरा कड़ा-कंकट के अन्य आधान की व्यवस्था करे, उसका स्थान परिवर्तन करे या उसे हटा दे अथवा किसी प्रतिरिक्त नाली, शौचगर्त, शौचालय, मूत्रालय या मलकुण्ड अथवा यथार्थतः अन्य आधान की व्यवस्था करे, जिसकी व्यवस्था नगरपालिका की राय में निर्माण या भूमि के लिए, ऐसी रीति में ऐसे प्रकार की होनी चाहिए, जो वह निर्दिष्ट करे।

(2) नगरपालिका, नोटिस द्वारा, ग्राम से अधिक कर्मचारियों या श्रमिकों का नियोजन करने वाले व्यक्ति से ऐसे शौचालयों और मूत्रालयों की, जो नगरपालिका उचित समझे व्यवस्था करने की और उन्हें समुचित अवस्था में रखवाने की तथा प्रतिदिन साफ करने की अपेक्षा कर सकती है।

(3) नगरपालिका, नोटिस द्वारा, किसी निर्माण या भूमि के स्वामी या अधिभोगी से अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे निर्माण या भूमि के लिए बनाए गए शौचगर्त, शौचालय या मूत्रालय का पर्याप्त छत तथा दीवार या बाड़ द्वारा इस प्रकार बन्द कर दे कि वह उधर से गुजरने वाले या पड़ोस में निवास करने वाले व्यक्तियों को दिखाई न पड़े अथवा नगरपालिका के निदेशानुसार किसी शौचगर्त, शौचालय या मूत्रालय के किसी दरवाजे या फर्श के दरवाजे को, जो किसी गड़क या नाली पर खुलता हो, हटाए या परिवर्तित करे।

(4) नगरपालिका जनता के उपयोग के लिए शौचालयों और मूत्रालयों की व्यवस्था कर सकती है, और यदि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो, तो ऐसी व्यवस्था करेगी।

131. नगरपालिका नोटिस द्वारा, किसी निर्माण के स्वामी या अधिवासी में शीघ्रता कर मानी है कि वह किसी नाली, शीचन, शीचन, मूलानय, मूलकुण्ड या गन्दगी अथवा कूड़ा-कंकट के आधान की सम्मति करे, उसे परिवर्तित करे या सुव्यवस्थित रखे अथवा उम्मीद सम्मति किसी नाली, शीचन, शीचन, मूलानय या मूलकुण्ड को बन्द करे ।

नालियों, शीचनों की शक्ति की सम्मति और उनका बन्द किया जाना ।

(2) नगरपालिका, नोटिस द्वारा, ऐसे व्यक्ति में, जिसने उनकी लिखित अनुज्ञा के बिना या उसके निर्देशों के या नियमों में अथवा इन शर्तियों के उपबन्धों के प्रतिकूल कोई नई नाली, शीचन, शीचन, मूलानय, मूलकुण्ड अथवा गन्दगी या कूड़ा-कंकट के आधान का सम्मति कर लिया है अथवा जिसने किसी ऐसी नाली, शीचन, शीचन, मूलानय, मूलकुण्ड अथवा गन्दगी या कूड़ा-कंकट के आधान का सम्मति कर लिया है, पुनर्निर्माण कर दिया है या उसे खोल दिया है, जिसके अन्तिम किण्व जान या रोक जाने अथवा न बचाव जाने का उसे आदेश दिया है, अपेक्षा कर सकती है कि वह उस नाली, शीचन, शीचन, मूलानय, मूलकुण्ड या आधान का नाट व अथवा उसे ऐसे परिवर्तित करे, जिसे नगरपालिका उचित समझे ।

132. नगरपालिका, नोटिस द्वारा किसी भी व्यक्ति में, जो उसकी लिखित अनुज्ञा के बिना नगरपालिका क्षेत्र में निर्माण किया मूल-नाली, नाली, नाली, नाली या नाली की शक्ति पर किसी अथवा नाली में निर्माण या पुनर्निर्माण करे, उसे निर्माण की अपेक्षा कर सकती है अथवा ऐसी कार्रवाई कर सकती है जो वह उचित समझे ।

नालियों द्वारा निर्माण ।

133. (1) नगरपालिका, नोटिस द्वारा, किसी स्वामी या अधिवासी में, जिसकी भूमि पर कोई नाली, शीचन, शीचन, मूलानय, मूलकुण्ड अथवा गन्दगी या कूड़ा-कंकट का कोई अन्य आधान सम्मति किसी ऐसे व्यक्ति, कृषि, मालान, जलानय या अन्य क्षेत्र के पचास फुट के भीतर स्थित है, जहाँ में मार्बलित उपयोग के लिए जल प्राप्त किया जाता है या प्राप्त किया जा सकता है, अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे नोटिस की तारीख में एक सप्ताह के भीतर उसे हटा दे या बन्द कर दे ।

जल प्रदाय के किसी क्षेत्र के नाट शीचनों, शक्ति का हटाया जाना ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना, इन धारा के अधिनो नोटिस के पञ्चास फुट याता में दीयेर सम के लिए कोई नाली, शीचन, शीचन, मूलानय, मूलकुण्ड अथवा गन्दगी या कूड़ा-कंकट का कोई अन्य आधान, किसी ऐसे व्यक्ति, कृषि, मालान, जलानय या अन्य क्षेत्र के पचास फुट के भीतर बनाता है या रखता है, जहाँ में मार्बलित उपयोग के लिए जल प्राप्त किया जाता है या प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ में दीयेर सम के पञ्चास फुट के भीतर अपेक्षा कर सकता है, अपेक्षा कर सकता है कि वह नोटिस जारी किया जाने पर हटाया जावे कि वह अनुज्ञा अथवा की सम्मति के पञ्चास फुट के सम के पञ्चास फुट के भीतर अपेक्षा कर सकता है, अपेक्षा कर सकता है कि वह नोटिस जारी किया जाने पर हटाया जावे ।

134. कोई भी व्यक्ति, जो नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना किसी कुण्ड, मूल-प्रणाल या मूलकुण्ड की अनुज्ञाओं का या किसी अन्य उद्देश्य पदार्थ का, किसी मार्ग पर या मार्बलित स्थान में या किसी लिफ्ट शक्ति या किसी ऐसे मूल-प्रणाल या नाली में, जो इन प्रणाल के लिए अलग भरी बर्तन है, निर्यात, अपेक्षा या छोड़ा जाना अनिवार्य है या जान बूझकर या उद्देश्य ऐसा हानि देता है, जहाँ में दीयेर सम होगा, जो कम से कम पञ्चीय रूप में अधिक से अधिक दो सौ रूप्य होगा ।

मूल जल का नि-करण ।

प्राधिकार को
बिना नालियों
बनाना या
उनमें परि-
वर्तन करना।

135. कोई भी व्यक्ति, जो नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना नगरपालिकामें मिट्टिन
जिन्हें मल-प्रणाली या नल-निकास नालियों में मिलने वाली कोई नाली बनाया या बनवाता
है, अथवा उसमें परिवर्तन करता है, या करवाता है, जमीन से दण्डनीय होगा, जो कम
से कम पञ्चीम रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

तालाबों
नया तत्प-
दण जला-
णों आदि
से होने वाले
नूनेन दूर
करने की
अपेक्षा करने
की शक्ति।

136. नगरपालिका, नोटिन द्वारा, किसी भूमि या निर्माण को स्वामी या अधिभागी
में अपेक्षा कर सकती है कि वह उसमें ऐसे किसी निजी कुएँ, तालाब, जलाशय, पांखर,
गत अथवा उखनन की सफाई या मरम्मत करे, उसे ढके, भर दे या खाली कर दे, जो
नगरपालिका को स्वास्थ्य के लिए अतिकार या पड़ोस के लिए उद्देजक प्रतीत हो।

परन्तु यदि इन धारा के प्रवीन किसी नल-निकास को नष्ट करने के प्रयोजन के
लिए, किसी ऐसी भूमि को अर्जिन करना, जो उसी स्वामी की न हो, या किसी व्यक्ति
को अधिकार संदेत करना आवश्यक हो, तो नगरपालिका ऐसी भूमि की व्यवस्था करेगी
अथवा ऐसा अधिकार देगी।

प्राइवेट भूमि
ने होकर
तार, नालियाँ,
नालियों या
मल-प्रणाल
बिछाने या
ले जाने की
नगरपालिका
की शक्ति।

137. नगरपालिका, स्वामी या अधिभागी को युक्तियुक्त लिखित नोटिन देने के
पश्चात्, किसी भूदृक, मार्ग या ऐसे स्थान के, जो किसी मार्ग या भूदृक के रूप में
बनाया गया है या बनाना जाना अभ्यर्थित है, वॉल ने होकर या र-पार, नीचे
या ऊपर नगरपालिका-क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी भूमि या निर्माण में,
जो भी हो, बीच में होकर या पार-पार, उसके नीचे या ऊपर अथवा पास में दूरभाषिक
संचार या अन्य तत्पदण संचार स्थापित करने या प्रकाश, नल-निकास या मल-प्रणाल
की किसी पद्धति की व्यवस्था कार्यान्वित करने, स्थापित करने या बनाए रखने के
प्रयोजन के लिए, और ऐसी सीमाओं के बाहर पानी के गिरने या वितरण के प्रयोजन
के लिए या मल-जल के गिरने या हटाए जाने के लिए, कोई केबिल, तार, नली, नाली,
मल-प्रणाल या किसी प्रकार की मरणी नगरपालिका ले जा सकती है, और सभी समयों
पर ऐसे सभी कार्य कर सकती है, जो, यथास्थिति, ऐसी किसी केबिल, तार, नली,
नाली, मल-प्रणाल या मरणी की मरम्मत के लिए या उसे उन प्रयोजन के लिए,
जिनके लिए उसका उपयोग लिया जा सकता है या किया जाना आशयित है, कारण
हालत में बनाए रखने के लिए आवश्यक या नवीचीन हो।

परन्तु ऐसा कार्य इन प्रकार किया जाएगा जिससे किसी व्यक्ति का कम से कम
वास्तविक नूनेन या अनुविधा हो।

परन्तु यह और कि किसी स्वामी या अधिभागी को उन समय हुए ऐसे नुकसान के
लिए, जो किन्हीं ऐसे कार्यों को करने के कारण उसे प्रत्यक्षतः हुआ हो, युक्तियुक्त
प्रतिकर दिया जाएगा।

भूमि तल
के ऊपर
बिछाई या
ले जाई गई
मार्ग, नलियों,
नालियों या
मल-प्रणालों
के बारे में
उपबंध।

138. किसी भूमि तल के ऊपर या किसी निर्माण के पास से होकर या उन पर
बिछाई जाने वाली या ले जाई जाने वाली किसी केबिल, तार, नली, नाली, मल-प्रणाल
या मरणी की दशा में, यथास्थिति, ऐसी केबिल, तार, नली, नाली, मल-प्रणाल या
मरणी इन प्रकार बिछाई या ले जाई जाएगी कि ऐसी भूमि या निर्माण के सम्पर्क
उपयोग में स्वामी या अधिभागी के अधिकारों में यथासम्भव कम से कम बाधा हो
और ऐसे उपयोग के किसी ऐसे अधिकार में किसी नगरपूत बाधा के बारे में युक्तियुक्त
प्रतिकर दिया जाएगा।

139. ऐसे मामलों के विवाय, जिनमें धारा 222 और 224 सम्बन्धित हैं, नगरपालिका धारा 137 के अर्थात् निम्नलिखित मामलों को प्रारम्भ करने में पूर्व, स्वामी या अधिभागी को कम से कम चौदह दिन का लिखित नोटिस दिलाया जायेगा।

पूर्व नोटिस

140. (1) नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी प्रयोजन के लिए, चाहे वह जो भी हो, नगरपालिका द्वारा गन्निष्ठ या अनुरक्षित या उसमें निहित किसी कोबल, तार, नली, जोड़बूझ, नाली, मल-प्रणाल या मरणी के साथ कोई सम्बन्धन या संचार नहीं करेगा या करवाएगा।

नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना मुख्य नल के साथ

(2) उप-धारा (1) के निवर्तनों के उत्प्रेषण में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति जमाने में दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

सम्बन्धन का न किया जाता।

141. नगरपालिका, किसी भी समय, किसी मुख्य नल, नाली या मल-प्रणाल में किसी परिसर का कोई सम्बन्धन या संचार स्थापित कर सकती है, अथवा नोटिस द्वारा ऐसे किसी परिसर के स्वामी से ऐसी रीति में, या ऐसे समय के भीतर, जो नगरपालिका नोटिस द्वारा इस निमित्त विहित करे, उस स्वामी या अधिभागी के खर्च पर, ऐसा कोई सम्बन्धन या संचार स्थापित करने की अपेक्षा कर सकेगी।

मल-प्रणाल सम्बन्धन।

142. (1) नगरपालिका, नोटिस द्वारा, किसी मामले पर स्थित किसी निर्माण या भूमि के स्वामी से अपेक्षा कर सकेगी कि निर्माण या भूमि में जल और कूड़ा-कंकड़ आने देने, आगे ले जाने और उसे बाहर निकालने के लिए समुचित चुक्के तथा नालियाँ लगाए और उन्हें अच्छी दशा में रखे, जिनमें मार्ग में गुजरने वाले व्यक्तियों को असुविधा न हो।

वर्षा जल के लिए चुक्के तथा नालियाँ

(2) नगरपालिका किसी निर्माण या भूमि में भली-भाँति जल निचाम के प्रयोजन के लिए लिखित नोटिस द्वारा,—

(क) वॉ या अधिक निर्माणों के बीच किसी आंगन, गली, या रास्ते में उन निर्माणों के स्वामी या आंशिक स्वामी से ऐसी मामूली से और ऐसी रीति में जो नगरपालिका द्वारा अनुमोदित की जाए, खड्डा लगाने का अपेक्षा कर सकती है;

(ख) ऐसे खड्डे के बारे में अपेक्षा कर सकती है कि उसकी सचिव मरम्मत की जाती रहे।

143. कोई भी व्यक्ति, जो—

हेजा, चेचक आदि की सूचना देना।

(क) चिकित्सा व्यवसायी है या खुले आम और निरन्तर चिकित्सा व्यवसाय करता है और जिसे ऐसे व्यवसाय के अनुक्रम में सार्वजनिक चिकित्सालय में भिन्न किसी आवास में किसी संक्रामक रोग के विद्यमान होने का संज्ञान है; या

(ख) ऐसे आवास का स्वामी या अधिभागी है, और उस ऐंसे रोग के विद्यमान होने का संज्ञान है; या

(ग) ऐसे आवास में ऐंसे किसी रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति का आरसाधक है या उसकी सेवा में उपस्थित रहने वाला व्यक्ति है और उसे उसमें रोग के विद्यमान होने का संज्ञान है;

स्वास्थ्य अधिकारों को या किसी अन्य अधिकारों को, जिन नगरपालिका ऐसे रोग के नियंत्रण होने के बारे में सूचना दी जानी थी, धिक्कृत करने में प्रभावित रहता है, या जानबूझकर भ्रष्टाचार सूचना देता है, जर्मनी में दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा ।

सक्रामक रोगों में प्रत्येक

राज्यों को चिकित्सालय में ले आया जाना ।

144. (1) किसी नगरपालिका-क्षेत्र में, जिनको यह धारा राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय विस्तारित की गई हो, जब किसी सक्रामक रोग से प्रत्येक कोई व्यक्ति—

- (क) उचित संज्ञासमूह या वाहन-सुविधा के बिना पाया जाता है ; या
- (ख) किसी नराय, होटल, आश्रम, आवास या अन्य सार्वजनिक आवास में निवास करता हुआ पाया जाता है ; या
- (ग) किसी कमरे या गृह में निवास करता हुआ पाया जाता है, जिसका न तो वह स्वामी है और न ही उसके लिए यह निर्धारित होता है, और न ही किसी ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिधि या मालिक के रूप में अधिभोग कर रहा है, जो उसका स्वामी है या उसके लिए किया जाता है ; या
- (घ) दो या अधिक कुटुम्बों के सदस्यों द्वारा अधिभूत परिवार में संवास करता हुआ पाया जाता है ; और ऐसे अधिभोगियों में से कोई ऐसे परिवार में उसके संवास करते रहने पर आरोप करता है ;

तो नगरपालिका, या उनके द्वारा इन निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, महापौर शल्यचिकित्सक से प्रतिष्ठित पदों के किसी चिकित्सक अधिकांशों को नगरपालिका पर रोगी को किसी ऐसे चिकित्सालय या स्थान को ले जा सकता है जहां ऐसे रोग से प्रत्येक व्यक्तियों को चिकित्सकीय उपचार के लिए प्रवेश दिया जाता है, और इस प्रकार हटाने के लिए आवश्यक कोई कार्य कर सकता है ।

(2) नगरपालिका, यदि राज्य सरकार द्वारा अधिभोगित हो तो ऐसे आगर-प्रकार का, जैसा सरकार समोचीन समझे, सक्रामक रोग चिकित्सालय परिनिमित्त करेगी ।

निर्माणों और वस्तुओं का रोगाणुनाश ।

145. यदि नगरपालिका को पता है कि किसी निर्माण या उसके किसी भाग की, या उसके भीतर की किसी वस्तु की, निर्माण रोगाणु लगे रहना संभावित है, यहाँ ऐसे करने या रोगाणुनाशन करने से किसी रोग का या उसके फैलने का निवारण होगा, तो वह नोटिस द्वारा स्वामी या अधिभोगी से ऐसे नोटिस में विहित रीति और समय के भीतर उसे साफ करने या उसका रोगाणुनाशन करने की या ऐसी वस्तु नष्ट करने की अपेक्षा कर सकती है ।

रोगाणु-युक्त गृह किराए पर देने के लिए शक्ति ।

146. प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई गिरा गृह या अन्य निर्माण या ऐसे गृह या निर्माण का कोई भाग, जिसमें कोई व्यक्ति किसी सक्रामक रोग से प्रभावित रहा है, किसी ऐसे गृह या अन्य निर्माण या उसके भाग और उसमें की सभी वस्तुओं को, जिनमें रोगाणु रहना संभावित है, नगरपालिका से नगराधानपद रूप में रोगाणुनाशन करवाए बिना, किराए पर देता है, शक्ति का दावा होगा जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगी ।

राष्ट्रीयकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी होटल या आवास गृह के मालिक के सम्पत्ति में वह समझा जाएगा कि अपने अपने होटल या आवासगृह में प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपने गृह का भाग किराए पर दिया है ।

147. नगरपालिका. —

रोगाणुनाश
के लिए
स्थानों और
उपकरणों
की व्यवस्था।

- (क) सभी भवारियों, बस्तों, बिस्तरों या अन्य वस्तुओं के, जो संक्रमण के लिए उच्चतम रही हैं, रोगाणुनाश के लिए सभी आवश्यक परिचारकों और साधनों सहित उचित स्थानों की व्यवस्था कर सकती है, और जब राज्य सरकार ऐसे निर्दिष्ट करे तो ऐसी व्यवस्था करेगी ;
- (ख) रोगाणुनाश के लिए लाई गई भवारियों, बस्तों या अन्य वस्तुओं का निष्प्रभार, या ऐसे प्रभारों के अधीन, जो उनके द्वारा अनुमोदित हैं, रोगाणुनाश करा सकती है और यदि राज्य सरकार ऐसा निर्दिष्ट करे, तो ऐसा कराएगी ;
- (ग) किसी ऐसे बस्तों, बिस्तरों या अन्य वस्तुओं के, जिसका रोगाणुनाश होना संभाव्य है, रोगाणुनाश या नष्ट किए जाने के लिए निर्देश कर सकती है और इस उप-धारा के अधीन नष्ट की गई किसी वस्तुओं के लिए प्रतिकर मंजूर करने के लिए निर्देश कर सकती है और यदि राज्य सरकार ऐसा निर्दिष्ट करे, तो ऐसा निर्देश करेगी ।

148. कोई भी व्यक्ति, जो किसी संक्रमण, संसर्गित या घृणित रोग में रूचि होते हुए, —

कतिपय रोगों
से ग्रस्त
व्यक्तियों
द्वारा किए
गए कार्य ।

- (क) मानवीय उद्देशों के लिए खाने या पीने की कोई वस्तु या कोई औषधि या औषधि बनाना है या विक्रय के लिए प्रस्थापित करता है ; या
- (ख) अन्य द्वारा विक्रय के लिए रखी ऐसी किसी वस्तु, औषधि या औषधि को छूता है ; या
- (ग) मैन वस्त्र धोने या बहन करने के कारखाने में कोई भाग लेता है ;

जुमनि से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा ।

149. कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसे प्रादेशों की प्रबन्धना में, जो नगरपालिका में मुख्यतः और अन्य जीव जन्तुओं को मृत्यु-जन जाने में, या निवारणियों या जीव-जन्तुओं के स्वास्थ्य के लिए क्षतिकर होने से निवारित करने के लिए किए हों, कोई मुख्य या अन्य जीवजन्तु रखता है, पचास रुपये के और पञ्चाश्वर्ग प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए एक सौ रुपये के जुमनि से दण्डनीय होगा ।

जीवजन्तुओं
का ऐसे
रखा जाना
कि वे
स्वास्थ्य
के लिए
क्षतिकर हों ।

150. जो कोई भी, किसी ऐसे पशु की, जिस दुग्ध उपयोग के प्रयोजन के लिए रखा गया है या जिसका उपयोग आहार के लिए किया जा सकता है, शानिकारक पदार्थ, गन्धी या किसी भी प्रकार का कच्चा शिवाज है या शिवाने की अनुमति देता है, वे जुमनि से दण्डनीय होगा, जो पचास रुपये तक का हो सकेगा ।

पशुओं की
क्षतिकारक
पदार्थ
शिवाना ।

स्वास्थ्य
पर जल का
उपयोग का
नगरपालिका
द्वारा निषेध।

151. यदि स्वास्थ्य अधिकारी की रिपोर्ट पर नगरपालिका गमसती है कि किसी कुएं, तालाब या अन्य स्थान में जल, यदि उसका उपयोग पीने के लिए किया जाता है, कोई भयानक रोग उत्पन्न कर या फैला सकता है, तो वह—

(क) नॉर्वेजिक नोटिस द्वारा, पीने के लिए ऐसे जल का ले जाया जाना या उसका उपयोग निषिद्ध कर सकती है;

(ख) नोटिस द्वारा ऐसे कुएं, तालाब या स्थान के स्वामी या उसका नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति से सर्वसाधारण द्वारा ऐसे जल तक पहुंच रखी जाने की या उसका उपयोग किए जाने को या उसका उपयोग किए जाने को निवारित करने के लिए ऐसे कदम उठाने की अपेक्षा कर सकती है, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किए जाएं; या

(ग) ऐसे कदम उठा सकती है जो वह, स्वास्थ्य अधिकारी की राय पर, किसी ऐसे रोग के खतरे या फैलने को निवारित करने के लिए समीचीन गमसे।

अवमानक
खाद्य पदार्थ
और पेय के
विक्रय को
लिए शक्ति।

152. (1) जो कोई भी, किसी क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी खाद्य या पेय की वस्तु को बेचना है, जो क्रेता द्वारा मंगी गई वस्तु की प्रकृति, तत्व या क्वालिटी की नहीं है, जमाने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

परन्तु निम्नलिखित दशाओं में अपराध, इन धारा के अधीन किया गया नहीं समझा जाएगा, अर्थात् :—

(क) जहां कोई पदार्थ या संघटक जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो, खाद्य या पेय में उसके उत्पादन या तैयार करने, वाणिज्यिक तौर पर उसे बहान करने या उसे उपयोग के लिए ठीक रखने के लिए मिलाया गया हो और उसे परिमाण, भार या मात्रा को बढ़ाने के लिए या घटिया क्वालिटी को छिपाने के लिए कपटपूर्वक न मिलाया गया हो;

(ख) जहां खाद्य या पेय में, एंटीकरण या तैयार करने की प्रक्रिया में कोई बाह्य पदार्थ अपरिहार्य तौर पर मिलाया गया हो।

(2) इस धारा के अधीन किसी भी अभियोजन में, यह अधिव्यक्त करना निवृत्तता, उम्र द्वारा विक्रय की गई वस्तु की प्रकृति, तत्व या क्वालिटी से अनभिज्ञ था या क्रेता ने ऐसी वस्तु केवल विश्लेषण के लिए लाई है जिससे विक्रय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रतिरक्षा नहीं होगी।

(3) इस धारा के उपबंध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अनिवार्यतः कि उसके अन्वय में होगा।

(1979 का 22) 153. (1) जो कोई भी नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी गवा या नदीजनित स्थान में दुराग्रह से गोबर मांगता है, या दान देने के लिए उसका ले के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या गोमारी या किसी पशुपालक को गोबर या गोबर को अर्पित करता है या प्रदर्शन करता है, वह हिमाचल प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1979 के उपबन्धों के अर्थात् दण्डनीय होगा। गोबर को याचना करना।

154. नगरपालिका कूड़ा-कचरा, काठ-कबाड़ या किसी प्रकार के उद्देजक पदार्थ जमा करने या जीव-जन्तुओं के शवों के व्यसन के लिए नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या उपायुक्त के अनुमोदन में उनके बाहर, स्थान नियत कर सकता है और, सार्वजनिक नोटिस द्वारा समय, राति, और शर्तों के सम्बन्ध में निदेश दे सकती है जिस पर, जिसमें और जिनके अधीन, ऐसा कूड़ा-कचरा, काठ-कबाड़ या उद्देजक पदार्थ या जीव-जन्तुओं के शव किसी मार्ग की वगल में डटाने जा सकते हैं और ऐसे स्थानों पर जमा किया जा सकते हैं। उद्देजक वस्तुएं हटाना और जमा करना।

155. जहाँ राज्य सरकार ऐसा अपेक्षा करती है, नगरपालिका का यह कर्तव्य होगा कि वह सम्पूर्ण गोबर को स्मॉलस्ट खाद बनाए। कम्पास्ट खाद तैयार करना।

156. (1) जहाँ किसी गोबर में सम्पत्ति नगरपालिका से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग में निहित है, वह ऐसी नगरपालिका, जिसने अंतिम पूर्ववर्ती धारा के अधीन अपेक्षा की गई है, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर, जो वह व्यक्तिगत समझे, गोबर में पूर्वोक्त व्यक्तियों के अधिकार या हित, चाहे स्थायी रूप से या किसी अवधि के लिए, जिनकी वह उचित समझे, अजित करेगी और एतत्परचात् उपर्युक्त रीति में प्रतिकर निर्धारित कर सकती है। अर्जन याद करने की शक्ति।

(2) जहाँ ऐसा कोई गोबर इस धारा के अधीन अधिगृहीत या अजित किया जाता है, वहाँ संदेय प्रतिकर की राशि नीचे प्रमाणित रीति में नवा निदाओं के अनुसार अवधानित की जाएगी :—

(क) जहाँ प्रतिकर की राशि करार द्वारा नियत की जा सकती है, वहाँ वह ऐसे करार के अनुसार दी जाएगी ;

(ख) जहाँ ऐसा कोई करार नहीं किया जा सकता, वहाँ नगरपालिका और यथापूर्वोक्त एक या एकाधिक व्यक्ति कोई ऐसा मध्यस्थ नियुक्त करेंगे, जिसे अधिगृहीत या अजित गोबर में सम्पत्ति या हित की कीमत का ज्ञान हो ;

(ग) मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों के प्रारम्भ पर, नगरपालिका और व्यक्ति, जिसे प्रतिकर दिया जाना है, कथित करेंगे कि उनकी अपनी-अपनी राय में प्रतिकर की उचित राशि क्या है ;

(घ) मध्यस्थ; पंचाट तैयार करने में परिक्षेप में गोधर के बाजाप-मूख को, उक्त व्यक्ति को या व्यक्तियों को होने वाले लाभों में कमी के कारण होने वाले नुकसान को, यदि कोई हो, और इसी प्रकार किसी अन्य बात को, ध्यान में रखेगा ;

(ङ) इस अधिनियम या नियमों में ऐतद्वेषात् अन्यथा उपबन्धित के सिवाए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई भी बात इस धारा के अधीन माग्यस्थम् को लागू नहीं होगी ।

अपील और
पुनरीक्षण का
अधिकार ।

157. (1) धारा 156 के अधीन दिए गए किसी पंचाट द्वारा व्यक्ति-कोई व्यक्ति-उसे पंचाट की समुचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उस जिले के जिनमें नगरपालिका स्थित है, उपायुक्त को निम्नलिखित रूप में अपील प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) उपायुक्त, नगरपालिका से मामले के अभिलेखों को मांगने के पश्चात् और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, और यदि आवश्यक हो, या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी के द्वारा ऐसी प्रतिरिक्त जांच करने के पश्चात्, जो कि वह उचित समझता है, अपील का विनिश्चय करेगा ।

(3) अगर अपील राज्य सरकार को हो सकेगी, परन्तु यदि उपायुक्त द्वारा पंचाट पुष्ट कर दिया जाता है तो ऐसी कोई भी अपील नहीं हो सकेगी ।

(4) राज्य सरकार, किसी भी समय, उपायुक्त के नमूने लम्बित या उसके द्वारा निपटाए गए किसी मामले के अभिलेख को मांगा सकती है :

परन्तु राज्य सरकार द्वारा उस दशा में इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जब उसे उप-धारा (3) के अधीन अपील प्रस्तुत की गई है :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार इस उप-धारा के अधीन किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले किसी आदेश को पुनरीक्षित या उपांतरित करने वाला कोई आदेश ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं करेगी ।

अधिकारिता
का वर्जन ।

158. किसी भी सिविल न्यायालय को धारा 156 या धारा 157 में निर्दिष्ट प्रतिकर के प्रति अधिकार या उसमें हित या राशि-अथवा उसके संदाय, प्रभाजन या तत्संबद्ध किसी विषय के संबंध में किसी बाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही को ग्रहण करने या उस का न्याय निर्णय करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

हानिकर
पदार्थ हटाने
में अग्रगण्यता ।

159. कोई भी व्यक्ति, जो किसी निर्माण या किसी भूमि का स्वामी या अधिभोगी है, धूल, गंधार, हड्डियाँ, राख, विण्डा या गन्दगी या हानिकर या उद्बजक पदार्थ ऐसे निर्माण या भूमि के अन्दर या उसके ऊपर किसी उचित आधान या गड्ढे से भिन्न किसी स्थान पर चौबीस घंटे से अधिक के लिए रखता है या जानबूझकर या उपेक्षापूर्ण रखने देता है या किसी ऐसे आधान या गड्ढे को गन्दी या हानिकर दशा में रहने देता

है या उसे साफ और शुद्ध करने के लिए उचित माधनों का प्रयोग करने में उपेक्षा करता है, जमाने में दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

160. कोई भी व्यक्ति, जो नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना या उसके आदेशों की अवहेलना में, कोई मिट्टी या किसी प्रकार का कोई पदार्थ या कुड़ा-कचरा या काठ-कबाड़ या किसी प्रकार का कोई उद्देजक पदार्थ किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर या किसी सिचाई जल-संरक्षणी, सार्वजनिक मल-प्रणाल या सार्वजनिक नाली में या किसी सिचाई जल-संरक्षणी, सार्वजनिक मल-प्रणाल या सार्वजनिक नाली में मिलान वाली किसी नाली में फेंकता या जमा करता है, या अपने जेबकों को या अपने नियंत्रणाधीन अपने घर के सदस्यों को फेंकने या जमा करने देता है, जमाने में दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

गड़कों पर या नालियों में किसी प्रकार की मिट्टी या सामग्री को जमा करना या फेंकना।

161. कोई भी व्यक्ति, जो नगरपालिका-क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी सार्वजनिक स्थान में, जिस तक डग धारा का प्रवर्तन, राज्य सरकार द्वारा, इस निमित्त किसी अधिसूचना द्वारा किया गया है, नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाई गई नालियों या आधान से मिलन स्थान में धुंकरा है, प्रथम या द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्ध पर, जमाने में दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

बनाई गई नालियों या आधानों में निम्न स्थानों में धुंकरा।

(1860 का 45)

162. कोई भी व्यक्ति, जो अपने नियंत्रणाधीन किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 82, 83 तथा 84 के उपबन्ध लागू होते हैं, किसी मार्ग में या किसी सार्वजनिक मल-प्रणाल या नाली में या उसमें मिलाने वाली किसी नाली में कोई न्युसेन्स धरने देता है, जमाने में दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

बालकों तथा अन्यो द्वारा न्युसेन्स।

163. किसी घर या निर्माण में या उसका संबंधित किसी बाथरूम, रीजलिन, गृहापमार्जन मूलालय, मलकुंड या ऐसे मलपदार्थ के लिए अन्य सामान्य आधान में गन्दगी, कुड़े-कारकट, मल उद्देजक पदार्थ का हटाना गृहापमार्जन कहलाता है।

गृहापमार्जन की परिभाषा।

164. (1) नगरपालिका, किसी भी समय अधिभोगी के आवेदन पर या उसकी समिति में किसी गृह या निर्माण का अपमार्जन अपने हाथ में ले सकती है।

नगरपालिका द्वारा गृहापमार्जन का

(2) नगरपालिका, सार्वजनिक नोटिस द्वारा, नोटिस के जारी होने के कम से कम दो मास बाद की किसी तारीख से नगरपालिका क्षेत्र में निम्नी गृहों या निर्माणों का अपमार्जन अपने हाथ में ले सकती है।

अपने हाथ में किया जाना।

(3) नोटिस द्वारा प्रभावित किसी गृह या निर्माण का अधिभोगी, नोटिस जारी होने के पश्चात् किसी भी समय, उस गृह या निर्माण को नोटिस से अपर्याप्त करने के लिए नगरपालिका को आवेदन कर सकता है।

(4) नगरपालिका, ऐसे प्रत्येक आवेदन पर विचार करेगी और उस की प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर उस पर आदेश करेगी, और वह ऐसे किसी आदेश द्वारा, ऐसे गृह या निर्माण को नोटिस से अपर्याप्त कर सकती है।

(5) यह विनिश्चित करने में कि क्या किसी गृह या निर्माण की प्रोटिस से अप-वर्जित करना है, नगरपालिका, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिभोगी, यदि कोई हो, द्वारा गृहापमार्जन के लिए दिए गए प्रवन्धों की दक्षता पर तथा उस प्रयोजन पर विचार करेगी जिसके लिए वह गन्दगी, कूड़े-करकट, मल या अन्य उद्देगिक पदार्थ प्रयोग करता है।

रूढ़िगत
अधिकारों
की समाप्ति।

165. (1) इस अधिनियम के प्रवर्तन में श्रान का तारीख से, गृहापमार्जन के बारे में किसी सफाई मजदूर के रूढ़िगत अधिकार, यदि कोई हों, समाप्त हो जाएंगे।

(2) नगरपालिका, ऐसे सफाई मजदूर को, जिसके रूढ़िगत अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं, ऐसी राशि का, जो वह उचित मज्ज, अनुदान के रूप में संदाय कर सकती है और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए तो ऐसा संदाय करेगी। राशि और उसके हकदार व्यक्ति का अवधारण नियमों के अनुसार किया जाएगा।

अपमार्जन
आदि।

166. (1) कोई भी व्यक्ति, किसी आधान में मन का अपने सिर पर बहन नहीं करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो 18 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं है, गृहापमार्जन या झाड़ू लगाने के काम में किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लगाया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, जुर्माने में दण्डनीय होगा, जो कम से कम पन्चोस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

नगरपालिका
द्वारा एक
बार अपन
हाथ में लिए
गये गृहा-
पमार्जन का
चालू रखा
जाना।

167. जब नगरपालिका ने, इन अध्याय के अधीन किसी गृह या निर्माण का गृहापमार्जन एक बार अपने हाथ में ले लिया है, तो वह ऐसे गृह या निर्माण का तत्पश्चात् अधिभोगी की नभ्मति से या उसके बिना ऐसा गृहापमार्जन चालू रख सकता है।

समुचित रूप
से गृहाप-
मार्जन करने
के लिए
नगरपालिका
की बाध्यता।

168. जब नगरपालिका ने किसी गृह या निर्माण का गृहापमार्जन हाथ में ले लिया है, तो वह उसको समुचित रूप में करने के लिए तब तक आग्रह होगी, जब तक उसने स्वयं को धारा 164 की उप-धारा (4) के अधीन आदेश द्वारा बाध्यता में निर्मूक्त न कर लिया हो।

नगरपालिका
के सेवकों
को गृहाप-
मार्जन प्रया-
जनों के लिए
शक्तिदा।

169. गृहापमार्जन में लगे नगरपालिका के सेवक, सभी युक्तियुक्त समर्थों पर, नगरपालिका द्वारा हाथ में लिया गया गृहापमार्जन उचित रूप में करने के लिए आवश्यक सभी कार्य कर सकते हैं।

170. गृहापमाजन के अनुक्रम में नगरपालिका के भवको द्वारा हवाई गई मनी मामली नगरपालिका की होगी।

गृहापमाजन से हुए संग्रहण का नगरपालिका में निहित होगा।

171. नगरपालिका वाल्मीकियों की ऐसी महिलाओं के बालकों के लिए, जो नगरपालिका के नियोजन में है या, निजि गृहों में काम करती है, शिशु-सदनों की स्थापना और उनके अनुकरण के लिए नियमों द्वारा विहित रीति में व्यवस्था कर सकती है, और जब राज्य सरकार द्वारा ऐसा निर्देश किया जाए, तो ऐसी व्यवस्था करेगी।

मफाई मजदूरों के शिशु सदनों की स्थापना।

172. (1) नगरपालिका, उपायुक्त के अनुमोदन से, या तो नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अथवा उससे बाहर जीव-जन्तुओं के या ऐसे जीव-जन्तुओं के किसी विनिर्दिष्ट प्रकार के विक्रयार्थ वध के लिए परस्पर नियत कर सकती है, और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो नियत करेगी, और तत्समूह अनुमोदन से ऐसे परिसरों के प्रयोग के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान कर सकती है और उनका वापस ले सकती है, या यदि ऐसे परिसर नगरपालिका के हों, तो उनके प्रयोग के लिए क्रिया अथवा फीस प्रभारित कर सकती है।

जीव-जन्तुओं के विक्रयार्थ वध के लिए स्थान।

(2) जब नगरपालिका द्वारा ऐसे परिसर, नगरपालिका-क्षेत्र की सीमाओं के बाहर नियत किए गए ह, तो वह उनका निरीक्षण तथा विनियमन, उप-विधियों के अनुसार करेगी, माना वे नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर ही हों।

(3) जब ऐसा कोई परिसर नियत कर दिया गया है, तो कोई भी व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी अन्य स्थान पर ऐसे किसी जीव-जन्तु का विक्रयार्थ वध नहीं करेगा।

(4) यदि कोई स्थान इस प्रकार नियत किए गये हैं, तो कोई व्यक्ति, जो इस धारा के अधीन नगरपालिका द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के भीतर नियत स्थान से भिन्न किसी स्थान पर किसी जीव-जन्तु का विक्रयार्थ वध करता है, ऐसे जुमाने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

173. जब कभी किसी व्यक्ति के भारसाधन में कोई जीव-जन्तु विक्रयार्थ अथवा किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए वध से अग्र्यथा मर जाता है, तो उन जीव-जन्तु का भार-साधक व्यक्ति चौबीस घण्टे के भीतर या तो—

मृत जीव-जन्तुओं का ध्वजन।

(क) नगरपालिका द्वारा जीव जन्तुओं के शवों के ध्वजन के लिए धारा 154 के अधीन नियत किसी स्थान को, यदि कोई हो, अथवा ऐसे किसी स्थान को जो नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं से कम से कम एक किलोमीटर बाहर हो, शव को पहुंचाएगा; या

(ख) जीव-जन्तु की मृत्यु पर नगरपालिका को नोटिस देगा, जिस पर नगरपालिका शव का व्ययन करायेंगी ।

(2) उप-धारा (1) के अन्ध (ख) क प्रयोजन किसी जीव जन्तु के शव के व्ययन के सम्बन्ध में, नगरपालिका ऐसी काम प्रभारित कर सकती है, जो नगरपालिका ने सार्वजनिक नोटिस द्वारा विहित की हो ।

(3) इस धारा के प्रयोजन के लिए "जीव जन्तु" शब्द में, सभी सींगधारी पशु, हाथी, ऊँट, घोड़े, टट्टू, गधे, खच्चर, हिरन, भेड़ें, बकरियाँ, सुथर तथा अन्य बड़े जीव जन्तु अभिप्रेत समझे जाएंगे ।

(4) इस धारा को उप-धारा (1) के अनुसार कार्य करने के लिए प्रत्येक कोई व्यक्ति, यदि वह ऐसा कृत्य करने में सफल रहता है, जूमनि में दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा ।

मांगों के
संबंध में
शर्तियाँ ।

174. नगरपालिका का निम्नलिखित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं—

(क) किसी नए मार्बजनिक मार्ग का अभिव्यास तथा बनाया जाना और सुरंगों तथा उनके अनुषंगी अन्य संरमाँ का सन्निर्माण ;

(ख) नगरपालिका में निहित किसी वर्तमान मार्बजनिक मार्ग को चौड़ा करना, नम्बा करना, उसका विस्तार करना, उसे बढ़ाना, उसको तलानन या तलावनन करना अथवा अन्यथा उसका सुधार करना ;

(ग) किसी मार्बजनिक मार्ग या उसके किसी भाग को किसी मार्बजनिक प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से बन्द करना ;

(घ) इस प्रकार निहित किसी मार्बजनिक मार्ग को मोड़ना, उसकी दिशा परिवर्तित करना, उसे रोक देना या बन्द कर देना ;

(ङ) अपने विवेकाधीन ऐसे आकार-प्रकार के, जो वह उचित समझे, निर्माण-स्थलों की व्यवस्था करना, जो नगरपालिका द्वारा खण्ड (क) तथा खंड (ख) के अधीन या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए, चौड़े किए गए, लम्बे किए गए, विस्तारित, बढ़ाए गए, सुधार किए गए, तलानन या तलावनन किए गए किसी मार्बजनिक मार्ग के साथ संलग्न या साथ में लगे हों ;

(च) ऐसी शर्तों को विहित करने वाले किसी नियम के उपबन्धों के अध्वधीन, जिन पर नगरपालिका द्वारा सम्पत्ति अर्जित की जा सकती है, किसी ऐसी भूमि का, उस पर के निर्माण के माध्यम, अर्जन करना, जो वह, पूर्ववर्ती खंड के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, हाथ में ली गई या प्रायोजित किसी स्कीम या संक्रम के प्रायोजन के लिए, आवश्यक समझती है ;

छ) ऐसी शर्तों को विहित करने वाले किसी नियम के उपबन्धों के अध्वधीन, जिन पर नगरपालिका में निहित होने वाली सम्पत्ति अर्जित की जा

माली है, खाड़ (च) के प्रयोग नगरपालिका द्वारा भविष्य में नगरपालिका को पट्टे पर देना, उद्योग विकास करना, पक्का भवन बनाना, या नगरपालिका में निहित और उनके द्वारा किसी मार्गजनित मार्ग के लिए प्रयुक्त किसी भूमि को, जिसकी उन प्रयोग के लिए अब कोई परेशानी नहीं है, पट्टे पर देना, उनका विक्रय करना या परेशानी बनाना, और इस प्रकार करने में उस पर के निर्माता के हड़ने तथा निमार्ण को विनिर्दिष्ट करने, जिनमें ऐसी भूमि नहीं जा सकती है :

परन्तु सरदार में भिन्न स्वतन्त्रधारियों के स्वतन्त्राधीन भूमि 25 वर्ष की अवधि के लिए किसी मार्गजनित मार्ग के रूप में प्रयोग के बिना नगरपालिका ने निरन्तर रूप से निहित रहने के बाद नगरपालिका को आत्यन्तिक सम्पत्ति बन जायेगी; किन्तु ऐसी भूमि का उद्देश्य जिसके प्रयोग की, उन समय में, जब में वह नगरपालिका में निहित हुई है, पञ्चवत्सवर्ष की मर्यादा में पूर्व, किसी मार्गजनित मार्ग के रूप में परेशानी नहीं है, ऐसी भूमि के मुधारों के लिए नगरपालिका को उनके द्वारा मुक्तिपूर्ण प्रतिफल या मर्यादा देने पर, और ऐसी निमार्णों के उद्देश्य, जो नगरपालिका ऐसी भूमि के आवां उपयोग के सम्बन्ध में अधिरोहित है, उनके स्वतन्त्राधीन को अधिरोहित कर दिया जायेगा और यदि स्वतन्त्राधीन प्रयोग की राशि संकलन करने के लिए अनिवार्य या अनिवार्य हो, तो नगरपालिका ऐसा नहीं करेगी के पञ्चवत्सवर्ष, जो वह उचित समय, भूमि के नतीजे और ऐसी प्रयोग की, जो प्रतिफल की राशि की, जो नगरपालिका निधि में संग्रह हो जायेगी, प्रतिफल हो, भू-स्वामी को सदैव कर देगी, अथवा भूमि का व्ययन ऐसी राशि में कर देगी है, जो वह उचित समय में ।

175. (1) कोई भी व्यक्ति, नगरपालिका को निम्नलिखित सूची अनुसूची के बिना, ऐसी किसी पेट्टों को नहीं काटेगा या किसी पेट्टों को किसी प्राप्ति को नहीं काटेगा, या किसी निर्माण अथवा उसके किसी भाग को परिवर्तित या भविष्य में विस्तार देगा या किसी निर्माण की बाहर की तरफ परिवर्तित या मरम्मत नहीं करेगा, जहाँ ऐसी कार्रवाई की प्रकृति ऐसी है जिससे किसी मार्ग या प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति के लिए अवरोध, संतुष्ट या क्षति या जोड़न करित होता है ।

यहाँ को जोड़ने, निर्माता के परिवर्तन या जोड़ने के समय नतीजे का नगरपालिका ।

(2) नगरपालिका, किसी समय, नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकती है कि उप-धारा (1) में निहित कार्य में में कोई कार्य करने वाला या करने का प्रस्तावना करने वाला कोई व्यक्ति, उस कार्य को आरम्भ करने से या सलू रखने से विरत रहेगा, जब तक वह ऐसे विज्ञापन पट्टे या पर्दे, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट या वर्णित हों गये हैं, पर्याप्त प्रमाण व्यवस्था सहित सूची में सूचीबद्ध नहीं करता है, नहीं बनाए रखता है और उनकी व्यवस्था नहीं करता है और नगरपालिका द्वारा किसी समय, नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकती है कि उनके कार्य में किसी कार्य के पूर्वानुमान में या उनके अनुसरण में परिवर्तित किसी विज्ञापन-पट्टे को, नोटिस में विनिर्दिष्ट हों करने वाले समय के भीतर हटाए, जाए ।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो उप-धारा (1) के अधिन में उप-धारा (2) के अधिन किसी नोटिस के निष्कर्षों का पता लगाने में शक्यता रहता है, जमाने में दण्डनीय होगा, जो उस में उन दण्डनीय कार्य और अधिन में अधिन दो सी रूपों होगा तथा जब उप-धारा का अनुसरण करने वाले हो तो ऐसे प्रतिष्ठित जमाने में दण्डनीय होगा, जो प्रयोग में दिव के बिना,

जितने दीपन प्रथम उल्लेखन या अनुवृत्तन के पश्चात् उल्लेखन या अनुवृत्तन होता रहता है, वस्तुस्थिति होगी।

किसी मार्ग के बनाने से पूर्व नोटिस।

176 (1) कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की स्वीकृति के बिना किसी मार्ग या अभिव्यक्ति नहीं करेगा या उसको नहीं बनायेगा अथवा उसका अभिव्यक्ति या बनाना प्रारम्भ नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी मार्ग का अभिव्यक्ति करेगा या उसे बनाना चाहता है, नगरपालिका को ऐसे आवेदन का लिखित नोटिस देगा।

(3) जहाँ किसी नगरपालिका ने धारा 177 के खण्ड (ख) के अधीन कोई आदेश जारी किया है, वहाँ उप-धारा (2) के अधीन कोई भी नोटिस तब तक विधिमान्य नहीं समझा जाएगा, जब तक ऐसे आदेश के अर्थात् अपेक्षित विनिर्दिष्ट नगरपालिका के समाधानमूलक रूप में प्रस्तुत नहीं कर दी गई है।

धारा 176 के अर्थात् नोटिस का आदेश।

177. नगरपालिका, धारा 176 को उप-धारा (2) द्वारा अपेक्षित नोटिस की प्राप्ति के एक मास के भीतर, निम्नलिखित जारी कर सकती है—

(क) यह निर्दिष्ट करते हुए कोई आदेश कि आदेश में विनिर्दिष्ट किसी अवधि के लिये, जो ऐसे आदेश की तारीख से एक मास से अधिक नहीं होगी, आश्रित कार्य में आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी; अथवा

(ख) अतिरिक्त विनिर्दिष्टों की अपेक्षा करने हुए कोई आदेश।

नए मार्ग की गन्तव्य।

178. धारा 176 की उप-धारा (2) द्वारा अपेक्षित नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् दो मास के भीतर, नगरपालिका प्रस्तावित मार्ग की स्वीकृति देने के इन्तजार कर सकती है या उसका अन्तर्त स्वीकृति दे सकती है अथवा मार्ग का तब बहाल करने, उसको पक्का करने, उस पर खर्च का लगाने, जन निवास की दिशा के साधनों तथा चौड़ाई के बारे में ऐसे निश्चित विदेशों के अधधीन, जो नगरपालिका जारी करता उचित समझे, स्वीकृति दे सकती है तब ऐसे मार्ग का अभिव्यक्ति करने वाला या बनाने वाला व्यक्ति नगरपालिका की स्वीकृति की प्रत्येक विनिर्दिष्ट का अनुपालन करेगा।

परन्तु यदि नगरपालिका ऐसे नोटिसों की प्राप्ति के पश्चात् दो मास तक या धारा 177 के खण्ड (ख) के अधीन कोई आदेश जारी किया गया है, और नगरपालिका ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस सम्बन्ध में स्वीकृति या अस्वीकृति का कोई आदेश करने में तथा उस व्यक्ति को, जिसने ऐसा नोटिस दिया है, आदेश पत्रित करने में उपेक्षा करे, तो वह अथवा असफल रहे तो यह समझा जाएगा कि प्रस्तावित मार्ग की पूर्ण रूप से स्वीकृति दे दी गई है।

स्वीकृति का प्रयत्न।

179. किसी मार्ग का अभिव्यक्ति करने या बनाने के लिये प्रत्येक स्वीकृति, जो किसी नगरपालिका द्वारा दी जाएगी, या दी हुई समझी जाएगी, ऐसी स्वीकृति की तारीख से केवल एक वर्ष के लिये प्रवृत्त रहेगी। यदि मार्ग का अभिव्यक्ति करना या बनाना उक्त एक वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया गया है, तो स्वीकृति के धार में यह समझा जाएगा कि वह समाप्त हो गई है, किन्तु स्वीकृति की ऐसी संप्राप्ति, इस अधिनियम में पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन नई स्वीकृति के लिए पश्चात् के किसी आवेदन को बाधित नहीं करेगी।

राष्ट्रीयकरण—जिसे मार्ग को निहित या अधिनियम उस समय समझा जाएगा जब भूमि पर विहित स्थानीय सीमा विवादों द्वारा उसको सीमांकित कर दिया जाता है।

180. कोई भी व्यक्ति, जो धारा 176 द्वारा अपेक्षित नोटिस देने दिया या इस अधिनियम की धारा 178 के अंतर्गत किये गये किसी निहित विवादों के या किसी उप-विधि या इस अधिनियम के उपबंध के उल्लंघन में किसी मार्ग या अभिन्यास करता या बनाने का प्रयत्न करता है, जानबूझता है या पूरा करता है, जमाने का दायी होना जो उसे कम पचान रुपये तथा अधिक से अधिक पांच सौ रुपये होगा।

अधिन।

181. किसी ऐसी दशा में, जहां नगरपालिका यह समझती है कि धारा 176 के द्वारा अपेक्षित नोटिस दिये जाने के बिना या इस अधिनियम की धारा 178 के अंतर्गत नगरपालिका द्वारा किये गये किसी निहित विवादों के, या किसी उप-विधि के या इस अधिनियम के उपबंध के उल्लंघन में किसी भूमि को किसी मार्ग के रूप में अभिन्यास किया जा रहा है या किया गया है, तो नगरपालिका निहित नोटिस द्वारा सूचनाओं से ऐसी रीति में मार्ग को परिवर्तित करने की शक्ती कर सकती है, जो वह आवश्यक समझे।

मार्ग के नीचे की भूमि को स्वामी को नोटिस।

182. (1) (क) जब नगरपालिका यह समझती है कि नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी सार्वजनिक मार्ग में निहित किसी मार्ग में या ऐसे मार्ग के किसी भाग में सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुविधा या सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उस मार्ग को तल बराबर करने, उस पर उड़ानें बनाने, उस को पक्का करने, उस पर सड़ियों काटने, सड़ियों बनाने, गलियां बनाने प्रकाश व्यवस्था करने या उनकी सफाई के लिए कोई कार्य किया जाए, तो नगरपालिका ऐसे मार्ग या उसके किसी भाग के स्वामी या स्वामियों से निहित नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकती है कि ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट किए गये वाले किसी समय के भीतर ऐसा कार्य निष्पादित करे।

मार्गों की सुरक्षित अपेक्षा करने तथा ऐसे मार्गों को सार्वजनिक मार्गों में परिवर्तित करने की शक्ति।

(ख) यदि स्वामी विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्य का निष्पादन करने में असफल रहता है, तो नगरपालिका निहित नोटिस द्वारा, ऐसे मार्ग के या उसके किसी भाग के नामने के, नगर या मार्ग में लगी छूट या निर्माण के स्थापितों से अपेक्षा कर सकती है कि ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, कार्य का निष्पादन कराए।

(2) यदि उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी किये गये नोटिस के निषेधों या अनुशासन विनिर्दिष्ट करने के भीतर नहीं किया जाता है, तो नगरपालिका यह समझती है कि नगरपालिका क्षेत्र के भीतर यह आवश्यक है कि उस मार्ग या उसके किसी भाग के नामने के, नगर या मार्ग में लगी छूट या निर्माण के स्थापितों से अपेक्षा कर सकती है कि ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, कार्य का निष्पादन कराए।

(3) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी किये गये नोटिस के निषेधों या अनुशासन विनिर्दिष्ट करने के भीतर नहीं किया जाता है, तो नगरपालिका यह समझती है कि नगरपालिका क्षेत्र के भीतर यह आवश्यक है कि उस मार्ग या उसके किसी भाग के नामने के, नगर या मार्ग में लगी छूट या निर्माण के स्थापितों से अपेक्षा कर सकती है कि ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, कार्य का निष्पादन कराए।

के स्वामी के व्यय पर नगरपालिका द्वारा, ऐसे कार्य का निष्पादन कराने के पश्चात् वह मार्ग या उनका कोई भाग, जिसमें ऐसा कार्य कराया गया है, उक्त मार्ग या उसके किसी भाग के अधिकांश प्रभाग के स्वामी या स्वामियों द्वारा अपेक्षा-पत्र दिये जाने पर या उन व्यक्तियों की बहुसंख्या द्वारा अपेक्षा-पत्र दिये जाने पर जिन पर उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन नोटिस की तामील की गई है, नगरपालिका द्वारा वहां कोई सार्वजनिक नोटिस लगाने के पश्चात्, उसे सार्वजनिक मार्ग घोषित कर दिया जाएगा और वह नगरपालिका में निहित हो जाएगा।

(4) कोई नगरपालिका, किसी समूह, किसी ऐसे मार्ग या उसके किसी भाग में, जो नगरपालिका द्वारा अनुरक्षणीय नहीं है, लगाए गये नोटिस द्वारा उसको सार्वजनिक मार्ग घोषित करने के अपने दाय्ये को प्रजापता दे सकती है, और जब तक ऐसे नोटिस को लगाए जाने के पश्चात् के आगामी एक मास के भीतर ऐसे मार्गों के ऐसे भाग के स्वामी या विभिन्न स्वामियों में से किसी स्वामी द्वारा नगरपालिका के कार्यालय में उस सम्बन्ध में दाय्ये नहीं दिया जाता, तो नगरपालिका ऐसे मार्ग में या ऐसे भाग में लगाए गये निहित नोटिस द्वारा उसको नगरपालिका में निहित सार्वजनिक मार्ग घोषित कर सकती है।

मार्ग पर
व्यक्तिगत
या प्रत्यक्षी
संरचना के
लिए बंद।

183. (1) कोई भी व्यक्ति, जो नगरपालिका की निहित अनुज्ञा के बिना, मार्ग पर या उसके नीचे किसी माल-प्रणाल, या जलमार्ग पर या उसके उपर यावा नीचे कोई स्थावर वस्तु स्थापित करता है, या उक्त भूतल के उपर किसी स्थान पर किसी मार्ग की ओर बाहर निकली हुई कोई स्थावर प्राम्नी संरचना परिवर्तित करता है या पुनः परिवर्तित करता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये तथा अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नगरपालिका, नोटिस द्वारा किसी व्यक्ति से, जिसने उक्त उप-धारा के उपबन्धों को भंग किया है, अपराधिकृत सन्निवृत्ति को तुरन्त बन्द करने तथा सात दिन की अवधि के भीतर यथा पूर्वोक्त ऐसे स्थावर वस्तु स्थापना या प्राम्नी संरचना को हटाने या परिवर्तित करने की अपेक्षा कर सकती है और यदि ऐसा व्यक्ति सात दिन की उक्त अवधि के भीतर नगरपालिका को समाधानप्रद रूप में हेतुक दक्षित करने में असफल रहता है, तो नगरपालिका स्वयं ऐसे उपाय कर सकती है, जो उसे आदेश की प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक प्रतीत हों, और ऐसे उपायों का व्यय, यदि उससे मांग की जाने पर संदत्त नहीं किया जाता, तो ऐसे व्यक्ति ने भू-राजस्व के बचाया के रूप में अनुसूची योग्य होगा।

सार्वजनिक
मार्ग के
व्यक्तिगत
या प्रत्यक्षी
संरचना के
लिए बंद।

184. (1) नगरपालिका, ऐसी शर्तों पर, जो मार्ग से गुजरने वाले या पड़ने वाले निवास करने वाले या कार्य करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा या सुविधा के लिए उपायों द्वारा अनुमोदित की जाएं, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए अनुज्ञा दे सकती है, और स्वयंसेवक द्वारा अनुज्ञा वापस ले सकती है—

(1) किसी सार्वजनिक मार्ग के भूतल पर या किसी माल-प्रणाल, नदी या जलमार्ग पर या उसके उपर कोई जंगम अतिशय प्रखन या उक्त भूतल के उपर किसी स्थावर या ऐसे सार्वजनिक मार्ग की ओर बाह्य निर्माता हुई कोई चाल प्राम्नी संरचना बनाना;

- (ख) किसी सार्वजनिक मार्ग के बाड़ों या खंभों के लिए लड़ने, या अन्य सामग्री को उतारना या अधिकृत करना;
- (ग) किसी सार्वजनिक मार्ग पर निर्माण सामग्री, निर्यात के लिए सामान या अन्य वस्तुओं का जमा करना या जमा करना;
- (घ) किसी मार्ग के ऊपर, उसके अन्दर या उसके नीचे कोई सुराख करना या खुदाई करना, या किसी मार्ग के नीचे से सामग्री हटाना, जिससे तल के धंस जाने का जोखिम उत्पन्न हो ; या
- (ङ) किसी सार्वजनिक मार्ग में कोई बाड़, खम्भा, स्तंभ या पाइल, परिवर्तित करना या स्थानित करना है;

और ऐसी अनुज्ञा के लिए उपर्युक्त द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले मान मान के अनुसार फीस प्रसारित करवाती है ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो नगरपालिका की निहित अनुज्ञा के बिना उप-धारा (1) में वर्णित कार्य या तो कोई कार्य करता है, जानते से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पञ्चास रुपये और अधिक से अधिक दो लाख रुपये होगा और नगरपालिका या कार्यकारी अधिकारी या, लिखित या स्वरूपित अधिकारी या नगरपालिका द्वारा प्राविष्टत कोई व्यक्ति,—

(i) स्वामी को क्षति नगर्षा हटाने के लिए मुक्तिपत्र अथवा दिए जाने और उसके ऐसा करने में अथवा करने के पश्चात्, पुनित या किसी अन्य अधिकरण द्वारा, कि नहीं ऐसे जंगल अधिकारियों या प्रमुखी संरचनाओं की और सामग्री, सामान या वणिज्य, की वस्तुओं की और किसी ऐसी बाड़, खम्भे, स्तंभ या पाइल को हटाने या हटाना करना है ;

(ii) मार्ग को किसी ऐसे परिवर्तित, उत्खनन या नुकसान से पहुँच की स्थिति में करने के लिए उत्तरदायी होता है ।

(3) यदि उप-धारा (2) के खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट सामग्री या दावा नगरपालिका द्वारा सुरक्षित अधिकारों के लिए उत्तरदायी जमा किए जाने के पश्चात् एक पक्षबाड़े के भीतर स्वामी द्वारा नहीं लिया गया है, या यदि स्वामी हटाए जाने या सुरक्षित अधिकारों में जमा करने का वास्तविक खर्च नगरपालिका को संवत् करने में असमर्थ रहता है, तो नगरपालिका स्वामी को जोखिम पर सामग्री को नुकसान द्वारा बेच या तो है, और ऐसे विक्रय-आय का अधिभाग, नगरपालिका द्वारा लिए गए व्यय की सीमा के पश्चात् स्वामी को संवत् किया जाएगा, या यदि स्वामी अपना नहीं करता या यदि वह नदीय को स्वीकार करने में इच्छा रखता है, तो अधिभाग नगरपालिका द्वारा तब तक जमा रखा जाएगा, जब तक उनके अधिकारी व्यक्ति द्वारा उत्तरदायी नहीं दिया जाता, और यदि दो वर्ष के भीतर कोई भी दावा नहीं किया जाता, तो नगरपालिका राजी को नगरपालिका-निधि में जमा करवा सकती है ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "जंगल अधिकरण" के अन्तर्गत है, कोई सीट या बैंक और "जंगल प्रमुखी संरचना" के अन्तर्गत है, किसी सामग्री के बा. कोई सामान ।

सतिश्रवण
पठनं वा
उपायुक्तं वा
सिद्धिः ।

[illegible]

तिसी मार्ग
यी पंथि-
यो विनिध-
यित्त एवमे
की शांति ।

196. (1) यदि कोई व्यक्ति, कुत्ता, दीवार या अन्य निर्माण यन्त्रवा किसी निमित्त या कोई बात, या तो विद्यमान रूप में, यावा भविष्य के लिए बना व्यवस्थित रूप में, या निर्माण के प्रक्रम को पूरे उसके दोनों में से किसी एक मार्ग की, निमित्त पक्षों में बहुरी वड़ा हुआ है, तो न्यायनिता, अतः किसी ऐसा मानव, कुत्ता, दीवार या अन्य निर्माण या उद्देश्य भाग, या तो पूर्णतः या अंशिकतः ऊपर लिखे गया है या जो, दिया गया है, या नीचे लिखा है, सोडा या ऐसे निमित्त या भाग को जब वह पुनः निर्मित किया जा रहा हो, पीछे की एक निमित्त पक्षों की श्रौरता नि-उ निर्माण के प्रक्रम की श्रौर करने की प्रवृत्ति कर लाती है; और इस प्रकार पीछे की श्रौर करने या हटाने में मर्ग में पक्षिष्ठ भूमि या उद्देश्य मार्ग या भाग या कक्षा श्रौर न्यायनिता में निर्मित हो जाता।

प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्माण या भूमि को स्वामी को, उनके निर्माण या भूमि को पछि हटाने के प्राप्ति के लिए प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए।

(2) कृषि-संशोधन एवं विद्यार्थियों पर शिक्षण हेतु उच्च शिक्षा, प्रसारण, ग्रामीण विकास के मन्त्रालय के तहत विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले प्राध्यापकों का प्रशिक्षण प्रदान किया है।

सुखासी
वर्ष ।

187, 188, 183, 184 या 186 पक्षों में 202 के कण्ड (अ) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सभापति या किसी सदस्य के पदस्थिति, विधायकता या अन्य किसी बात के कारण सभा में विहित है, तो—

(ग) नगरपालिका १, नगर निकाय के सम्बन्ध में, जो को हरेम नगर को बनाया गया, जिसका नगरपालिका की विधित्त अनुदान के धिना दिया जाना बादा 183 या धारा 184 के अधीन उपलब्ध है, अथवा धारा 186 को सम्बन्ध (2) को उपनवीन के अधीन लिखित धिना धारा लाया जाना, जिसका धारा धारा 187 की स्विकृति है, जो लागू नवीन नगरों के लिसी को के सम्बन्ध में या की ती धिनेष नगरों के सम्बन्ध में दी जा नाली है, अनुदान नहीं करेगी:

[illegible]

की संविधान या कृषि की नीति को विचारित किया जाता है कि इसी सीमाओं के भीतर रहते नैतिकता के अन्तर्गत है।

छत्ता तथा बाहुय दोवारों का व्यवस्थित व्यवस्थापन करना, धान, चाराईयों, पत्तों या अन्य पत्तों के जलनशील पदार्थों को बनाई या नष्ट करने की जाहाना; और नगरपालिका, विभिन्न नगरों द्वारा कृषि में व्यवस्थापन, जिसने किसी ऐसे निदेश की व्यवस्था की है, अधिकांश करती है कि इस प्रकार या नष्ट करने की गई छत्ता या दोवारों को हटा दे या इस प्रकार विचारित कर दे, जिन प्रकार नगरपालिका उचित समझे।

196. (1) कोई भी व्यक्ति, जो नगरपालिका की कृषि के विना किसी मार्ग पर नीचे जगहों को बोधना है, या नीचे जगहों को हटा दे या किसी बाधना किसी प्रकार के नष्टों या जोव कृषि के लिए विचारित स्थान। के रूप में या विचारित स्थान के रूप में नगरपालिका द्वारा है अधिकांश जगहों को हटा दे या नष्ट करने के लिए, जगहों में नष्ट करने के लिए, जो कम से कम पञ्चीन रूप से और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

(2) किसी नगरपालिका स्थान में, नगरपालिका की कृषि के विना बोधना, पत्तों में बोधना या बाधना घुसना पाया गया कोई जोव कृषि, नगरपालिका के किसी कर्मचारी द्वारा या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कृषि हाऊस में बोधना या बाधना है।

उचित बलियों के विना दानों का चनाना। 197. (1) कोई भी व्यक्ति, जो सुप्रीम के अधीन बोधना में सुप्रीम में बाधना बोधना पूर्व तक की बाधना के दौरान किसी मार्ग में उचित बलियों के विना किसी बाधना या चनाना है या धकेलना है, जगहों में दण्डनीय होगा, जो कम से कम पञ्चीन रूप से और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो किसी मार्ग में किसी बाधना को चनाते, बाधना या धकेलते हुए, पुलिस अधिकारी के विना—

(क) बाधना रखने, या

(ख) जब वह, उसी और जा रहे किसी बाधना को बाधना हो उन बाधना के बाधना और रहने में बाधना रहता है, जगहों का बाधना होगा, जो कम से कम पञ्चीन रूप से और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

इन बाधना बनाता। 198. कोई भी व्यक्ति, जो नगरपालिका द्वारा जारी किए गए किसी बाधना या विचारित प्रतिपक्ष के उल्लंघन में, नगरपालिका की कृषि के विना, कोई इस या बाधना बनाता है, नष्ट या बाधना बनाता है या कोई बाधना या बाधना बाधना या बाधना बनाता है या उसमें बाधना करता है, जगहों में दण्डनीय होगा, जो पञ्चीन रूप से अधून और दो सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।

संस्थापन—1. बाधना की दशा में ऐसे बाधना प्रत्येक बाधना प्रत्येक इस प्रकार के बाधना दण्डनीय होगा।

संस्थापन—11. इस धारा के प्रस्तावों के लिए "बाधना" के अन्तर्गत होगा, कोई बाधना, कोई बाधना-बाधना, कोई बाधना-बाधना या बाधना बाधना या बाधना बाधना कोई ऐसे बाधना जो और की बाधना उत्पन्न कर सकता है।

199. कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसी रीति में, प्रत्यापुत्र न जाता है या प्रतिशत्रुजी, प्रमि गुजर या प्रसोदरु बनाता है या किसी ऐसे अन्य क्षेत्र में गता है, जिसमें गुजरने वाले अथवा पड़ोस में रहने वाले या काम करने वाले व्यक्तियों के लिए संकट अथवा सम्पत्ति को क्षति का जोखिम कारित हो या कारित होने की संभावना हो, जर्मनी से दण्डनीय होगा जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपए होगा।

प्रत्यापुत्र
प्रादि
बनाता।

200. कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसी रीति में, प्रदान किया करता है, विस्फोट करता है, काट काटता है या निर्माण संक्रियाएं जारी रखता है, जिसमें गुजरने वाले अथवा पड़ोस में रहने वाले या काम करने वाले व्यक्तियों के लिए संकट कारित हो या कारित होने की संभावना हो, जर्मनी से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपए होगा।

निर्माण,
प्रदान-
क्रिया,
विस्फोट
संक्रिया या
काट का
काटना।

201. कोई नगरपालिका, उपायुक्त की पूर्ण स्मृति में, हिमाचल प्रदेश में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से, जिस पर नगरपालिका द्वारा इसकी उप-धारा (2) के अन्तर्गत खर्च करना है, और विशेष के लिए मान्य प्रयोजन करने वाले व्यक्तियों और लाभ के लिए कोई व्यय करने वाले सभी व्यक्तियों में, मने के संघ में नियोजित जल-वाहकों, प्रभावार्थकों और अन्य व्यक्तियों के विचार, स्वच्छता प्रयत्नों, निगरानी और पहरा तथा इन्हें जैसे जगहों को पूरा करने के लिए प्रत्येक फीस उद्गृहीत कर नकेंगी।

मने पर फीस
उद्गृहीत
करने को
प्रयत्न।

अध्याय-1।

उप-विधियां

202. नगरपालिका उप-विधियों द्वारा निम्नलिखित कर मकोसों और यदि राज्य सरकार द्वारा प्रवेक्षा की जाए, तो करेगी,—

साधारण
उप-
विधियां

(क) नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर रखे गए या किराए के लिए चल रहे मोटर यानों से भिन्न यानों अथवा पशुओं के स्वत्वधारियों या चालकों के लिए अनुज्ञप्तियों आवश्यक बनाएंगी और ऐसी अनुज्ञप्तियों के लिए संवेद्य फीस और शर्तें नियत करेगी, जिन पर वेदी या रद्द की जा सकती है, और ऐसी शर्तों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ पहियों के टायरों के लिए न्यूनतम चौड़ाई और पहियों के न्यूनतम व्यास के लिए उपबंध कर नकेंगी;

(ख) भारों या व्यक्तियों का वहन करने के लिए किसी वाहन, गाड़ी या अन्य सवारी की, अथवा किराए पर लिए गए पशुओं के किराए, अथवा भारों का वहन, या ऐसी सवारियों को धकेलने या वहन करने के लिए किराए पर लिए गए व्यक्तियों की सेवाओं के लिए दरें सीमित करेगी, जो यानी जा सकती हैं और नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किराए के लिए चल रहे किसी पशु या वाहन, गाड़ी अथवा अन्य सवारी द्वारा वहनीय भारों को सीमित करेगी;

(ग) जन्म, विवाह तथा मृत्यु के उचित पंजीकरण और जनगणना करने के लिए उपाय करेगी;

(घ) उन व्यक्तियों की संख्या नियत करेगी तथा समय-समय पर उनमें परिवर्तन करेगी, जो किसी ऐसे निर्माण या उनके भाग का अधिमान रहे, जो संवत्सर के लिए किराए पर दिया जाता है या एक से अधिक कटुम्व के सदस्यों द्वारा अधिभुक्त है अथवा ऐसे छोड़-बाड़ वाले वाजार क्षेत्रों में स्थित है, जैसा उपविधि में विनिर्दिष्ट

दिया जाए, और निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करेंगी —

- (i) ऐसे निर्माणों का परीक्षण और निरीक्षण ;
- (ii) होटलों और संवासगृहों का अनुज्ञापन और ऐसी अनुज्ञापितियों के लिए संदेय फीस तथा शर्तें, जिन पर वेदों या रद्द की जा सकती हैं ;
- (iii) ऐसे निर्माणों में स्वच्छता तथा संवातन को बढ़ावा देना ;
- (iv) ऐसे निर्माणों में फैल रही किसी संक्रामक या सांसारिक बीमारी की दशा में दिए जाने वाले नोटिस तथा की जाने वाली पूर्वावधानियाँ ;
- (v) ऐसे निर्माणों में अपमार्जन, सभी कूड़े-कराट, गन्दगी, विष्टा, कूड़े-कचरे या मल-जल का हटाना और ध्वसन ;
- (vi) होटल, सराय और संवासगृहों के मालिकों तथा आवासीय कलबों के सचिवों की दशा में आगन्तुकों और संवासियों की पंजियाँ ऐसे प्ररूप में रखना, जैसा नगरपालिका विहित करे ; और
- (vii) साधारणतया ऐसे निर्माणों का उचित विनियमन ;

(इ) निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करेंगी —

- (i) शिविर, प्रांगणों, बाँजी हाऊसों, बरायों, बेकरियों, सोडा वाटर बाखानों, बर्फ कारखानों, धाँवी घाटों, आटा मिलों, खाद्यन्न गोदामों, औषध-वितरक रत्नाघनों की दुकानों, बधे-शालाओं का और धारा 125 के अधीन अनुज्ञापन स्थानों का निरीक्षण और उचित विनियमन ;
- (ii) मंडियों और स्टालों का निरीक्षण और उचित विनियमन, प्रचलित मूल्य-सूची तैयार और प्रदर्शित करना और ऐसी मंडियों और स्टालों पर उद्ग्रहणीय फीस, किराए और अन्य प्रभार नियत करना ;
- (iii) नगरपालिका क्षेत्र के भीतर या नगरपालिका के नियंत्रणाधीन भूमे और औद्योगिक प्रदर्शनियाँ लगाना और धारा 201 के अधीन फीसों का संग्रहण ;
- (iv) कब्रिस्तान और श्मशान के प्रयोग और प्रबन्ध का नियंत्रण और विनियमन ;
- (v) सार्वजनिक कुपों, तालाबों, चश्मों या अन्य स्तों का, जिनसे सर्वसाधारण के प्रयोग के लिए, चाहे नगरपालिका क्षेत्र के भीतर हो या बाहर, जल उपलब्ध है या उपलब्ध कराया जा सकता है, पर्यवेक्षण, विनियमन तथा प्रदूषण से संरक्षण ;
- (vi) थिएटरों और सार्वजनिक सैर, मनोरंजन या मनोविनोद के अन्य स्थानों का अनुज्ञापन, निरीक्षण और उचित विनियमन ;
- (vii) ऐसी जन-मार्गणियों का निरीक्षण और उचित विनियमन, जिनमें ऐसी नहर से जल-प्रदाय किया जाता है, जिसको या तो उत्तरी भारत नहर और जल विकास अधिनियम, 1873 (1873 का 8) या हिमाचल प्रदेश लघु नहर अधिनियम, 1976 (1976 का 42) लागू होता है ;

(च) नगरपालिका क्षेत्र में निर्माणों या भूमि के स्वामियों द्वारा, जो नगरपालिका क्षेत्र के निवासी नहीं हैं, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर या निकट रहने वाले व्यक्तियों को इस अधिनियम या नियमों के प्रयोजनों में से सभी या किसी के लिए उनके अभिवर्तता क रूप में कार्य करने के लिए नियुक्ति की अपेक्षा करेंगी और ऐसी नियुक्ति विनियमित करेंगी ;

(छ) परिसर को पशुशालाओं, गोशालाओं अथवा भेड़ों, बकरियों या सुअरों के लिए घरों या बाड़ों के रूप में प्रयोग करने के लिए अनुज्ञापितियाँ आवश्यक बनाएंगी और ऐसी अनुज्ञापितियों के जारी किए जाने तथा वापिस लिए जाने को विनियमित करेंगी ;

- (ज) किसी नगरपालिका क्षेत्र में, जहाँ नगरपालिका द्वारा पशु पक्ष-प्राणियों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की गई है, या अनुज्ञप्ति दी गई है, वहाँ इस अधिनियम के अधीन अनुसंधान या अनुज्ञप्ति नहीं दी किसी पशु-पक्ष-प्राणियों के स्थान पर पक्ष-प्राणियों, पशु, भेड़, बकरी या सूअर के अभिसर्जन या परिशोधन नाम में निम्न भाग के विषय के प्रयोजन के लिए नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर प्रवेश को निषेधित, विनियमित या प्रतिषिद्ध करेगी और किसी किसी उप-विधि के अन्वयेन में नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर लागू नहीं किसी मान के अभिसर्जन, विनाश या अन्यथा व्ययन का उपबन्ध करेगी ;
- (झ) नगरपालिका क्षेत्र के भीतर ऐसे पॉन्जर नियत करेगी, जिनमें किसी विशेष प्रकार के ऐसे पशुओं का, जो विषय के लिए नहीं है, पक्ष-प्राणियों जाना अनुज्ञात किया जाएगा और नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी अन्य स्थान पर ऐसे पक्ष को, आवश्यकता की दशा के सिवाय, प्रतिषिद्ध करेगी ;
- परन्तु ऐसी कोई भी उप-विधियाँ, धार्मिक प्रयोजन के लिए बंध किए गए पशुओं को लागू नहीं होगी ;
- (अ) ग्रन्थायुध, आतिशवाजी, अग्नि-गुब्बारे, बम या प्रस्फोटक छोड़ने को (1) नगरपालिका को अनुज्ञा या ऐसी अनुज्ञा देने के लिए मजबूर किसी नगरपालिका अधिधीन को अनुज्ञा, (2) ऐसी जगहों के अधिधीन, जिन्हें नगरपालिका अधिधीनित करे, और (3) ऐसी फीसों, यदि कोई हों, के संदर्भ पर, जो नगरपालिका द्वारा इस निमित्त किसी समय नियत की गई हों, के सिवाय, प्रतिषिद्ध करेगी ;
- (ट) ऐसी जगहें विनियमित करेगी, जिन पर तट-क्षेत्रों या जमीन-क्षेत्रों की स्थापना करने के लिए धारा 126 के अधीन सम्मति दी जाएगी ;
- (ठ) वाष्प, जल, विद्युत शक्ति, यांत्रिक शक्ति या अन्य शक्ति द्वारा कारित उत्पाद के उपभोग के लिए निर्देश जारी करने का उपबन्ध करेगी ;
- (ड) निजी गृहों और पत्तियों तथा इस अधिनियम के उपबन्धों में नैदियाँ के अधीन सम्मति द्वारा स्थापित या अनुसंधान-मुख्य नलों या सेवा केबलों, तारों, नलों, नालियों, मल प्रणालियों और अन्य-संरचनाओं की बीच संबंधों या संकरों के बनाने और प्रयोग को विनियमित करेगी ;
- (ड) वर्षा जल के संग्रहण, भंडारण, प्रदूषण से परिरक्षण और उपयोग को विनियमित करेगी और धारा 100 से 106 तक के उपबन्धों को कार्यान्वित करेगी ;
- (ण) इन्हें शोर और विज्ञापनों को लगाने तथा नामपट्टों, संकेतपट्टों और संकेत खम्बों की स्थिति, आकार, आकृति और ढंग को विनियमित करेगी ;
- (त) किसी सार्वजनिक मार्ग या नगरपालिका में निर्मित संरचना के साथ लगाने वाली, इनके पश्चात् परिनिमित्त या पुनः परिनिमित्त सौभाग्य-दीवारों, बाड़ों और घेरों के सम्मिर्माण को नमूने, अनुसंधान और उनकी नामों के लिए उपबन्ध करेगी, उनका विनियमन करेगी, उनकी अपेक्षा करेगी या उनका प्रतिषेध करेगी ;
- (थ) सड़कों पर किसी भी प्रकार के यातायात को विनियमित या प्रतिषिद्ध करेगी और एनर्जेटिका कारित शोर को कम करने के लिए व्यवस्था करेगी ;
- (द) किसी ऐसे निर्माण में, जो धारा 125 के अधीन पंजीकृत या अनुज्ञप्ति नहीं है, किसी नियत अधिकतम मात्रा से अधिक किसी विस्फोटक पदार्थ, पेट्रोलियम, स्प्रिंट, नैफ्था या अन्य ज्वलनशील सामग्री के भण्डारण का प्रतिषेध करेगी ;
- (घ) नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर भटकने वाले स्वामीहीन पशुओं के अभिसर्जन और अधिहरण के लिए उपबन्ध करेगी ;
- (न) कुत्तों के विनिर्दिष्ट वर्गों में से सभी या किसी के पंजीकरण के लिए उपबन्ध करेगी और विशेषतया तथा पूर्ववर्ती की व्याख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना—
- (i) ऐसे पंजीकरण के लिए किसी व्यक्ति फीस के अधिरोपण के लिए उपबन्ध करेगी ;

- (ii) अपेक्षा करेगी कि प्रत्येक पंजीकृत कुत्ते के गले में पट्टा होगा, जिसमें नगर-पालिका द्वारा जारी किया गया धातु का टोकन लगा होगा ;
- (iii) उपबन्ध करेगी कि कोई कुत्ता, जो पंजीकृत नहीं है और जिसके गले में ऐसा टोकन नहीं है, यदि किसी सार्वजनिक स्थान में पाया जाता है, इस प्रयोजन के लिए ध्वजा बनाए गए स्थान पर निरुद्ध किया जा सकता है और उप-विधियों में दो जाने वाली किसी अवधि के पश्चात् नष्ट किया जा सकता है या उनका अन्यथा व्ययन किया जा सकता है ;
- (घ) पशुवहन के लिए लगाए गए ठेलों, विनय के लिए वस्तुओं की फेरी लगाने और ऐसे ठेलों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए अनुज्ञप्तियां आवश्यक बना देगी और ऐसी अनुज्ञप्तियां देने और रद्द करने के लिए शर्तें विहित करेगी ;
- (ङ) वे शर्तें जिन पर, और अवधियां जिन के लिए, धारा 183 की उप-धारा (1) और धारा 184 की उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञा दी जा सकती है, विनियमन करेगी और ऐसी अनुज्ञा के लिए फीसों और किरायों के उद्धरण के लिए उपबन्ध करेगी ;
- (च) संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के आवास और उपचार के लिए सामान्यतः प्रयुक्त निर्माणों के पंजीकरण, निरीक्षण और उचित विनियमन के लिए और ऐसे व्यक्तियों की, जो ऐसे निर्माणों या उनके भाग में निवास करते हैं, संध्या नीमित करने के लिए उपबन्ध करेगी ;
- (छ) नाधारणतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उपबन्ध करेगी ;
- (ज) पेड़ों या झाड़ियों या खनन करने या मिट्टी को हटाने या खदानों की विनियमित या प्रतिपिद्ध करने के लिए, जहां नगरपालिका को, जल की आपूर्ति बनाए रखना भूमि की परीक्षण, भू-खनन या वेगद्वारा की विरचना की रोकथाम अथवा भूमि को कटाव या उस पर रेत, कंकड़ या पत्थरों के जमा होने के विरुद्ध संरक्षण के लिए, आवश्यक प्रतीत हो ;
- (झ) स्थान नियत करना जहां इमारती लकड़ी या किसी भी प्रकार की लकड़ी का चूड़ा लगाया जा सकता है, और वह रीति, यथास्थिति, जिसमें ऐसी इमारती लकड़ी या लकड़ी का चूड़ा लगाया जाएगा, जहां नगरपालिका को, आग या अन्य खारे या जनता को होने वाली नुस्खीर असुविधा या भूमि के सखलन या भूमि की मरहू पर अन्य हानिकारक गड़बड़ के रोध्याम के लिए आवश्यक प्रतीत हो ;
- (ञ) उन व्यक्तियों के लिए जो नगरपालिका के लिए कुली के रूप में कार्य करते हैं —
- (i) उन व्यक्तियों के लिए माल ले जाने के लिए कुली के रूप में कार्य कर रहे हैं ;
- (ii) उन पशुओं या वाहनों के लिए जो दिन या उनके भाग के लिए किराये पर दिए जाते हैं ; और
- (iii) वाहनों को धकेलने या बहन करने वाले व्यक्तियों के लिए ;
- (न) ऐसी अनुज्ञप्तियों के लिए फीस नियत करने के लिए, जो इस धारा में निर्दिष्ट है, और वे शर्तें जिन पर ऐसी अनुज्ञप्तियां स्वीकृत और प्रतिसंहत की जा सकती हैं ।

स्वीकृत के
विना
निर्माण का
प्रतिषेध ।

203. (1) कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की स्वीकृत के बिना किसी निर्माण का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण, अथवा परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण का आरम्भ, नहीं करेगा ।
(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी निर्माण का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण करता चाहता है, नगरपालिका को ऐसे आशय का लिखित नोटिस देगा ।

(3) नगरपालिका उप-विधियों द्वारा —

(क) ऐसी रीति विहित करेगी, जिसमें किसी निर्माण के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण करने के आशय का नोटिस नगरपालिका को दिया जाएगा;

(ख) अपेक्षा करेगी कि ऐसे प्रत्येक नोटिस के साथ उस भूमि का, जिस पर ऐसे निर्माण का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण किया जाता आशयित है, स्थल रेखांक और ऐसे स्वरूप के निर्माण का रेखांक और विनिर्देश तथा ऐसे व्यंश प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनकी उप विधि द्वारा अपेक्षा की जाए;

परन्तु ऐसा प्रत्येक रेखांक और विनिर्देश अर्न्तःप्राप्त संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा मध्यक रूप में हस्ताक्षरित होगा जो इस प्रयोजन के लिए नगरपालिका में रजिस्ट्रीकृत होगा।

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए पद "अर्न्तःप्राप्त संरचनात्मक इंजीनियर" में स्थानिक (मिविल) इंजीनियर शामिल है।

(ग) जहाँ निर्माण की आवश्यकता के रूप में प्रयुक्त किए जाने की संभावना प्रतीत होती है वहाँ, उसके सम्बन्ध में पर्याप्त आवाज सुविधा की व्यवस्था की अपेक्षा करेगी;

परन्तु राज्य सरकार स्वयं अथवा किसी नगरपालिका के अभ्यावेदन पर, उप-विधियों में इन प्रकार परिवर्तन, अथवा उत्पत्ति कर सकती है, जिनमें उप-विधियों किसी नगरपालिका की विशिष्ट आवश्यकताओं के उपयुक्त हो सकें।

(4) जहाँ इस धारा के अर्थात् उप-विधियाँ बनाई गई हैं, वहाँ उप-धारा (2) के अधीन कोई भी नोटिस तब तक विधिमान्य नहीं समझा जाएगा, जब तक, ऐसी उप-विधियाँ द्वारा अपेक्षित सचना, यदि कोई हो, नगरपालिका की समाधानप्रद रूप में प्रस्तुत नहीं कर दी गई है।

204. (1) नगरपालिका, यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, नगरपालिका क्षेत्र या उसके भाग के भीतर किसी निर्माण के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण के करने में निम्नलिखित को विनियमित करने के लिए उप-विधियाँ बना करेगी—

(क) बाह्य तथा मध्य दीवारों, छतों, फर्शों, सीढ़ियों, लिफ्टों, अंगीठियों और चिमनियों के लिए प्रयोज्य सामग्री तथा ननिर्माण की पद्धति;

(ख) अंगीठियों, चिमनियों, नालियों, शौचालयों, जल सील शौचालयों, शौचगृहों, मृदाणियों और मलकुण्डों की गोमयी तथा ननिर्माण की पद्धति और उनकी स्थिति;

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "जल सील शौचालय" में शामिल है, न्यूनतम 20 गैलामीटर वाला जल सील शौचालय, जिसमें जल द्वारा मल मूल-अन्दर धकेल दिया जाता है या प्रवाहित कर दिया जाता है और जिसे हाथ द्वारा हटाया जाना अपेक्षित नहीं है।

(ग) सब में ऊँची मंजिल के ऊपर, जिस पर मनुष्यों को रहना है या भोजन बनाना है, छत की ऊँचाई और ढाल;

(घ) वायु के अवरोध संचरण को सुनिश्चित करने के लिए संवातन तथा निर्माण के चारों ओर छोड़ी जाने वाली जगह तथा अग्नि निवारण;

(ङ) अन्नभाग की रक्षा, जहाँ निर्माण मांस के साथ लगता है;

(च) ऐसी मंजिलों की संख्या और ऊँचाई, जिनकी मंजिलों का निर्माण होना चाहिए;

(छ) आग लगने की दवा में निर्माण से बाहर जाने के लिए दूनाएँ जाने वाले मध्यन;

नगरपालिका की निर्माणों के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण के सम्बन्ध में उप-विधियाँ बनाने की शक्ति।

- (ज) पक्कीय विद्युत में अधिक खर्चा के भण्डारण के लिए अस्थायी गोदामों को मराने योग्य बनाने के उद्देश्य से उनके निर्माण में प्रयोज्य सामग्री और सन्निर्माण की पद्धति ;
- (झ) रहने के कमरों या सोने के कमरों के रूप में प्रयोग के लिए अस्थायी कमरों की न्यूनतम लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई ;
- (ञ) कमरों का संवातन तथा दरवाजों और खिड़कियों की न्यूनतम लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई ;
- (ट) किसी निर्माण की किसी बाह्य दीवार की, बहिर्मुख से परे परिशिष्ट भागों की स्थािति तथा लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई ;
- (ठ) कारखाना चिमनियों की ऊंचाई तथा किसी कारखाने की किसी अंगोठी या भट्टी में प्रयुक्त ज्वलनशील पदार्थ से उत्पन्न होने वाले धूम्र का समाप्ति के लिए की जाने वाली व्यवस्था ।

(2) धारा 208 में किसी धान के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन बनाई गई किसी उप-विधि के उल्लंघन में किसी निर्माण का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण नहीं करेगा ।

निर्माण-
स्कीम ।

205. (1) कोई नगरपालिका, निम्न स्कीम क्षेत्रों के लिए कोई निर्माण और अर्निमित क्षेत्रों के लिए नगर-योजना संबंधी स्कीम तैयार करेगी, और यदि उपायुक्त द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो वह ऐसे अवेक्षा पत्र की भारीख में छः मास के भीतर ऐसी स्कीम तैयार करेगी जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकता है, अर्थात् :—

- (अ) सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र या उनके किसी भाग में निर्माणों के किसी वर्ग के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण का और उस उपयोग का, जिस के लिए उन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है, निबंधन ;
- (ब) किसी विद्यमान या प्रस्थापित मार्ग के किसी एक ओर या दोनों ओर किसी निर्माण रेखा का निर्धारण ;
- (ग) किसी ऐसे अर्निमित क्षेत्र में भूमि या ऐसा भाग, जो नगरपालिका को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, जिस में सार्वजनिक मार्गों के रूप में प्रयोग सम्मिलित है, भूस्वामियों द्वारा या तो प्रतिस्पर्ध के संदाय पर या अन्यथा अन्तर्गत किया जाएगा, परन्तु इन प्रकार अन्तर्गत कुल भाग किसी अर्निमित क्षेत्र के भीतर किसी एक स्वामी की भूमि के कालोम प्रतिगत से अधिक नहीं होगा और संदाय के बिना अन्तर्गत भाग पञ्चमीप्रतिगत से अधिक नहीं होगा ;
- (घ) किसी पुनर्गठित भूखण्ड के भाग तथा आकार का अवधारण, जिस से उसे निर्माण के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त बनाया जा सके और जहाँ भूखण्ड पर पहले ही निर्माण हो चुका है, वहाँ यह सुनिश्चित करना कि निर्माण के सम्बन्ध में, यथासम्भव, खुले स्थानों के द्वारे में स्कीम के उपबन्धों का अनुपालन किया जाता है ;
- (ङ) किसी मूल भूखण्ड की सीमाओं के परिवर्तन द्वारा पुनर्गठित भूखण्ड बनाना ;
- (च) संलग्न भूमियों के पूर्णतः या अंशतः अन्तर्गण द्वारा पुनर्गठित भूखण्ड बनाना ;
- (छ) स्कीम को बढ़ावा देने के लिए किसी वेबसाइट स्वामी को भूखण्ड का आवंटन ;

- (ज) किसी भूखण्ड के स्वामित्व का एक व्यक्ति या किसी दूसरे व्यक्ति का अधिग्रहण ;
- (झ) आन्तरिक सेवाओं के विवरण, उनकी व्यवस्था का प्रावधान करने, खर्चों के मद्दाय के संबंध में निर्माण तथा भूमियों के स्वामियों के दायित्व का परिणाम तथा खर्चों के संदाय की रीति ।

संश्लेषण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

- (1) "पुनर्गठित भूखण्ड" में अधिभूत होगा, कोई ऐसा भूखण्ड, जो नगरयोजना संबंधी कोई स्कीम बनाने के परिणाम स्वरूप स्वामित्व में या अन्यथा परिवर्तित किया जाता है ;
- (2) "आन्तरिक सेवाओं" में अधिभूत होगा,—
 - (i) सड़कों का पक्का करना तथा पटरियों पर खड़ेजा लगाना ;
 - (ii) खुले स्थानों पर घास तथा वृक्ष लगाना ;
 - (iii) मार्गों पर प्रदीप व्यवस्था ;
 - (iv) पर्याप्त और स्वास्थ्यप्रद जल-प्रदाय ;
 - (v) बरसाती तथा गन्दे पानी के लिये सवप्रणाल्य तथा नालियाँ तथा उनके उपयोग और व्ययन के लिए आवश्यक व्यवस्था ;
 - (vi) कोई अन्य संक्रम, जिस नगरपालिका, स्कीम में सम्मिलित क्षेत्र के विभाग के लिए आवश्यक समझे ।

(2) जब उप-धारा (1) के उपबन्धों के अधीन कोई स्कीम तैयार की गई है, तो नगरपालिका ऐसी स्कीम या आर्बजमिन नोटिस देगी और उसी समय ऐसे नोटिस की तारीख से कम से कम तीस दिन बाद की ऐसी तारीख या प्रकाशन करेगी जिस तक कोई व्यक्ति ऐसी स्कीम के संबंध में कोई ऐसा आक्षेप या सुझाव, जिसे वह देना चाहे नगरपालिका को निश्चित रूप में प्रस्तुत कर सकता है ।

(3) नगरपालिका स्कीम के संबंध में ऐसे प्रत्येक आक्षेप और सुझाव पर विचार करेगी, जो उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन प्रकाशित तारीख तक प्राप्त हो और वह ऐसे किसी आक्षेप या सुझाव के फलस्वरूप स्कीम को उपांतरित कर सकती है और तब मूलरूप में तैयार की गई या तथा उपांतरित ऐसी स्कीम उपायुक्त को भेजेगी जो, यदि उचित समझे तो उसे नगरपालिका को विनिर्दिष्ट तारीख तक पुनर्विचारण और पुनः प्रस्तुतीकरण के लिए लौटा सकता है, और उपायुक्त, यथास्थिति, भेज गए अथवा पुनः प्रस्तुत स्कीमों को अपनी राय सहित, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जो ऐसी स्कीम को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है अथवा इसे नगरपालिका को इस निर्देश के साथ लौटा सकती है कि वह उस पर पुनर्विचार करके किसी विनिर्दिष्ट तारीख तक पुनः प्रस्तुत करे ।

(4) यदि कोई नगरपालिका, उप-धारा (1) के अधीन कोई स्कीम प्रस्तुत करने की अपेक्षा किये जाने के छः मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहती है अथवा जब उसमें उप-धारा (3) के अधीन ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, किसी स्कीम को विनिर्दिष्ट तारीख तक पुनः प्रस्तुत करने में असफल रहती है या कोई ऐसी स्कीम पुनः प्रस्तुत करती है जो राज्य

भरदार द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती तो उपायुक्त कोई स्कीम बना सकता है, जिसका मार्केजिक नोटिस अधिसूचना द्वारा और नगरपालिका क्षेत्र के भीतर प्रकाशन द्वारा ऐसी तारीख की प्रज्ञापना सहित दिया जाएगा, जिस तारीख कोई व्यक्ति उपायुक्त को कोई आक्षेप या मुद्दा, जो वह देना चाहे, लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है और उपायुक्त ऐसे किसी आक्षेप या मुद्दा को अपनी राय सहित, राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार मूल रूप में यथा अधिसूचित या किसी ऐसे आक्षेप या मुद्दा के परिणामस्वरूप ऐसे उपोत्तरित, जैसे राज्य सरकार ठीक समझे, ऐसी स्कीम को स्वीकृत कर सकती है, और ऐसी स्कीम का धर्चा या पत्र का ऐसा भाग, जो राज्य सरकार ठीक समझे, नगरपालिका निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) किसी स्कीम को स्वीकृत करते समय, राज्य सरकार, स्कीम की प्रगति के संबंध में उपायुक्त या सरकार को नियतकालिक रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण के लिये और राज्य सरकार द्वारा स्कीम के निरीक्षण तथा परीक्षण के लिये लगे अधिरोपित कर सकती है।

(4) स्कीम के स्वीकृत हो जाने से पश्चात् नगरपालिका आंतरिक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही करेगी और स्कीम स्वीकृत होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर उभय पूर्ण करेगी।

सन्निवृत्त
निर्माणों का
नियमित
करण।

206. (1) धारा 205 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार लोकहित में, किसी भी क्षेत्र में निर्माणों को निर्माण कर नक़्शों चाहें उनका सन्निर्माण मंजूरी सहित या मंजूरी रहित किया गया हो और जिनके बारे में कोई निर्माण स्कीम या नगर योजना स्कीम स्वीकृत नहीं की गई हो।

(2) नगरपालिका उप-धारा (1) के अधीन आए क्षेत्र के लिए निर्माणों और प्लाटों के स्वामियों को धारा 205 की उप-धारा (1) में परापूर्वभाषित आंतरिक, सेवाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी और ऐसी सेवाओं से व्यवस्था के लिए धारा 70 के उपबंधों के अनुसार फॉन अधिरोपित करेगी।

धारा 205
के अधीन
निर्माण
स्कीम को
स्वीकृत कर
निर्माण के
परिनिर्माण
या पुनः
परिनिर्माण
के लिए
दंड।

207. यदि धारा 205 के अधीन स्वीकृत किसी स्कीम के उपबंधों के अधीन किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये, निर्माणों का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण प्रतिषिद्ध किया जाता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति, जो ऐसी स्कीम को स्वीकृत होने के पश्चात् किसी निर्माण का ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, जब तक वह स्कीम को स्वीकृत होने से पूर्व इस प्रयोजन के लिये उपयोग में नहीं लाया जाता था, दोषनिष्ठि पर, जुर्माने का दायी होगा, जो कम से कम एक सौ रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये होगा, और यदि ऐसी दोषनिष्ठि के पश्चात् वह ऐसे निर्माण का ऐसे प्रयोजन के लिये उपयोग करता रहता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिनके दौरान उपयोग होता रहता है, पचास रुपये के अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा।

निर्माणों के
परिनिर्माण
या पुनः
परिनिर्माण
के स्वीकृत
अस्वीकृत

208. (1) नगरपालिका धारा 294 की उप-धारा (1) के अधीन बनाई गई किसी उप-विधि के अन्वय में, या धारा 205 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन स्वीकृत किसी स्कीम के अन्वय में, किसी निर्माण के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण को स्वीकृत करने में इस्तेमाल करेगी जब तक किसी ऐसी स्कीम के अन्वय में किसी निर्माण के परिनिर्माण का स्वीकृत नवा किसी निर्माण के पीछे हटाने के लिए धारा 186 द्वारा परापूर्वभाषित प्रतिकर मंदाय करने की नगरपालिका की प्रथममर्त्या के कारण आवश्यक न हो।

प्रत्यापना है, नगरपालिका को नहीं है या उनमें निहित नहीं है, स्वीकृत हुआ अनुरोध प्राप्त, 1994

(2) जब, नगरपालिका को राय में, किसी निर्माण के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण से, धारा 205 के प्रवीन प्रस्थापित किसी स्कीम का लागू करने में बाधा पड़ने की सम्भावना है, तो नगरपालिका स्वीकृति देने से इन्कार कर सकती है, और ऐसी दशा में ऐसी इकाई और उनके कारण, आवेदन को उमक आवेदन की प्राप्ति भाठ दिन के भीतर निश्चित रूप में पूर्ण करेगी और आवेदन नगरपालिका निश्चित नोटिस द्वारा नगरपालिका से यह प्रस्ताव कर सकता है कि वह प्रस्थापित स्कीम गणसम्भव बोध गति से तैयार करे के लिए प्रयत्न करे। यदि, नगरपालिका द्वारा उपर विनिर्दिष्ट गति के भीतर इन्कार आवेदन नहीं किया गया है या यदि इन्तरे पूर्व निर्दिष्ट आवेदन की निश्चित नोटिस के परिधान की मांग में बारह मास के भीतर प्रस्थापित स्कीम का राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्ति नहीं हुई है तो भी आवेदन स्वीकृत किया गया सम्झा जाएगा :

परन्तु यदि ऐसी स्वीकृति देने से इन्कार करने वाला कोई भी नगरपालिका धारा 263 के प्रवीन निश्चित किया जाए तो ऊपर विहित अधि धारा 266 के प्रवीन निर्देश या उपाय द्वारा अंतिम आवेदन की संसूचना की तारीख से पुनः गारम्भ होगी।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रवीन कोई स्कीम, यदि नगरपालिका को इनकी नैयारी के लिये प्रस्तावित उपायों में बाधा हुआ है या यदि स्कीम का नैयार किया जाना नगरपालिका के विचारधाम है, प्रस्थापित सम्झा जाएगा।

(3) नगरपालिका, आवेदन को निश्चित रूप में सम्पन्नित लिये जाने वाले किसी ऐसे अन्य कारणवश, जिसे वह, ऐसे निर्माण को प्रभावित करने के लिये स्थापित और पर्याप्त सम्झती है, किसी निर्माण के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण की स्वीकृति देने से इन्कार कर सकती है या ऐसी स्वीकृति देने में उन्तका में भी इन्कार कर सकती है, यदि वह भूमि जिस पर ऐसे निर्माण का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण किया जाना प्रस्थापित है, सरकार या नगरपालिका में निहित है और, यथास्थिति, सम्बद्ध नगर या नगरपालिका की सम्मति प्राप्त नहीं हो गई है, या यदि भूमि का स्वत्व ऐसे व्यक्ति और नगरपालिका या किसी सरकार के बीच विवादाम्भ है।

(4) उप-धारा (1) के उपबन्धों के अध्वधीन, नगरपालिका किसी निर्माण के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण को या तो यात्वधिक रूप में यथवा उपनिधियों और नियमों के अनुसार ऐसे उपायों के अध्वधीन, जिन्हें वह उचित समझे, स्वीकृत कर सकती है।

(5) उप-धारा (1) या उप-धारा (3) में किसी बात के होने हुए भी, किन्तु धारा 204 की उप-धारा (2) और इन धारा की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अध्वधीन यदि, नगरपालिका किसी व्यक्ति से, किसी निर्माण के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण करने के ऐसे व्यक्ति के आग्रह के विधिमात्र नोटिस की प्राप्ति के भाठ दिन के भीतर या यदि नोटिस उसी स्वत या उनके भाग पर निर्माण से संबंधित है, जिन पर पूर्ववर्ती बारह मासों के भीतर किसी निर्माण के परिनिर्माण की स्वीकृति में इन्कार कर दिया गया है, तो एक भी बीर दिन के भीतर ऐसे परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण की स्वीकृति करे या स्वीकृति करने से इन्कार करने वाला आवेदन करने में प्रस्ताव या लगे करता है, तो ऐसा परिनिर्माण, या पुनः परिनिर्माण, जब तक वह भूमि, जिन पर ऐसे निर्माण के परिनिर्माण या पुनः निर्माण करने वाले की प्रस्थापना है, नगरपालिका की नहीं है या उनमें निहित नहीं है, स्वीकृत हुआ समझा जाएगा,

विचार नहीं कि जहाँ तक वह निजी उपविधि या धारा 205 के अधीन स्वीकृत किसी निर्माण या नगर योजना संबंधी स्कीम का सम्बन्ध करता है :

परन्तु यदि ऐसी स्वीकृति संसूचित करने वाला अथवा इन्कार करने वाला कोई संकल्प धारा 263 के अधीन निलम्बित किया जाए, तो इस उप-धारा द्वारा विहित प्रबंध, धारा 266 के अधीन निर्देश या उपायुक्त धारा अंतिम आदेश की संसूचना की तारीख से पुनः प्रारम्भ हो जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि उपस्थित सदस्यों की सख्या के पाँचवें भाग से अग्र्यून सदस्य, स्वीकृति संसूचित करने वाले किसी संकल्प के विरुद्ध मत देते हैं, तो स्वीकृति तब तक संसूचित की गई नहीं समझी जाएगी, जब तक संकल्प के पारित होने से चौदह दिन समाप्त न हो जाएँ ।

निर्माण को
स्वीकृत
रेखा में
निर्माण की
पूर्व होने
के पूर्व उप-
धारा नि-
र्देश करने
की नगर-
पालिका की
शक्ति ।

208. (1) निम्न क्षेत्र के लिए भवन स्कीम और अनिर्मित क्षेत्र के लिए नगर योजना स्कीम तैयार करने के प्रयोजन के लिए नगरपालिका और यदि सरकार द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, ऐसे प्रयोजन द्वारा संचालित नगरपालिका क्षेत्र का भू-विज्ञान सर्वेक्षण ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति में करवाएगी, जो विहित की जाए ।

(2) जहाँ भवन रेखांक मंजूर किया जाता है वहाँ वह व्यक्ति जिसके कहने पर भवन प्रचालन किया जाता है, नींव की खोदई के पश्चात् और वहाँ पर निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नींव की खोदई के बारे में नगरपालिका को सूचित करेगा ।

(3) यह सुनिश्चित करने के लिए जिस भूमि की परत जिस पर भवन का निर्माण किया जाना है, भू-विज्ञान की दृष्टि से उचित है और भवन प्रचालन मंजूर किए गए रेखांक के अनुसार किया जा सकता है, नगरपालिका उप-धारा (2) के अधीन प्राप्त सूचना से सात दिन के भीतर इस प्रकार और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, खोदई गई नींव का निरीक्षण करा सकती है :

परन्तु वह व्यक्ति जिनके कहने पर भवन प्रचालन किया गया है निरीक्षण में सह-योजित हो जाएगा ।

(4) उप-धारा (3) के अधीन निरीक्षण करने वाले व्यक्ति, उप-धारा (2) के अधीन जिस व्यक्ति से सूचना प्राप्त हुई है, उसको ऐसे निरीक्षण के परिणाम के बारे में अपने विचार संसूचित करेंगे और उक्त व्यक्ति को तब सुनिश्चित करने के पश्चात् ऐसे निरीक्षण के परिणाम पर, की जाने वाली कार्रवाई के बारे में उक्त व्यक्ति को लिफाफे करेंगे और नगरपालिका के कार्यपालक अधिकारी को भी, यदि कोई कार्रवाई जो ऐसी लिफाफे के माध्यम से प्रयोजन के लिए की जानी प्रस्तावित हो, रिपोर्ट करेंगे ।

(5) नगरपालिका उप-धारा (4) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर उप-धारा (2) के अधीन सूचना की तारीख से सात दिन के भीतर सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसा निर्देश देगी जो वह उचित समझे ।

(6) पूर्ववर्ती उप-धारा में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी समय धारा 208 के अधीन मंजूर किए गए भवन के निर्माण की पूर्णता से पूर्व नगरपालिका मंजूर किए गए भवन रेखांक में कोई उपांतरण प्रस्ताव आवश्यक समझती है तो वह

(ड) जब स्वीकृति समाप्त हो गई है ; या

(च) धारा 204 के अधीन बनाई गई किसी उप-विधि के उल्लंघन में या किसी ऐसे निर्माण की दशा में जिसका परिनिर्माण धारा 208 की उप-धारा (5) के अधीन स्वीकृति समाप्त गया है, यदि वह धारा 205 के अधीन स्वीकृति किसी स्कीम के उल्लंघन में ;

आरम्भ या परिनिर्मित किया जाए, तो नगरपालिका, निर्माण के पूरा होने से छः मास के भीतर स्वामी को परिदत्त नोटिस द्वारा निर्माण को ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परिवर्तित या भंजित करने की, जैसा वह आवश्यक समझे, अपेक्षा कर सकती है :

परन्तु नगरपालिका किसी निर्माण को भंजित या परिवर्तित कर मक़ेगी जहाँ तक यह धारा 205 के अधीन तैयार किए गए निर्माण स्कीम के उल्लंघन से बचने के लिए आवश्यक हो :

परन्तु यह और कि इन धारा के अधीन, यथास्थिति, कार्यपालक अधिकारी या सचिव द्वारा कोई नोटिस इन आधार पर जारी किया जाता है कि कोई निर्माण, दो गई किसी स्वीकृति के निबन्धनों के उल्लंघन में अथवा धारा 204 के अधीन बनाई गई किसी उप-विधि के उल्लंघन में आरम्भ अथवा परिनिर्मित किया गया है, तो वह व्यक्ति जिसे नोटिस जारी किया जाता है, ऐसे नोटिस की तामील से पन्द्रह दिन के भीतर नगरपालिका को अपील कर सकता है और नगरपालिका का विनिश्चय धारा 212, 263 तथा 269 के उपबन्धों के अध्याधीन अन्तिम होगा :

परन्तु यह और कि नगरपालिका के अन्तिम आदेश को प्रतिलिपि उसके लिए जाने के तुरन्त पश्चात् अपीलार्थी को मुफ्त दो जाएगी ।

(2) जहाँ निर्माण का स्वामी अपने स्थगित किए गए कार्य या उस द्वारा पूर्ण किए गए कार्य के संशोधित रेखांक प्रस्तुत करना है और मंजूर रेखांक से विचलन लघु प्रकृति के है, तो नगरपालिका उप-धारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश या धारा 11 के अध्याधीन विचचन के मामलों का प्रणयन कर सकती

महतीकरण.—इन उप-धारा के प्रयोजन के लिए "लघु प्रकृति" अभिव्यक्ति में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे:—

(क) स्वीकृत रेखांक से परे भूजल का परिवहन;

(ख) निर्माण का परिनिर्माण—

(i) किसी नगरपालिका भूमि या नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी में निहित भूमि ;

(ii) किसी लो. नदर, मर्ग, पथ या नाली को अःच्छादित करते हुए ।

(3) इस अधिनियम में अन्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार समय-समय पर स्वीकृति रेखांकों से विचलन अस्तव्यस्त करने वाले मामलों के प्रणयन से सम्बन्धित निति के विषयों में ऐसे विशेष या साधारण निदेश दे सकती, जैसे कि इसकी राय में इस धारा की उप-धारा (2) के अधीन ऐसे मामलों के प्रणयन के लिए नगरपालिका द्वारा अपनए जाने अपेक्षित हैं ।

(4) यदि भवन का स्वामी स्वीकृत प्लान (रेखांक) से परे किसी भूजल को बढ़ाने द्वारा किसी नगरपालिका भूमि या नगरपालिका में निहित भूमि पर भवन के निर्माण द्वारा, या

परन्तु जब तक ऐसे नोटिस के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्ष की या अधिक अवधि के लिए निर्माण निर्माणों अथवा संशुद्धि दंगा में होने के कारण मान्यता अथवा न के लिए अनुपयुक्त न हो गया हो अथवा जब तक धारा 120 के अधीन जारी किया गया कोई प्रतिबंध यादेश ऐसे निर्माण के बारे में प्रवृत्त रहा हो और प्रतीति प्रवृत्त हो, तब तक नगरपालिका स्वामी को उनके निर्माण या उसके किसी भाग को पोंछे हटाने के परिणामस्वरूप उभरे होने वाले किसी नुकसान के लिये पूरा प्रतिबद्ध रहेगा।

आइए तथा के वि- निर्माण, तैयारी और विक्रय को विनियमित करने की नगरपालिका की शक्ति।

214. नगरपालिका उप-विधियों द्वारा निम्नलिखित कर सकती और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, तो करेगी :—

- (क) नगरपालिका द्वारा अनुज्ञप्त किसी स्थान अथवा परिसर में ग्राह्य तथा पेय की किसी विनिर्मित वस्तुओं के विनिर्माण, विक्रय अथवा तैयारी या विक्रय के लिये खुला रखने का प्रतिबंध करना ;
- (ख) नगरपालिका क्षेत्र के भीतर ग्राह्य तथा पेय की किसी विनिर्मित वस्तुओं के परिवहन या समय तथा रीतिविनियमित करना तथा ऐसा मार्ग विहित करना जिन में होकर ऐसी वस्तुओं का वहन किया जाएगा ;
- (ग) नगरपालिका द्वारा अनुज्ञप्त व्यक्तिगत द्वारा दूध, मक्खन, घी, दही, मांस, शिफार का मांस, मछली अथवा कुकुर प्रदि के विक्रय का प्रतिबंध करना ;
- (घ) नगरपालिका द्वारा अनुज्ञप्त व्यक्तियों द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के भीतर विक्रय के लिये दूध, मक्खन, घी, दही, मांस, शिफार का मांस, मछली अथवा कुकुर आदि के अयात का प्रतिबंध करना ;
- (ङ) इस धारा के अधीन अनुज्ञप्तिदा देने तथा वापस लेने तथा उनके लिये फीसों के उद्ग्रहण को विनियमित करना ;

परन्तु कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे परिसर में, जो ऐसी उप-विधि बनाए जाने के समय विनिर्माण, निर्मित या विक्रय प्रदर्शन या विक्रय के प्रयोजन के लिये प्रयोग में लागू जते हैं, ऐसे विनिर्माण, निर्मित या विक्रय प्रदर्शन या विक्रय जारी रखने के कारण हो इस धारा के खण्ड (क) के अधीन बनाई गई किसी उप-विधि के अंग के लिये तब तक दण्डनीय नहीं होगा, जब तक उसने उस परिसर में ऐसा विनिर्माण, निर्मित, विक्रयार्थ, प्रदर्शन या विक्रय बन्द कर देने के लिये छः मास का लिखित नोटिस नगरपालिका से प्राप्त न किया हो :

परन्तु यह और कि इसमें की गई कोई भी बात हिमाचल प्रदेश में दया प्रवृत्त पंजाब विधि-अधिनियम, 1872 (1872 वा 4) की धारा 43 तथा तद्वर्धन बनाए गए नियमों के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी।

वन्ध जीव- जन्तुओं के कब्जे अथवा विक्रय का प्रतिबंध।

215. कोई भी वन्ध जीव- जन्तु, जिसने बारे में अन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 वा 8) की धारा 16 के प्रतीत राज्य सरकार द्वारा निषिद्ध अन्य अधिसूचित किया गया हो, किसी नगरपालिका क्षेत्र के भीतर ऐसे निषिद्ध अंग के दौरान मृत अथवा जीवित रूप में रखा अथवा बेचा नहीं जाएगा और ऐसे किसी भी जीव-जन्तु का नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी अन्य नगर पर विक्रय नगरपालिका द्वारा दी गई लिखित अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के बिना नहीं किया जाएगा :

परन्तु ये प्रतिबंध पालन रूप में रखे या बेचे जाने वाले वन्ध जीव-जन्तुओं को लागू नहीं होंगे।

उप-विधियों के अतिरिक्त के लिए नास्ति।

216. इस अध्याय की किसी धारा के अधीन कोई उप-विधि बनते हुए नगरपालिका निषिद्ध कर सकती है कि उसमें कोई अंग या उसके अंग का कोई दूषण जुमाने से दण्डनीय होगा, जो दो साल तक रहता है, और जब अंग चालू रखने वाला हो तो ऐसे अधिनियम जुमाने से दण्डनीय होगा, जो प्रत्येक अंग के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दण्ड के लिये, जिसके दौरान अंग चालू रहता है, दस रुपये होगा।

217. (1) इस अधिनियम की किसी धारा के अधीन बनाई गई उप-विधियाँ (यदि उप-विधियाँ नहीं होतीं) जब वे राज्य की संसद द्वारा अपनी पुष्टि प्राप्त करवा दी गई हो और जिस समय के लिए और ऐसी सीमा में प्राधिकार प्राप्त हो, जैसा कि राज्य के लिए उन विधियों में विहित करें।

उप-विधियों की पुष्टि।

(2) राज्य सरकार, ऐसी उप-विधियों की अपनी पुष्टि को रद्द कर सकेंगी और तदुपरि उप-विधियाँ प्रभावहीन हो जाएंगी।

218. (1) किसी भी ऐसी दशा में, जिन में नगरपालिका द्वारा धारा 202 अथवा धारा 203 अथवा धारा 204 अथवा धारा 214 के अधीन कोई उप-विधियाँ नहीं बनाई गई हैं तो राज्य सरकार उन प्रयोजन के लिये उप-विधियाँ बना सकेंगी।

उप-विधियाँ बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

(2) पूर्वोक्त उप-धाराओं के अधीन बनाई गई उप-विधियाँ इन दशा में प्रयत्न नहीं कर सकेंगी जब नगरपालिका उस निमित्त कोई उप-विधियाँ बना दे।

219. इस अधिनियम के अधीन बनाई गई सभी उप-विधियाँ पूर्व प्रमाणन के अधीन होंगी।

उप-विधियाँ बनाने के लिए प्रक्रिया।

220. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी नगरपालिका के लिए बनाई गई सभी उप-विधियों को एक प्रति नगरपालिका के कार्यालय में रखी जाएगी और कार्यालय समय के दौरान किसी निवासियों के निरीक्षण के लिये निष्प्रभार खुली रहेगी।

उप-विधियों का क्रय तथा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होता।

(2) ऐसी सभी उप-विधियों की प्रतियाँ अधिनियम के अधिकांश रूप में मूल्य पर सर्वसाधारण को विक्रय, नगरपालिका के कार्यालय में रखी जाएगी।

अध्याय-12

मिट्टी का कटाव और पहाड़ी पार्श्व सुरक्षा का निवारण

221. (1) कोई भी व्यक्ति, बिना प्राधिकारी द्वारा बिहित रीति से प्राप्त किए गए अनुज्ञापत्र के बिना, राज्य में किसी नगरपालिका की अधिकारिता के अंतर्गत बिहित बग के किसी वृक्ष को नहीं गिराएगा यदि वह उतना हो या अगल हो।

नगरपालिका परस्परिता को भीतर वृक्षों के गिराए जाने का निमित्त-यमन।

स्पष्टीकरण:— इस अध्याय के प्रयोजन के लिए पद "वृक्ष के गिराने" के अन्तर्गत वृक्ष का काटना, विनाश करना या काटने या विनाश को आरंभ करना या हानि पहुँचाना है किन्तु वस्तुतः काट-छाट, पतन या अन्यथा काटने या फल वृक्षों का केवल आगवानी के प्रयोजन के लिए और अन्य छोटें वृक्ष जैसे कि टहनियाँ या काटना, पतन या काटना और इन प्रकार के वृक्ष जिससे व्यक्ति या सम्पत्ति को इसके परिणाम-स्वरूप कोई तात्त्विक हानि न हो, इसके अन्तर्गत होंगे।

(2) वृक्ष गिराने के अनुज्ञापत्र की मंजूरी के लिए तब तक कोई आवेदन नहीं किया जाएगा जब तक उसके साथ 10 रुपये की फीस न लगाई हो। यह राशि नये रोपण के लिए उपयोग की जाएगी।

तो ऐसे निरीक्षण के प्रयोजन के लिये खुरवाया गया हो, क्षतिग्रस्त हुआ हो या हटाना गया हो, नगरपालिका द्वारा भरा जायेगा, पुनः स्थापित किया जायेगा और हानि पूरी की जायेगी।

(3) इस धारा के अधीन गाँवपाल, मूत्रालय अथवा गाँवपाल के अधिकारी या निर्माण में तब तक प्रवेश नहीं किया जायेगा, जब तक नगरपालिका द्वारा अथवा नगरपालिका द्वारा प्रवेश करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्माण के अधिभोगी को छः घंटे का नोटिस नहीं दे दिया गया है।

223. (1) यथास्थिति, नगरपालिका अथवा कार्यपालक अधिकारी या सचिव, निर्माण के अधिभोगी, अथवा यदि कोई अधिभोगी न हो तो उसके स्वामी को तीन घंटे का नोटिस देने के पश्चात् सूचोदय और सूचोदय के बीच किसी व्यक्ति को प्रवेश तथा निरीक्षण के लिए जहाँ ऐसा निरीक्षण स्वच्छता के कारणों के लिये आवश्यक प्रतीत हो, प्राधिकृत कर सकता है।

निर्माणां
आदि का
निरीक्षण।

(2) यदि निरीक्षण किया जाने वाला निर्माण घाँड़ों या अस्तरवत् अथवा गाँवों या अन्य पशुओं के लिये कोई गृह या आश्रय है तो निरीक्षण करने से पहले नोटिस को अपेक्षा नहीं होगी।

224. नगरपालिका अथवा कार्यपालक अधिकारी या सचिव, किसी निर्माण या भूमि के अधिभोगी को, अथवा यदि कोई अधिभोगी न हो तो स्वामी को, चौबीस घंटे का नोटिस देने के पश्चात् किसी व्यक्ति को सूचोदय और सूचोदय के बीच किसी भी समय, निम्नलिखित के लिये प्राधिकृत कर सकता है:—

निर्माणां या
भूमियों पर
प्रवेश की
अन्य
शक्तियाँ।

(क) किन्हीं निर्माणों अथवा किसी भूमि पर प्रवेश तथा सर्वेक्षण करना अथवा उनका तल मापना अथवा माप लेना ;

(ख) किसी निर्माण में या किसी भूमि पर सम्पत्तिनिष्ठ संक्रमों का परीक्षण, मूल-प्रणालियों का, नलियों के मार्ग का अभिनियन्त्रण करना अथवा किसी ऐसे संक्रम या किसी अभिनियम द्वारा नियन्त्रित करने या अनुमति देने के लिये दृढ़ भक्षण है, नियन्त्रित अथवा मरम्मत के प्रयोजन के लिये, प्रवेश करना ;

(ग) किसी निर्माण में या किसी भूमि पर, गैर, जल, टैलीफोन, विद्युत सम्बन्धी अथवा अन्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण अथवा मरम्मत के प्रयोजन के लिये और उनसे सम्बन्धित मोटरों के वाहन के प्रयोजन के लिये, प्रवेश करना ;

(घ) निर्माण में या किसी भूमि पर, दृढ़ अभिनियन्त्रित करने के प्रयोजन के लिये कि क्या कोई निर्माण स्वीकृति के बिना या नगरपालिका या कार्यपालक अधिकारी या सचिव द्वारा दी गई किसी स्वीकृति के उल्लंघन में या धारा 204 के अधीन बनाई गई किसी उपविधि अथवा धारा 205 के अधीन स्वीकृत निर्माता के उल्लंघन में परिनिर्मित या पुनःपरिनिर्मित किया गया है या किया जा रहा है और ऐसे माप लेने तथा किन्हीं ऐसे अन्य कार्यों के करने के लिये, जो ऐसे प्रयोजन के लिये आवश्यक हैं, प्रवेश करना।

बाध तथा पेय आदि के विक्रय के स्थानों के निरीक्षण तथा विक्रय के लिए खुली रखी गई अस्वास्थ्यप्रद वस्तुओं के अभिग्रहण की शक्ति।

225. यथास्थिति, नगरपालिका अथवा कार्यपालक अधिकारी या सचिव किसी व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी मण्डी, निर्माण, दुकान, स्टाल या मनुष्य के लिये खाद्य या पेय के विक्रय के लिये या वधशाला के रूप में या औषधियों के विक्रय के लिये प्रयुक्त स्थान में प्रवेश तथा निरीक्षण के लिये और किसी खाद्य अथवा पेय, जीव-जन्तु अथवा औषधि का, जो उनमें हों, निरीक्षण अथवा परीक्षा करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है, और यदि उसमें मानव उपभोग के लिये आशयित कोई खाद्य या पेय की कोई वस्तु अथवा कोई जीव-जन्तु अनुपयुक्त प्रतीत होता है, तो उसे अभिगृहीत कर सकता है तथा हटवा सकता है अथवा उसे ऐसी रीति में नष्ट करवा सकता है या उसका व्ययन करवा सकता है कि उसे विक्रय के लिये खुला रखना अथवा ऐसे उपभोग के लिये प्रयुक्त किया जाना निवारित हो सके, और उस दशा में जिसमें यह युक्तियुक्त संदेह किया गया हो कि कोई औषधि ऐसी रीति में अप्रामिथित की गई है कि उसकी प्रभावकारिता कम हो गई है, उसके प्रभाव में परिवर्तन हो गया है या वह हानिकारक हो गई है तो उसकी रसद देकर उसे हटाने और उसके स्वामी को इस बात की जांच के लिये कि क्या उसके बारे में कोई अपराध किया गया है तथा उक्त औषधि के व्ययन के बारे में आदेश के लिये मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराने के लिये प्राधिकृत कर सकता है।

पशुओं के अर्बुद वध के स्थानों का निरीक्षण।

226. यदि यह विश्वास करने के लिये युक्तियुक्त आधार है कि किसी पशु का वध, किसी ऐसे स्थान या परिसर में, जो धारा 172 के अधीन ऐसे प्रयोजन के लिये नियत नहीं किया गया है अथवा धारा 202 के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (1) के अधीन बनाई गई किसी उप-विधि के उल्लंघन में किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, तो नगरपालिका या कार्यपालक अधिकारी अथवा सचिव या इन में से किसी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी स्थान या परिसर में प्रवेश तथा निरीक्षण कर सकता है :

परन्तु इस धारा के उपबन्धों के अधीन अग्र्यतः अथवा स्वास्थ्य अधिकारी के लिखित आदेश के बिना कोई भी प्रवेश नहीं किया जायेगा। ऐसे आदेश में प्रवेश किये जाने वाला स्थान या परिसर तथा परिक्षेत्र, जिसमें वह स्थित है और अवधि, जो सात दिन से अधिक नहीं होगी, जिसके लिये यह प्रवृत्त रहना है, विनिश्चित होगी।

निरीक्षण कराने में इन्कार।

227. कोई भी व्यक्ति, जो धारा 224 या धारा 225 या धारा 226 या धारा 229 के उल्लंघन में किसी परिसर, खाद्य, पेय, औषधि या जीव-जन्तुओं का निरीक्षण कराने से इन्कार करता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पचीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

प्राधिकृत मात्ता से अधिक ज्वलनशील अथवा विस्फोटक सामग्रों की तलाशी।

228. (1) नगरपालिका अथवा कार्यपालक अधिकारी या सचिव किसी व्यक्ति को, किसी भी युक्तियुक्त समय पर किसी ऐसे गृह अथवा निर्माण में, जिसके बारे में इस अभिनियम अथवा तदधीन बनाये गये या प्रकाशित किये गये किसी नियम, उप-विधि अथवा सार्वजनिक सूचना के उपबन्धों के अधीन ऐसे गृह अथवा निर्माण में पेट्रोलियम, विस्फोटक अथवा अन्य ज्वलनशील सामग्रों रखने के लिये अनुज्ञात मात्ता से आधिक्य में रखने का संदेह है, प्रवेश तथा निरीक्षण करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है।

(2) यदि ऐसी सामग्री की कोई ऐसी अधिक मात्ता पाई जाये, तो वह ऐसे आदेश के अर्धधीन, जो मजिस्ट्रेट इन सम्बन्ध में करे, अभिगृहीत तथा धारित की जा सकती है।

(3) यदि मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि अभिगृहीत सामग्री इस अभिनियम अथवा तदधीन बनाये गये या प्रकाशित किये गये किसी नियम, उप-विधि अथवा सार्वजनिक

सूचना के उपबन्धों के प्रतिकूल उस गृह अथवा निर्माण में रखी गई बा, तो वह उसे अधिकृत करने वाला कोई आदेश करेगा।

(4) तत्समय अधिभूत मामलों को लागू किन्हीं साधारण नियमों के अध्वधीन ऐसी मामलों मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा विक्रय की जा सकती है और आगम ऐम विक्रय के खर्च चुकाने के पश्चात् नगरपालिका निधि में जमा कर दिये जायेंगे।

(5) इस धारा के अधीन अधिहरण का कोई भी आदेश किसी ऐसे अन्य दांडिक या मित्रन कार्यवाही को रोकने के लिये लागू नहीं होगा, जिसके लिए अनुज्ञान से अधिक मात्रा में मामलों का भण्डार करने वाला व्यक्ति दायी हो।

229. (1) स्वास्थ्य अधिकारी अथवा नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी किसी भी समय, तीन घण्टे का नोटिस देने के पश्चात् किसी निर्माण अथवा परिसर में जहां किसी संक्रामक रोग के होने के बारे में रिपोर्ट की जाती है या उसके होने का संदेह है, ऐसे निर्माण या परिसर का निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिये प्रवेश कर सकता है।

(2) ऐसा कोई भी निरीक्षण सूर्यास्त और सूर्यास्त के बीच के समय के निवाय नहीं किया जायेगा।

230. यथास्थिति, नगरपालिका अथवा कार्यपालक अधिकारी या सचिव इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं द्वारा प्रदत्त प्रवेश की शक्तियों का या तो साधारणतः सभी निर्माणों तथा भूमियों के सम्बन्ध में अथवा विशिष्ट तथा विनिर्दिष्ट निर्माणों तथा भूमियों या निर्माणों तथा भूमियों के वर्गों के सम्बन्ध में प्रयोग करने के लिये व्यक्तियों को प्राधिकृत कर सकता है।

231. जब मानव निवास के रूप में प्रयुक्त किसी निर्माण में इस अधिनियम के अधीन प्रवेश किया जाता है, तो अधिभागियों को सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं का सम्बन्ध ध्यान रखा जाएगा, और इससे पूर्व कि इस अधिनियम के अधीन किसी स्त्री के वस्तुतः अधिभाग में किसी कक्ष में प्रवेश किया जाये, जो रुद्धि के अनुसार जनसाधारण के समक्ष नहीं आती, तो उसे नोटिस दिया जायेगा कि उस वहां में निकलने की स्वतन्त्रता है और उसे वहां से निकलने के लिये युक्तियुक्त सुविधा दी जायेगी।

232. जब इस अधिनियम के अधीन किसी नोटिस में किसी ऐसे कार्य के किये जाने की अपेक्षा की जाती है, जिसके लिये इस अधिनियम द्वारा कोई भी समय नियत नहीं है, तो उस में उसे करने के लिए कोई युक्तियुक्त समय नियत किया जाएगा।

233. (1) इस अधिनियम के अधीन अथवा किसी नियम या उप-विधि के अधीन समिति द्वारा जारी किया गया प्रत्येक नोटिस लिखित रूप में होगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव द्वारा अथवा नगरपालिका द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्टतः प्राधिकृत किसी उप-समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और ऐसे प्रत्येक नोटिस तथा धारा 208 के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश की उस व्यक्ति पर, जिसे वह सम्बंधित किया गया है, तामील की जा सकती है, अथवा वह उस के निवास या कारबार के सामान्य स्थान पर उस को बुद्धिमान के किसी व्यक्ति गुरु सदस्य या नौकर को परिदत्त किया जा सकता है, अथवा बहा छिपा जा सकता है, या यदि उसकी इस रीति में तामील नहीं की जा सकती है तो वह उसके निवास या कारबार के स्थान में किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकाया जा सकता है।

वामारी फलने से रोकने के प्रयोजन के लिए प्रवेश को शक्ति।

शक्तियों का प्राधिकरण।

निवासों में प्रवेश के लिए अनुपालनीय प्रावधान-निवा।

अनुपालन के लिए युक्तियुक्त समय नियत करना।

नोटिसों का अधिप्रमाणन, एवकीतामील तथा विधि-मायता।

(2) जब ऐसे व्यक्ति का, जिस को नोटिस सम्बोधित किया जाता है, निवास या कारबार का स्थान नगरपालिका क्षेत्र के भीतर नहीं है, तो नोटिस की तामील उनके प्राथमिक निवास को संबोधित रजिस्ट्री पत्र भेज कर की जा सकती है।

(3) यदि किसी सम्पत्ति के स्वामी का निवास या कारबार का स्थान नगरपालिका क्षेत्र के भीतर नहीं है, तो उसको ऐसे स्वामी की हैमियत में सम्बोधित ऐसे प्रत्येक नोटिस की तामील अधिभोगी पर की जा सकती है।

(4) जब किसी सम्पत्ति के अधिभोगी के निवास या कारबार का स्थान ज्ञात नहीं है, तो ऐसे अधिभोगी की हैमियत में उसको सम्बोधित प्रत्येक ऐसे नोटिस की तामील सम्पत्ति के किसी सहजदृष्य स्थान पर उसको चिपका कर की जा सकती है।

(5) इस अधिनियम या किसी नियम अथवा उप-विधि के अधीन नगरपालिका द्वारा जारी किया गया कोई भी नोटिस प्रकृष्ट में त्रुटि के कारण अधिविधमान्य नहीं होगा।

तामोल
जब स्वामी
तथा अधि-
भोगी भिन्न-
भिन्न
व्यक्ति हैं।

234. जब कभी इस अधिनियम द्वारा यह उपबन्धित किया गया है कि किसी भूमि अथवा निर्माण के स्वामी या अधिभोगी को कोई नोटिस दिया जाये और स्वामी तथा अधिभोगी भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं, तो ऐसा नोटिस उनमें से ऐसे व्यक्ति को दिया जायेगा, जो ऐसे नोटिस का अनुपालन करने के लिये प्राथमिकतया दायी हो, और संदेह की दशा में दोनों को दिया जायेगा।

परन्तु किसी ऐसे मामले में, जहाँ कोई भी स्वामी नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निवासी नहीं है, वहाँ ऐसे नोटिस का अधिभोगी को दिया जाना ही पर्याप्त होगा।

सम्पत्ति के
स्वामी अथवा
अधिभोगी
को नोटिस
देने का ढंग।

235. जब इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी सम्पत्ति के अधिभोगी या स्वामी को कोई नोटिस दिया जाना है अथवा उसकी तामील कराई जानी है, और यह अज्ञात है, तो नोटिस निम्नलिखित रूप में दिया जा सकता है—

(क) सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति को कोई लिखित नोटिस परिदत्त करके अथवा, यदि सम्पत्ति पर कोई व्यक्ति न हो जिसे यह दिया जा सके, तो उसे सम्पत्ति के किसी सहजदृष्य भाग पर चिपका कर; अथवा

(ख) उस सम्पत्ति का, जिन के बारे में नोटिस दिया जाता है, नाम देते तथा लिखित नोटिस को अतर्विष्ट करते हुए, एक पूर्व संदत्त पत्र डाक से भेजकर, जो सम्पत्ति के "स्वामी या अधिभोगी" को उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में उसके विवरण के अनुसार सम्बोधित किया जायगा। ऐसी दशा में उस व्यक्ति का नाम और विवरण देना आवश्यक नहीं होगा।

सार्वजनिक
नोटिसों का
प्रकाशन।

236. इस अधिनियम अथवा नियम या उप-विधि के अधीन किसी समिति द्वारा दिया गया प्रत्येक सार्वजनिक नोटिस, उद्घोषणा द्वारा या ऐसी अन्य रीति में प्रकाशित किया जायेगा, जो राज्य सरकार, नियम द्वारा निर्दिष्ट करे।

नगरपालि-
काओं के
आदेशों की
अवज्ञा का
निष्काशित।

237. कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका द्वारा, सार्वजनिक नोटिस द्वारा क्रिय गय किसी विधिपूर्ण निदेश अथवा प्रतिपेक्षादेश की, अथवा तदधीन उसके द्वारा विधि-पूर्णतः जारी क्रिय गय किसी लिखित नोटिस की अवज्ञा करता है, अथवा उन शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है, जिनके अधधीन नगरपालिका द्वारा उक्त उन शक्तियों के अधीन कोई अज्ञात की गई थी, और अवज्ञा अथवा लोप किसी अन्य द्वारा के अधीन

दण्डनीय कोई अपराध नहीं है तो, जुमाने में दण्डनीय होगा, जो कम से कम पक्कीन रुपये तथा अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा, तथा चालू रहने वाले भंग की दशा में ऐसे अनिश्चित जुमाने में दण्डनीय होगा जो प्रथम भंग के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके दौरान भंग चालू रहता है, दस रुपये होगा।

238. इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य या लोप के कारण किसी अपराध के लिये मिददोष प्रत्येक व्यक्ति किसी ऐसे दण्ड के होने हुए भी, जिससे वह ऐसे अपराध के लिये दण्डित किया गया हो, ऐसे किसी नुकसान के लिये, जो ऐसे कार्य या लोप के परिणामस्वरूप नगरपालिका को किसी सम्पत्ति को हुरा हो, नगरपालिका को प्रतिरु संदत करेगा, जिम की राशि उम मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जाएगी, जिसके समस वह इस प्रकार भिददोप किया गया था।

नकमानके
लिए
प्रतिकर।

239. जब कभी धारा 183 के अधीन नोटिस में भिद किसी नोटिस के निवन्धनों का अनुपालन नहीं किया गया है, तो नगरपालिका छः घण्टे का नोटिस देने के पश्चात् कार्य को अपने अधिकारियों द्वारा करा सकती है।

अनुपालन
की दशा में
नगरपालिका
की शक्ति।

240. नगरपालिका या नगरपालिका के किसी कर्मचारी अथवा नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जान-बूझ कर बाधा डालने वाला कोई व्यक्ति, जुमाने में दण्डनीय होगा, जो कम से कम पक्कीन रुपये तथा अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

बाधा के
लिए
शक्ति।

241. (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका ने संपत्ति के स्वामी या अधिभागी से अपेक्षा की है कि वह किसी संकर्म का निष्पादन करे और उम अपेक्षा के अनुपालन में व्यतिक्रम हो गया है तथा नगरपालिका ने संकर्म का निष्पादन कर दिया है वहाँ नगरपालिका व्यतिक्रमी व्यक्ति में संकर्म का खर्चा वसूल कर सकती है।

निष्पादन
के खर्च की
वसूली।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि स्वामी तथा अधिभागी के और नगरपालिका के बीच, स्वामी तथा अधिभागी, दोनों ने, व्यतिक्रम किया है, किन्तु उनमें से वही प्राथमिकतः व्यतिक्रमी समझा जाएगा, जिस पर भू-स्वामी या किराएदार के बीच, या तो किराएदारी की मविदा के अनुसरण में या विधिक अनुसार अपेक्षित कार्य करने के कर्तव्य का समुचित भार हो।

(3) जब प्राथमिकतः व्यतिक्रमी व्यक्ति स्वामी है और नगरपालिका ने सम्पूर्ण खर्च या उसका कोई भाग अधिभागी से वसूल किया है अथवा उमने उनकी भाग किये जाने पर उसका संदाय किया है, तो वह अपने द्वारा स्वामी का समय-समय पर देय किराये में से इस प्रकार वसूल की गई या संवत् राशि काट सकता है या ऐसे स्वामी से अन्यथा वसूल कर सकता है :

परन्तु किसी भी अधिभागी से उप-धारा (3) के अधीन ऐसी राशि में अधिक किसी राशि के संदत्त करने की तब तक अपेक्षा नहीं की जाएगी, जो या तो यथापूर्वोक्त ऐसी मांग की तारीख को देय किराये के संबंध में या तत्पश्चात् प्रोद्भूत होने वाले किराये के संबंध में तत्समय उसके द्वारा स्वामी को देय हो, जब तक उमने नगरपालिका द्वारा मांग किये जाने पर, अपने किराये की राशि तथा उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसको वह सदेय है, सही-सही बतलाने से इन्कार नहीं कर दिया है ; किन्तु इस भूत का भार अधिभागी पर होगा कि नगरपालिका द्वारा अधिभागी से इस प्रकार मांगी गई राशि, मांग के समय देय किराये में अथवा तब से प्रोद्भूत हुए देय किराये में अधिक है।

(4) किसी नगरपालिका द्वारा इस धारा के अधीन वसूली योग्य समस्त धन, नगरपालिका क्षेत्र में अधिकांश प्राप्त किसी मजिस्ट्रेट को आवेदन किये जाने पर, उस व्यक्ति की, जिसे धन वसूली-योग्य है, जंगम संपत्ति की जक्ती तथा उसके विक्रय द्वारा वसूल किया जा सकता है, और यदि धन, सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संदेय हो, तो वह संपत्ति पर तब तक भार रहेगा जब तक उसका संदाय नहीं कर दिया जाता।

(5) इस धारा की कोई भी बात किसी स्वामी तथा अधिभोगी के बीच किसी संविदा पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(6) जहां धारा 116 या धारा 117 के अधीन नगरपालिका ने किसी संकर्म का निष्पादन किया है, वहां धारा 116 के अधीन किये गये संकर्म के सम्बन्ध में उसका खर्च स्वामी या अधिभोगी से और धारा 117 के अधीन किये गये संकर्म के सम्बन्ध में उनका खर्च स्वामी से, किसी व्यक्तिकी स्वामी या अधिभोगी से संकर्म के खर्च की वसूली के लिये इसमें उपबन्धित रीति में और इसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधधीन वसूल किया जा सकता है।

अभिकर्ताओं
तथा न्या-
सियों को
छूट।

242. (1) जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति या सोसाइटी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में अपने द्वारा स्थावर संपत्ति का किराया प्राप्त करने के कारण या प्राप्त करने के लिये हकदार होने के कारण इन अधिनियम के अधीन, संपत्ति के स्वामी पर इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित किसी ऐसी बाध्यता के उन्मोचन के लिए आबद्ध हो, जिसे उन्मोचन के लिये धन की प्रपेक्षा होती है, तो वह बाध्यता के उन्मोचन के लिए तभी आबद्ध होगा, यदि उसके पाम स्वामी का, और उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धन हो अथवा उनके स्वयं के अनुचित कार्य या व्यक्तिकर्म के अभाव में ऐसा धन उनके पाम होता।

(2) किसी अभिकर्ता या न्यासी को इस धारा के अधीन छूट का हकदार बनाने वाले तथ्य को प्रमाणित करने का भार अभिकर्ता या न्यासी पर ही होगा।

(3) जब किसी अभिकर्ता या न्यासी ने इस धारा के अधीन अपने छूट के अधिकार का दावा किया है और उसको प्रमाणित कर दिया है, तो नगरपालिका उस प्रथम धन से, जो स्वामी की ओर से या उसके प्रयोग के लिये उसके हाथ में आये, यथापूर्ववत् ऐसी बाध्यता के उन्मोचन के लिये प्रयोग में लाने के लिये नोटिस दे सकती है और यदि वह ऐसे नोटिस का पालन करने में असफल रहता है, तो वह ऐसी बाध्यता के उन्मोचन के लिये व्यक्तिगत रूप से दायी मजबूत जाएगा।

प्रतिकर का
संदाय।

243. (1) नगरपालिका किसी ऐसे व्यक्ति को नगरपालिका निधि में से प्रतिकर दे सकती है, जिसे इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका में या उसके कर्मचारियों में निहित शक्तियों के प्रयोग के कारण नुकसान हुआ हो और उस दशा में ऐसा प्रतिकर देगी, जहां नुकसान, नगरपालिका की या उसके कर्मचारियों की उपेक्षा के कारण हुआ था और नुकसान उठाने वाला व्यक्ति उस विषय में, जिसके बारे में शक्ति का प्रयोग किया गया था, स्वयं व्यक्तिकी नहीं था।

(2) यदि किसी ऐसे प्रतिकर की राशि के संबंध में, जिसका किसी निमाण या भूमि को हुई या उसके बारे में हुई क्षति के लिये संदाय करना नगरपालिका से इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है या जिसे प्राप्त करने के लिये नगरपालिका इन अधिनियम द्वारा मणस्त है, कोई ऐसा बिनाद उत्पन्न हो, जिसका निपटाने के लिये किसी अन्य धारा द्वारा कोई भी अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं किया गया है, तो वह ऐसी रीति में निपटारा जायेगा, जिस के लिए पक्षकार

महसूस हो या उनके महसूस न होने पर, भीम अर्जुन अधिनियम, 1894 (1894 का संसदीय अधिनियम सं० 1) द्वारा लोक प्रयोजनों के लिये भूमि के अर्जन और उसके प्रतिफल के संसार के बारे में उपबन्धित रीति में जहाँ तक वह लागू की जा सके, निपटाया जाएगा।

244. (1) निम्नलिखित से व्यर्थत कोई व्यक्ति—

(क) धारा 208 के अधीन किसी निर्माण के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण की स्वीकृति से इन्कार द्वारा; अथवा

(ख) धारा 182 के अधीन किसी नगरपालिका के नोटिस द्वारा, जिसमें किसी मार्ग को नालीयुक्त करने, उसका तल बराबर करने, उस पर खड़े जा लगाने, उस पर पथर लगाने, उसे पक्का करने अथवा उस पर समुचित प्रकाश व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई हो अथवा किसी मार्ग को भावजनिक मार्ग के रूप में घोषित किया गया हो; या

(ग) धारा 111 या धारा 128 या धारा 125 या धारा 128 या धारा 237 द्वारा अपने को प्रदत्त शक्तियों के अधीन किसी नगरपालिका या किसी कार्यपालक अधिकारी अथवा सचिव द्वारा किये गये किसी आदेश द्वारा

ऐसे प्रतिबंध, नोटिस या आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार ऐसी अपीलें या उनसे से किसी की सुनने के प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, अथवा ऐसी नियुक्ति न होने की दशा में उपायुक्त को, अपील कर सकता है, और ऐसा इन्कार, नोटिस या आदेश ऐसी अपील से अन्यथा प्रभुत्व नहीं किया जा सकेगा।

(2) अपील प्राधिकारी, यदि वह ठीक समझे तो उप-धारा (1) द्वारा अपील के लिये दी गई अवधि बढ़ा सकता है।

(3) अपील प्राधिकारी का ऐसे इन्कार, नोटिस या आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, अपास्त अथवा उपांतरित करने वाला आदेश अन्तिम होगा।

परन्तु इन्कार, नोटिस अथवा आदेश तब तक उपांतरित अथवा अपास्त नहीं किया जाएगा, जब तक अपीलकर्ता तथा नगरपालिका का सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है।

245. जब धारा 111, धारा 128 और धारा 237 में विनिर्दिष्ट प्रकार के किसी आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है, और ऐसे आदेश के विरुद्ध की गई है तो ऐसे आदेश का प्रवृत्त करने के लिए सभी कार्यवाहियां तथा उसके किसी भाग के लिए सभी अभियोजन अपील का विनिश्चय लम्बित रहने तक निर्लम्बित कर दिए जाएंगे और यदि ऐसा आदेश अपील में अपास्त कर दिया जाता है तो उसकी अवज्ञा अपराध नहीं समझी जायेगी।

246. धारा 228 के अधीन अधिहरण के प्रत्येक आदेश के विरुद्ध ठीक अगले बरिष्ठ न्यायालय में अपील हो सकती है किन्तु उसके विरुद्ध अपील अन्यथा नहीं हो सकती।

नगर-पालिका के आदेशों के विरुद्ध अपीलों।

कतिपय मामलों में अभियोजन का निलम्बित किया जाना।

कतिपय आदेशों के विरुद्ध अपीलों।

प्रभियोक्त
त निष्
प्राधिकार।

247. जब तक अधिनियमन: अन्यथा उपस्थिता न हों, कोई भी नगरपालिका अधिनियम प्रस्ताव किसी नियम या किसी उपविधि के अधीन उपरोक्त विधियों के अधीन नगरपालिका या कार्यपालक अधिकारी या सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के परित्याग के बिना प्रस्ताव उनमें प्राप्त जानकारी के बिना नहीं करेगा।

महत्त्वपूर्ण.—नगरपालिका प्रस्ताव उसका कार्यपालक अधिकारी/सचिव, किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है कि वह नगरपालिका को पुनर्निर्माण किए बिना इस अधिनियम तथा नियमों प्रस्ताव उपविधियों के विरुद्ध साधारणतया सभी अपराधों के बारे में, प्रस्ताव विनिर्दिष्ट केवल विनिर्दिष्ट अपराधों या विनिर्दिष्ट वर्ग के अपराधों के बारे में, परित्याग करे प्रस्ताव जानकारी दे तथा राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति इस प्रकार प्राधिकृत समझा जाएगा। यदि प्राधिकृत किया जाने वाला व्यक्ति नगरपालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यपालक अधिकारी या सचिव प्रस्ताव किसी पुलिस यात्रा का भारमाध्यम अधिकारी है, तो वह अपने प्राधिकृत किया जा सकता है। अन्य दशाओं में प्राधिकार व्यक्तिगत रूप में ही दिया जाना चाहिए। प्राधिकार सभी दशाओं में लिखित रूप में ही होना चाहिए और वह नगरपालिका द्वारा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

अपराधों के
प्रशमन की
शक्ति।

248. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्यथा उपस्थित के बिना, नगरपालिका या कार्यपालक अधिकारी या सचिव प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा इन निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह है कि उसने इस अधिनियम या किसी नियम या उपविधि के विरुद्ध कोई अपराध किया है, ऐसे अपराध के प्रशमन के रूप में कम से कम पाँच वर्षों की कोई धनराशि स्वीकार कर सकता है।

(2) ऐसा धनराशि के संदाय पर, संदिग्ध व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में है तो, उपस्थित कर दिया जाएगा और ऐसे प्रशमन किसी अपराध प्रस्ताव अभिकथित अपराध के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(3) इस धारा के अधीन प्रशमन के रूप में मंदत की गई राशियाँ नगरपालिका निधि में जमा कर दी जाएंगी।

(4) नगरपालिका द्वारा, उप-धारा (1) के अधीन अभिकथित अपराधों का प्रशमन स्वीकार करने का प्राधिकार इस अधिनियम और नियमों तथा उप-नियमों के अधीन सभी अपराधों के सम्बन्ध में साधारणतया या विनिर्दिष्ट केवल विनिर्दिष्ट अपराधों या अपराधों के विनिर्दिष्ट वर्ग के सम्बन्ध में दिया जा सकेगा, और किसी भी समय नगरपालिका द्वारा वापिस किया जा सकेगा।

(5) यदि नगरपालिका ने उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी अधिकारी को प्राधिकृत नहीं किया है तो वह, यदि उपायुक्त द्वारा ऐसी अपेक्षा की गई हो तो उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी अधिकारी को ऐसा प्राधिकार देगा, और ऐसी अपेक्षा पर दिए गए प्राधिकार को उपायुक्त की मंजूरी के बिना वापिस नहीं लेगी।

बजट का
पुनरीक्षण।

250. यदि नगरपालिका, स्थानीय वर्ग के दौरान प्राप्तिपूर्ण या विनिम्नतापूर्ण पर, जिनका वह जिम्मा लेती है, साथ ही जाने वाली राशियों के वितरण के बारे में बजट में लिए गए उपबन्धों को उपांतरित करना आवश्यक समझती है तो वह ऐसा उपांतरण कर सकती है :

परन्तु सरकार द्वारा राज्य की संश्लिष्ट विधि में से अन्तर्गत अनुदानों का इन अनुदानों के अन्तर्गत न जाने वाले प्रयोजन, कार्यक्रम या स्कीम के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि निदेशक के अनुमोदन के बिना,—

- (क) नगरपालिका के निजी विकासगत कार्यों के लिए अनुमोदित अनुदानों में दस प्रतिशत से अधिक कमी नहीं की जाएगी ; और
- (ख) धन्य सन्निधि, धारा 249 की उप-धारा (3) के खण्ड (अ) के अधीन निगत राशि से कम नहीं किया जाएगा ।

अनुपूर्वक
बजट ।

251. जब आवश्यक हो अनुपूर्वक बजट तैयार व प्रस्तुत किया जा सकेगा । नगरपालिका वर्ष के दौरान, जिसके लिए निदेशन द्वारा बजट मंजूर किया गया है, किसी भी समय अनुपूर्वक बजट तैयार करवा सकती है । ऐसे प्रत्येक अनुपूर्वक बजट पर नगरपालिका विचार करेगी और उसे अनुमोदित करेगी तथा उसे उपयुक्त के माध्यम से अनुमोदन के लिए निदेशक को प्रस्तुत करेगी ।

लेखी शून्यता
की व्यवस्था
के निर्बन्धन ।

252. (1) नगरपालिका की साथ और साथ के लेखे ऐसे नियमों के अनुसार लेखे जाएंगे जो विहित किए जाएंगे ।

(2) नगरपालिका विधि से और, इस अधिनियम में जैसा अनिवार्य रूप से उपस्थित है के विचार, ऐसी मंजूरी, भागी और परिधीयताओं के अधीन रहते हुए, जैसी विधि की जाएं, उपयुक्त किया जाएगा ।

(3) नगरपालिका, शासकीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तीन मास से अधिक अवधि के भीतर उक्त वर्ष के लेखाओं को पारित करेगी ।

लेखाओं का
पारिष्पण ।

253. नगरपालिका द्वारा जैसे ही वार्षिक लेखे अन्तिम रूप से पारित कर दिए जाते हैं, वह इन निमित्त विहित प्रारूप में लेखा निदेशक को प्रस्तुत करेगी, और इससे सम्बन्धित विवरण और बाउन्डरी प्रस्तुत करेगी जैसा निदेशक समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

प्रचालनीय
राशियों को
बट्टे खाते
ठालने की
प्रतिष्ठा ।

254. नगरपालिका, ऐसे निर्बन्धनों के अधीन जो विहित किए जाएंगे, उसे देय किसी राशि को बट्टे-खाते में डाल सकती है यदि उसकी राशि में ऐसी राशि अवस्थित हो :

परन्तु एक हजार रुपये से अधिक कोई राशि निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना बट्टे खाते नहीं डाली जाएगी ।

255. (1) नगरपालिका-निधि के धन की लेखा परीक्षा-निदेशक के निम्नलिखित एक पृष्ठ और स्थानज लेखा-परीक्षा अभिलेख द्वारा की जायगी और लेखा-परीक्षा अभिलेख की लेखा-परीक्षा के प्रमाण के लिए नगरपालिका के सभी केताओं और अन्य अभिलेखों तक पहुँच होगी।

लेखों की लेखा-परीक्षा।

(2) लेखा-परीक्षा अभिलेख, लेखा परीक्षा की समाप्ति के एक मास के भीतर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति नगरपालिका को प्रेषित करेगा और नगरपालिका एक रिपोर्ट की प्रति पर ध्या-सक्त-णीत मुद्राओं या अभिलेखनाओं का, यदि कोई रिपोर्ट में बतायी गई हो, उपचार करने की और बत की गई या की जाने की प्रस्तावित कार्यवाही, यदि कोई हो, के संक्षिप्त कथन सहित कथित रिपोर्ट की अपनी प्रतियाँ जिसकी राज्य सरकार द्वारा अधीक्षित हो अभिलेख उपायुक्त और निदेशक के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित करेगी।

(3) राज्य सरकार, नगरपालिका की वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति पर, उन्हें राज्य विधान सभान के समक्ष रखेगी।

256. (1) नगरपालिका, लेखा-परीक्षा अभिलेख की रिपोर्ट पर या स्व-प्रेरणा से और सम्बन्धित व्यक्ति से स्पष्टीकरण लेने के पश्चात् या ऐसा जान जैसी वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, लेखा-परीक्षा अभिलेख द्वारा बनाए गए अभिलेखित धन या उधका या कदाचार द्वारा, राशि में हुई कोई कमी या हानि के लिए या प्राप्ति की गई किसी राशि जिसका लेखा परीक्षा जाना चाहिए या पश्चात् लेखा नहीं रखा गया है, के लिए, उत्तरदायी व्यक्ति को आरोपित करेगा और प्रत्येक ऐसे मामले में ऐसे व्यक्ति से देन राशि को प्रमाणित करेगा।

नगर-पालिका द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर कार्यवाई।

(2) नगरपालिका, प्रत्येक वार्षिक के वारे में अपने दिनिष्ठ रूप में कारणों का कथन करने, और इसकी एक प्रति उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध आरोप लगाया है, भेजेगी।

257. (1) नगरपालिका द्वारा प्रमाणित प्रत्येक राशि जो धारा 256 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति से देन होगी है, उन व्यक्ति द्वारा, उसे विनिश्चित की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर नगरपालिका को मद्धत हो जाएगी।

प्रमाणित राशि की वसूली।

(2) ऐसी राशि यदि देन राशि पर देन होने की तारीख से पन्द्रह प्रतिशत प्राप्ति पर ध्या-सक्त-णीत स्पष्ट रूप से संदेह नहीं की जाती है तो उसकी वसूली के आवश्यक अर्थ सहित भू-राजस्व के वसूली के रूप में वसूली होगी और नगरपालिका निधि में जमा की जाएगी।

258. (1) जब मांग पर मदेय कोई राशि—

नगर-पालिका के देन की वसूली करने की प्रक्रिया।

(क) जो इन अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या द्वारा उक्त अध्याय में उपबन्धित रीति में वसूली पोषित की गई हो; या

(ख) जो इन अधिनियम या अधिनियम द्वारा या किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन नगरपालिका का देन कोष या अन्य राशि के रूप में सेवा योग्य हो,

संदेय हो गई है और देय होने के पन्द्रह दिन के पश्चात् भी अवसरा नहीं है, तो, महास्थिति, कार्यकारी अधिकारी या सचिव या उस द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से निश्चित रूप में प्राधिकृत कोई अधिकारी (जिसे इसमें दृष्टक पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी निर्दिष्ट किया गया है) ऐसी राशि को संदेय करने के लिए दायी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को विहित प्ररूप में निश्चित नोटिस की तामील कर सकेगा।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति, उसे दिए गए मांग नोटिस की तामील में पन्द्रह दिन के भीतर देय राशि को संदेय नहीं करता है, या कार्यकारी अधिकारी या सचिव के समाधानबद्ध रूप में, कारण नहीं बताता है कि ऐसी राशि क्यों संदेय नहीं की जाती चाहिए तो कार्यकारी अधिकारी या सचिव व्यक्ति/कोई जंगम-ममति के कारणस्वम् और विक्रय द्वारा सभी लागतों सहित ऐसी राशि को वसूल कर सकेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन कारणस्वम् और सम्पत्ति का विक्रय करने के लिए, महास्थिति, कार्यकारी अधिकारी या सचिव, या प्राधिकृत अधिकारी विहित प्ररूप में वारण्ट जारी करेगा और ऐसे प्रत्येक वारण्ट के लिए एक समया वारण्ट फीन उद्घाट्य होगी।

(4) महास्थिति, कार्यकारी अधिकारी या सचिव, या प्राधिकृत अधिकारी कारणस्वम् की गई सम्पत्ति को तात्काल तैयार करेगा, तथा मांग किए जाने पर उसकी एक प्रति व्यक्ति/कोई या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को प्रदत्त की जाएगी और यदि देय राशि कारणस्वम् के पश्चात् पन्द्रह दिनों के भीतर संदेय नहीं की जाती है, तो सम्पत्ति का विक्रय किया जा सकेगा।

(5) महास्थिति, कार्यकारी अधिकारी या सचिव या प्राधिकृत अधिकारी, देय राशि को संदेय करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उस द्वारा हस्ताक्षरित उसकी रसद देगा या दिववापणा। ऐसी रसद निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगी:—

- (अ) उसके संदाय की तारीख;
- (ख) संदाय करने वाले व्यक्ति का नाम;
- (ग) देय राशि जिसके बारे में मुगलान किया गया है;
- (घ) अवधि जिसके लिए संदाय किया गया है; और
- (ङ) राशि जिसके बारे में यह प्रवृत्त की गई है।

(6) इस अधिनियम के अधीन वगण-विता को देय कोई राशि संग्रहण के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भू-राजस्व के वसूल के रूप में वसूली होगी।

कारणस्वम्
और विक्रय
की शर्तें।

259. (1) जब सभी धारा 258 के अधीन किसी सम्पत्ति का, किसी देय राशि के संदाय के गणितात्मक रूप कारणस्वम्, अभिसंग्रहण या विक्रय किया जाता है तो ऐसा कारणस्वम्, अभिसंग्रहण और विक्रय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के द्वारा सभी उप-धाराओं और धारा 62 के उपबन्धों के अध्वर्धन किया जाएगा।

(2) ऐसी समस्त सम्पत्ति जिसे विहित प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा डिफेंड की निम्नलिखित में कुर्बी या विक्रय से छूट प्राप्त है, उदाहरण धारा क अधीन कारणस्वम् या विक्रय से छूट प्राप्त होगी।

(3) प्रत्येक जिला योजना समिति प्राकृतिक विकास योजना तैयार करने में—

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी—

- (i) नगरपालिकाओं और पंचायतों के मध्य समूहित हित के विचार, जिनमें खुली योजना, पानी का विभाजन, और अन्य भौतिक और प्राकृतिक साधन, संरचना का एकीकृत विचार और पर्यावरण संरक्षण भी है ;
- (ii) उपलब्ध साधनों के परिणाम और विस्म, चाहे वित्तीय हों या अन्यथा ;
- (ख) ऐसे संस्थानों और संगठनों से परामर्श करना जो राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

(4) प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष, ऐसी समिति द्वारा जैसी शिफारिश की गई हो, विचार योजना को राज्य सरकार को अर्पणित करेगा ।

अध्याय-16

नियन्त्रण

उपायुक्त द्वारा
नियन्त्रण ।

262. (1) उपायुक्त या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा, किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त साक्ष्य कोई व्यक्ति—

- (क) किसी नगरपालिका या संयुक्तकमिति द्वारा अधिसूक्त किसी स्थावर सम्पत्ति पर, या उसके निदेशाधीन चल रहे किसी संदर्भ पर प्रवेश, उक्त निरीक्षण और सर्वेक्षण कर सकता है या प्रवेश, निरीक्षण और सर्वेक्षण करवा सकता है ;
- (ख) कार्यकारी अधिकारी या सचिव को संबंधित लिखित आदेश द्वारा किसी नगरपालिका के दफ्ते में या नियन्त्रणाधीन किसी यहाँ या किसी दस्तावेजों को मंगा सकता है और उनका निरीक्षण कर सकता है या निरीक्षण करवा सकता है और नगरपालिका या दफ्तर या कर्मचारी, जिसके दफ्ते में ऐसी वहाँ या दस्तावेज है, ऐसी वहाँ या दस्तावेज को तुरन्त सचिव के नियन्त्रणाधीन रख देगा, जो ऐसे आदेश का तुरन्त अनुपालन करेगा और अधिकापन के बारे में अध्यक्ष को तुरन्त सूचना देगा । यह इस विषय को नगरपालिका के ठीक आगामी अधिवेशन में नगरपालिका के नोटिस में भी जाएगा ;
- (ग) कार्यकारी अधिकारी या सचिव को संबंधित लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसी नगरपालिका या संयुक्त नगरपालिका से, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, नगरपालिका के ऐसे विवरण, लेखे, रिपोर्ट और ऐसी कार्यवाहियों या कार्रवायों से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियाँ, जिन्हें मंगवाना वह ठीक समझे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है ;
- (घ) नगरपालिका के कार्यवाहियों की यह अभिलिखित करने के लिए साधारणतया जांच कर सकता है कि नगरपालिका क्षेत्र का प्रशासन समाधानप्रद रूप में चल रहा है या नहीं, और ऐसी जांच के प्रयोजनों के लिए, नगरपालिका किसी संपत्ति का

उपयोग कर सकता है और खण्ड (ग), (घ) और (ग) में वर्णित अधिकार का प्रयोग कर सकता है, और नगरपालिका के सदस्य और कर्मचारियों को जो वे ऐसा महायोजना देंगे, जैसी आवश्यक समझी जाए।

1860 का 45 स्पष्टीकरण.— हम प्रारंभ संभव कोई भी व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अंतर्गत लोचन सेवा समझा जाएगा।

(2) उपयुक्त ऐसी किसी नगरपालिका की कार्यवाहियों या दत्तियों के बारे में ऐसी टिप्पणियाँ शामिल कर सकता है, जिन्हें वह ऐसी नगरपालिका के विचारार्थ प्रस्तुत करना उचित समझे।

(3) प्रत्येक नगरपालिका उपयुक्त को या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी को, ऐसी नियमकालिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिनके लिए राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

263. (1) राज्य सरकार या निदेशक या विहित प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, और उसमें कथित किए जाने वाले कारणों से, नगरपालिका द्वारा पारित किसी संकल्प के, जारी किए गए किसी आदेश या दो गई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के निष्पादन को निलम्बित कर सकेगा या किसी नगरपालिका द्वारा किसी दृष्टि के पालन को प्रतिषेध कर सकेगा, यदि उसकी राय में—

आदेशों
आदि का
निष्पादन
निलम्बित
करने की
शक्ति।

(क) ऐसा संकल्प, आदेश, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, या कार्य वैध रूप से पारित, जारी, मंजूर या प्राधिकृत नहीं किया गया है/नहीं की गई है; या

(ख) ऐसा संकल्प, आदेश, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या कार्य इन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परे है या किसी विधि के प्रतिकूल है; या

(ग) ऐसे संकल्प या आदेश के निष्पादन से या ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के लगातार प्रवृत्त बन रहने से या ऐसा कार्य किए जाने से—

(i) नगरपालिका में निहित किसी धन की हानि, दुर्घटन या दुर्लभ होना या उसमें निहित किसी संपत्ति को नुकसान होना संभाव्य है;

(ii) सार्वजनिक स्वस्थ, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है;

(iii) जनता या व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय को क्षति या असुविधा होना संभाव्य है; या

(iv) शांति भंग होना संभाव्य है।

(2) जब कभी निदेशक या विहित प्राधिकारी द्वारा उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश किया जाता है, तो वह, तत्काल और किसी भी दशा में आदेश की तारीख से अधिक से अधिक दस दिन के भीतर, उस आदेश की, एक प्रति ऐसा आदेश किए जाने के कारणों के कथन सहित, राज्य सरकार को अर्पित करेगा, और राज्य सरकार ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकेगी, उसे अग्रस्त कर सकेगी या उसे उपांतरित कर सकेगी जैसा वह उचित समझे।

264. (1) आपात दशा में उपयुक्त किसी ऐसे संकल्प के निष्पादन या किसी कार्य के करने के लिए व्यवस्था कर सकता है जिसके निष्पादन या करने के लिए नगरपालिका संभव है और जिसका तुरन्त निष्पादन किया जाना उसकी राय में सार्वजनिक सेवा या सुरक्षा के लिए आवश्यक है और निदेश कर सकता है कि संकल्प के निष्पादन में या कार्य करने में हुए खर्च नगरपालिका द्वारा तुरन्त संदत्त किए जाएंगे।

आपात
दशाओं में,
उपायुक्त
की शक्ति।

(1) यदि वह इन प्रकार संवत् न किया जाए, तो उपायुक्त उन व्यक्ति को, जिसकी सम्पत्ति में नगरपालिका निधि का अधिग्रहण है, ऐसे व्यक्ति का या उसके उत्तरे भाग का, जिसका उन अधिग्रहण में से समय-समय पर संबंध है, उनके सम्बन्ध में सभी अन्य प्रभागों से पूर्ववत् होने हुए, संवत् करने का आदेश कर-सकेगा।

265. (1) जब उपायुक्त का सम्बन्ध प्राप्त करने का पता चलता है समाधान हो जाता है कि नगरपालिका से इन अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अधीन किसी आदेश या नियम द्वारा उन पर अधिग्रहण किसी व्यक्ति के पक्ष में व्यक्तिगत किया है, तो वह, लिखित आदेश द्वारा, उन अधिग्रहण के पक्ष में कोई व्यक्ति नियत कर सकता है और यदि ऐसा है, इन प्रभाग नियम की गई शर्तों के अंतर्गत पालन न किया जाए तो वह उनके पक्ष में लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और यह आदेश कर सकता है कि उनमें से कोई व्यक्ति के अंतर्गत, जैसी वह नियत करे, नगरपालिका द्वारा संवत् लिए जायेंगे।

(2) यदि वह इन प्रकार संवत् न किया जाए, तो उपायुक्त उन व्यक्ति को, जिसकी सम्पत्ति में नगरपालिका निधि का अधिग्रहण है, ऐसे व्यक्ति का या उसके उत्तरे भाग का, जिसका उन अधिग्रहण में से समय-समय पर संबंध है, उनके सम्बन्ध में सभी अन्य प्रभागों से पूर्ववत् होने हुए, संवत् करने का आदेश कर सकता है।

266. जब उपायुक्त द्वारा 264 या धारा 265 के अधीन कोई आदेश करता है, तो वह आयुक्त को उसके एक प्रति, आदेश को निष्पादन करने के विवरण सहित, और ऐसे संपत्ति का साक्ष्य, यदि कोई हो, जैसा ऐसे नगरपालिका क्षेत्र की नगरपालिका देगा चाहे, तुल्य भेजेगा, और सब नगरपालिका, आदेश को पुष्ट, उपस्थित या विद्विष्ट कर सकता है।

परन्तु यदि, प्रत्येक लिखित अधिनियमों के अधीन उपायुक्त का अधिनियम कोई अधिकारी धारा 264 या धारा 265 के अधीन कोई आदेश करता है तो ऐसे आदेश को पुष्ट उपस्थित या निष्पादन की शक्ति उपायुक्त में निहित होगी, जो ऐसी शक्ति का प्रयोग करने में पूर्व ऐसे नगरपालिका की संपत्ति के ऐसे संपत्तिकरण पर विचार करेगा जो वह देना चाहे, और वह उपायुक्त आदेश को पुष्ट, उपस्थित या विद्विष्ट कर सकता है।

267. राज्य सरकार, इन अधिनियमों के प्रयोगों को लागू करने के लिए और विविध प्रकार निम्नलिखित के सम्बन्ध में, विदेश किसी नगरपालिका को जारी कर सकेगी—

निदेश देने की शक्ति सरकार की शक्ति।

- (क) विविध प्रयोगों, जिसके लिए किसी नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत स्थित किसी भूमि का उपयोग किया जा सकता है;
- (ख) कृषिों का प्रसिद्धि तथा बाधनोंओं का निर्वहन;
- (ग) करों की वसूली;
- (घ) नियमों और उप-विधियों का अनुमोदन;
- (ङ) लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और सन्ध्या के उत्थान के लिए विकास उपाय और उपायों का अयोजना;
- (च) स्वास्थ्य और सफाई;
- (छ) अभिनयन की व्यवस्था और अनुमोदन;
- (ज) लोक हित में किसी कार्य का निष्पादन;

268. (1) जब इस अधिनियम के अधीन कोई नया नगरपालिका क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो राज्य सरकार नगरपालिका की शक्तियों के प्रयोग, उनके तत्त्वों के नियंत्रण तथा कृत्यों के पालन करने के लिए किसी व्यक्ति को नए नगरपालिका के लिए नियुक्त कर सकती है, जब तक नगरपालिका स्थापित नहीं कर दी जाती और वह पूर्वाधिकार प्रयोग के लिए नगरपालिका बनना जाएगा।

नगर-पालिका की स्थापना संबंधित करने वाले नगरपालिका की शक्ति का प्रयोग।

(2) उप-धारा (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति ऐसे लोगों का अनुपातपूर्ण होगा, जो राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रयोग के नियंत्रण के लिए समान-अनुपात देने दिए जाएंगे।

269. (1) राज्य सरकार और निदेशक के आदेशाधीन कार्य करने वाले विहित प्राधिकारी इस बात को प्रोत्साहित करने के लिये आवश्यक होंगे कि नगरपालिकाओं की आवश्यकताओं, माध्यामिक शिक्षा के क्षेत्रों को, जिन पर नगरपालिका का प्राधिकार है, तत्पक्ष लागू किसी अधिनियमित के अधीन प्रदत्त विधि तथा नियमों के अनुरूप हों।

नगरपालिका के सम्बन्ध में राज्य सरकार और उसके अधिकारियों की शक्ति।

(2) राज्य सरकार इस तत्त्व के पालन के लिये आवश्यक सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, और प्रत्येक व्यक्ति को साधन-साधन, निहित आदेश द्वारा, किसी कार्यवाही को, जिसे वह व्यापारिक विधि या नियमों के अनुरूप न समझे, या जिन प्राणियों ने, जिनके अधीन पर उपर्युक्त नियमों, धारा 263 के अधीन निदेशक या किसी विहित प्राधिकारी द्वारा स्थापित करने से कोई आदेश दिया जा सकता था, निष्पत्तिगत अवस्था उत्पन्न करने पर लगे हों।

(3) निदेशक या विहित प्राधिकारी उक्त प्रयोग के लिये प्रत्येक अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, जो राज्य सरकार द्वारा इन निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उम्मेद प्रदत्त की जाएगी।

270. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह अपने किसी अधिकारी के द्वारा आदेश को, जो इस अधिनियम के अधीन किया गया है या किया गया तत्पक्षित है, उत्क्रान्त या उन्मूलित कर दे, यदि राज्य सरकार मानती है कि वह उक्त अधिनियम या नियमों के अनुरूप नहीं है या कि प्रारम्भ में अनुमोचित है, और राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोग को प्रभावित करने के लिये माध्यामिक या अपने अधिकारियों के संघर्ष के अन्तर्धान, निदेशक और निदेशक की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी।

राज्य सरकार की माध्यामिक शक्तियाँ

परन्तु राज्य सरकार के किसी अधिकारी के प्रवेश को उत्क्रान्त या उन्मूलित करने की शक्ति प्राधिकृत अधिकारी या जिसे स्वीकृति प्राप्त निदेशक में प्राप्ति आदेश को लागू नहीं होगी।

271. (1) यदि किसी भी समय राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई नगरपालिका, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्पक्षित प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उन पर अधिनियमित शक्तियों का पालन करने में बाध-बाध व्यतिक्रम कर रही है या अपनी शक्तियों में परे कार्य करती है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है या राज्य सरकार या भूमि प्राधिकारी के किसी आदेश या पालन नहीं करती है, तो राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा ऐसी नगरपालिका को विघटित कर सकता और उसके तत्त्वों के लिये आदेश दे सकता।

व्यतिक्रम, शक्तियों के दुरुपयोग आदि के लिए नगरपालिकाओं को विघटित करने की राज्य सरकार की शक्ति।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश जब तक पारित नहीं किया जाता जब तक नगरपालिका को प्रत्येक स्वीकृति देने के लिए शक्ति प्राप्त व्यवस्था न दे दिया गया हो। स्वीकृति प्राप्ति का नोटिफिकेशन नगरपालिका के अधीन की संस्थापित किया

जाएगा और उसके नामों विहित रीति में की जाएगी। नोटिस के संबंध में सहायक निरीक्षक उत्तर नगरपालिका के सचिव द्वारा समचित होगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन नगरपालिका के विघटित हो जाने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

- (क) सभी सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ऐसे आदेश को तारीख से अपने-अपने पद रिक्त कर देंगे;
- (ख) नगरपालिका की नारी शक्तियों तथा उसके कर्तव्यों का, नगरपालिका का पुनर्गठन होने तक प्रयोग और पालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की ऐसी समिति द्वारा किया जाएगा जिसे राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी इस संबंध में नियुक्त करे और जहाँ व्यक्तियों की कोई समिति इस प्रकार नियुक्त की जाती है, वहाँ राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी ऐसी समिति का प्रधान भी नियुक्त करेगा;
- (ग) जहाँ कोई समिति खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त की जाती है, वहाँ ऐसी समिति का, उसके द्वारा सम्पन्न रूप से प्राधिकृत कोई सदस्य, नगरपालिका की ओर से वाद चला सकेगा या विधिक कार्यवाही संस्थित कर सकेगा या नगरपालिका के विरुद्ध चलाए गए किसी वाद या संस्थित किसी विधिक कार्यवाही में प्रतिवाद कर सकेगा।

(4) कोई ऐसा व्यक्ति जो, नगरपालिका के विघटित रहने का कालावधि के दौरान नगरपालिका की शक्तियों का प्रयोग और उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है अपनी सेवाओं के लिए संबंधित नगरपालिका निधि से ऐसा संशय प्राप्त कर सकेगा जो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, अवधारित करे।

(5) उप-धारा (1) के अधीन विघटित किसी नगरपालिका का इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठन उसके विघटन के छः मास के भीतर किया जाएगा। ऐसी पुनर्गठित नगरपालिका उन नगरपालिका की शेष अवधि के लिए कार्य करेगी:

परन्तु यदि अनवसित कालावधि छः मास से कम है तो इस कालावधि के लिए नगरपालिका पुनर्गठित नहीं की जाएगी।

नगर-पालिका के पदाधिकारियों का नियन्त्रण।

272. (1) विहित प्राधिकारी किसी पदाधिकारी को पद से नियन्त्रित कर सकेगा—

- (क) जिसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय 5-ए, 6, 9-ए, 10, 12 और अध्याय 16 की धारा 302, 303, 304-ड, 305, 306, 312 से 318 तक, 366-के, 366-ख, 373 से 377 तक और अध्याय 17 की धारा 395 से 398 तक, 408, 409, 458 से 460 तक तथा अध्याय 18 के अधीन या बाह्य सामग्री और औषधि अपभ्रंश के निवारण, स्त्रियों तथा बालक के सम्बन्ध में अनैतिक व्यापार दमन और सिविल अधिकारों के संरक्षण सम्बन्धी तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन किन्हीं दण्डित कार्यवाहियों में आरोप विरचित किए गए हैं; या

- (ख) जिस पर इन अधिनियम के अधीन उन पद से हटाए जाने के लिए कारण बताओ नोटिस आरोप पत्र के साथ तामील किया गया है।

(2) जहाँ विरोधण रिपोर्ट या संग्रहित रिपोर्ट के पदधारी द्वारा नगरपालिका विधि के अनुविधान, दुस्वसन या गवर्नर या प्रशासन होता है और विहित प्रक्रिया को समाप्त हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पद पर वने रहने के अन्तर्गत 273 के अधीन होने पर प्रतिक्रिया प्रभाव रहने और अनुविधान में गठबद्ध करने और साक्षियों को रोकने की शक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को नियन्त्रण कर सकेंगे और यदि उनके रोज में नगरपालिका का कोई अनुविधान, धन या अन्य सम्पत्ति है तो उसे ऐसे अनुविधान या सम्पत्ति को नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी/साक्ष्य को सौंपने का आदेश देगा।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन दिए गए नियन्त्रण आदेश की रिपोर्ट राज्य सरकार को 7 दिनों की अवधि के भीतर की जाएगी और वह ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए होगा जो राज्य सरकार पत्रित करना उचित समझे। यदि नियन्त्रण आदेश की पुष्टि राज्य सरकार द्वारा ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से 90 दिनों के भीतर नहीं की जाती है तो वह निष्प्रभावी कर दिया गया समझा जाएगा।

(4) नगरपालिका के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही के उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के अधीन नियन्त्रण कर दिए जाने की वजह से नगरपालिका, अध्यक्ष या अध्यक्ष का पद धारण करने के लिए अहित किसी पदधारी को, दयार्थक्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगा। ऐसा व्यक्ति उस अवधि के दौरान जिसमें ऐसा नियन्त्रण चालू रहता है, दयार्थक्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के समाना कार्य को पालन और उनकी सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(5) कोई व्यक्ति, जिसे उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन नियन्त्रित कर दिया गया है, किसी ऐसी अन्य नगरपालिका या स्थानीय समिति या जिला योजना समिति या किसी अन्य समिति के सदस्य के या पदधारी के पद संभालने नियन्त्रित हो जाएगा जिससे कि वह सदस्य या पदधारी है। ऐसा व्यक्ति, अपने नियन्त्रण के दौरान, इस अनुविधान के अधीन निर्वाचन के लिए भी निर्वाहित होगा।

273. (1) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, ऐसी शक्ति के पदधारी को वह उचित समझे, किसी पदधारी को, किसी भी समय हटा सकेंगे—

नगर-
पालिका के
पदधारी-
रियों का
हटाया
जाता।

- (क) यदि उनसे इन अनुविधान के अधीन कोई निरवस्था उद्भव कर रहा है;
- (ख) यदि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवधारण का दोषी रहा है;
- (ग) यदि वह नगरपालिका से हटकर गंगा या राज्य करने के लिए अनुमति नहीं देता है या उसे विवादास्पद न्यायनिर्णीत किया गया है;
- (घ) यदि वह युक्ति युक्त हेतुओं के बिना नगरपालिका या इसकी समिति की लगातार तीन बैठकों में दयार्थक्य रहता है;
- (ङ) यदि उसका पद पर बना रहता लोकहित में अव्यवहार है;

परन्तु किसी भी व्यक्ति को पद संभालने नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे यह कारण बताते हुए अवधारण दे दिया गया हो कि उसे उसके पद से हटा दिया जाए।

संघटीकरण.-- इस उद्देश्य के प्रतीक के लिए 'असमधारण' के अन्तर्गत है--

(क) ऐसा कोई कार्य जिसका--

(i) भारत की प्रगल्भता, एकता और अखण्डता पर;

(ii) राज्य के सभी लोगों में समरसता और समान आतुत्व की ऐसी भावना के निर्माण पर जो धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो;

(iii) स्त्रियों के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा अपेक्षा;

(ग) नगरपालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट अन्तराल पर नगरपालिका की बैठक बुलाने में असफलता।

(2) कोई व्यक्ति, जिसे उद्देश्य (1) के अन्तर्गत हटा दिया गया है, तबतल किसी अन्य नगरपालिका या स्थायी समिति या जिला योजना समिति या अन्य समिति या समन्वय नहीं रहेगा जिसका नि वह सदस्य है। ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन छः वर्ष की अवधि के लिए नगरपालिका के प्रमुखता के रूप में निर्वाचन के लिए निर्हित हो जाएगा।

अभिलेख
संग्रह की
शक्ति।

274. राज्य सरकार, किसी भी समय, नगरपालिका द्वारा पारित मसौदा या नियम या आदेश अथवा इस अधिनियम या अधिनियम बनाए गए नियमों या उप-विधियों के अधीन किए जाने के लिए तात्पर्य किसी आदेश की रचना या अधिव्यक्ति के बारे में अपने समाधान के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, निम्न संलग्न या आदेश से सम्बन्धित अभिलेख को संग्रह करेगी और निरीक्षण कर सकेगी और उनके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जो यह उचित समझे:

पारित मसौदा या आदेश में हितगढ़ पक्षधारों को चुनवाई का व्यक्तिगत अवसर प्रदान किए बिना, केफार नहीं दिया जाएगा या उलटा नहीं जाएगा, अथवा निम्न प्रकार या यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा संलग्न या आदेश विधि विरुद्ध प्रतिकूल के कारण दूषित हो गया है।

निरीक्षण
और पर्य-
वेक्षण की
शक्ति।

275. (1) निदेशक, नगरपालिका के कार्यों का निरीक्षण कर सकेगी और निम्न-लिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी--

(क) किसी नगरपालिका की कार्यवाहियों या उसके कब्जे में किसी पुस्तिका या दस्तावेज या उद्घरण या लेखाओं की विवरणी या रिपोर्ट संग्रह करेगी;

(ख) किसी नगरपालिका से, किसी आपत्ति पर जो किए जाने वाले या ऐसी नगरपालिका द्वारा किए जा रहे किसी कार्य में उसे विद्यमान प्रतीत हो या किसी सूचना पर जिस पर ऐसी नगरपालिका द्वारा कोई बात ऐसी अवधि के भीतर जैसी वह नियत करे, की जाती उसे आवश्यक प्रतीत हो, विचार करने की, इच्छा करना;

(ग) किसी पक्ष को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करने का आदेश देना यदि नगरपालिका द्वारा किसी कर्तव्य के लिए जाने में अतिवृत्ति किया गया है और यदि ऐसा कर्तव्य विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो ऐसे कर्तव्य के पालन के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करना और

निर्देश देगा कि उक्त सर्वेक्षणों में काली नगरपालिका द्वारा ऐसी सर्वेक्षों के भीतर संवेदन दिया जाएगा, जो उस द्वारा नियत की जाए;

- (घ) नगरपालिका या काली किसी भी अर्थन की बैठक द्वारा, या अन्य किसी भी अर्थन की बैठक नहीं की गई है।

(2) नगरपालिका, उप-अध्या (1) के खण्ड (ग) के अधीन निर्देशन के अधिन के विरुद्ध तीन दिन के भीतर सरकार की अपील कर सकेगी।

276. (1) निम्नाध्याय और जिसका अर्थन स्तर के विभागों के प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका के निम्नलिखित विभागों में संवेदनशीलता या विभाग स्तरों का निरीक्षण कर सकेंगे और सरकार द्वारा निर्देशन दी गई है।

तकनीकी पर्यवेक्षण और निरीक्षण।

(2) निरीक्षण के क्षेत्र के अन्तर्गत तब तक की पहलुओं सहित, राज्य का आर्थिक, आर्थिक व्यवस्था, नगरपालिका और उपनगरपालिका का विकास है।

(3) ऐसे निरीक्षण के पश्चात् ऐसे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की रिपोर्टों संवेदनशील नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी और अधिकारियों के लिए प्रेषित की जाएगी।

277. यदि राज्य सरकार के पक्ष पर राज्य सरकार का मतप्रधान हो जाता है कि किसी नगरपालिका ने इनका अधिकार नहीं है कि उसकी कोई विशेषता या विभाग अपने कर्तव्यों में से न करेगा या कि उसका पक्षन करने में उचित है या स्थिति रूप में पक्षन नहीं करता, तो वह नगरपालिका के निम्नलिखित तब तक ऐसी किसी राज्य या विभाग को निरीक्षण में ले जाती है और ऐसी राज्य या विभाग के कर्तव्यों के दखलाने के लिए आवश्यकता अनुसार अधिकारियों समर्थनित्व निरूपित कर जाती है, और निर्देशन कर जाती है कि उनके द्वारा नगरपालिका द्वारा ऐसे समय के भीतर संवेदन दिया जाएगा, जो राज्य सरकार इन निर्देशन दिया करे।

नगरपालिका की कतिपय शाखाओं या विभागों को निरीक्षण में लेना।

278. (1) दो या अधिक नगरपालिकाओं या नगरपालिका और किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच किसी ऐसे विषय के संबंध में जिसमें संयुक्त रूप से हितवद्द है, कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में, ऐसा विवाद राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और राज्य सरकार का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा। परन्तु यदि विवाद नगरपालिका और छावनी बोर्ड के बीच है तो राज्य सरकार का विनिश्चय केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन होगा।

नगरपालिकाओं और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच विवाद।

(2) राज्य सरकार, इन अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे हैं द्वारा नगरपालिकाओं के और नगरपालिकाओं तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच उन विषयों में जिसमें वे संयुक्त रूप से हितवद्द हो, संवेदनशीलता विनिश्चय कर सकेगी।

279. (1) राज्य सरकार किसी नगरपालिका की किसी कार्यवाही के निम्न प्रमुख विनिश्चित कर सकती है और इस अधिनियम के प्रभावों को कार्यनिष्ठ करने के लिये इनके संगत कोई नियम बना सकती है और पूर्वागामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनिश्चित निम्नलिखित नियम बना सकती है—

प्रमुख विनिश्चित करने और नियम बनाने की शक्ति।

(क) नगरपालिकाओं की शक्तियों और उत्तरों के बारे में;

(ख) नगरपालिका क्षेत्रों की बाड़ों में या निवासियों के वर्गों में विभाजन के

बारे में या नगरपालिका क्षेत्रों के बाड़ों में और निवासियों के वर्गों में विभाजन के बारे में;

- (ग) प्रत्येक बाड़ी या वर्ग के लिए समुचित प्रतिनिधियों की संख्या के बारे में;
- (घ) नगरपालिका के अपने अधिकारों को दोष देने वाली प्रक्रिया के बारे में;
- (ङ) उप-प्राधिकार के बारे में, जिन पर नगरपालिका निधि में संघन संदर्भ दिया जा सकता है;
- (च) नगरपालिका के अधिनियमों द्वारा क्षेत्रों के गठन और कार्यकरण के बारे में, और ऐसे अधिनियमों द्वारा अपने अधिकारों के दक्ष निर्वहन के लिए अधिकारों, मणोतरी या सूचना समुचित करने के साधनों के बारे में;
- (छ) ऐसे शर्तों के बारे में, जिन पर नगरपालिका द्वारा सम्पत्ति अधिनियम की जा सकती है या जिन पर नगरपालिका में निहित सम्पत्ति, विषय, बंधन, पट्टे, विनियमन द्वारा या अन्यथा दायित्व की जा सकती है;
- (ज) गणपती दायित्व या कार्यलयों के बारे में, यदि कोई हों, जिनके माध्यम से नगरपालिका या नगरपालिकाओं के सदस्यों और राज्य सरकार अथवा उस सरकार के अधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार होगा;
- (झ) नगरपालिकाओं के व्यवसाय पर पूर्णतः या संशतः सन्निहित चिये जाने वाले संघर्षों के रखावों और प्रावधानों की तैयारी के लिए और धारा 58 के अधीन बनाए गए मानचित्रों तथा पंक्तियों की तैयारी और नियंत्रणित पुनरीक्षण के लिए और प्राधिकारियों के लिए जिनके द्वारा और शर्तों के लिए जिनके अधीन, ऐसे रखावें, प्रावधान, मानचित्र और पंक्तियाँ तैयार और स्वीकृत की जाती हैं;
- (ञ) विद्युत ऊर्जा के प्रदाय के लिए विद्युत प्रदाय सम्पत्तियों के साथ संबंधों के विनियमन के लिए;
- (ट) इस अधिनियम के अधीन अधिकारों के निर्धारण और संग्रहण के लिए, और शर्तों का प्रशसन करने, उनका प्रतिपादन करने या उनके प्रतिपादनों को सीमित करने के लिए, और उनका व्यवस्थापन करने के लिए, और योग्य नोटिफिकेशन के लिए संदेय फीसें नियत करने के लिए;
- (ठ) उन शर्तों के बारे में जिन पर नगरपालिका, परिवर्द्ध भांडार में जीव अन्तुओं या वस्तुओं को प्राप्त कर सकती है और परिवर्द्ध भांडार में जीव अन्तु या वस्तु जमा करने के इच्छुक व्यक्तियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित चिये जाने वाले शर्तों के बारे में;
- (ड) नगरपालिकाओं द्वारा रखे जाने वाले क्षेत्रों के बारे में, उन शर्तों के बारे में, जिनपर ऐसे लेख इस अधिनियम के अधीन किसी प्रकार संशोधन करने वाले ऐतिहासिक निरीक्षण के लिए कृते रहते हैं, उन शर्तों के बारे में, जिसमें लेखों की परीक्षण और प्रमाणित किया जाता है, और अस्वीकृत और अधिभार के सम्बन्ध में लेख-परीक्षकों की शक्ति के बारे में;
- (ड) नगरपालिकाओं की शक्ति और व्यवस्था के प्रावधान तैयार करने के बारे में, और उन शक्तियों के बारे में, जिनके द्वारा और उन शर्तों के बारे में जिन के अधीन ऐसे प्रावधान स्वीकृत चिये जा सकते हैं;
- (ण) नगरपालिकाओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों, विवरणों और रिपोर्टों के बारे में;
- (न) धारा 269 के अधीन उपयुक्तों द्वारा प्रयोज्य शक्तियों के और ऐसे स्वतंत्र स्वतंत्र जलन नोई या निरीक्षणालय द्वारा प्रयोज्य शक्तियों के बारे में, जिनमें राज्य सरकार स्वयं के बारे में;
- (त) उन भाषा के बारे में, जिनमें और निरूपित किया जाएगा, आवश्यकियाँ अभिलेखित की जाएंगी और नोटिफिकेशन चिये जाएंगे;
- (द) नोटिफिकेशन के प्रावधान के बारे में;

- (घ) अधिनियम अधिनियमों के द्वारा धारा 243 के अधीन प्रस्ताव स्वीकृत करने के लिए नगरपालिका क्षेत्रों के कार्यकारी निकायों के समक्ष के लिए;
- (न) धारा 156 के अधीन निर्धारण, प्रतिस्पर्धा का उनके हस्तक्षेप, व्यक्तिगतों के बीच प्रभावित और उनको संभावित रूप से;
- (प) धारा 156 के अधीन निर्धारण, उनसे प्रभावित व्यक्तिगतों को, सम्बन्धित करने का होगा;
- (फ) रीति, जिसमें सम्पत्ति खाने बनाई जानी है;
- (व) नगरपालिका के कार्यकारी निकायों के लिए प्रशिक्षण निकायों के स्थापना तथा कार्यकारी निकायों के विभिन्न वर्गों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में;
- (भ) जहाँ स्वामी, नगरपालिका द्वारा उपलब्ध कराई गई सूच सूचियाँ, जहाँ, विद्युत, नल-नल प्रदाय, मल-प्रणाल आदि का लाभ नहीं उठाने, वहाँ जमाने के अधिनियम के बारे में;
- (म) नगरपालिका, में लगे हुए सफाई मजदूरों को सवलत दिये जाने वाले प्रभावित व्यक्तिगत करने के बारे में;
- (य) अपने प्राधिकार के अधीन क्षेत्र की सीमाओं या परिवर्तित सीमाओं को परिनिश्चित करने हुए पर्याप्त सीमा-चिह्नों के परिनिर्माण और स्थापना को निश्चित करने के बारे में;
- (य क) मार्ग काटने या मार्गों या नालियों को अवरुद्ध करने वाली बाधा या अवरोधों के हटाने के लिए शक्ति के बारे में;
- (य ख) सूखे, या अन्य अपरिहार्य कारण या दुर्घटना, आदि की दशा में जल-प्रदाय के काटने अथवा जल प्रदान करने के लिये किसी निर्माण को किसी सम्पत्ति, शक्ति या नुकसान के दायित्व से छूट के बारे में;
- (य ग) मण्डलों के अनुसूचना, मण्डलों बनाने, मण्डलों और क्षेत्रों के संगठन तथा ऐसे व्यक्तियों के हटाने को निश्चित करने के बारे में, जो मण्डलों में, मालों या स्थल या असाध्यित रीति में अधिनियम करते हैं;
- (य घ) नगरपालिकाओं के वर्गों से तय रिपोर्टों की जमा करने तथा उन पर विचार-विमर्श करने के लिए और उनके संबंध में उपलब्ध उपकरणों का सुझाव देने के लिए मंडल तथा जिला मुख्यालयों पर शासकीय तथा सार्वजनिक सदस्यों की समितियों का गठन करने के बारे में;
- (य ङ) रीति जिसमें जिला योजना समिति की सीटें भरी जाएगी, के बारे में;
- (य च) रीति जिसमें जिला योजना समिति का अध्यक्ष चुना जाएगा, के बारे में;
- (य छ) जिला योजना समिति में संबंधित व्यक्तियों के बारे में;
- (य ज) साधारणतः इन अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए;
- (2) उप-धारा (1) के अधीन नियम, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित विषयों के लिए भी उपबन्ध कर सकते हैं,—
- (i) "नगरपालिकाओं" में स्थानों के आरक्षण के लिए;
- (ii) नगरपालिकाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या के अधिनियम के लिए।
- (3) वर्तमानतः प्रचलित नगरपालिका लेखा संहिता इन धारा की उप-धारा (1) द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में किया गया संज्ञा जाएगा।
- (4) उप-धारा (1) के खण्ड (च) और (ट) के अधीन नियम बनते समय राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि इन के उपबन्धों के किसी उल्लंघन में, जमाना दिया जा सकेगा, जो पचास रुपये से कम और पांच सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।
- (5) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम पूर्व प्रकाशन के अधीन होंगे।
- (6) इस धारा के अधीन बनाया गया नियम सभी नगरपालिका क्षेत्रों के लिए माध्यम हो सकेगा या एक या अधिक नगरपालिकाओं के सम्पूर्ण या किसी भाग के लिए विशेष हो सकेगा जैसा कि राज्य सरकार निदेश दे।

अध्याय-17

निर्वाचन सम्बन्धी विधाय

परिभाषाएं।

280. इन अध्याय में, जब तक कि मन्त्रों में अन्यथा प्रवेशित न हो, -

- (क) "एजेन्ट" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उनकी निम्नलिखित महामति में उम्मीदवार द्वारा अपने निर्वाचन के लिए किसी निर्वाचन में निम्नलिखित रूप में नियुक्त किया गया हो;
- (ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से धारा 282 के अधीन निर्वाचन अर्जों की सुनवाई का प्राधिकृत अधिकारी, अभिप्रेत है;
- (ग) "उम्मीदवार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है या किए जाने का दावा करता है और ऐसे किसी व्यक्ति को तब से अपनी निर्वाचन में उम्मीदवार मगना जाएगा जब से वह अपने आपको भावी उम्मीदवार के रूप में प्रकट करना प्रारम्भ करता है;
- (घ) "अष्ट आचरण" से धारा 301 में विनिर्दिष्ट कोई आचरण अभिप्रेत है;
- (ङ) "नागत" से निर्वाचन अर्जों के विचारण या उनसे अनुपयोगिता मारी लागत, प्रसार और खर्च, अभिप्रेत है;
- (च) "निर्वाचन" से इन अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी पद को भरने के लिए किया गया निर्वाचन, अभिप्रेत है;
- (छ) "निर्वाचन अधिकारी" से किसी व्यक्ति का किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न खड़े होने प्रथमा दृष्टि करने या मत देने प्रथमा मतदान से विलंब रहने का अधिकारी अभिप्रेत है।

नगर
निर्वाचन
आयोग।

281. (1) नगरपालिकाओं की सहायता सुविधों की तैयारी के लिए बार्डों के परिसीमन, भूकृतिकरण द्वारा स्वतंत्रों के आरक्षण और आवंटन के लिए तथा नगरी निर्वाचनों में संचालन के लिये अक्षेपण, निर्देशन तथा नियन्त्रण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ड तथा 243-य के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 160 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

निर्वाचन
पत्रियों की
सुनवाई
करने के
लिए प्राधि-
कृत अधि-
कारी।

282. (1) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन अर्जियों की सुनवाई नगरपालिका क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले उप-मण्डल अधिकारी (मिनिस्टर) द्वारा की जाएगी।

(2) आयोग अपने नियम विवरित करेगा और अपनी प्रक्रिया अधिकृत करेगा।

निर्वाचन
प्रक्रिया।

283. इस अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन को, सिवाये इस अध्याय के उप-बन्धों के अनुसार निर्वाचन अर्जों उपस्थापित करने, प्रशसन नहीं किया जाएगा।

अर्जों उप-
स्थापित
करना।

284. (1) नगरपालिका का कोई मतदाता, विहित रीति में विहित प्रतिभूति दे देने पर परिणाम के प्रशसन से तीस दिन के भीतर, धारा 296 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक बाधाओं पर, इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के निर्वाचन के विरुद्ध, प्राधिकृत अधिकारों को, विहित निर्वाचन अर्जों उपस्थापित कर सकेगा।

(2) प्राधिकृत अधिकारी को निर्वाचन अर्जी उपस्थापित : जो गई नमज़ी जाएगी—

(र) जब यह प्राधिकृत अधिकारी को—

(i) अर्जी करने वाले व्यक्ति द्वारा परिलक्षित की जाती है; या

(ii) अर्जी करने वाले व्यक्ति द्वारा इन निम्नित निम्नित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाती है; या

(ख) जब यह राजस्वीकृत डाक द्वारा भेजी जाती है और प्राधिकृत अधिकारी को या इसे प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को परामर्श हो जाना है।

285. (1) निर्वाचन अर्जी—

(क) उन तात्त्विक नदियों के संक्षिप्त चयन से युक्त होंगे जिन पर अर्जीदार निर्देश करता है ;

अर्जी की
अनुरोध ।

(ख) उन अष्ट आचरणों की पूर्ण विनिर्दिष्टता उपस्थित करेगा जिन्हें अर्जीदार अभिलेखित करता है, जिसके अन्तर्गत, ऐसा अष्ट आचरण करने के लिए अभिलेखित पक्षधरों के नाम और ऐसे प्रत्येक आचरण के लिए जाने की तारीख और स्थान का क्या सम्भव पूर्ण अभिलेखन भी है; और

(ग) अर्जीदार द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और निम्न प्रक्रिया संहिता, 1908 में अभिवक्तों के अन्वय के लिए प्रसिद्धित रीति में अन्वयित की जाएगी :

परन्तु जहाँ अर्जीदार कोई अष्ट आचरण अधिकारित करता है, वहाँ अर्जी के साथ ऐसे अभिलेखित अष्ट आचरण और उनकी विनिर्दिष्टों के समर्थन में विहित प्रमाणों के साथ-साथ लगाया जाएगा।

(2) अर्जी की कोई अनुपूर्व या उपरान्त, अर्जीदार द्वारा उनी रीति में हस्ताक्षरित और अन्वयित किया जाएगा, जिनमें अर्जी की जाती है।

286. यदि निर्वाचन अर्जी विहित रीति में प्रस्तुत नहीं की जाती है, या अर्जी धारा 284 में विनिर्दिष्ट अर्जी के भीतर उपस्थापित नहीं की जाती है तो, प्राधिकृत अधिकारी अर्जी को खारिज कर देगा।

निर्वाचन
अर्जी की
प्राप्ति पर
प्रक्रिया।

परन्तु अर्जी, अर्जीदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना खारिज नहीं की जाएगी।

287. निर्देश, पक्षधरों को निर्दिष्ट के पक्षधर और कारणों को अभिलेखित करके किसी भी प्रक्रम पर, प्राधिकृत अधिकारी के अगस्त व्यक्ति निर्वाचन अर्जी को वापस ले लेंगे और इसे सुनवाई के लिए राज्य में निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी को अन्वयित कर सकेंगे और ऐसे अन्वयित पर वह प्राधिकृत अधिकारी उन प्रक्रम में जिनमें इसे वापस लिया गया था अर्जी पर कार्यवाही आरम्भ करेगा।

अर्जियों का
वापस लेना
और अन्वयण।

परन्तु ऐसा प्राधिकृत अधिकारी, यदि वह उचित समझे, किसी नाक्षी को निम्न परीक्षण पहले कर लिया गया हो, पुनः बुला सकेंगे और परीक्षण कर सकेंगे।

288. (1) इन अधिनियम के उपबंधों और तदर्थान बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रत्येक निर्वाचन अर्जी की सुनवाई विहित प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद के सुनवाई के लिए लागू प्रक्रिया के अन्वयित किया जाएगा और, इसे धारा 284 के अधीन उपस्थापित किए जाने की तारीख

प्राधिकृत
अधिकारी
के अगस्त
प्रक्रिया।

ये छः मानकों अधीन के होते हैं उन पर विनिश्चय किया जाएगा:

प्राप्त प्राधिकृत अधिकारों को, अधिकारों को, अधिकारिता को, मानकों को, मानकों को परीक्षण करने से इनकार करने का विवेकाधिकार प्राप्त होगा, यदि इन को यह पता हो कि उनका माध्यमों के विनिश्चय के लिए तात्त्विक नहीं है या माध्यमों को पेश करने वाला पक्षारों कुछ अधिकारों पर या कार्यवाहियों को विलम्बित करने के लिए, ऐसा कर रहा है।

(2) इन अधिनियम के अधीन रहते हुए, भारतीय संघ अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के उपबंध सभी प्रकार से निर्वाचित अर्जों के विचारण के लिए लागू समझे जायेंगे।

प्राधिकृत
अधिकारी
के समक्ष
उपसंज्ञाति।

289. प्राधिकृत अधिकारी को समक्ष कोई उपसंज्ञाति, आवेदन या कार्य पक्षार द्वारा व्यक्तिगत रूप में या उसकी ओर से सम्मुख रूप से नियुक्त प्लीडर द्वारा की जा सकेगी या किया जा सकेगा।

प्राप्त प्राधिकृत अधिकारी किसी भी पक्षार को व्यक्तिगत रूप से उपसंज्ञाति होने का निर्देश दे सकेगा, जब भी प्राधिकृत अधिकारी, इसे आवश्यक समझे।

प्राधिकृत
अधिकारी
को
शक्तियाँ।

290. निम्नलिखित मामलों के बारे में विचारण करते समय प्राधिकृत अधिकारी को, वे शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन न्यायालय में निहित हैं:—

- (क) प्रतीकरण और निरीक्षण;
- (ख) नाक्षियों को हजरि कराना और उनके दायें को जमा कराने की अपेक्षा करना;
- (ग) दस्तावेज पेश करने के लिए वाध्न करना;
- (घ) नाक्षियों का शपथ पर परीक्षण;
- (ङ) स्वयं मंजूर करना;
- (च) शपथ-पत्र पर लिए गए साक्ष्य को प्राप्त करना;
- (छ) माक्षियों के परीक्षण के लिए नमूना निशान।

और किसी व्यक्ति को जिसका माध्यम तात्त्विक प्रतीति हो, स्वप्रेरणा से समन और उनका परीक्षण करना तथा यह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345 और 346 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय समक्षा जाएगा।

स्वाधीकरण.—नाक्षियों को हजरि कराने के प्रयोगन के लिए प्राधिकृत अधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमा, हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा होगी।

दस्तावेजों
संभव।

291. निर्वाचित अर्जों को सुनवाई पर, अस्थापित और अविस्तीकृत दस्तावेजों को पेश करने के बारे में लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 93 के उपबंधलागू होंगे।

1951 का 3
43.

मानदण की
गोपनीयता

292. (1) किसी भी ताक्षी या अन्य व्यक्ति से यह बता देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी कि उनसे निर्वाचित में किसी को मत दिया है।

(2) प्रत्येक अधिकारी, लिपिक एजेंट या अन्य व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में मतों के अभिलेखन अभिनवा से सम्बन्धित दस्तियों का पालन करता है, मतों की गोपनीयता को बनाए रखेगा और दाए रखने में सह्यता करेगा और (सिवाय किसी लिपि या उसके अधीन प्राधिकृत लिपि प्रयोगन के) किसी व्यक्ति को ऐसी गोपनीयता या अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई सूचना संतुष्टि नहीं करेगा।

(3) कोई व्यक्ति जो जानबूझकर इस धारा के उल्लंघन में कार्य करता है, दोनों में से किसी भी धारा के अन्तर्गत से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

293. (1) किसी भी माध्यामिक निर्वाचन अर्जी को मूख्य में विवाद दिनांक में नुसंगत किसी विषय के बारे में लिए गए किसी प्रश्न पर उत्तर देने ; इस प्रश्न पर छुट नहीं दी जाएगी जो कि प्रश्न का उत्तर उस अवसर में फंसा गया या उसकी अवधारण में फंसा गया हो सकता है या उसको किसी व्यक्ति या समूह द्वारा जेखिम में डाला जाएगा या जेखिम में डालने का वादा किया जाएगा ;

अवधारण में फंसा जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना और निर्वाचन का प्रभाव ।

परन्तु —

- (i) वह माध्यामिक जो उन्हें उसी प्रश्नों पर सही उत्तर देना है जिसका उत्तर देने की उम्मीद उपेक्षा की जाती है, प्राधिकृत अधिकारी से परीक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का हवाला होगा ; और
- (ii) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा या उसके समक्ष पूछे गए प्रश्नों का माध्यामिक द्वारा दिया गया उत्तर, उस माध्यामिक सम्बन्धी शायद भंग के लिए दार्ष्टिक सार्व-वाही के बारे में माध्यामिक के विषय में किसी निमित्त या दार्ष्टिक सार्व-वाही में उसके विरुद्ध माध्यामिक में प्रारूप नहीं होगा ।

1960
का 45

(2) अब किसी माध्यामिक की परीक्षण प्रमाण-पत्र दे दिया जाता है, तो उन द्वारा उनका किसी न्यायलय में अभिव्यक्त किया जा सकता और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय 9-न के अधीन उस विषय में किसी ऐसे प्रमाण-पत्र सम्बन्धित है, प्रोद्भव होने वाले किसी आरोप पर या उनके विरुद्ध और पूरी प्रतिक्रिया करेगा, किन्तु वह उस दण्डाभिव्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिराजित निर्वाचन में सम्बन्धित किसी ऐसे निर्वाचन में, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होगा ।

294. माध्यामिक को हजिर होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा उपगत व्यक्तिगत वय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को अनुवाद दिया जा सकता और जब तक प्राधिकृत अधिकारी अन्यथा निर्देश न दे, वह अलग का भान उत्तरा जाएगा ।

माध्यामिक के वय ।

295. (1) जहाँ कोई निर्वाचन अर्जी प्राप्त 296 के अधीन खारिज नहीं की गई है, वहाँ प्राधिकृत अधिकारी निर्वाचन अर्जी के अन्तर्गत में जांच करेगा और जांच की सम्पत्ति पर—

प्राधिकृत अधिकारी का विनि-मय ।

- (i) निर्वाचन अर्जी को खारिज करेगा ; या
- (ii) निर्वाचन अर्जा को सही कर देगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आदेश करते समय प्राधिकृत अधिकारी यह आदेश भी करेगा,—

- (i) जहाँ निर्वाचन में लिए गए किसी प्रष्ट अवधारण की अर्जी में आरोप लगाया गया हो, यह अभिव्यक्ति करते हुए कि—
- (i) निर्वाचन में लिए गए किसी प्रष्ट अवधारण का किया जाना निन्दित हुआ है, या नहीं और उन प्रष्ट अवधारण की प्रकृति ; और
- (ii) उन सभी व्यक्तियों के नाम, यदि कोई हों जिनके बारे में विचारण में यह सिद्ध हुआ है कि वे किसी प्रष्ट अवधारण के दोषी हैं और उन अवधारण की प्रकृति ; और

(ख) संदेश लागू की कुछ राशियाँ निश्चित हों और उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करते हों, जिन द्वारा और जिनको लागू संदेश की जाएगी :

परन्तु वह व्यक्ति, जो अर्जा में पक्षकार नहीं है, खण्ड (1) के उप-खण्ड (2) के अधीन आदेश में नामित नहीं किया जाएगा, जब तक कि —

- (i) उसे प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष हाजिर होने और यह कारण बताने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो कि, उसे इन प्रकार क्यों नामित किया जाए; और
- (ii) यदि वह नोटिस के अनुमरण में हाजिर होता है, उसे किसी माधो की प्रतिपरीक्षा करने जिसका प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पहले परीक्षण किया जा चुका है और उसकी विरुद्ध साक्ष्य दिया है, अपनी प्रतिपरीक्षा में साक्ष्य देने और सुनवाई का अवसर दिया गया है।

निर्वाचन
अपास्त
करने के
लिए
आधार।

296. (1) यदि प्राधिकृत अधिकारी को यह पता हो कि —

- (क) निर्वाचित व्यक्ति अपने निर्वाचन की तारीख को इन अधिनियम के अधीन निर्वाचन के लिए अर्हित नहीं था या निर्वाचित था; या
- (ख) निर्वाचित व्यक्ति या उसके एजेंट द्वारा या निर्वाचित व्यक्ति या उसके एजेंट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अपराध आचरण किया गया है; या
- (ग) किसी नामनिर्देशन को अनुचित रूप से रद्द कर दिया गया है; या
- (घ) निर्वाचन का परिणाम, जहाँ तक यह निर्वाचित व्यक्ति से सम्बन्धित है, निर्वाचन रूप से निम्नलिखित द्वारा प्रभावित हुआ है —
 - (i) किसी नामनिर्देशन की अनुचित स्वीकृति द्वारा; या
 - (ii) किसी मत के अनुचित ग्रहण, इत्यादि या स्वीकृति अथवा किसी मत के ग्रहण द्वारा जो गलत है, या
 - (iii) इन अधिनियम या इन अधिनियम के अधीन बचाए गए किसी नियमों के उपबन्धों के किसी अननुपालन द्वारा, तो प्राधिकृत अधिकारी निर्वाचित व्यक्ति को अपास्त कर देगा।

(2) जब उप-धारा (1) के अधीन किसी निर्वाचन को अपास्त कर दिया जाता है, तो नया निर्वाचन परमात्रा जाएगा।

निर्वाचन
छत्रियों का
उपशमन।

297. निर्वाचन अर्जा का उपशमन केवल एतन्मात्र अर्जाकार या कई अर्जाकारों के उत्तर-जवाबों को मिला पर ही होगा।

खर्च और
प्रतिभूति
निर्देशों में
ने मदाय
और ऐसे
निर्देशों को
वापसी।

298. (1) खर्च, जिनके अन्तर्गत प्लीडर की फीस भी है, प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधीन होगी।

(2) यदि इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन खर्चों के बारे में किसी आदेश में, किसी पक्षकार द्वारा किसी व्यक्ति को खर्चों को मदाय किए जाने के लिए निर्देश है, तो ऐसे खर्च यदि वे पहले संदेन नहीं किए गए हों, तो उस व्यक्ति द्वारा जिसके पक्ष में खर्च अधिनियमित किए गए हैं, ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उपानुक्त को इन निर्मित निर्देशों के आदेशन किए जाने पर, इस अध्याय के अधीन ऐसे पक्षकार द्वारा किए गए प्रतिभूति निर्देशों को पूर्णतः या जहाँ तक सम्भव हो संदेन किए जाएंगे।

(3) यदि इस अध्याय के अधीन प्रस्तावित नियमों के अन्तर्गत (1) के तहत का उप-धारा में विनिर्दिष्ट वर्षों के सदन के प्रत्येक कोई अधिवेशन बच जाता है, तो ऐसा अधिवेशन, या जहाँ खर्चा अधिवर्षों में नहीं किया गया है, उचित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया गया है तो उक्त सम्पूर्ण प्रतिनिधि निक्षेप, उक्त अधिवेशन द्वारा, जिसने प्रतिनिधि निक्षेप को है, या यदि ऐसे व्यक्ति या गैर-निक्षेप करने के पश्चात् देहान्त हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के निधिम प्रतिनिधि द्वारा इन निमित्त उपायवत को निधिम आवेदन किए जाने पर, तथा स्थिति, उक्त व्यक्ति को या उनके निधिम प्रतिनिधि द्वारा इस निमित्त उपायवत को निधिम आवेदन किए जाने पर, व्यवस्थित, उक्त व्यक्ति को या उनके निधिम प्रतिनिधि को वपन किया जाएगा।

290. इस अध्याय के उपधाराओं के अधीन खर्चों के बारे में आदेश ऐसे प्रधान निधिम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है जिसकी अधिपति का स्थानीय न्यायाधीशों के भीतर उन व्यक्ति या निमित्त या निमित्त का स्थान है, जिसे कोई प्रस्तावित संदेश के लिए ऐसे आदेश द्वारा निदेश दिया गया है और ऐसे न्यायालय आदेश को उक्त सदन में और उक्त प्रक्रिया द्वारा निष्पादित किया जा निष्पादित प्रकाशित, सदन कि वह वह में धन के सदृश के लिए उनके द्वारा की गई ठीकी हो।

उक्त
प्रस्तावों
आदेशों का
निष्पादन।

परन्तु जहाँ धारा 298 की उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तावित आवेदन द्वारा, की गई खर्च या उसके किसी भाग की कमी की जाए, वहाँ इस धारा के अधीन कोई आवेदन ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि वह किसी खर्चों के उक्त अधिवर्षों के अन्तर्गत की जाया न हो, जो उन उप-धारा की अधिनियम किए गए आवेदन के पश्चात् उक्त उप-धारा में विनिर्दिष्ट प्रतिनिधि निक्षेपों को या उनके कार्यालयों के कारण बच नहीं किया जा रहा है।

300. धारा 301 में विनिर्दिष्ट अष्ट आचरण, उक्त तारीख में सम्मिलित छः वर्षों की अवधि के लिए, जिसको ऐसे आचरण के सम्बन्ध में प्राथमिक अधिपति का निक्षेप दिया गया है नगरपालिका की सदस्यता के लिए निरन्तर जारी है।

अष्ट
आचरण
जिनसे
निर्वाह हो
जाती है।

परन्तु सरकार, कारणों को अधिलिखित करते हुए, निरन्तर की हट सकती या उनकी अवधि कम कर सकती।

301. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अष्ट आचरण समझे जाएंगे —

अष्ट
आचरण।

(i) स्थित अर्थ —

(अ) किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा अथवा उम्मीदवार या उसके एजेंट को सहमत से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को वह वोट जो वोट भी हो, किसी परिस्थिति या दान, प्रत्याभूति या वचन जिसका उद्देश्य इच्छितः या परीक्षातः है—

(क) किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न होने के लिए, या उम्मीदवारी वापस लेने के लिए; या

(ख) किसी निर्वाचन में नगरपालिका क्षेत्र के मतदाता को वोट देने या वोट देने से विरत रहने के लिए, या निम्नलिखित को नगरपालिका के लिए उम्मीदवार करना —

(i) किसी व्यक्ति को एक प्रकार खड़े होने या खड़े न होने का, या उम्मीदवारी को वापस ले लेने का; या

(ii) नगरपालिका क्षेत्र के किसी मतदाता को इस बात के लिए कि उसने मत दिया है या वोट मत देने से विरत रहा है :

(आ) निर्मातृलिखित द्वारा किसी परितोषण की प्राप्ति या प्राप्त करने का अस्वर, चाहे पुरस्कार के रूप में या हस्तक्षेप के रूप में—

(क) किसी व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या, उम्मीदवारी बाधित होने ; या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा जिस किसी को अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के लिए, या नगरपालिका क्षेत्र के किसी मतदाता को मत देने या मतदान करने से विरत रहने के लिए, या किसी उम्मीदवार को प्रती उम्मीदवारी बाधित होने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करना ।

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए शब्द 'परितोषण' धनीय परितोषण या धन से प्राकटलनीय परितोषणों तक ही निर्बन्धित नहीं है और इनके अन्तर्गत सभी प्रकार के सत्कार और पुरस्कार के लिए सभी प्रकार के नियोजन भी हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत किसी निर्वाचन में या निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए आदभावपूर्णता उत्पन्न किन्हीं व्यक्तियों का संदाय नहीं है ।

(2) अनुचित प्रभाव, प्रभाव, किसी निर्वाचित अधिकारी के अवधि प्रयोग में उम्मीदवार या उनके एजेंट की ओर से या उम्मीदवार या उनके एजेंट की बहुमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न :

परन्तु—

(क) इस खण्ड के उपबन्धों की व्यापकता पर आनुगत प्रभाव डालने बिना, उनमें तथा विनिर्दिष्ट ऐसा कोई व्यक्ति, जो --

(i) किसी उम्मीदवार या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने उम्मीदवार लिखित है, किसी प्रकार की क्षति जिसके अन्तर्गत आत्मसिद्ध बहिष्कार और किसी जाति या नस्ल से बाहर करना या निष्काशन भी है, पहुँचाने की धमकी देता है ; या

(ii) किसी उम्मीदवार या नगरपालिका क्षेत्र के किसी मतदाता को मत विरत करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें वह हितवर्त है, देवी अग्रनाथ या आद्यशक्ति परितोषण का पात्र हो जायेगा या बना दिया जाएगा ;

इस खण्ड के अर्थ के अन्तर्गत ऐसे उम्मीदवार या नगरपालिका क्षेत्र के मतदाता के निर्वाचन अधिकार के अवधि प्रयोग में हस्तक्षेप करता हुआ समझा जाएगा ।

(2) लोक नीति को कोई धावणा या लोक कार्यवाई का वचन, अथवा निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के अन्तर्गत किसी विधिक अधिकार का प्रयोग इस खण्ड के अर्थ के अन्तर्गत हस्तक्षेप नहीं समझा जाएगा ।

(3) किसी व्यक्ति को उनके धर्म, सुवर्ण जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या न देने से विरत रहने को उम्मीदवार या उनके एजेंट द्वारा

अथवा उम्मीदवार या उनके एजेंट द्वारा अथवा किसी उम्मीदवार या उनके एजेंट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उन उम्मीदवार के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अप्रसर करने के लिए या किसी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा को जगाना या संचारित करना या संचारित करने का प्रयत्न करना।

(4) किसी उम्मीदवार या उनके एजेंट द्वारा अथवा किसी उम्मीदवार या उनके एजेंट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उन उम्मीदवार के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अप्रसर करने के लिए या किसी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा को जगाना या संचारित करना या संचारित करने का प्रयत्न करना।

(5) किसी उम्मीदवार या उनके एजेंट द्वारा अथवा उम्मीदवार या उनके एजेंट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार के वैयक्तिक चरित्र या आचरण के सम्बन्ध में, या किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी या उम्मीदवारी वापस लेने के बारे में उम्मीदवार की निर्वाचन सम्भाव्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए यथोचित रूप से प्रकल्पित कथन होते हुए किसी ऐसे तथ्य के कथन का प्रकाशन जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसको या तो विश्वास है या तथ्य होने का विश्वास नहीं है।

(6) उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा अथवा उम्मीदवार या उसके एजेंट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे संदाय पर या अन्यथा, नगरपालिका क्षेत्र की किसी मतदाता, समा सदस्य (स्वयं उसके कुटुम्ब के सदस्य या एजेंट से भिन्न) को किसी मतदान केंद्र या मतदान के लिए नियत स्थान को या वहां से ले जाने के लिए किसी यान को भाड़े पर ले लेना या उत्पात करना।

स्पष्टीकरण:—इन खंड में शब्द "यान" से अभिप्रेत है कोई ऐसा यान, जो सड़क परिवहन के प्रवाजन के लिए उपयोग में लाया जाता है या लागू जाने योग्य है, चाहे वह यांत्रिक शक्ति से चालित है या अन्यथा और चाहे अन्य यानों को खींचने के लिए उपयोग में लाया जाता है या अन्यथा।

(7) उस उम्मीदवार की निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अप्रसर करने के लिए किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा, अथवा उम्मीदवार या उसके एजेंट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति से जो सरकार, भारत सरकार, या किसी अन्य राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की सेवा में है, कोई सहायता अभिप्राप्त करना या उत्पात करना अथवा अभिप्राप्त या उत्पात करने का प्रयत्न या दुर्व्यवहार करना।

302. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इन अध्याय के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश से व्यतिरिक्त कोई व्यक्ति, विहित समय और विहित रीति में नगरपालिका क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले निदेशों को अपील कर सकता और वह 90 दिन के भीतर अपील का निपटारा करेगा और अपील पर उभय विनिश्चय अंतिम होगा।

अपीलें।

303. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी —

- (क) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए या बनाए जाने के लिए तत्परित्यक्त निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से सम्बन्धित किसी विधि की विधिवान्यता को किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा;
- (ख) प्राधिकृत अधिकारी के प्रस्तुत की गई निर्वाचन याचिका द्वारा तथा ऐसी रीति में जो नियमों द्वारा विहित की जाए क निवाय, किसी नगरपालिका का कोई निर्वाचन प्रशंगत नहीं किया जाएगा।

निर्वाचन के मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक।

- निर्वाचन के मतदान के लिए निर्वाचन में सम्बन्धित सभी मामलों के लिए निर्णय बना सकेंगी।

अध्याय-18

प्रकीर्ण

नगर- 305. (1) प्रत्येक नगरपालिका परिषद् में एक कार्यकारी अधिकारी और प्रत्येक पालिकाओं में कार्य- नगर पंचायत में एक सचिव होगा, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और नगर को ऐसी शक्तों द्वारा अर्पित होगा जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) यथास्थिति, कार्यकारी अधिकारी और सचिव का यह कर्तव्य होगा की वह, यथास्थिति, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के अध्यक्ष का इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उनके कर्तव्य के निर्वहन में सहायता करे।

(3) इस अधिनियम के अधीन या द्वारा अभिव्यक्त रूप में उपविधियों के सिवाये उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी—

- (क) इस अधिनियम द्वारा या अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उम्मेद्विननिर्दिष्ट रूप में अधिरोपित और प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा ;
- (ख) सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार नगरपालिका के अधीन पदधारण करने वाले अधिकारियों और पदधारियों का पर्यवेक्षण और निगरान तथा तत्समय अधिस्थित करेगा ;
- (ग) नगरपालिका के सभी संस्थानों के निष्पादन का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करेगा ;
- (घ) नगरपालिका के सभी संस्थानों और विभाग स्तरों के नीचे निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय करेगा ;
- (ङ) नगरपालिका और इसकी स्थायी समितियों और अन्य समितियों की बैठकों की कार्यवाहियों में सम्बन्धित सभी लेखन पत्रों और दस्तावेजों तथा सामान्य मुद्रा को अभिरक्षा में रखेगा ;
- (च) नगरपालिका निधि में से धन निकालेगा और उचित वितरण करेगा ;
- (छ) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं ;
- (ज) नगरपालिका की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होगा और इसकी किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने और विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकारी होगा किन्तु उसे किसी संस्थान को चलान या मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। यदि उसकी राय में कोई प्रस्ताव इस अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई किसी अन्य विधि, नियम या आदेश के उपबन्धों में अंगत है या उनका उल्लंघन करता है तो उसका यह कर्तव्य होगा कि वह उसे सरकार के नोटिस में लाए।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे में किसी नगरपालिका में सम्बन्धित धन, भूखे, अभिलेख और अन्य सम्पत्ति है, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी को इस प्रयोजन के लिए लिखित सन्देश पर तत्काल ऐसे धन को या ऐसे लेखों, अभिलेखों और अन्य सम्पत्ति को उक्त अधिकारी को या अधीनस्थ में उन्हें प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को सौंप देना या परिदस्त करना।

(5) कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका के नोटिस में, नगरपालिका के ऐसे किसी कार्य या माल को नाएगा, जो नगरपालिका के किसी अनुदेश या इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करता हो, किन्तु यदि, यथा स्थिति, ऐसे कार्य या माल को अनुदेशों या इस अधिनियम के उपबन्धों में बूट की संयुक्तता के 15 दिनों के भीतर परिष्कारित नहीं कर दिया जाता तो, कार्यकारी अधिकारी या वह उत्तंभ होगा कि वह ऐसा बूट या उल्लंघन को सरकार के नोटिस में लाए।

306 (1) इस अधिनियम और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994 में अन्तर्निहित उपबन्धों के अन्तर्गत रहने हुए, नगरपालिका, राज्य सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से ऐसे अधिकारियों और भवकों को नियुक्त कर सकेंगे जिन्हें वह अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन के लिए आवश्यक समझे।

नगर-
पालिका
में पद और
उनकी
नियुक्ति।

(2) ऐसे अधिकारियों और भवकों की अर्हताएं, भर्ती का इरादा, छुट्टियां, भत्ते और अनुशासनात्मक विषयों सहित सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

(3) इस अधिनियम के अधीन, नगरपालिका के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियोजित नदस्तियों को उनकी सेवा-शर्तों के अनुसार अपेक्षित वेतन, भत्ते, उपदान, पेंशन, अंगदान और अन्य संदाय नगरपालिका निधि से विहित रीति में प्रभावित किए जाएंगे।

(4) नगरपालिका के नियोजित नियोजन में कोई अधिकारी या पदाधिकारी भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के अधीन उसको अनुज्ञेय अंगदायी भविष्य निधि के बदले में सेवा और परिवार पेंशन के लिए अपना वित्त दे सकेगा और उस दान में वह राज्य सरकार के कर्मचारियों को यथा लागू नियमों द्वारा शामिल होगा, और ऐसा व्यक्ति सामान्य भविष्य निधि में अभिदाय करेगा :

परन्तु —

(क) नगरपालिका द्वारा अंगदान के धन के भाग, उस पर प्रोद्भूत व्याज सहित जो ऐसे व्यक्ति के अंगदान भविष्य निधि में जमा है, उस प्रयोजन के लिए स्थापित पेंशन और उपदान निधि में जमा किया जाएगा;

(ख) धन का भाग, इस पर प्रोद्भूत व्याज सहित उसके अपने अंगदान के कारण ऐसे अंगदान भविष्य निधि में जमा किया गया है, इस प्रयोजन के लिए स्थापित सामान्य भविष्य निधि खाते में अन्तर्लिप्त किया जाएगा और सेवा के दौरान आह्वरण द्वारा नगरपालिका को हुए किसी घाटे को उसके द्वारा पूरा किया जाएगा।

(5) नगरपालिका, उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिन्होंने उप-धारा (1) के अधीन पंजन के लिए वित्त का प्रदान किया है, अपने अंगदान को नियमित रूप से, परन्तु आगामी मास जिससे कि अंगदान सम्बन्धित है, मास के पाँचवें दिन तक पंजन और उपदान में जमा करेगा।

(6) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट "गिज़ा" और "उपदान निधि" और सम्मान्य निधि निधि निदेशन अहरी स्थानीय नि.ाय हिमचल प्रदेश द्वारा ऐसी रीति में जो विहित की जाए, स्थापित किया जाएगा और रखा जाएगा।

(7) इस अधिनियम में किसी बात के प्रतिफल होते हुए भी वे व्यक्ति भी जो 1-4-92 को किसी नगरपालिका की नियमित सेवा में थे और 30 मई, 1994 से पहले सेवा निवृत्त हो गए हैं, इस अधिनियम के अधीन सेवा और संदेय कुटम्ब पेंशन के लिए पात्र होंगे, परन्तु यह तब जबकि वे इस धारा के अधीन सेवा और कुटम्ब पेंशन के लिए आवश्यक और निदेशन की ऐसी अवधि के भीतर जो निर्दिष्ट की जाए, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजन के अभिदाय का, नियोजन से उन द्वारा प्राप्त ब्याज सहित, इसके नि.ालने की तारीख से प्रतिसंदय की तारीख तक उस पर छः प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ प्रतिदाय करें।

(8) नगरपालिका में पदों का सृजन निदेशन द्वारा, नगरपालिका की आवश्यकता में और इसकी वित्तीय क्षमता को देखते हुए किया जाएगा।

(9) इस धारा में निर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्ति करते समय, नियुक्ति प्राधिकारी, सरकार द्वारा नियुक्तियों के आरक्षण या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग की वास्तव समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों, का अनुपालन करेगा।

अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का नगरपालिका के साथ किसी संबंध इत्यादि में हितवद्ध न होना।

307. (1) कोई भी व्यक्ति नगरपालिका में, नियुक्ति के लिए विहित हो जाएगा, यदि वह प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वयं के साथ की गई किसी संबद्ध या भागीदार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नगरपालिका के साथ की गई किसी संबद्ध या उसके लिए किए जा रहे किसी संयम में उसके कर्मचारी होने से अन्यथा कोई अंश या हित रखता है।

(2) यदि ऐसा कर्मचारी प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वयं या भागीदार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उप-धारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी किसी संबद्ध या संक्रम में कोई अंश या हित रखता है तो वह, जब तक कि उस नियुक्ति करने वाली प्राधिकारी जिन्हीं विशिष्ट मामलों में अन्यथा विनियमित करे, ऐसे प्राधिकारी के आदेशों से, अपने पद से हटाए जाने के लिए दायी होगा।

परन्तु हटाए जाने का आदेश करने से पूर्व ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के सम्बन्ध में, कारण बताने का सुक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

कतिपय अधिकारियों और पदधारियों के अवचर के बारे में रिपोर्ट और जांच करने की शक्ति।

308. (1) नगरपालिका को किसी सदस्य द्वारा या शिकायत किए जाने पर कि नगरपालिका के किसी अधिकारी या पदधारी या सरकार के किसी अन्य अधिकारी या पदधारी ने नगरपालिका के ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जिन्हें सरकार से अधिसूचना द्वारा इस धारा के उपबन्धों को विस्तारित किया है, अपने पदीय हैसियत में अवचर किया है तो नगरपालिका मामले में जांच करेगी और ऐसे विरुद्ध अधिकारियों को जिनसे कि यह सम्बन्धित है या, यथास्थिति, उपायुक्त या उप-मण्डल अधिकारी (सिविल) को प्रथम दृष्टया साध्य सहित रिपोर्ट भेजेगी और उक्त अधिकारी ऐसा आगामी जांच करने के पश्चात् जो कि अपेक्षित हो निदेशन और नगरपालिका को संसूचित करके युक्तियुक्त कार्रवाई करेगा।

(2) किसी सदस्य द्वारा ऐसी रिपोर्ट किए जाने पर कि नगरपालिका के किसी अधिकारी या पदधारी या सरकारी अधिकारियों या पदधारियों के किसी वर्ग ने नगरपालिका के जिन्हें ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में जिन्हें कि सरकार ने अधिसूचना द्वारा इस धारा के उपबन्धों तक विस्तारित किया है के अधीन या किसी विधि या नियम द्वारा अधिरोपित जिन्हें कर्तव्यों के निर्वहन में असफल रहा है तो नगरपालिका सूचना द्वारा युक्तियुक्त अवधि नियत करके उससे कर्तव्यों के निर्वहन की अपेक्षा कर सकेगी और उसके ऐसा करने में

असफल रहने पर सम्बन्धित बरिष्ठ अधिकारियों को या उपायकों को मामले को फिरोई देनी और उक्त अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जो निरक्षित हो निदेशों को नगरपालिका को सूचना के अधीन पुनस्तयुक्त निर्देश देना।

309. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा कोई ऐसी बात कर सकेगी जो उसके उपबन्धों से असंगत न हो जो इसकी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन में इस आवश्यकता या सर्वाधिक प्रतीत हो :

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस धारा के अधीन, इस अधिनियम के प्रारम्भ संश्लेष को अधिध की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश विधान सभा के फल पर रखा जाएगा।

310. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को और से, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 (जिसे इसके पश्चात् निरक्षित अधिनियम कहा गया है) निरक्षित हो जाएगा :

1968 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं 0 19 का निरक्षण।

परन्तु निम्न निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा,—

- (क) निरक्षित अधिनियम का पूर्व प्रवर्तन या तद्वर्धन की गई या होने दी गई बात ; या
- (ख) निरक्षित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व ; या
- (ग) निरक्षित अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के बारे में उपगत कोई शास्ति, सम्पहरण या दण्ड ; या
- (घ) निरक्षित ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, सम्पहरण या दण्ड से सम्बन्धित किसी अन्वेषण, विधिगत कार्यवाही, या उपकरण और ऐसा अन्वेषण, विधिगत कार्यवाही या उपकरण संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति सम्पहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं किया गया हो :

परन्तु यह और नि पुनर्वर्ती परन्तु के अधीन रहते हुए निरक्षित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई (जिसके अन्तर्गत की गई कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी की गई अधिसूचना, नोटिस, आदेश, अनुदेश या निदेश, विरचित नियम, विनियम, उप-विधियां बनाई गई योजना, प्राप्त प्रमाण-पत्र, मंजूर किया गया अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति, किया गया रजिस्ट्रेशन, अधिरोपित कर या उद्गृहीत फीस या रेंट है) जहां तक इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त और इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है, अधिनियम के और तदनुसार प्रवृत्त कर्ता रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्यवाई द्वारा अधिग्रहण नहीं कर दी जाती।

- (2) विद्यमान नगरपालिकाएं अपनी बालावधि के अवधान तक बनी रहेंगी जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या विधान सभा द्वारा पारित संकल्प द्वारा, उस से पहले ही विषटित नहीं कर दिया जाता है।
- (3) निरसित अधिनियम के अधीन विद्यमान नगरपालिकाओं के लिए व्यवस्था तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन तत्स्थानी नगरपालिका का गठन नहीं किया जाता है।

1994 के
अध्यादेश
संख्यांक 2
का निरसन।

311. (1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अध्यादेश, 1994 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अध्यादेश, 1994 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

अनुसूची-1

[धारा 3 (2)]

नगरपालिका परिषदें

भाग-1

क्रम संख्या	नगरपालिका समिति का नाम	पुनः नामित नगरपालिका परिषदें
1.	2.	3.
1.	नगरपालिका समिति, रामपुर	नगरपालिका परिषद, रामपुर
2.	नगरपालिका समिति, ठियांग	नगरपालिका परिषद, ठियांग
3.	नगरपालिका समिति, सोलन	नगरपालिका परिषद, सोलन
4.	नगरपालिका समिति, नालागढ़	नगरपालिका परिषद, नालागढ़
5.	नगरपालिका समिति, नाहन	नगरपालिका परिषद, नाहन
6.	नगरपालिका समिति, पौंटा साहिब	नगरपालिका परिषद, पौंटा साहिब
7.	नगरपालिका समिति, श्री नैना देवी जी	नगरपालिका परिषद, श्री नैना देवी जी
8.	नगरपालिका समिति, विलासपुर	नगरपालिका परिषद, विलासपुर
9.	नगरपालिका समिति, ऊना	नगरपालिका परिषद, ऊना
10.	नगरपालिका समिति, हमीरपुर	नगरपालिका परिषद, हमीरपुर
11.	नगरपालिका समिति, धर्मशाला	नगरपालिका परिषद, धर्मशाला
12.	नगरपालिका समिति, कांगड़ा	नगरपालिका परिषद, कांगड़ा
13.	नगरपालिका समिति, नूरपुर	नगरपालिका परिषद, नूरपुर
14.	नगरपालिका समिति, पालमपुर	नगरपालिका परिषद, पालमपुर
15.	नगरपालिका समिति, चम्बा	नगरपालिका परिषद, चम्बा
16.	नगरपालिका समिति, डलहौजी	नगरपालिका परिषद, डलहौजी
17.	नगरपालिका समिति, मण्डी	नगरपालिका परिषद, मण्डी
18.	नगरपालिका समिति, सुन्दर नगर	नगरपालिका परिषद, सुन्दरनगर
19.	नगरपालिका समिति, कुल्लू	नगरपालिका परिषद, कुल्लू

नगर पंचायतें

भाग-II

क्रम संख्या	अधिसूचित क्षेत्र समिति का नाम	पुनः नामित नगर पंचायतें
1.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, ढली	नगर पंचायत, ढली
2.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, मुन्नी	नगर पंचायत, मुन्नी
3.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, नारकण्डा	नगर पंचायत, नारकण्डा
4.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, कोटखाई	नगर पंचायत, कोटखाई
5.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, जुब्बल	नगर पंचायत, जुब्बल
6.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, चौपाल	नगर पंचायत, चौपाल
7.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, रोहडू	नगर पंचायत, रोहडू
8.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, अर्की	नगर पंचायत, अर्की
9.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, परवाणू	नगर पंचायत, परवाणू
10.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, राजगढ़	नगर पंचायत, राजगढ़
11.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, मराहन	नगर पंचायत, मराहन
12.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, घमारखी	नगर पंचायत, घमारखी
13.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, तलाई	नगर पंचायत, तलाई
14.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, शगरेट	नगर पंचायत, शगरेट
15.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, दालतपुर चौक	नगर पंचायत, दालतपुर चौक
16.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, मेहतपुर	नगर पंचायत, मेहतपुर
17.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, सताखगढ़	नगर पंचायत, सताखगढ़
18.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, नर्दान	नगर पंचायत, नर्दान
19.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, मुजानपुर	नगर पंचायत, मुजानपुर
20.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, भोटा	नगर पंचायत, भोटा
21.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, ज्वाला जी	नगर पंचायत, ज्वाला जी
22.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, देहरा	नगर पंचायत, देहरा
23.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगरौटा बगदां	नगर पंचायत, नगरौटा बगदां
24.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, चौवाड़ी	नगर पंचायत, चौवाड़ी
25.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, रिवालभर	नगर पंचायत, रिवालभर
26.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, सरकाघाट	नगर पंचायत, सरकाघाट
27.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, जोगिन्दरनगर	नगर पंचायत, जोगिन्दरनगर
28.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, मनौली	नगर पंचायत, मनौली
29.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, भुन्तर	नगर पंचायत, भुन्तर
30.	अधिसूचित क्षेत्र समिति, बंजार	नगर पंचायत, बंजार

उद्देश्यों और कारणों का कथन

नगरीय स्थानीय निकाय, नियमित और नियतकालिक चुनावों की असफलता, लम्बे समय तक अधिकरण, कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, शक्तियों का अपर्याप्त न्यायमन और वित्तीय स्रोतों की कमी इत्यादि कारणों से कमजोर और अप्रभावी रहे हैं। संसद द्वारा, संविधान (74वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 मुख्यतः उपरोक्त कमियों का निराकरण करने और नगरीय स्थानीय निकायों अर्थात् देश में नगरपालिकाओं और नगर निगमों को लक्षित बनाने और पुनरजीवित करने को उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है ताकि वे नगरों और शहरों में नगरीय जनसंख्या की बढ़ती हुई मांगों को पूरा कर सकें। इससे संविधान के अनुच्छेद 243-य च द्वारा अनुदत्त, प्रथम जून, 1994 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अन्तःकालीन अवधि के भीतर हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 के विद्यमान उपबन्धों के पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी। हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 के उपबन्धों को संवैधानिक संशोधनों के अनुरूप बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अध्यादेश, 1994 (1994 का 2) 30 मई, 1994 को प्रस्तापित किया गया। उक्त अध्यादेश को अब निम्नित अधिनियमित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को उपांतरणों सहित प्रतिस्थापित करने के लिए है।

जय बिहारो लाल खाची,
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख 19 सितम्बर, 1994.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक में अन्तर्लिखित उपबन्ध अधिनियमित होने पर, विद्यमान हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 को प्रतिस्थापित करेगा। विधेयक के खण्ड 65 और 66 नगरपालिकाओं को प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण, जैसे सम्पत्ति कर, व्यवसायिक कर, यानों और पशुओं पर कर, विद्युत के उपभोग पर कर, विज्ञापनों पर कर मनोरंजन कर इत्यादि के लिए सशक्त करते हैं। इन करों के सम्पूर्ण आगम खण्ड 52 के अधीन प्रदेश नगरपालिका के लिए गठित नगरपालिका निधि में जमा किए जाएंगे। खण्ड 64 के अधीन, राज्य वित्त आयोग क्षेत्रीय स्थानीय निकाय को वित्तीय स्थिति का पुनर्विचार करेगा और सरकार को उन सिद्धान्तों के बारे में सिफारिश करेगा जिन द्वारा राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, पयकरों और फीसों के आगमों को राज्य और नगरपालिकाओं के बीच वितरित किया जाएगा तथा नगरपालिकाओं को राज्य सरकार की संचित निधि से सहायता अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य में नगरपालिकाओं के कार्यों के संयोजन के लिए, खण्ड 35 निदेशालय नगरीय स्थानीय निधाय गठित करने का उपबन्ध करता है। यद्यपि विधेयक के उपबन्ध राज्य सरकार के पास उपलब्ध विद्यमान प्रशासनिक तन्त्र के माध्यम से कार्यान्वित किए जाएंगे तथापि राज्य सरकार को राज्य में स्थानीय निकायों को वित्तीय महायुता देने पर और विद्यमान स्थानीय निकाय के निदेशालय को सुदृढ़ बनाने के लिए राजकोष से प्रतिवर्ष बीस लाख रुपये का आवर्ती व्यय और पांच लाख रुपये का अनावर्ती व्यय अतिरिक्त उपगत करना पड़ेगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 13(3), 23(3), 165(2), 221(4), 279 और 304 विधेयक के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करेंगे। खण्ड 34 और 218 नगरपालिकाओं को उनके कारवार के संचालन और उनके कर्तव्यों के पालन के लिए राज्य सरकार को उप-विधियाँ बनाने के लिए सशक्त करते हैं। इनके अतिरिक्त, खण्ड 51, 172(2), 202, 203, 204 और 214 नगरपालिकाओं को उनमें वर्णित विधियों के बारे में उप-विधियाँ बनाने के लिए सशक्त करते हैं। प्रत्यायोजित की जाने वाली शक्तियाँ प्रस्तावित विधान के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हैं और सामान्य प्रकृति की हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नसित संख्या एल0 एस0 जी0-1-ए (3)2/91)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका विधेयक, 1994 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

कारणों के कथन का स्पष्टीकरण : जनसे हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अध्यादेश, 1994 (1994 का 2) में उपांतरण आवश्यक हुआ

नगरीय नगरपालिका निवासियों के नुसार कम से कम कार्य के लिए, कार्यवाहक अधिकारियों को, सम्बन्धित नगरपालिका के पूर्व अनुमोदन से नगरपालिका की सम्पत्तियों से संव्यवहार करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत करने के लिए खण्ड 57 में उपांतरण करना आवश्यक हो गया है। खण्ड 102, 203, 209 और 210, यह निश्चित करने के लिए उपान्तरित किए जा रहे हैं कि भूमि की परत का, जिस पर भवनों का निर्माण किया जाना है, निर्माण की प्रथम प्रवस्था में भू-विज्ञान की दृष्टि से परीक्षण कर लिया गया है और भवन प्रचालन पूर्णतया अनुमोदित भवन रेखांक के अनुसार किए हैं। निर्वाचन विवाद ने सम्बन्धित खण्ड 281, 282, 292 और 302 को पंचायती राज मस्यानों सम्बन्धी तरस्थानी उपबन्धों के समरूप होने के लिए उपान्तरित किए जा रहे हैं। खण्ड 306 (1) का संशोधन उन व्यक्तियों को पेंशन राहा देने के लिए किया गया है जो 1-4-1992 से 30-5-1994 की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त हो गए थे क्योंकि नगरपालिका के कर्मचारियों को पेंशन सुविधाएं 1-4-1992 से दे दी गई है।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 14 of 1994.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL BILL, 1994

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to consolidate and amend and replace the law relating to municipalities in Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-fifth year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994.

Short title, extent and commencement.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall and shall be deemed to have come into force on the 30th day of May, 1994.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

Definitions.

(1) "annual value" notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, means—

(a) in the case of land, the gross annual rent—

(i) to be calculated on the basis of fair rent fixed under the law relating to rent restriction for the time being in force; or

(ii) where no fair rent referred to in item (i) is fixed, at which it is expected to be let or it is actually let, whichever is greater:

Provided that, in the case of land assessed to land revenue or any other tax in lieu thereof or of which the land revenue has been wholly or in part released, compounded for, redeemed or assigned, the annual value shall, if the State Government so directs, be deemed to be double the aggregate of the following amounts, namely:—

(i) the amount of the land revenue or any other tax in lieu thereof for the time being assessed on the land, whether such assessment is leviable or not, or when the land revenue has been wholly

- or in part compounded for or redeemed, the amount which, but for such composition or redemption, would have been leviable; and
- (ii) when the improvement of the land due to canal irrigation has been excluded from account in assessing the land revenue, the amount of owner's rate or water advantage rate, or other rate imposed in respect of such improvement ;
- (b) in the case of any house or building, together with its appurtenances or any furniture that may be let for use and enjoyment therewith, is let subject to the following deductions:—
- (i) a deduction not exceeding ten per centum of the gross annual rent as the municipality in each particular case may consider a reasonable allowance on account of the furniture let therewith;
 - (ii) a deduction of ten per centum for the cost of repairs and for all other expenses necessary to maintain the building in a state to command such gross annual rent. The deduction under this sub-clause shall be calculated on the balance of the gross annual rent after the deduction, if any, under item (i) ;
 - (iii) where land is let with a building, such deduction, not exceeding ten per centum of the gross annual rent, as the municipality in each particular case may consider reasonable on account of the actual expenditure, if any, annually incurred by the owner on the maintenance of the land, in a state to command such gross annual rent.

Explanation-I.—For the purposes of this clause it is immaterial whether the house or building, and the furniture and the land let for use or enjoyment therewith, are let by the same contract or by different contracts, and if by different contracts, whether such contracts are made simultaneously or at different times.

Explanation-II.—The term “gross annual rent” shall not include any tax payable by the owner in respect of which the owner and tenant have agreed that it shall be paid by the tenant;

- (c) where the gross annual rent of any land or building cannot be determined under clause (a) or clause (b),—
- (i) in the case of land, ten per cent of the cost of land; and
 - (ii) in the case of buildings ten per cent of the sum of the cost of erection of the building and the cost of land :

Provided that in the calculation of the rateable value of any building, ten per cent of the rateable value so determined shall be deducted for the cost of repairs and for all other expenses necessary to maintain the building :

Provided further that where a building is in the occupation of the owner for the purpose of his own residence, the annual value shall

first be determined as in clause (c) and further be reduced—

- (i) where the covered area of a building by full amount so ing under self occupation does not determined; exceed one hundred square metres;
- (ii) where the covered area of a building, exceeds one hundred square metres; by full amount so determined for first one hundred square meters and by half of the amount so determined for the area by which it exceeds one hundred square meters;
- (d) where the gross annual rent of the whole of the land or a building cannot be determined under any of the clauses (a), (b) and (c),—
 - (i) in relation to that part or portion of such land or building to which clause (a) or (b) applies, as determined under the said clause; and
 - (ii) in relation to the remaining part or portion of such land or building, as determined under clause (c).

Explanation.—For the purposes of this section “cost of land” and “cost of erection of the building” shall mean cost of land and/or cost of erection of building at the time of purchase of such land and/or erection of building, as the case may be.

- (2) “backward classes” means such classes of citizens other than scheduled castes and scheduled tribes as may be identified and notified for the purposes of reservation for appointments or posts in the services under the State Government;
- (3) “building” means any shop, house, hut, out-house, stable, a factory, an industrial shed and a temporary structure erected by means of tents and structures, raised for entertainment purposes whether roofed or not and whether used for the purposes of human habitation or otherwise and whether of masonry, bricks, wood, mud, thatch, metal or any other material whatever, and includes a wall and a well;
- (4) “building line” means a line beyond which the outer face or any part of an external wall of a building may not project in the direction of any street, existing or proposed;
- (5) “built area” is that portion of a municipality of which the greater part has been developed as a business or residential area;
- (6) “bye-laws” mean bye-laws made under this Act;
- (7) “committee” means a committee of a municipality, constituted or deemed to have been constituted by or under this Act;
- (8) “compost manure” means the produce prepared from dung by subjecting it to the process of compost making in the manner prescribed by rules

- (9) "Deputy Commissioner" or "Deputy Commissioners of the districts" includes Additional Deputy Commissioners, or any other officer at any time appointed by the State Government to perform in any district or districts the functions of a Deputy Commissioner under this Act;
- (10) "Director" means the Director of Urban Local Bodies appointed by the State Government;
- (11) "District" means a revenue district;
- (12) "District Planning Committee" means a committee constituted under article 243 ZD of the Constitution of India and under section 185 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 at the district level to consolidate the plans prepared by the Panchayats and the municipalities in the district; 4 of 1994
- (13) "dry latrine" means a latrine from which the excreta is removed manually;
- (14) "dung" means night soil, sewage, sullage, sludge, refuse, filth or rubbish or animal matter of any kind;
- (15) "election" means and includes the entire election process commencing on and from the date of notification calling for such election of members and ending with the date of declaration and notification of results thereof;
- (16) "erect or re-erect any building" includes—
- (a) any material alteration or enlargement of any buildings;
 - (b) the conversion by structural alteration into a place for human habitation of any building not originally constructed for human habitation;
 - (c) the conversion into more than one place for human habitation of a building originally constructed at one such place;
 - (d) the conversion of two or more places of human habitation into a greater number of such places;
 - (e) such alterations of a building as effect an alteration of its drainage or sanitary arrangements, or materially affects its security;
 - (f) the additions of any rooms, buildings, out-houses or other structures to any building;
 - (g) the construction in a wall adjoining any street or land not belonging to the owner of the wall of a door opening on to such street or land;
- (17) "Executive Officer" means a person, by whatever name called, appointed under section 305 of this Act to discharge the functions of the Executive Officer in relation to a Municipal Council and that of Secretary in relation to a Nagar Panchayat;
- (18) "explosive" and "petroleum" have the meanings assigned to those words in the Indian Explosive Act, 1884, and the Petroleum Act, 1934, respectively; 4 of 1884
30 of 1934
- (19) "factory" shall have the meaning assigned to it in the Factory Act, 1948; 63 of 1948
- (20) "infectious disease" means cholera, plague, small-pox, tuberculosis or such other dangerous disease as the State Government may notify in this behalf;

- (21) "inhabitant" includes any person ordinarily residing or carrying on business, or owning or occupying immovable property, in any municipality; or in any local area which the State Government has by notification under this Act, proposed to declare to be a municipality; and in case of any dispute, means any person or persons declared by the Deputy Commissioner to be inhabitant or inhabitants;
- (22) "municipal council" means the municipal council constituted by or under this Act;
- (23) "municipal area" means the territorial area of a municipality notified by the State Government and includes any territorial area which forms part of a municipality at the commencement of this Act;
- (24) "municipality" means an institution of Self Government constituted as a Nagar Panchayat or a municipal council under this Act;
- (25) "Nagar Panchayat" means the Nagar Panchayat constituted under this Act;
- (26) "nuisance" includes any act, omission, place or thing which causes or is likely to cause injury, danger, annoyance or offence to the sense of sight, smell or hearing or which is or may be dangerous to life or injurious to health or property;
- (27) "occupier" includes an owner in actual occupation of his own land or building, and also any person for the time being paying or liable to pay to the owner the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which the word is used; for the purposes of Chapters VI and X, occupier shall include hotel-keeper, lodging house-keeper, and any owner whose premises are let to more than one tenant;
- (28) "office-bearer" means in relation to a municipality a member, Vice-President or a President of a municipality and in relation to a Municipal Corporation, a Councillor, Mayor or Deputy Mayor of the Municipal Corporation and in relation to a Panchayat an office bearer of a Panchayat as defined in clause (23) of section 2 of Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994;
- (29) "owner" includes the person for the time being receiving the rent of land and buildings, or either of them, whether on his own account or as agent or trustee for any person or society or for any religious or charitable purpose, or who would so receive the same if the land or building were let to a tenant;
- (30) "Panchayat" means an institution of Self-Government (by whatever name called) constituted for rural areas under the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994;
- (31) "population" means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;
- (32) "public place" means a place which is open to the use or enjoyment of the public whether or not private property and whether or not vested in the municipality;

(33) "public street" shall mean any street—

- (i) heretofore levelled, paved, metalled, channelled, sewerred or repaired out of municipal or other public funds unless before such work was carried out there was an agreement with the proprietor that the street should not thereby become a public street or unless such work was done without the implied or express consent of the proprietor; or
- (ii) which under the provisions of section 182 is declared by the municipality to be or under any other provision of this Act becomes, a public street;

(34) "rules" mean the rules made under this Act;

(35) "scheduled castes" shall have the same meaning as assigned to it in clause (24) of article 366 of the Constitution of India;

(36) "scheduled tribes" shall have the same meaning as assigned to it in clause (25) of article 366 of the Constitution of India;

(37) "State Election Commission" means the State Election Commission constituted by the State Government under article 243 K and 243ZA of the Constitution of India and section 160 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994;

4 of 1994

(38) "State Finance Commission" means the State Finance Commission constituted by the State Government under articles 243-I and 243-Y of the Constitution of India and section 98 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994;

4 of 1994

(39) "street" shall mean any road, footway, square, court, alley or passage, accessible, whether permanently or temporarily to the public, and whether a thoroughfare or not; and shall include every vacant space, notwithstanding that it may be private property and partly or wholly obstructed by any gate, post, chain or other barrier, if houses, shops or other buildings abut thereon, and if it is used by any person as a means of access to or from any public place or thoroughfare, whether such persons be occupiers of such buildings or not, but shall not include any part of such space which the occupier of any such building has a right at all hours to prevent all other persons from using as aforesaid, and shall include also the drains or gutters therein, or on either side and the land, whether covered or not by any pavement, verandah or other erection, upto the boundary of any abutting property not accessible to the public;

(40) "unbuilt area" is an area within the municipal limits which is declared to be such at a special meeting of the municipality by a resolution confirmed by the State Government, or which is notified as such by the State Government;

(41) "vehicle" includes bicycle, tricycle and automotor car and every wheeled conveyance which is used or capable of being used on a public street.

CHAPTER-II

CLASSIFICATION OF MUNICIPALITIES AND MUNICIPAL AREA

3. (1) There shall be constituted three classes of municipalities in accordance with the provisions of this section as specified below :—

Classification of municipalities.

- (i) "Nagar Panchayat" for a transitional area with population exceeding two thousand and generating annual revenue exceeding rupees five lakhs for the local administration;
- (ii) "Municipal Council" for a smaller urban area with population exceeding five thousand and generating the annual revenue exceeding rupees twenty lakhs for the local administration;
- (iii) "Municipal Corporation" for a larger urban area with population exceeding fifty thousand and generating annual revenue exceeding rupees two crores for the local administration and which has been declared to be a municipal area under section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994:

of 1994

Provided that a municipality under this section may not be constituted in such urban areas or part thereof as the State Government may, having regard to the size of the area and the municipal services being provided or proposed to be provided by an industrial establishment in that area and such other factors as it may deem fit, by notification, specify to be an industrial township :

Provided further that no cantonment or part of a cantonment shall form part of a municipality.

Explanation.—In this sub-section, "a transitional area", "a smaller urban area" or "a larger urban area" means such area as the State Government may, having regard to the population of the area, the density of the population therein, the revenue generated for local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities, the economic importance or such other factors as the State Government may deem fit, specify by notification for the purpose of this section.

(2) The State Government shall, by notification, constitute the municipalities and specify the class to which a municipality shall belong in accordance with the provisions of this section after observing the procedure as laid down in section 4 :

Provided that the municipalities existing at the commencement of this Act and listed as Nagar Panchayat or as Municipal Council in the Schedule to this Act, would be deemed to have been constituted and notified as such, under and in accordance with the provisions of this section :

Provided further that the State Government may, after giving a reasonable notice of not less than thirty days of its intention to do so,

amend the schedule, by notification and declare any Nagar Panchayat as a Municipal Council or any Municipal Council as a Nagar Panchayat.

Procedure
for dec-
laring mu-
nicipal area.

4. (1) The State Government may, by notification, propose any local area to be a municipal area under this Act.

(2) Every such notification under sub-section (1) shall define the limits of the local area to which it relates.

(3) A copy of every notification under this section, with a translation thereof in such language as the State Government may direct shall be affixed at some conspicuous place in the office of the Deputy Commissioner, within whose jurisdiction the local area to which the notification relates lies, and at one or more conspicuous places in that local area.

(4) The Deputy Commissioner shall certify to the State Government the date on which the copy and translation were so affixed and the date so certified shall be deemed to be the date of publication of the notification.

(5) If any inhabitant desires to object to a notification issued under sub-section (1), he may, within six weeks from the date of its publication, submit his objection in writing through the Deputy Commissioner to the State Government and the State Government shall take his objection into consideration.

(6) When six weeks from the date of publication have expired, and the State Government has considered and passed orders on such objections as may have been submitted to it, the State Government may, by notification, declare the local area for the purposes of this Act to be a municipal area.

(7) The State Government may, by notification, direct that all or any of the rules which are in force in any municipal area shall, with such exceptions and adaptations as may be considered necessary, apply to the local area declared to be a municipal area under this section, and such rules shall forthwith apply to such municipal area without further publication.

(8) When a local area, the whole or part of which was a notified area under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968 or a Nagar Panchayat under this Act, is declared to be municipal council under this section, the municipal council shall be deemed to be a perpetual successor of such notified area committee or of Nagar Panchayat, as the case may be, and in respect of all its rules, bye-laws, taxes, and all other matters, whatsoever and the Nagar Panchayat shall continue in office and shall notwithstanding anything contained in this Act be deemed to be the municipal council until the appointment and election of members is notified by the State Government under section 27.

19 of 1968

(9) A municipality shall come into existence on such day as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

5. (1) The State Government may, by notification, and in such other manner as it may determine, declare its intention to include within a municipal area any local area in the vicinity of the same and specified in the notification.

Notification of intention to include a local area in a municipal area.

(2) Any inhabitant of a municipal area or local area in respect of which a notification has been published under sub-section (1) may, if he objects to the alteration proposed, submit his objection in writing through the Deputy Commissioner to the State Government within six weeks from the publication of the notification; and the State Government shall take such objection into consideration.

(3) When six weeks from the publication of the notification have expired, and the State Government has considered the objections, if any, which have been submitted under sub-section (2) the State Government may, by notification, include the local area in the municipal area.

(4) When any local area has been included in a municipal area under sub-section (3) of this Act, and, except as the State Government may, by notification, direct otherwise, all notifications, rules, bye-laws, orders, directions and powers issued, made, or conferred under this Act and in force throughout whole of the municipal area at the time shall apply to such area.

6. The State Government may, by notification and in such other manner as it may deem fit, declare its intention to exclude from a municipal area any local area comprised therein and specified in the notification.

Notification of intention to exclude local area from a municipal area.

7. (1) Any inhabitant of a municipal area or local area in respect of which a notification has been published under section 6 may, if he objects to the exclusion proposed, submit his objection in writing through the Deputy Commissioner to the State Government within six weeks from the publication of the notification and the State Government shall take his objection into consideration.

Exclusion of local area from a municipal area.

(2) When six weeks from the publication of the notification have expired and the State Government has considered the objections, if any, which have been submitted under sub-section (1), the State Government may, by notification, exclude the local area from the municipal area.

8. When a local area is excluded from a municipal area under section 7—

Effect of exclusion of local area from municipal area.

- (a) this Act and all notifications, rules, bye-laws, orders, directions and powers issued, made or conferred under this Act, shall cease to apply thereto; and
- (b) the State Government shall after consulting the municipality, frame a scheme determining what portion of the balance of the municipal fund and other property vesting in the municipality shall vest in the State Government and in what manner the liabilities of the municipality shall be apportioned between the municipality and the State Government, and, on the scheme being

notified, the property and liabilities shall vest and be apportioned accordingly.

Power to
abolish mu-
nicipal area.

9. (1) The State Government may, by notification, abolish any municipal area declared under section 4.

(2) When a notification is issued under this section in respect of any municipal area, this Act and all notifications, rules, bye-laws, orders, directions and powers issued, made or conferred under this Act shall cease to apply to the said municipal area; the balance of the municipal fund and all other property at the time of the issue of the notification vested in the municipality shall vest in the State Government and the liabilities of the municipality shall be transferred to the State Government.

(3) Where any municipal area is abolished under sub-section (1) and subsequently the area comprising the municipal area so abolished is declared to be a Sabha area under sub-section (1) of section 3 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, the assets and liabilities referred to in sub-section (2) shall vest in the Gram Panchayat of the Sabha area from the date of its establishment under section 4 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994.

4 of 1994.

4 of 1994.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, the assets shall include all arrears of tax, tolls, cesses, rates, dues and fees imposed under this Act or rule or any bye-law which fell due to the municipality of the municipal area immediately before the date of its abolition and the same shall be recoverable by the Gram Panchayat as if these were arrears due to the Gram Panchayat.

CHAPTER-III

MUNICIPALITIES

Composition
of mu-
nicipalities.

10. (1) The municipalities constituted under section 3 shall consist of such number of elected members not less than seven as may be determined by the State Government, by adopting the criterion that in municipal area having population of:—

(i)	not exceeding 5,000	7 members
(ii)	exceeding 5,000 but not exceeding 10,000	9 members
(iii)	exceeding 10,000 but not exceeding 20,000	11 members
(iv)	exceeding 20,000 but not exceeding 30,000	13 members
(v)	exceeding 30,000 but not exceeding 40,000	15 members
(vi)	exceeding 40,000 but not exceeding 50,000	17 members
(vii)	exceeding 50,000	19 members:

Provided that the determination of the number of members as aforesaid shall not affect the composition of the municipality until the expiry of the term of office of the elected members then in office.

(2) Save as provided in sub-section (3), all seats in the municipality shall be filled in by persons chosen by direct election and for the purpose

of election, the Deputy Commissioner shall, in accordance with such rules as may be prescribed by the State Government,—

- (a) divide the municipal area into wards in such a manner that—
 - (i) one member shall be elected from each ward ; and
 - (ii) as far as possible the population in each ward shall be equally distributed ;
- (b) determine the territorial extent of each ward ; and
- (c) determine the ward or wards in which seats are reserved under section 11.

(3) In addition to persons chosen by direct election from the wards the State Government may by notification in the Official Gazette, nominate not more than three persons having special knowledge or experience in municipal administration ; as members of a municipality :

Provided that the persons nominated under this sub-section shall not have the right to vote in the meeting of the municipality :

Provided further that the Executive Officer in the case of a Municipal Council and the Secretary in the case of a Nagar Panchayat, shall have the right to attend all the meetings of the municipality and to take part in discussion therein but shall not have the right to vote.

11. (1) Seats shall be reserved in a municipality,—

Reservation
of seats.

- (a) for the scheduled castes ; and
- (b) for the scheduled tribes ;

and the number of seats so reserved shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in the municipality as the population of the scheduled castes and the scheduled tribes in the municipal area bears to the total population of that municipal area :

Provided that in case no reservation of seats is possible as aforesaid due to small population of the scheduled castes and the population of scheduled castes of the municipal areas is atleast five per cent of the total population of the municipal area, one seat shall be reserved for the scheduled castes in such a municipality :

Provided further that where there is no eligible candidate belonging to the scheduled castes to be elected as a member of the municipality, no seat shall be reserved for scheduled castes :

Provided further that in non-tribal areas where there is scheduled tribes population in a municipal area, seats shall be reserved for such members of the scheduled tribes within the reservation provided for the members of the scheduled castes and the determination of seats to be reserved amongst the scheduled castes and scheduled tribes shall be in proportion to their population in that municipal area.

Explanation.—The expression “non-tribal area” for the purpose of this proviso shall mean the areas other than the Scheduled Areas specified in relation to the State of Himachal Pradesh.

(2) One-third of seats, reserved under sub-section (1), shall be reserved for women belonging to the scheduled castes or, as the case may be, the scheduled tribes.

(3) One-third (including the number of seats reserved for women belonging to the scheduled castes and the scheduled tribes) of the total number of seats to be filled by direct election shall be reserved for women.

(4) The State Government may, by general or special order, reserve such number of seats for persons belonging to backward classes in a municipality, not exceeding the proportion to the total number of seats to be filled by direct election in the municipality as the population of the persons belonging to backward classes in that municipal area bears to the total population of that area and may further reserve one-third of the total seats reserved under this sub-section for women belonging to backward classes.

(5) The seats reserved under sub-sections (1), (3) and (4) shall be allotted by rotation to different wards in the municipal area in such manner as may be prescribed.

(6) The reservation of seats under this section shall be given effect through notification issued at the time of each election, by the State Government.

Reservation
of offices
of Chairper-
sons.

12. (1) There shall be reserved by the Government, in the prescribed manner such number of offices of Chairpersons in the municipalities in the State for the persons belonging to the scheduled castes and scheduled tribes and the number of such offices, bearing as may be the same proportion to the total number of offices in the State as the urban population of the scheduled castes in the State or of the scheduled tribes in the State bears to the total urban population of the State.

(2) One-third of the total number of offices of Chairpersons reserved under sub-section (1), shall be reserved for women belonging to the scheduled castes or, as the case may be, the scheduled tribes.

(3) One-third (including the number of offices reserved for women belonging to the scheduled castes and the scheduled tribes) of the total number of offices of Chairpersons of municipalities in the State shall be reserved for women.

(4) The State Government may, by general or special order, reserve such number of offices of Chairperson for persons belonging to backward classes in municipalities not exceeding the proportion to the total number of offices to be filled by direct election in the municipalities as the urban population of the persons belonging to backward classes in the State bears to the total urban population of the State and may further reserve one-third of the total seats reserved under this sub-section for women belonging to backward classes.

(5) The offices of Chairpersons reserved under sub-sections (1), (3) and (4) shall be allotted by rotation to different municipalities in the State in such manner as may be prescribed.

Explanation.—For the removal of doubts it is hereby declared that for the purpose of this section the expression “urban population” shall mean the population of municipal areas of the State, except that of the municipal area declared to be a municipal area for the purposes of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994.

of 1994

13. (1) The term of office of elected members shall be five years from the date appointed for the first meeting of the municipality.

Term of office of members.

(2) The term of the nominated members shall be co-terminus with the term of elected members.

(3) When as a result of an enquiry held under Chapter XVII, an order declaring the election of any member void has been made such member shall forthwith cease to be the member of the municipality.

(4) The members shall be entitled to receive allowances for attendance at meetings of the municipality and of its committees at such rates as may be prescribed by the State Government from time to time.

14. (1) Every municipality unless sooner dissolved under any law for the time being in force, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer:

Duration of municipality.

Provided that a municipality shall be given a reasonable opportunity of being heard before its dissolution :

Provided further that all municipalities existing immediately before the commencement of this Act shall continue till the expiration of their duration unless sooner dissolved by a resolution passed to that effect by the State Legislature.

(2) An election to constitute a municipality shall be completed,—

- before the expiry of its duration specified in sub-section (1);
- before the expiration of a period of six months from the date of its dissolution;

Provided that when the remainder of the period for which the dissolved municipality would have continued is less than six months, it shall not be necessary to hold any election under this section for constituting the municipality for such period :

Provided further that the first election to a municipality constituted after the commencement of this Act, may be held within a period of one year of its being notified as a municipality:

(3) A municipality constituted upon the dissolution of a municipality before the expiration of its duration shall continue only for the remainder

of the period for which the dissolved municipality would have continued under sub-section (1) had it not been so dissolved.

Resignation
of member
of municipi-
pality.

15. (1) The member of a municipality may resign by tendering his resignation in writing to the President who shall place the same before the municipality for its acceptance, unless withdrawn within fifteen days from the date of tendering the resignation.

(2) On the acceptance of the resignation under sub-section (1) the seat of the member shall be deemed to have become vacant and the same be filled up under section 19 of this Act.

Disqualifi-
cations.

16. (1) A person shall be disqualified for being chosen as and for being an office bearer of a municipality,—

- (a) if he is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of the election to the State Legislature :

Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than 25 years, if he has attained the age of 21 years.

- (b) If he has been convicted of any offence involving moral turpitude, unless a period of six years has elapsed since his conviction; or
(c) if he has encroached upon, or is a beneficiary of the encroachment upon, any land belonging to, or taken on lease or requisitioned by, or on behalf of the State Government, a Municipality, a Panchayat or a Co-operative Society unless a period of six years has elapsed since the date on which he is ejected therefrom or he ceases to be the encroacher;

Explanation.—For the purposes of this clause, the expression “beneficiary” shall include the spouse and legal heirs of the encroacher; or

- (d) if he has been convicted of an election offence under any law for the time being in force; or
(e) if he has been ordered to give security for good behaviour under section 110 of the Code of Criminal Procedure, 1973; or
(f) if he has been disqualified for appointment in public service, except on medical grounds; or
(g) if he is in the employment or service under any municipality or of any other local authority or Co-operative Society or the State Government or Central Government or any Public Sector Undertaking under the control of the Central or the State Government,

Explanation.—For the purposes of this clause the expressions “service” or “employment” shall include persons appointed, engaged or employed on whole time, part time, casual, daily or contract basis, or

- (h) if he is registered as a habitual offender under the Himachal Pradesh Habitual Offenders Act, 1969 ; or
(i) if, save as hereinafter provided, he has directly or indirectly any share or interest in any work done by an order of a municipality, or in any contract or employment with, or under or by, or on behalf of the municipality; or

2 of 1974

8 of 1970

22-1955

- (j) if he has not paid the arrears of any tax imposed by a municipality or had not paid the arrears of any kind due from him to the municipal fund; or has retained any amount which forms part of the municipal fund;
 - (k) if, he is a tenant or lessee holding a tenancy or lease under a municipality is in arrears of rent of lease or tenancy held under the municipality;
 - (l) if he has been convicted of an offence punishable under the Protection of Civil Rights Act, 1955, unless a period of six years has elapsed since his conviction; and
 - (m) if he is so disqualified by or under any other law made by the State Legislature.
- (2) The question whether a person is or has become subject to any of the disqualifications under sub-section (1), shall, after giving an opportunity to the person concerned of being heard, be decided,—
- (i) if such question arises during the process of an election, by an officer who may be authorised in this behalf by the State Government, in consultation with the State Election Commission; and
 - (ii) if such question arises after the election process is over, by the Director.

17. If a person who is chosen as a member of a municipality becomes a Member of the House of the People, the Council of States, the State Legislative Assembly or the Councillor of the Municipal Corporation or is or becomes an office-bearer of a Panchayat then at the expiration of a period of fifteen days from the date of publication of the election result of, as the case may be, within fifteen days from the date of the commencement of term of office of a Member of the House of People, the Council of States or the State Legislative Assembly or the Councillor of a Municipal Corporation or the office-bearer of a Panchayat his seat in a municipality shall become vacant unless he has previously resigned his seat in the House of People, the Council of States, the State Legislative Assembly, the Municipal Corporation or the Panchayat, as the case may be.

Bar to hold more than one office.

Lodging of Ac
Section 17(A) &
Accounts of elect
persons under

18. (1) The State Government may, in consultation with the State Election Commission and by notification, remove any member of a municipality,—

Power of State Government as to removal of members.

- (a) if he refuses to act, or becomes, in the opinion of the State Government, incapable of acting, or has been declared a bankrupt or an insolvent by a competent court or has been convicted of any such offence or subjected by a criminal court to any such order as implies in the opinion of the State Government, a defect of character which renders him unfit to be a member;
- (b) if he has been declared by notification to be disqualified for employment in, or has been dismissed from the public service and the reason for the disqualification or dismissal is such as implies in the opinion of the State Government, a defect of character which renders him unfit to be a member;
- (c) if he has without reasonable cause in the opinion of the State Government absented himself for more than three consecutive months from the meetings of the municipality;

- (d) if he fails to pay any amount due from him to the municipality within three months of the service of notice making the claim. It shall be the duty of the Executive Officer, to serve such a notice at the earliest possible date after the amount has become due;
- (e) if in the opinion of the State Government he has flagrantly abused his position as a member of the municipality or has through his negligence or misconduct been responsible for the loss, or misapplication of any money or property of the municipality;
- (f) if he has, since his election or nomination, become subject to any disqualification which, if it had existed at the time of his election or nomination, would have rendered him ineligible under any law for the time being in force for election or nomination, or if it appears that he was, at the time of his election or nomination subject to any such disqualification; and
- (g) if, being a legal practitioner, he acts or appears in any legal proceeding on behalf of any person against the municipality or on behalf of or against the State Government where in the opinion of the State Government such action or appearance is contrary to the interests of the municipality:

Provided that no removal of a member shall be notified unless the matter has been enquired into by an officer, not below the rank of an Additional Deputy Commissioner, appointed by the State Government and the member concerned has been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) A person removed under this section or whose election has been declared void, for corrupt practices or intimidation, under the provisions of section 295 shall be disqualified for election for a period not exceeding six years.

Filling of casual vacancies.

19. (1) Whenever a vacancy occurs by the death, resignation or removal, or by the vacation of seat, under the provisions of sub-section (3) of section 13, of any member, the vacancy shall be filled within six months of the occurrence of such vacancy in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(2) Every person elected or nominated, to fill a casual vacancy, shall be elected or nominated to serve for the remainder of his predecessor's term of office.

Incorporation of municipality.

20. Every municipality shall be a body corporate to be known as by the name of Municipal Council or the Nagar Panchayat of its municipal area and shall have perpetual succession and a common seal, with power to acquire and hold property, both movable and immovable, and subject to the provisions of this Act or the rules made thereunder, to transfer any property held by it, to contract and to do all other things necessary for the purpose of its constitution; and may sue and be sued in its corporate name.

Members and employees to be public servants.

21. Every member of the municipality and every person employed by the municipality, whether for the whole or part of his time, shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

22. Every Nagar Panchayat or Municipal Council shall elect one of its elected members to be the President and another to be the Vice-President, and the member so elected shall become President or the Vice-President, as the case may be, of the Nagar Panchayat or Municipal Council:

Election of President and Vice-President.

Provided that the office of the President in Nagar Panchayats and Municipal Councils shall be reserved for scheduled castes, scheduled tribes and women in accordance with the provisions made in section 12 :

Provided further that if the office of the President or Vice-President is vacated during his tenure on account of death, resignation, removal or no confidence motion, a fresh election for the remainder of the period shall be held from the same category.

23. (1) The term of office of President or Vice-President shall be five years or the residue of the term of his office as a member, whichever is less.

Term of office of and honorarium to President and Vice-President.

(2) An outgoing President and Vice-President shall if otherwise qualified, be eligible for re-election.

(3) The President and Vice-President shall be entitled to the payment of such honorarium and allowances for attendance at meeting of the municipality and its committees at such rate as may be prescribed by the State Government from time to time.

24. (1) The President may, by writing under his hand addressed to the Vice-President, resign his office.

Resignation of President or Vice-President.

(2) The Vice-President may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office.

(3) The resignation under sub-section (1) or (2) shall take effect from the date of its acceptance by the Vice-President or the President, as the case may be.

25. (1) A motion of no-confidence against the President or Vice-President may be made in accordance with the procedure laid down in the rules.

Motion of no confidence against President or Vice-President.

(2) Where a notice of intention to move a resolution requiring the President or Vice-President of the municipality to vacate his office, signed by not less than majority of its total elected members is given and if a motion of no-confidence is carried by a resolution passed by a majority of elected members present and voting at its general or special meeting, the quorum of which is not less than one-half of its total elected members, the President or the Vice-President against whom such resolution is passed shall cease to hold office forthwith.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder the President or Vice-President of the municipality shall not preside over a meeting in which a motion of no-confidence is discussed against him. Such meeting shall be presided over by such a person, and convened in such manner, as may be prescribed and the person against whom a motion of no-confidence is moved, shall have a right to vote to take part in the proceedings of such a meeting.

(4) Motion of no-confidence under this section shall not be maintainable within one year of the date of his election to such office and any subsequent motion of no-confidence shall not be maintainable within the interval of one year of the last motion of no-confidence.

Removal of
President or
Vice-
President.

26. The State Government may, at any time, by notification, remove a President or Vice-President from his office on the ground of abuse of his power or of habitual failure to perform his duties :

Provided that no removal of the President or Vice-President shall be notified unless the matter has been enquired into by an officer, not below the rank of the Sub Divisional Officer (Civil) appointed by the State Government and the President or Vice-President, as the case may be, has been given a reasonable opportunity of being heard.

Notification
of elections
and nomi-
nations.

27. (1) Every election or nomination of a member and election of a President and Vice-President of a Nagar Panchayat or Municipal Council shall be notified in the Official Gazette and no member shall enter upon his duties until his election or nomination has been so notified and until, he has made or subscribed at a meeting of the Nagar Panchayat or Municipal Council, an oath or affirmation of his allegiance to the Constitution of India in the following form, namely:—

"I, AB, having been elected (or nominated) member/President/Vice-President of a Nagar Panchayat or Municipal Council of—
do swear in the name of God/solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and I will faithfully, discharge the duties upon which I am about to enter".

(2) Every election of a member shall be notified in the Official Gazette by the State Election Commission and every election of a President and Vice-President shall be notified by the State Government in the Official Gazette within thirty days from the date of declaration of the result of such election.

(3) If any such person omits or refuses to take or make the oath or affirmation as required by sub-section (1) within thirty days of the date of notification of his election or nomination, as the case may be, his election or nomination shall be deemed to be invalid, and his seat shall become vacant.

Time for
holding
meetings.

28. (1) Every municipality shall meet for the transaction of business at least once in every month at such time as may, from time to time, be fixed by the bye-laws.

(2) The President or, in his absence or during his incapability to attend to his duties or during the vacancy of his office, the Vice-President may, whenever he thinks fit and shall, within a period of ten days from the date of receipt of a requisition signed by not less than one-half of the total number of members of the municipality, convene either an ordinary or a special meeting at any other time:

Provided that the requisition shall specify the purpose for which the meeting is to be held.

(3) If the President or the Vice-President fails to convene a meeting of the municipality within a period of ten days from the date of receipt of such requisition, the members who signed the requisition may request the Sub Divisional Officer (Civil) to convene the meeting.

(4) The Sub Divisional Officer (Civil) on receipt of request under sub-section (3) shall within a period of ten days of such request, convene the meeting.

29. (1) Every meeting of municipality shall be either ordinary or special.

Ordinary
and special
meetings.

(2) All business may be transacted at an ordinary meeting unless required by this Act or the rules framed thereunder, to be transacted at a special meeting.

30. (1) The quorum necessary for the transaction of business at a special meeting of a municipality shall be one-half of the number of sitting members of the municipality. Quorum.

(2) The quorum necessary for the transaction of business at an ordinary meeting of a municipality shall be such number or proportion of the members of the municipality as may, from time to time, be fixed by the by-laws, but shall not be less than three:

Provided that, if at any ordinary or special meeting of a municipality a quorum is not present, the Chairman shall adjourn the meeting to such other day, as he may think fit, and the business which would have been brought before the original meeting if there had been a quorum present shall be brought before, and transacted at the adjourned meeting.

31. At every meeting of a municipality the President, or, in his absence or during the vacancy of his office, the Vice-President and if there be no President or Vice-President, then such one of the members as the members present may elect, shall preside.

Chairman
of meeting.

32. Except as otherwise provided by this Act or the rules, all questions which come before any meeting of a municipality shall be decided by a majority of the votes of the members present, and in case of an equality of votes the Chairman of the meeting shall have a second or casting vote.

Vote of
majority
decisive.

33. (1) Minutes of the proceedings at each meeting of a municipality shall be drawn up and recorded in a book to be kept for the purpose, shall be signed by the Chairman of the meeting or of the next ensuing meeting.

Records
and publi-
cation of
proceedings.

(2) The minutes of the proceedings referred to under sub-section (1) shall be published in such manner as the State Government may direct, and shall, at all reasonable times and without charge, be open to inspection by any inhabitant.

(3) A copy of resolution passed at any meeting of a municipality shall, within three days from the date of the meeting, be forwarded to the Deputy Commissioner and the Director.

Bye-laws.

34. The State Government may, for all or any of the municipality, provide by bye-laws consistent with this Act and with the rules for—

- (a) the time and place of its meetings;
- (b) the manner in which notice of ordinary and special meetings and adjourned meetings shall be given;
- (c) the quorum necessary for the transaction of business at ordinary meetings;
- (d) the conduct of proceedings at meetings and the adjournment of meetings;
- (e) the custody of the common seal and the purposes for which it shall be used;
- (f) the appointment of sub committees and their duties, the division of duties among the members of the municipality and the powers to be exercised by such members as are primarily responsible for current executive administration, whether President, Vice-President, Members of sub committees or individual members;
- (g) the persons by whom receipts shall be granted on behalf of the municipality for money received under this Act;
- (h) the condition on which registers, documents, maps and plans of the municipality may be inspected by the public, and copies thereof supplied, and the fees payable for such inspection or for the supply of such copies;
- (i) the appointment, duties, executive powers, leave, suspension and removal of employees of the municipality;
- (j) appeal from orders of any committee, the President, Vice-President, Members, Officers and employees of the municipality; and
- (k) any other matter which is to be or may be prescribed by bye-laws made under this Act.

Appoint-
ment of
Director.

35. (1) The State Government may by notification appoint a Director, and subject to such conditions and restrictions as it may deem fit, may invest him with all or any of the powers conferred on the State Government by this Act.

(2) There shall be such other classes of officers as the State Government may, by notification, declare and the State Government may appoint as many persons as it deems fit to be officer of these classes and declare what powers under this Act shall be exercised by the Officers of each class.

Delegation
of powers
and
functions.

36. (1) The State Government may, by notification delegate all or any of its powers under this Act, except the powers to prescribe forms or make rules under section 279 to any officer subordinate to it.

(2) Every delegation of powers under sub-section (1) may be subject to such restrictions and conditions as may be specified in the notification.

(3) Wherever it is expedient to do so in the public interest and for the efficient performance of the functions entrusted to the municipality under this Act, the municipality may, with the prior approval of the State Government, entrust any of its civic services and amenities (including

collection of taxes and revenues) is related to any matter to which the power of the municipality extends, to any person or agency subject to such conditions and restrictions, as it may consider necessary to impose.

37. (1) On the occurrence or threatened occurrence of any event involving or likely to involve extensive damage to property or danger to human life or grave inconvenience to the public, the President or in the absence of the President or during the vacancy of his office, a Vice-President or in the absence of both, the Executive Officer may, if in his opinion there is any emergency necessitating immediate action before the matter can be considered by the municipality, direct the execution of any such work or the doing of any such act which the municipality is empowered to execute or do, as the emergency shall in his opinion justify or require, and may direct that the expenses of executing such work or doing such act be paid from the municipal fund:

Power of President or Vice-President in emergency.

Provided that every such action shall be reported to the municipality at its next meeting.

(2) The President or Vice-President or the Executive Officer shall not act under this section in contravention of any order of the municipality.

(3) The President or in his absence or during the vacancy of his office a Vice-President may prohibit, until the matter has been considered by the municipality, the doing of any act which is in his opinion undesirable in the public interest: provided that the act is one which the municipality has power to prohibit.

38. A municipality may concur with any other municipality or with any Zila Parishad, or with any Panchayat Samiti, or with any cantonment authority, or with more than one such municipality, Zila Parishad, Panchayat Samiti or authority in appointing out of their respective bodies a joint committee for any purpose in which they are jointly interested and in delegating to any such joint committee any power which might be exercised by either or any of the municipalities, Zila Parishads, Panchayat Samities or authorities concerned, and in framing or modifying regulations as to the proceedings of any such joint committee, and as to the conduct of correspondence relating thereto.

Joint committees.

39. (1) Notwithstanding anything contained in this Act but subject to any general or special order of the Government, where two-third of the total members of a municipality have been elected, the municipality shall be deemed to have been constituted under this Act.

Vacancies and irregularities not to invalidate acts and proceedings.

(2) No act done or proceedings taken under this Act, shall be questioned merely on the ground of the existence of any vacancy in any municipality or any defect in the election or qualification of the President, Vice-President, the presiding authority or member of the municipality or the joint committee, or on account of any defect or irregularity of such act or proceeding or its procedure not affecting the merits of the case.

40. A municipality may, subject to the rules and provisions of section 41, delegate to one or more of its members the power of entering on its behalf into any particular contract or into any class of such contracts.

Authority to contract.

Mode of
executing
contracts
and trans-
fer of pro-
perty.

41. (1) Every contract made by or on behalf of the municipality shall be in writing and must be signed by two members, of whom the President or Vice-President shall be one, and also the Executive Officer or the Secretary of the municipality, as the case may be.

(2) Every transfer of immovable property belonging to any municipality shall be by an instrument in writing executed by the President or Vice-President of the municipality and Executive Officer or Secretary of the municipality, as the case may be.

Penalty on
member or
employee
being inter-
ested in any
contract
with a mu-
nicipality.

42. (1) If any member or employee of a municipality or of a joint committee, without the previous permission in writing of the Deputy Commissioner voluntarily renders himself interested in any contract made with that municipality or joint committee, under section 38 or if within one month of his becoming interested in any such contract he neither resigns nor obtains the permission in writing of the Deputy Commissioner for his remaining a member or employee of the municipality or joint committee in spite of his interest in such contract, he shall be punishable for an offence under section 168 of the Indian Penal Code, 1860.

45 of 1860

(2) No member or employee of a municipality or a joint committee shall by reason only of his being a shareholder in or a member, any incorporated or registered company, be held to be interested in any contract entered into between the said company and the municipality or joint committee but no such person as aforesaid shall take part in any proceedings of the municipality or joint committee relating to any such contracts.

Suits against
municipi-
pality and
its emp-
loyees.

43. No suit shall be instituted against a municipality, or against any employee of a municipality, in respect of any act purporting to be done in its or his official capacity, until the expiration of one month next after notice in writing has been, in the case of a municipality, delivered or left at his office, and in the case of an employee, delivered to him or left at his office or place of abode, stating the cause of action and the name and place of abode of the intending plaintiff; and the plaint must contain a statement that such notice has been so delivered or left.

Provided that nothing in this section shall apply to any suit instituted under section 38 of the Specific Relief Act, 1963.

47 of 1963

But of juris-
diction of
civil courts.

44. No civil court shall grant any temporary injunction or make any interim order—

- (a) restraining any person from exercising the powers or performing the functions or duties of a President or Vice-President, member and employee of a municipality on the ground that such person has not been duly elected, nominated or appointed as such President, Vice-President, member or employee; or
- (b) restraining any person or persons or any municipality from holding any election, in any particular manner.

Protection
of action
taken in
good faith.

45. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any municipality or against any employee of a committee or against any person acting under and in accordance with the directions of any such municipality or employee or of a lawful authority in respect of anything which is in

good faith done or intended to be done in pursuance of this Act, rules and bye-laws.

46. (1) Every member, officer or official of the municipality shall be liable for the loss, waste or misappropriation of any money or other property belonging to a municipality, if such loss, waste is reported by the Comptroller and Auditor General of India or other audit authority empowered by the State Government in this behalf to be a direct consequence of his neglect or misconduct in the performance of his duties while a member, officer or official of the municipality, and he may after being given an opportunity, by notice served in the manner provided for the service of summons in the Civil Procedure Code, to show cause by written or oral representation why he should not be required to make good the loss, be surcharged with the value of such property or the amount of such money by the Director and if the amount is not paid within fourteen days from the expiry of the period of appeal prescribed by sub-section (2) the Collector at the request of the Director, shall proceed forthwith to recover the amount as if it were an arrear of land revenue, and have it credited to the municipal fund.

Liability for loss.

5 of 1908

(2) The person against whom an order under sub-section (1) is made, may, within thirty days of such order, appeal to the State Government who shall appoint an officer to hear the appeal and the appellate authority shall have the power of confirming, modifying or disallowing the surcharge :

Provided that no person shall under this section be called upon to show cause after the expiry of a period of four years from the occurrence of such loss, waste or misappropriation or after the expiry of one year from the time of his ceasing to be a member :

Provided further that nothing in this section shall be deemed to debar the aggrieved party from seeking remedy in Civil Court against an order made under sub-section (1).

CHAPTER-IV

FUNCTIONS OF THE MUNICIPALITIES

47. (1) Subject to the provisions of this Act and the rule, regulations and bye-laws made thereunder the municipal administration of a smaller urban area and transitional area shall vest in the Municipal Council and a Nagar Panchayat respectively.

General powers of municipalities.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), it shall be the duty of the municipality to consider all periodical statements of the receipts and disbursements and all progress reports and pass such resolutions thereon as it thinks fit.

48. (1) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1) of section 47, the State Government shall, by notification endow the municipalities with such powers and authorities as may be necessary from time to time to enable them to function as institutions of Local Self Government, subject to such conditions as may be

Powers and authorities of municipalities.

specified therein, with respect to, —

- (i) the preparation of plans for economic development and social justice;
- (ii) the performance of functions and implementation of the schemes which may be entrusted to them including the following, namely:—

- (1) urban planning including town planning;
- (2) regulation of land-use and construction of buildings;
- (3) planning for economic and social development;
- (4) roads and bridges;
- (5) water supply for domestic, industrial and commercial purposes;
- (6) public health, sanitation, conservancy and solid waste management;
- (7) fire services;
- (8) urban forestry, protection of the environment and promotion of ecological aspects;
- (9) safeguarding the interests of weaker section of society, including the handicapped and mentally retarded;
- (10) slum improvement and upgradation;
- (11) urban poverty alleviation;
- (12) provisions of urban amenities and facilities such as parks, gardens and playgrounds;
- (13) promotion of cultural, educational and aesthetics aspects;
- (14) burials and burial grounds, cremations, cremation grounds and electric crematoriums;
- (15) cattle ponds and prevention of cruelty to animals;
- (16) vital statistics including registration of births and deaths;
- (17) public amenities including street lighting, parking lots, bus stops and public conveniences;
- (18) regulation of slaughter houses and tanneries;

Provided that the notification regarding devolution of powers under this sub-section shall be issued within three month from the date of commencement of this Act, in the first instance.

(2) Nothing contained in the provisions of this section shall be construed to divest the municipalities of various powers and functions vested in them under various provisions of this Act, rules and bye-laws, made thereunder.

49. (1) The municipality shall have the following Standing Committees.

- (a) General Standing Committee;
- (b) Finance, Audit and Planning Committee;
- (c) Social Justice Committee.

(2) Each Standing Committee shall consist of not less than three and not more than five members including the President or Vice President, as the case may be, elected by the members of the municipality from amongst the elected members:

Provided that Social Justice Committee shall include at least one member who may be a woman or a member of scheduled caste or of a scheduled tribe.

(3) The President shall be the Ex-officio member and also Chairman of the General Standing Committee and Finance, Audit and Planning Committee. The Vice President shall be the Ex-officio member and Chairman of the Social Justice Committee:

Provided that if the Vice President acts as the President of the municipality, the members of the Social Justice Committee shall elect its Chairman from amongst themselves.

(4) No elected member of the municipality shall be eligible to serve on more than two Standing Committees.

(5) The Executive Officer or the Secretary of the municipality shall be the ex-officio Secretary of every Standing Committee.

50. (1) The General Standing Committee shall perform functions relating to the establishment matters, communications, buildings, urban housing, relief against natural calamities, water supply and all residuary matters.

Functions of the Standing Committees.

(2) The Finance, Audit and Planning Committee shall perform the functions relating to the finance of the municipality, framing of budgets, scrutinising proposals for increase of revenue, examination of receipts and expenditure statements, consideration of all proposals affecting the finances of the municipality, general supervision of the revenue and expenditure of the municipality and co-operation, small saving scheme and any other function relating to the development of the municipal area.

(3) The Social Justice Committee shall perform functions relating to—

- (a) promotion of education, economic, social, cultural and other interests of the scheduled castes and scheduled tribes and Backward Classes, women and other weaker section of the society;
- (b) protection from social injustice and all other forms of exploitation;
- (c) amelioration of the scheduled castes, scheduled tribes and backward classes, women and other weaker sections of the society; and
- (d) securing social justice to the scheduled castes, scheduled tribes, women and other weaker sections of the society.

(4) The Standing Committees shall perform the functions referred to above to the extent the powers are delegated to them by the municipality.

51. (1) The municipalities may frame bye-laws relating to election of members of standing committees, conduct of business therein, and all other matters relating thereto.

Conduct of business by the Standing Committees.

(2) The Chairman of every standing committee shall in respect of the work of the committee, be entitled to call for any information, return, statement, account or report from the office of the municipality and to enter on and inspect any immovable property of the municipality or work in progress connected with the work of the committee.

(3) Each standing committee shall be entitled to require attendance at its meetings of any officer of the municipality who is connected with the

work of committee. The Executive Officer or the Secretary as the case may be, shall under instruction of the committee, issue notice and secure the attendance of such officer.

CHAPTER V

MUNICIPAL FUND AND PROPERTY

Constitution of municipal fund. 52. There shall be formed for each municipality a municipal fund, and there shall be placed to the credit thereof—

- (a) all sums received by, or on behalf of, the municipality under this Act or otherwise; and
- (b) the balance, if any, standing at the credit of the municipal fund of the municipal area at the commencement of this Act.

Application of fund. 53. (1) The municipality shall set apart and apply out of the municipal fund—

- (a) firstly, such sum as may be required for the payment of any amount falling due on any loan legally contracted by it;
- (b) secondly, such sum as the municipality may be required by the State Government to contribute towards the cost of such Directorate of Local Self Government as the State Government may establish for the purpose of advising, assisting and supervising the work of municipalities and other local bodies ;

Provided that such sum shall not exceed an amount equal to one per centum of the income for the financial year preceding the year, in which the municipality is called upon to make the contribution;

- (c) thirdly, such sum as may be required to meet the establishment charges and the salary, allowances, provident fund and gratuity of the members of the municipal services and other municipal employees including such subscriptions and contributions as are referred to in the Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994 ;

of 1994

Provided that the total expenditure on establishment shall not exceed one third of the total expenditure of the municipality.

- (d) fourthly, such sum as may be required to pay the expenses incurred in auditing the accounts of the municipality, and such portion of the cost of any public expenditure by the Central Government or the State Government as may be held by the State Government to be equitably payable by the municipality, in return for services rendered to it ;
- (e) fifthly, such sum as the municipality may be required by the State Government to contribute towards the maintenance of pauper lunatic or pauper lepers sent from any place in the State to mental hospitals or public asylums whether in or outside the State;

- (f) sixty, such sums as may be due to the State Government in respect of the cost of services rendered by it to the municipality and for the maintenance of water works, drainage sewerage, roads, etc. by it on behalf of the municipality:

Provided that an amount allotted to the municipality by the Central or State Government or any other person or local authority for any specified work or purpose shall be utilised exclusively for such work or purpose and in accordance with such instructions as the State Government may either generally or specially issue in this behalf.

(2) Subject to the charges specified in sub-section (1) and to such rules as the State Government may make with respect to the priority to be given to the several duties of the municipality, the municipal fund shall be applicable to the payment in whole or in part of the charges and expenses incidental to the following matters within the municipal area and with the sanction of the State Government outside the municipal area, namely:—

- (a) the construction, maintenance, improvement, cleansing and repair of all public streets, bridges, town-walls, town-gates, embankments, drains, privies, latrines, urinals, tanks and watercourses and the preparation of compost manure ;
- (b) the watering and lighting of such streets or any of them;
- (c) the construction, establishment and maintenance of schools, hospitals and dispensaries, and other institutions for the promotion of education or for the benefit of the public health, and of rest-houses, sarais, poor-houses, markets, stalls, encamping grounds, pounds, and other works of public utility, and the control and administration of public institution of any of these descriptions;
- (d) grants-in-aid to schools, hospitals, dispensaries, poor-houses, leper-asylums, and other educational or charitable institutions;
- (e) the training of teachers and the establishment of scholarships;
- (f) the giving of relief and the establishment and maintenance of relief works in time of famine or scarcity ;
- (g) the supply, storage and preservation from pollution of water for the use of men or animals ;
- (h) the planting and preservation of trees, and the establishment and maintenance of public parks and gardens;
- (i) the taking of vital statistics including the registration of births and deaths, public vaccination and any sanitary measure;
- (j) the holding of fairs and industrial exhibitions;
- (k) the preparation and maintenance of a record of rights in immoveable property;
- (l) all acts and things which are likely to promote the safety, health, welfare or convenience of the inhabitants, or expenditure whereon may be declared by the municipality with the sanction of the State Government to be an appropriate charge on the municipal fund; and
- (m) purposes specified in sections 47 and 48 and for all other purposes for which, by or under this Act or any other law for the time being in force, powers are conferred or duties are imposed upon a municipality;

Provided that no expenditure shall be incurred out of the municipal fund unless provision therefor has been made in the budget of municipality or funds are obtained by re-appropriation duly approved except in such cases as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, no charges or expenses shall be paid from the municipal fund incidental to any matter which has been specifically declared by the State Government by general or special order to be a matter in regard to which expenditure shall be met from the municipal fund.

(4) Subject to the provisions of this Ordinance and the rules and bye-laws, it shall be the duty of the President and of any member presiding at any meeting of the municipality or its committee to disallow the consideration or discussion of any matter for which provision is not made in this section or any other section.

Payment of allowances to the members out of the municipal fund.

54. The allowances payable to the members of the municipalities and their committees, under this Act shall be paid out of the municipal fund constituted under section 52.

Custody of municipal fund

55. (1) In a place where there is a Government treasury or sub-treasury or a nationalised bank or a co-operative bank, a scheduled bank as defined in section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 or a bank to which the Government treasury business has been made over, or a post office, the municipal fund shall be kept in any such treasury, sub-treasury, nationalised bank, co-operative bank, scheduled bank or bank or post office.

2 of 1934

(2) In places where there is no such treasury or sub-treasury or nationalised bank, or co-operative bank or scheduled bank or bank or a post office, the municipal fund, may, with the previous sanction of the Deputy Commissioner, be deposited with any banker, or person acting as a banker, and who has given such security for the safe custody and repayment on demand of the fund so deposited as the Deputy Commissioner may in each case think sufficient.

Explanation.—In this section the expression “co-operative bank” shall mean a co-operative bank which holds a licence for carrying on banking business issued by the Reserve Bank of India under section 22 of the Banking Regulation Act, 1949.

10 of 1949

Power to deposit and invest surplus funds,

56. It shall be lawful for the municipality to deposit at interest in any of the co-operative bank or scheduled banks as defined in section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934, or in a post office, any surplus funds which may not be required for current charges and to invest such funds in the securities of the Central Government and such other public securities as the State Government may specify in this behalf.

2 of 1934

Property vested in a municipality.

57. (1) Subject to any special reservation made or to any special conditions imposed by the State Government, all property of the nature hereinafter in this section specified and situated within the municipal area, shall vest in and be under the control of the municipality and with all other

property which has already vested, or may hereafter vest in the municipality shall be held and applied by it for the purpose of this Act, that is to say:—

- (a) all public town-walls, gates, markets, stalls, slaughter houses, manure and night soil depots and public buildings of every description which have been constructed or are maintained out of the municipal fund;
- (b) all public streams, springs and works for the supply, storage and distribution of water for public purposes, and all bridges, buildings, engines, materials and things connected therewith or appertaining thereto, and also any adjacent land, not being private property appertaining, to any public tank or well;
- (c) all public sewers and drains, and all sewers, drains, culverts and water-courses in or under any public street, or constructed by or for the municipality alongside any public street, and all works, materials and things appertaining thereto;
- (d) all dust, dirt, dung, ashes, refuse, animal matter or filth or rubbish of any kind or dead bodies of animals, collected by the municipality from the streets, houses, privies, sewers, cesspools or elsewhere, or deposited in places fixed by the municipality under section 154;
- (e) all public lamps, lamp-posts and apparatus connected therewith or appertaining thereto;
- (f) all land or other property transferred to the municipality by the State Government or acquired by gift, purchase or otherwise for local public purposes;
- (g) all public streets, not being land owned by the State Government, and the pavements, stones and other materials thereof and also trees growing on, and erections, materials, implements and things provided for such streets.

(2) Where any immovable property is transferred otherwise than by the sale by the State Government to a municipality for public purposes, it shall be deemed to be a condition of such transfer, unless specially provided to the contrary that should the property be at any time resumed by the State Government, the compensation payable therefor shall, in no case exceed the amount, if any, paid to the State Government for the transfer, together with the cost of the present value, whichever shall be less, of any buildings erected on other works executed on the land by the municipality.

(3) The municipality shall maintain a register and a map of all immovable properties of which it is the proprietor, or which vests in it, or which it holds in trust for the State Government.

(4) The Executive Officer may, with the prior approval of the municipality—

- (i) dispose of by sale or otherwise any moveable property belonging to the municipality the value of which does not exceed one lakh rupees; or
- (ii) grant a lease, not exceeding a period of ten years, of any immovable property belonging to the municipality; or
- (iii) sell or grant a lease in perpetuity of any immovable property belonging to the municipality the value of which does not exceed one lakh rupees or the annual rent of which does not exceed ten thousand rupees.

(5) The Executive Officer may, with the prior approval of the municipality, sell or grant a lease in respect of properties, amenities and utility raised on loans from the non-Government sources to liquidate the liabilities.

Inventory
and map of
municipal
property.

58. (1) The municipality shall maintain an inventory and a map of all immovable property of which the municipality is proprietor, or which vests in it or which it holds in trust for the State Government.

(2) The copies of such inventory and map shall be deposited in the office of the Director and such other officer or authority as the State Government may direct and all changes made therein shall forthwith be communicated to the Director or other officer or authority.

Erection
and maintenance
of boundary
marks of
municipal
area.

59. Every municipality shall cease to be erected and set up and thereafter maintain substantial boundary marks defining the limits or the altered limits of the municipal area subject to its authority as set out in the notification issued under section 4.

Management
of public institutions.

60. (1) The management, control and administration of every public institution maintained out of the municipal fund shall vest in the municipality.

(2) When any public institution has been placed under the direction, management and control of the municipality, all property, endowments and funds belonging thereto shall be held by the municipality in trust for the purposes to which such property, endowments and funds were lawfully applicable at the time when the institution was so placed:

Provided that the extent of the independent authority of the municipality in respect of any such institution may be prescribed by the State Government:

Provided further that nothing in this section shall be held to prevent the vesting of any trust property in the Treasurer of Charitable Endowments under the Charitable Endowments Act, 1890.

Acquisition
of land.

61. When any land, whether within or without the limits of municipal area is required for the purposes of this Act, the State Government may, at the request of the municipality proceed to acquire it under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894 and on the payment by municipality of the compensation awarded under that Act, and of any other charges incurred in acquiring the land, the land shall vest in the municipality.

Explanation.—When any land is required for a new street or for the improvement of an existing street, the State Government may on the request of the municipality proceed to acquire in addition to the land to be occupied by the street, the land necessary for the sites of the buildings to be erected on both sides of the street, and such land shall be deemed to be required for the purposes of this Act.

Transfer to
Government
property vesting
in municipality.

62. The municipality may, with the sanction of the State Government, transfer to the State Government any property vesting in the municipality under section 57 or section 60 but not so as to affect any trust or public rights subject to which the property is held.

Power to
takeover
management
of water works,
sewerage works
and roads
etc.

63. (1) Whenever the State Government is satisfied that the municipality has neglected to perform its duties in respect of maintenance or construction of water works, sewerage works or roads and that it is in public interest to take-over the management of such water-works, sewerage works or roads for a period not exceeding ten years, it may, after giving the municipality a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action, make an order to take over the management of water works, sewerage works or roads, as the case may be.

(2) The management of water works, sewerage works or roads, as the case may be, shall revert to the municipality after the expiry of the period

6 of 1890

1 of 1894

for which it was taken over by the State Government or earlier than that if deemed expedient by the State Government.

(3) It shall be the liability of the municipality to pay the expenses, if any, which may be incurred by the State Government as also the liability in respect of the salary and allowances of the persons employed, by the municipality before taking over the management, for and in connection with the maintenance, construction, management and control of the water works, sewerage-works or roads.

(4) Whenever the management of any water-works, sewerage-works or roads of any municipality is taken over by the State Government, the powers, duties and functions of the municipality under this Act in respect of such water-works, sewerage-works or roads shall be exercised and performed by the State Government.

64. (1) The Finance Commission constituted by the State Government under articles 243-I and 243-Y of the Constitution of India read with section 98 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 shall review the financial position of the municipalities and make recommendations to the Government as to.—

Finance
Commis-
sion.

(a) the principles which should govern—

- (i) the distribution between the State and the municipalities of the net proceeds of taxes, duties, tolls and fees leviable by the State, which may be divided between them and the allocation between the municipalities at all levels of their respective shares of such proceeds;
- (ii) the determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to, or appropriated by, the municipalities;
- (iii) the grants-in-aid to the municipalities from the Consolidated Fund of the State;

(b) the measures need to improve the financial position of the municipalities;

(c) any other matter referred to the Finance Commission by the Government in the interest of sound finances of the municipalities.

(2) The Government shall cause every recommendations made by the Finance Commission under this section together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon to be laid before the Legislature of the State.

CHAPTER VI

TAXATION

65. For the purpose of this Act and subject to the provisions thereof every municipality shall impose the following taxes namely:—

Taxes which
municipali-
ty shall im-
pose.

- (a) a tax payable by the owner on buildings and lands which shall not be less than seven and a half per centum and more than twelve and a half per centum, as the State Government may, by notification, direct, of the annual value of such buildings and lands;

- (b) if so authorised by the Government, a duty on transfer of property in the form of a surcharge on the duty imposed by the Indian Stamp Act, 1899 in its application to Himachal Pradesh, on instruments of sale, gift and mortgage with possession of immovable property situated in municipal area at such rate as may be fixed by the Government not exceeding two per cent on, as the case may be, the amount of the consideration, the value of the property or the amount secured by the mortgage, as set forth in the instrument ;

2 of 1899

the said duty shall be collected by the Registrar or sub-Registrar in the shape of non-judicial stamp paper at the time of registration of the document and intimation thereof shall be sent to the municipality immediately. The amount of the duty so collected shall be paid to the municipality concerned.

Taxes that
may be im-
posed.

66. (1) Subject to any general or special orders of the State Government in this behalf and to the rules, a municipality may, from time to time, for the purposes of this Act, impose in the whole or any part of the municipality any of the following taxes, tolls and fees, namely:—

- (i) a tax on profession, trades, callings and employments;
- (ii) a tax on vehicles, other than motor vehicles, plying for hire or kept within the municipal area;
- (iii) a tax on animals used for riding, draught or burden kept for use within the municipal area, whether they are actually kept within or outside the municipal area;
- (iv) a tax on dogs, kept within the municipal area;
- (v) a show tax;
- (vi) a toll on vehicles other than motor vehicles, and other conveyances entering the municipal area;
- (vii) a tax on boats moored within the municipal area;
- (viii) a tax on the consumption of electricity at the rate of one paise for every unit of electricity consumed by any person within the limits of the municipal area;
- (ix) a tax on advertisements other than advertisements published in the newspapers;
- (x) a tax on buildings payable alongwith the application for sanction of the building plans ;
- (xi) a fee with regard to pilgrimages;
- (xii) a fee with regard to drainage;
- (xiii) a fee with regard to lighting;
- (xiv) a fee with regard to scavenging;
- (xv) a fee for clearing of latrines and privies;
- (xvi) a fee in the nature of costs for providing internal services under the scheme framed under section 205.
- (xvii) an education cess;
- (xviii) a local rate on land revenue;
- (xix) with the previous sanction of the State Government, any other tax, toll or fee which the State Legislature has power to impose in the State under the Constitution of India.

(2) The rates of any tax, toll or fee under sub section (1) except that under clause (viii) thereof shall be determined by the municipality :

Provided that such rates shall not exceed the maximum limits which the State Government may from time to time, by notification, specify in this behalf.

67. Nothing contained in sections 65 and 66 shall authorise a municipality to levy any tax, toll or fee which the State Legislature has no power to impose in the State under the Constitution of India :

Limitation of taxing powers.

Provided that any tax, toll or fee which immediately before the commencement of the Constitution was lawfully being levied in any municipal area, may continue to be so levied until provision to the contrary is made by Parliament by law.

Explanation.—In this section 'tax' includes any duty or cess.

68. (1) A municipality, at a special meeting, shall pass a resolution, within a period of thirty days from the date of publication of notification under section 65, directing the imposition of tax with effect from the date to be fixed in the resolution if the municipality fails to pass such a resolution within the aforesaid period, the resolution in this behalf shall be deemed to have been passed by the municipality on the expiry of the period of said thirty days.

Procedure regarding taxes under section 65.

(2) After the resolution is passed or deemed to have been passed under sub-section (1) the State Government shall notify in the Official Gazette the imposition of the tax from the appointed date.

69. (1) The tax on consumption of electricity referred to in clause (viii) of section 66 shall be collected by the Himachal Pradesh State Electricity Board set up under the Electricity (Supply) Act, 1948, or by any other person, as the case may be, supplying electricity for consumption in municipal limits and paid to the municipality concerned :

Collection and payment of tax on consumption of electricity.

Provided that where any person generates electricity for his own use or consumption it shall be paid by such person.

(2) Such tax shall be collected and paid in the same manner as if it were electricity duty payable to the State Government under the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 1975.

(3) Such tax shall not be leviable on the consumption of electricity by the Government of India or where it is consumed in the construction, maintenance or operation of any railway by the Government of India.

70. (1) A municipality may, at a special meeting, pass a resolution to propose the imposition of any tax under section 66.

Procedure to impose taxes under section 66.

(2) When such a resolution has been passed, the municipality shall publish a notice, specifying the class of persons or description of property proposed to be taxed, the amount or rate of the tax to be imposed, and the system of assessment to be adopted.

(3) Any inhabitant, objecting to the proposed tax may, within thirty days from the publication of the said notice, submit his objection in writing to the municipality, and the municipality shall at special meeting take his objection into consideration.

(4) If the municipality decides to amend its proposals or any of them, it shall publish amended proposals, along with a notice indicating that they are in modification of those previously published for objection.

(5) Any objections to the amended proposals which may be received within thirty days of their publication shall be dealt with in the manner prescribed in sub-section (3).

(6) When the municipality has finally settled its proposals, it shall, if the proposed tax falls under clause (i) to clause (vi) of sub-section (1) of section 66, direct that the tax be imposed, and shall forward a copy of its order to that effect, to the Deputy Commissioner, Director and the State Government.

(7) If the proposed tax falls under clauses (vii) to (x/x) of sub-section (1) of section 66, the Deputy Commissioner shall submit the proposals and objections with his recommendation through the Director to the State Government.

(8) The State Government on receiving proposals for taxation under sub-section (7) may sanction or refuse to sanction the same, or return them to the municipality for further consideration.

(9) When—

(a) a copy of order under sub-section (6) and (7) has been received, or

(b) a proposal has been sanctioned under sub-section (8), the State Government shall notify the imposition of the tax in accordance with such order or proposal, and shall in the notification specify a date not less than one month from the date of the notification, on which the tax shall come into force.

(10) A tax leviable by the year shall come into force on the first day of January or on the first day of April or on the first day of July or on the first day of October in any year, if it comes into force on any other day then the first day, of the year by which it is leviable shall be leviable by the quarter till the first day of such year then next ensuing.

(11) A notification of the imposition of a tax under this Act shall be conclusive evidence that the tax has been imposed in accordance with the provisions of this Ordinance.

power of
Government
in respect
of taxation.

71. (1) The State Government, may, by special or general order notified in the Official Gazette, require a municipality to impose any tax, mentioned in section 66 not already imposed, at such rate and within such period as may be specified in the notification and the municipality shall there upon act accordingly.

(2) The State Government may require a municipality to modify the rate of any tax already imposed and thereupon the municipality shall modify the tax as required within such period as the State Government may direct.

(3) If the municipality fails to carry out any order passed under sub-section (1) or sub-section (2) the State Government may, by a suitable order notified in the official Gazette, impose or modify the tax. The order so passed shall operate as if it were a resolution duly passed by the municipality and as if the proposal was sanctioned in accordance with the procedure contained in section 70.

72. The municipality shall cause an assessment list of all buildings and lands on which any tax is imposed to be prepared, containing --

Preparation of assessment list.

- (a) the name of the street or division in which the property is situated;
- (b) the description of the property, either by name or by number sufficient for identification;
- (c) the names of the owner and occupier, if known;
- (d) the annual value;
- (e) the amount of the tax assessed thereon by the municipality.

73. When the assessment list has been completed, the municipality shall give public notice thereof and of the place where the list or a copy thereof may be inspected; and every person claiming to be either owner or occupier of property included in the list, and any authorised agent of such person, shall be at liberty to inspect the list and to make extracts therefrom without charge.

publication and completion of assessment lists.

74. (1) The municipality shall at the time of the publication of such assessment list give public notice of a time, not less than one month thereafter, when it will proceed to revise the valuation and assessment, and in all cases in which any property for the first time assessed, or the assessment thereof is increased, it shall give a specific notice thereof to the owner or occupier of the property.

Public notice of time fixed for revising assessment lists.

(2) All objections to the valuation and assessment shall be made in writing before the time fixed in the notice, or orally or in writing at that time.

75. (1) After the objections have been enquired into and the persons making them have been allowed an opportunity of being heard either in person or by authorised agent, as they may think fit, and the revision of the valuation and assessment has been completed, the amendments made in the list shall be authenticated by the signatures of not less than two members of the municipality who shall at the same time certify that no valid objection has been made to the valuation and assessment contained in the list, except in the cases in which amendments have been entered therein; and, subject to such amendments as may thereafter be duly made, the tax so assessed shall be deemed to be the tax for the year commencing on first day of April of the year in which notice was issued under section 73 or section 74 of this Act:

Settlement of list.

Provided that this date will not be earlier to the date on which the building comes into existence.

(2) The list when amended under this section shall be deposited in the office of the municipality and the same shall be kept open for inspection during office hours to all owners or occupiers of property comprised therein or the authorised agents of such persons, and a public notice that it is so open shall forthwith be published.

Further
amendments
of assess-
ment list.

76. (1) The municipality may at any time amend the list by inserting the name of any person whose name ought to have been or ought to be inserted, or by inserting any property which ought to have been or ought to be inserted, or by altering the assessment on any property which has been erroneously valued or assessed through fraud, accident or mistake, whether on the part of the municipality or of the assessee, or in the case of a tax payable by the occupier by a change in the tenancy, after giving notice to any person affected by the amendment, of a time, not less than one month from the date of service, at which the amendment is to be made.

(2) Any person interested in any such amendment may tender his objection to the municipality in writing before the time fixed in the notice, or orally or in writing at that time, and shall be allowed an opportunity of being heard in support of the same in person, or by authorised agent, as he may think fit.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, the municipality may with a view to give effect to the annual value as defined in clause (1) of section 2 of this Act, amend the assessment list of the year commencing on the first day of April of the relevant year for increasing or reducing annual value of any property and of the assessment thereupon after giving notice at any time to any person affected by the amendment of a period not less than one month from the date of service at which the amendment is to be made and the municipality shall consider any objection made in this regard by any such person and the amended assessment list shall come into force with effect from the first day of April of the year in which notice was given to the person affected.

New list
need not to
be prepared
every year.

77. It shall be in the discretion of the municipality to prepare for the whole or any part of the municipal area a new assessment list every year or to adopt the valuation and assessment contained in the list for any year, with such alterations as may in particular cases be deemed necessary, as the valuation and assessment for the year, giving to persons affected by such alterations the same notice of the valuation and assessment as if a new assessment list had been prepared:

Provided that the valuation and assessment contained in the list for any year shall not be adopted for a period exceeding five years.

Tax not
invalid for
defect of
form.

78. No assessment and no charge or demand of any tax made under the authority of this Act shall be impeached or affected by reason of any mistake in the name, residence, place of business or occupation of any person liable to pay the tax, or in the description of any property or thing liable to the tax, or of any mistake in the amount of assessment or tax, or by reason of any clerical error or other defect of form; and it shall be enough in respect of any such tax on property or any assessment of value for the purpose of any such tax if the property taxed or assessed is so described as to be generally known; and it shall not be necessary to name the owner or occupier thereof.

79. (1) A municipality may exempt, in whole or in part, for any period not exceeding one year, from the payment of any such tax, any person who by reason of poverty may in its opinion be unable to pay the same, and may renew such exemption as often as may be necessary.

Power of municipality to exempt payment of taxes.

(2) A municipality, by a resolution passed at a special meeting and confirmed by the State Government, may—

- (a) provide that all or any persons may be allowed to compound for taxes imposed under section 65, under clauses (ii), (iii), (iv), (vi), (xii), (xv), (xvi) and (xix) of sub-section (1) of section 66 and under section 67;
- (b) abolish, suspend or reduce in amount any tax imposed under section 65, 66 and 67;
- (c) exempt in whole or in part from the payment of any such tax, any person or class of persons or any property or description of property.

80. (1) The State Government may by order exempt in whole or in part from the payment of any such tax by any person or class of persons or any property or description of property.

Power of State Government to exempt payment of taxes.

(2) If at any time it appears to the State Government on complaint made or otherwise, that any tax imposed under the foregoing sections is unfair in its incidence or that the levy thereof or of any part thereof is injurious to the interests of the general public, it may require the municipality to take within a specified period measures to remove the objection; and if within that period the requirement is not complied with to the satisfaction of the State Government, the State Government may, by notification, suspend the levy of the tax or of such part thereof until the objection has been removed.

81. (1) When any property assessed to a tax under clause (a) of section 65 which is payable by the year or by instalments, has remained unoccupied and unproductive of rent throughout the year or the period in respect of which any instalment is payable, the municipality shall remit the amount of the tax or of the instalment, as the case may be:

Remission of tax on unoccupied immovable property.

Provided that no such remission shall be granted unless notice in writing of the circumstances under which it is claimed has been given to the municipality within the first month after the expiry of the period in respect of which it is so claimed.

(2) When any such property as aforesaid—

- (a) has not been occupied or productive of rent for any period of not less than sixty consecutive days; or
- (b) consists of separate tenements, one or more of which has or have not been occupied or productive of rent for any such period as aforesaid; or
- (c) is wholly or in greater part demolished or destroyed by fire or otherwise;

the municipality may remit such portion, if any, of the tax or instalment as it may think equitable.

(3) The burden of proving the facts entitling any person to claim relief under this section shall lie upon him.

(4) For the purposes of this section neither the presence of a caretaker nor the mere retention in an otherwise unoccupied dwelling house of the furniture habitually used in it shall constitute occupation of the house.

(5) For the purposes of this section a house shall be deemed to be productive of rent if let to a tenant who has a continuing right of occupation thereof, whether it is actually occupied by such tenant or not.

(6) The enquiry necessary for a decision whether any relief should be granted under this section shall be held by the Executive Officer or the Secretary who shall make such recommendation to the municipality as he may deem proper:

Provided that the municipality shall not grant any remission of tax unless such remission is recommended by the Executive Officer or the Secretary.

Duty to
furnish in-
formation.

82. (1) Every person shall on the demand of an officer duly authorised by the municipality in this behalf furnish such information as may be necessary in order to ascertain whether such person is liable to pay any municipal tax; and every hotel or lodging house keeper or Secretary of a residential club shall also on demand made as aforesaid furnish a list of all persons residing in such hotel, lodging-house or club.

(2) If any person so called upon to furnish such information omits to do so or furnishes information which is untrue, he shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than five hundred rupees.

Notice on
transfers of
titles.

83. (1) Whenever the title to or over any building or land of any person primarily liable for the payment of property taxes on such property is transferred, the transferor and the transferee shall within three months of the registration of the deed of transfer if it be registered, or if it be not registered within three months of its execution, or if no instrument be executed, of the actual transfer, give notice in writing of such transfer to the municipality.

(2) Every person primarily liable for the payment of a tax on any property, who transfers his title to or over such property, without giving notice of such transfer to the municipality as aforesaid, shall in addition to any other liability which he incurs through such neglect, continue liable for the payment of all such taxes from time to time payable in respect of the said property until he gives such notice, or until the transfer is recorded in the books of the municipality.

(3) Whenever the title to or over any building or land has devolved upon any person by inheritance, the heir shall within three months of the date of the death of the former owner give notice in writing of such inheritance to the municipality.

(4) Nothing in this section shall be held to diminish the liability of the transferee or heir for the said taxes or to affect the prior claim of the municipality for the recovery of the taxes due thereupon.

(5) Whoever contravenes the provisions of sub-sections (1) and (3) shall in addition to any other penalty which he incurs through such neglect, be punishable with a fine which shall not be less than twenty-five rupees and more than two hundred rupees, and in the case of a continuing breach with a further fine of ten rupees for every day after the first during which the breach continues.

84. The municipality may authorise any person—

Power of entry.

(a) after giving twenty-four hours notice to the occupier, or, if there be no occupier, to the owner, of any building or land, at any time between sunrise and sunset, to enter, inspect and measure any building for the purpose of valuation ;

(b) to enter and inspect any stable, coach-house or other place where in there is reason to believe that there is any vehicle or animal liable to taxation under this Act or for which a licence has not been duly taken out.

85. Subject to the provisions of section 68, sub-sections (7) and (8) of section 70 and section 75 and tax imposed under this Chapter and payable periodically shall be payable on such dates and in such instalments, if any, as the municipality, with the previous sanction of the Deputy Commissioner, may from time to time direct.

Taxes when payable.

86. (1) When any sum is due on account of a tax payable under this Act in respect of any property by the owner thereof, the municipality shall cause a bill for the amount, stating the property and the period for which the charge is made to be delivered to the person liable to pay the same.

Recovery of property taxes.

(2) If the bill be not paid within ten days from the delivery thereof, the municipality may cause a notice of demand to be served on the person liable to pay the same, and if he does not, within seven days from the service of the notice, pay the sum due, with any fee leviable for the notice or show sufficient cause for non-payment, the sum due, with the fee, shall be deemed to be an arrear of tax.

(3) The amount of every such arrear, besides being recoverable in any other manner provided by this Act shall, subject to any claim on behalf of the State Government, be a first charge on the property in respect of which it is payable and shall be recoverable on application made in this behalf by the municipality to the Collector, as if the property were an estate assessed to land revenue and the arrear were an arrear of such revenue due thereon.

(4) If any tax or sum leviable under this Act from the owner is recovered from the occupier, such occupier shall, in the absence of any contract to the contrary, be entitled to recover the same from the owner and may deduct the same from the rent then or thereafter due by him to the owner.